

ट्रेड यूनियन शिक्षा व्याख्यान टिप्पणियाँ

[पहला-दूसरा भाग]

ए० बी० बर्धन



राजस्थान पीपुलस पब्लिशिंग हाउस (ग्रा)लि.
चमोलीवाला मार्केट, सभ. आई. रोड, जयपुर-302001

**TRADE UNION EDUCATION
का हिन्दी अनुवाद**

एटक (अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस)
के सहयोग से प्रकाशित

राजस्थान पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा०) लि०
चमेलीवाला मार्केट, एम० आई० रोड,
जयपुर-302001

1988 (RPPH-36)

मूल्य : 7.50

भारती प्रिण्टर्स, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32 द्वारा मुद्रित तथा रामपाल द्वारा
राजस्थान पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा०) लि०, जयपुर की ओर से प्रकाशित

विषय-सूची

द्वितीय संस्करण पर टिप्पणी

5

आमुख

7

पहला भाग

1. मजदूर वर्ग का उद्भव और विकास एवं ट्रेड यूनियनों का उदय	11
2. भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का उदय	14
3. मजदूर वर्ग और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम	20
4. राजनीतिक प्रवृत्तियों के बीच संघर्ष और परिणामस्वरूप ट्रेड यूनियन आंदोलन में फूट	27
5. भारतीय अर्थव्यवस्था और कार्यशक्ति में स्वातंत्र्योत्तर विकास क्रम	34
6. स्वातंत्र्योत्तर मजदूर वर्ग-संघर्ष और ट्रेड यूनियन आंदोलन	43
7. संभिल निष्कर्ष	52
8. भारतीय मजदूर और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन आंदोलन	59
9. ट्रेड यूनियन का चरित्र	67
10. क्रांतिकारी ट्रेड यूनियनवाद बनाम सुधारवादी ट्रेड यूनियनवाद	73

द्वितीय भाग

11. मजदूरी का प्रश्न	80
12. मजदूरी का प्रश्न (जारी)	87
13. महँगाई भत्ते का प्रश्न	94
14. मजदूरी संघर्ष के निष्कर्ष एवं जारी बहस	101

15. አነዱ ሆኖ የተዘጋጀው ይገባል
111 116
16. የተዘጋጀው ይገባል : ይመስቀላለሁ የተዘጋጀበት ተቋም ይገባል
123 129
17. ይዘሩ ይታወች
147 138
18. ይመስቀላለሁ የተዘጋጀበት
19. ይመስቀላለሁ የተዘጋጀበት (የተገኘው)
20. የተዘጋጀው የተዘጋጀበት የተዘጋጀበት የተዘጋጀበት

द्वितीय संस्करण पर टिप्पणी

इस पुस्तक का पहला संस्करण इसके प्रकाशन के थोड़े समय में ही बिक गया था। यह उस इच्छा को प्रदर्शित करता है, जो काड़रों और सामान्य कार्यकर्ताओं में ट्रेड यूनियन शिक्षा के प्रति पायी जाती है।

इस बीच इस पुस्तक की प्रतियों के लिए ढेरों आदेश जमा हो गये हैं। भिन्न-भिन्न दृष्टियों से पुस्तक में सुधार करने व संशोधित करने के लिए विभिन्न तबक्कों से सुझावों को इकट्ठा करने और उन्हें सम्मिलित करने के लिए समय बहुत थोड़ा रहा है। थोड़े-बहुत जरूरी सुधारों के साथ इस दूसरे संस्करण को प्रकाशित करना ही एकमात्र विकल्प बचा है।

ट्रेड यूनियन शिक्षा एक निरन्तर प्रक्रिया है। मैं आशा करता हूँ कि निकट भविष्य में ट्रेड यूनियन क्षेत्र में लगे हुए 'शिक्षक', 'विद्यार्थी' व साथी अपनी प्रतिक्रियाएँ व सुझाव लिखने के लिए समय निकालेंगे और उन्हें एटक को भेजेंगे, जिससे अगली बार इसे और ज्यादा सुधारा जा सके।

नयी दिल्ली

—ए० बी० बर्धन

10-9-87

आमुख

एटक के सक्रिय कार्यकर्ताओं और दूसरे ट्रेड यूनियन काडरों के लिए यह व्यवस्थित अध्ययन-क्रम का प्रयास है।

ट्रेड यूनियन कार्य एक विशिष्टता है, और हर गुजरते दिन के साथ ट्रेड यूनियन मसले, ट्रेड यूनियन कार्य और ट्रेड यूनियन रणनीतियाँ, दिन-प्रतिदिन के ट्रेड यूनियन संघर्ष, मजदूर वर्ग के सामान्य वर्ग-संघर्षों और समकालीन विश्व की समस्याओं से जुड़ते हुए अधिकाधिक जटिल होते जा रहे हैं। इसलिए सक्रिय कार्यकर्ताओं और काडरों के लिए ट्रेड यूनियन शिक्षा पहली प्राथमिकता का कार्य है। तैरना सीखने के लिए एक व्यक्ति को पहले पानी में कूदना चाहिए या उसमें धकेल दिया जाना चाहिए। मगर यदि उस व्यक्ति को दाँवपेच और तकनीक को जानने और लहरों व धाराओं से संघर्ष करने की दक्षता हासिल करते हुए एक योग्य तैराक होना है तो उसे कठोर प्रशिक्षण के क्रम से गुजरना होगा। यही बात ट्रेड यूनियन कार्य के साथ भी है। यहाँ एक व्यक्ति को मजदूरों के बीच जाने से शुरुआत करनी होती है और संपर्क में आये मजदूरों के विशिष्ट तबके की स्थितियों और समस्याओं से स्वयं परिचित होना होता है। लेकिन इसके बाद, मूलभूत चीजों के बारे में जानकारी की कमी, या वस्तुस्थिति को समय और संयोगों के भरोसे छोड़ देना कोई अच्छी बात नहीं है। “अज्ञानता आज तक कभी भी किसी के लिए उपयोगी नहीं रही है।”

विशेषतया ट्रेड यूनियनों में मजदूरों के संयुक्त होने के बारे में बोलते हुए, कार्ल मार्क्स ने कहा था, “उनके (मजदूरों के) पास सफलता प्राप्त करने का एक ही तत्व है—संख्या : लेकिन संख्या तभी महत्व रखती है जबकि वह संगठित हो और ज्ञान द्वारा निर्देशित हो।”

यहाँ ‘ज्ञान’ से तात्पर्य ट्रेड यूनियन कार्यों के सिद्धांत और व्यवहार की जानकारी, उस वैज्ञानिक समाजवाद की जानकारी से है, जो क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन गतिविधियों का संदर्भान्तक आधार है।

यह अध्ययन-क्रम ज्ञान के भंडारण्ह का प्रवेशद्वारा है।

इस अध्ययन-क्रम में 29 अध्याय हैं, जिन्हें तीन भागों में बाँटा गया है।

पहले भाग में, सामान्यतः ट्रेड यूनियन आंदोलन के ऐतिहासिक विकास का और विशेष रूप से भारत में उसके विकास का वर्णन किया गया है।

दूसरे भाग में, ट्रेड यूनियन कार्यप्रणाली के विविध पक्षों और उन साधारण कार्यों, जिन्हें हमारी यूनियनों को आज अपने देश में संभालना है—आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, कानूनी, आदि को समाहित किया गया है।

तीसरा भाग समकालीन विश्व की कुछ समस्याओं के बारे में है, जो मजदूर वर्ग के सामने नयी चुनौतियाँ खड़ी कर रही हैं और जो नयी परिस्थितियों में प्रतिदिन के कार्यों को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों से जोड़े जाने की मांग करती हैं।

इन अध्यायों को तैयार करने में, मैंने उपलब्ध सामग्री और स्रोतों, जिसमें पाठ्यक्रम का वह मूल ढाँचा भी सम्पुलित है जिसका उपयोग भिन्न-भिन्न स्थानों पर हमारे साथी पिछले वर्षों में करते रहे हैं, की मदद ली है। इस उद्देश्य के लिए कई वर्ष पूर्व चलाये गये अत्यंत उपयोगी केन्द्रीय ट्रेड यूनियन विद्यालय के अनुभव का भी उपयोग किया गया है।

कुछ मुद्दों पर मैंने विस्तार से चर्चा की है जबकि कुछ पर कम। इससे अध्याय उल्टे-सीधे दिखायी पड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा एक उद्देश्य के तहत किया गया है। जहाँ मुझे लगा कि एक औसत अध्यापक स्वयं स्रोत सामग्री को छू पाने में असमर्थ रहेगा, या फिर कुछ मुद्दों पर बल देने से बचेगा, वहाँ मैंने कुछ विस्तार से लिखने का ध्यान रखा है। ऐसा दूसरे मुद्दों के साथ नहीं किया गया है, जहाँ सामग्री पहले ही आसानी से उपलब्ध है।

कुछ दोहराव भी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो चीज़ एक अध्याय में एक कोण से दी गयी है, अगले अध्याय में उसी को दूसरे कोण से उठाया गया है। इस प्रकार के अध्ययन-क्रम में ऐसा अपरिहार्य है। वास्तव में यह नैरन्तर्य को बनाये रखने और अन्तर्निहित संबंध पर बल देने के लिए आवश्यक है।

प्रत्येक अध्याय आवश्यक रूप से उस विषय पर दिये गये व्याख्यान से मेल नहीं खाता। उपलब्ध समय, समूह के स्तर और कक्षा के मुख्य लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक ही अध्याय एक से अधिक व्याख्यान-सत्र में खींचा जा सकता है, या फिर इसका उलट, यानी एक ही व्याख्यान में दो अध्यायों को समेटा जा सकता है। ऐसा प्रत्येक अवसर पर किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए—नये-नये तथ्य और आँकड़े, जो हर रोज़ पैदा होते रहते हैं—एक शिक्षक को अपने व्याख्यान में उनका उपयोग करना चाहिए।

सबसे कठिन चीज़ थी काड़ों के स्तर को चुनना, जिस पर यह अध्ययन-क्रम केन्द्रित है। यहाँ सारा बल बीच के स्तर पर केन्द्रित है—न तो नये प्रवेशार्थियों

और सामान्य कार्यकर्ताओं पर और न ही उच्चस्तरीय कार्यकर्ताओं व सर्वोच्च नेतृत्व पर ।

अपनायी गयी विधि मुख्य रूप से विश्लेषणात्मक होने के बजाय ऐतिहासिक है । ऐतिहासिक विधि सहज रूप से गणनीय है और गहन प्रभाव डालती है । यह वर्तमान को भली प्रकार समझने और भविष्य के लिए तैयार होने के योग्य बनाती है । इसके अलावा ट्रेड गूनियन आंदोलन निरन्तर विकासशील और गतिशील आंदोलन है । अतएव, इसका अध्ययन एक परिवर्तनशील यथार्थ की प्रक्रिया के रूप में किया जाना चाहिए, ऐसी प्रक्रिया जिसमें सामाजिक यथार्थ बदलता है, मज़दूर वर्ग बदलता है, यहाँ तक कि आंदोलन में भी परिवर्तन होते हैं—इनमें से प्रत्येक दूसरे परिवर्तनों को लाने में अपना योगदान देता है ।

नयी-नयी समस्याएँ सामने आती हैं । नयी चुनौतियाँ पैदा होती हैं । नये समाधान खोजने होते हैं । नयी उपलब्धियाँ हासिल होती हैं, नये तथ्यों, यहाँ तक कि नयी सांख्यिकीय सामग्री का भी आन रखना होता है, इसलिए इसके साथ हम-कदम होने के लिए अध्ययन-काम में भी निरन्तर संशोधन और परिवर्तन होते रहते चाहिए ।

आशा है कि आने वाले समय में ट्रेड गूनियन शिक्षा को गम्भीरतापूर्वक लिया जाएगा । और यदि इस अध्ययन-काम से इस कार्य में मादर मिलती है, तो इसका उद्देश्य सार्थक सिद्ध होगा ।

नयी दिल्ली

10 नवम्बर, 1986

पहला भाग

पाठ । १

मज़दूर वर्ग का उद्भव और विकास एवं ट्रेड यूनियनों का उदय

—मज़दूर वर्ग के उद्भव और उसमें विकास के साथ ही हम आधारिक सघषा—शोषित मज़दूरों और शोषक स्वामियों यानी पूँजीपतियों के बीच संघर्षों—के जन्म और विकास का पता लगा सकते हैं। इससे मज़दूरों के बीच, और इस प्रकार ट्रेड यूनियनों के संयोजनों के विभिन्न रूप पैदा होते हैं।

—ऐतिहासिक और तार्किक रूप से पूँजीवादी उत्पादन और इस प्रकार पूँजीवादी शोषण की शुरुआत तब होती है जब प्रत्येक पूँजीपति एक पूँजीवादी प्रशासन के तहत एक तरह की वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए एक ही जगह एक साथ बहुत बड़ी संख्या में मज़दूरों को काम पर रखता है। उत्पादन के साधनों के विकास की एक निश्चित अवस्था में यह जरूरी और सम्भव हो पाता है।

पूँजीपति उत्पादन के साधनों पर और बहुतेरे मज़दूरों की श्रमशक्ति का उपयोग करने का अधिकार रखने के कारण संकेन्द्रित सामाजिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि मज़दूर के पास मज़दूरी के बदले पूँजीपति को बेचने के लिए केवल निजी श्रमशक्ति ही होती है।

[“बुर्जुआ वर्ग से अभिप्राय सामाजिक उत्पादन के साधनों के स्वामी और वेतनभोगी मज़दूरों के नियोक्ता यानी आधुनिक पूँजीपति वर्ग से हैं। सर्वहारा का अर्थ आधुनिक वेतनभोगी मज़दूर से है जो उत्पादन के साधनों पर अधिकार न होने के कारण जीवित रहने के लिए अपनी श्रमशक्ति बेचने के लिए मज़दूर है।”¹¹]

—श्रमशक्ति के विक्रेता के रूप में मज़दूर और क्रेता के रूप में पूँजीपति के बीच दिखायी पड़ने वाली समानता उस वास्तविक असमानता, जो उपरोक्त संबंधों से पैदा होती है, को ढक देती है जहाँ अलग-अलग बिखरा हुआ, स्वयं अपने लिए ही खड़ा हुआ, और अपने जैसे ही दूसरे लोगों से प्रतियोगिता करता हुआ एक अकेला मज़दूर पूँजीपति का सामना करता है।

—ट्रैड यूनियनें मजदूरों की आपसी प्रतियोगिता को रोकते और पूँजीपति से ऐसी शर्त हासिल करते के उद्देश्य से, एक-दूसरे के निकट आने के आकस्मिक प्रत्यानों के कलत्वरूप पैदा और विकसित हुई, जिनसे उनकी स्थिति में सुधार हो और जो उन्हें कीतदास के स्तर से ऊपर उठा सके। मजदूरों के पास एक ही सामाजिक शक्ति है, वह है उनकी संख्या की शक्ति। मगर संख्या का तभी अर्थ है जब उनमें एकता और संगठन हो। यह समझने के लिए कि संघर्ष और अनुबव के द्वारा यह किस प्रकार संभव हुआ, हमें कार्ल मार्क्स के इस स्पष्ट वर्णन की ओर ध्यान देना चाहिए :

“सर्वहारा वर्ग विकास के विभिन्न चरणों से गुजरता है। अपने जन्म से ही इसका पूँजीपति वर्ग से संघर्ष आरम्भ हो जाता है। पहले-पहल यह लड़ाई मजदूरों द्वारा निजी स्तर पर, किरए एक फैंकर्टरी में काम पर लगे लोगों द्वारा, और फिर एक व्यवसाय में कार्यरत मजदूरों द्वारा एक स्थान पर व्यक्तिगत रूप से एक पूँजीपति के खिलाफ चलायी जाती है जो प्रत्यक्ष रूप से उनका शोषण करता है। उनके हमलों का निशाना उत्पादन की पूँजीवादी स्थितियाँ नहीं होतीं, बल्कि स्वयं उत्पादन के उपकरण होते हैं; वे उन आयातित व्यापारिक वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं जो उनके श्रम से प्रतियोगिता करती हैं, वे मशीनों को तोड़-फोड़ देते हैं, वे फैंकर्टरियों को आग लगा देते हैं, वे मध्ययुग के श्रमिकों की नष्ट हो गयी हैं। इस स्थिति को बल प्रयोग द्वारा पुनर्स्थापित करने की कोशिश करते हैं। “इस स्थिति में सारे देश में बिखरे हुए और आपसी प्रतियोगिता से दृढ़ हुए मजदूर एक बेमेल समूह निर्मित करते हैं…।

“लेकिन उच्चों के विकास के साथ-साथ सर्वहारा में न केवल संख्यात्मक बढ़ि होती है, बल्कि यह और बड़े समूहों में संकेंद्रित हो जाता है, इसकी ताकत बढ़ती है—और वह अपनी ताकत को बढ़ाता हुआ महसूस करता है…श्रमिकों और पूँजीपतियों के बीच टकराव अधिकाधिक दो वर्गों के बीच की टकरावों की विशेषताएँ हासिल करने लगता है। परिणामस्वरूप मजदूर पूँजीपति वर्ग के खिलाफ ट्रैड यूनियनों के रूप में एकत्र होते लगते हैं; मजदूरी की दरों में बढ़ि हेतु वे एकत्र हो जाते हैं, कभी भी भड़क उठने वाले बिदोहों के लिए पहले से ही तैयारी के लिए वे स्थायी संघों का निर्माण करते हैं…।

“कभी-कभी मजदूर विजयी होते हैं, लेकिन कुछ ही समय के लिए। उनके संघर्ष का वास्तविक प्रतिक्रिया तात्कालिक परिणाम में नहीं, बल्कि मजदूरों के लगातार विकृत होते संघों में निहित होता है। यह समूहबद्धता आधुनिक उद्योग द्वारा पैदा किये गये संचार के परिवर्तन साथों द्वारा लाभान्वित होती है जो भिन्न-भिन्न स्थानों के मजदूरों को एक-दूसरे के संपर्क में आने में मदद करती है। यही संपर्क शा जिसके एक ही चरित्र वाले विभिन्न स्थानीय संघर्षों को विभिन्न वर्गों के

बीच एक राष्ट्रीय संघर्ष में संकेन्द्रित करने की ज़रूरत थी...²

—इससे इस प्रचार और निन्दा का हमारे देश और विदेशों में शून्य निणायिक रूप से साधित हो जाता है कि मजदूर संगठन और मजदूर आंदोलन स्वार्थी व संकीर्ण प्रवाचिताओं से प्रेरित कुछ मुट्ठीभर 'ध्यावसायिक विद्रोहियों' की कारणजारी है। ट्रेड यूनियन मजदूर वर्ग के बीच से, अमानवीय शोषण के खिलाफ अपने संघर्षों से और मजदूरों के दुखों व कठोरों की आँख से मजबूत होते हुए पैदा हुए हैं। वे किसी के उक्साके का परिणाम नहीं हैं, वरन् इतिहास का अपरिहार्य प्रयाण है।

ट्रेड यूनियन आंदोलन की जड़े स्वर्यं जीवन में गहरे बँसी हैं।

—अपने जीवनकाल में मजदूर विभिन्न संगठन बनाते हैं। लेकिन ट्रेड यूनियन मजदूर वर्ग के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जन-संगठन है। ट्रेड यूनियन ही अपने भीतर व्यापक मेहनतकाश समझे यानी समृद्धि को समाहित कर सकते हैं। आज के समय में वे ही मजदूरों के संगठन और उनके संघर्षों का केन्द्र-बिन्दु हैं। अधिकांश देशों में ट्रेड यूनियन ही कुल मिलाकर सबसे बड़े जन-संगठन और सक्रिय रूप में प्रगति की ओर उत्तमत्व सर्वाधिक शक्तिशाली सामाजिक शक्तियां हैं।

टिप्पणियाँ :

1. कम्युनिस्ट धोषणापत्र में केंडरिक एंगेल्स द्वारा दी गयी टिप्पणी ।
2. कम्युनिस्ट धोषणापत्र : मार्क्स और एंगेल्स

जल्दर पढ़ें :

1. कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो : मार्क्स और एंगेल्स

पाठ : 2

भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का उदय

— औपनिवेशिक भारत में विलम्बित और परोक्ष पूँजीवादी विकास के कारण भारत में आधुनिक मज़दूर वर्ग के उद्भव में विलम्ब हुआ। यह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में आधुनिक कारखानों के स्थापित होने और खानों, बागानों, रेलवे व संचार माध्यमों के आरम्भ होने के साथ ही उत्पन्न हुआ।

ब्रिटिश औद्योगिक पूँजी के पास भारतीय उपनिवेश के लिए एक स्पष्ट व सोची-समझी नीति थी। वर्ष 1813 के अन्त तक व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को तोड़ते हुए इसने औद्योगिक पूँजीवादी शोषण की शुरुआत की। इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश पूँजी के ऐसे कृषि-स्रोत में बदलना था जो कच्चे माल की पूर्ति कर सके और अपने यहाँ तैयार माल के लिए बाजार प्रदान कर सके। इसका उद्देश्य हमारे संसाधनों को निचोड़ना और अपने पूँजी संचयन के लिए अधिकतम कर उगाहना था। नयी भूमि व्यवस्थाएँ लागू की गयीं जिन्हें नै मालिकों और बिचौलियों के एक नये वर्ग को थोप दिया और हमारे किसानों के ऊपर लगान और कर्ज़दारी का बोझ कई गुना बढ़ा दिया। भारतीय निर्माण और दस्तकारी उद्योगों के लगभग सम्पूर्ण विनाश ने लाखों दस्तकारों और कारीगरों को उत्पादन के साधनों से वंचित कर दिया और उन्हें जबर्दस्त ढंग से बर्बाद कर दिया। कृषि को नष्ट होने दिया गया जिससे देश में भुखमरी फैलने लगी। इसका परिणाम तबाह कर देने वाले अकालों की सृँखला में हुआ। 1825 से 1900 के दौरान क़रीब दो करोड़ लोग मर गये। लाखों लोग बागानों में काम करने के लिए समुद्रपार सुदूर ब्रिटिश उपनिवेशों में करारशुदा मज़दूरों के रूप में ले जाए गये। और अन्य लाखों लोगों को नये शहरों और उभरते हुए औद्योगिक केन्द्रों में जमा होने को मजबूर कर दिया जहाँ उन्हें कारखानों, खानों, बागानों और रेलवे लाइनों में काम मिल सके।

— वित्तीय पूँजी और इसके शासन यानी साम्राज्यवाद के साथ और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पराजय के साथ ही, कम्पनी को अन्तिम

रूप से समाप्त कर दिया गया, और ब्रिटिश पूँजी भारत में, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में आने लगी जिन्होंने भारतीय बाजार को ब्रिटिश घुसपैठ के लिए खोल दिया और जो ब्रिटिश निर्माण उद्योग के खिलाफ प्रतियोगिता में नहीं आ रहे थे। रेल और तार लाइनों का जाल बिछा दिया गया। बागानों और कोयला खानों का विकास किया गया। सूती कपड़ा और जूट मिलें स्थापित की गयीं।

पहली सूती कपड़ा मिल ने 1853 में बम्बई में उत्पादन कार्य शुरू कर दिया। 1858 में बंगाल में रिशड़ा में पहली जूट मिल में उत्पादन शुरू हो गया। पहली रेल लाइन 1852 में बिछायी गयी।

—ब्रिटिश निवेश के चलते, विशेषकर सूती कपड़ा उद्योग, नये भारतीय पूँजीपति वर्ग को आर्कषित करने लगे। जिसका व्यापारिक सूदखोर और वणिक समुदाय से उद्भव हो रहा था। भारतीय पूँजी को निश्चय ही ब्रिटिश पूँजी के साथ सहयोग करके और साथ ही कड़ी प्रतियोगिता करके अपना रास्ता बनाना था।

—इस तरह नये वर्ग और नयी शक्तियाँ—उभरता हुआ पूँजीपति वर्ग, अंग्रेजी पढ़ा-लिखा मध्य-वर्ग, गरीब किसानों और दस्तकारों के समूह से पैदा होता हुआ आधुनिक मज़दूर वर्ग—ये सब भारतीय दृश्यपटल पर उभरने लगे। औद्योगिक विकास की धीमी और डॉवाडॉल प्रक्रिया ने तथा उसके विशिष्ट रूप ने भी एक लम्बे समय तक भारतीय मज़दूर वर्ग के ढाँचे को निर्धारित करने का काम किया। सूती कपड़ा, जूट और रेलवे मज़दूर देश के उभरते हुए सर्वहारा के मुख्य तत्व थे।

—1914 तक, भारत में औद्योगिक मज़दूरों की संख्या फ़िक्टरी-एक्ट के अनुसार 9,51,000 थी। 1914 और 1918 के बीच, युद्ध के दबावों की वजह से, उद्योग की कुछ शाखाओं का तीव्र विस्तार हुआ। 1921 की औद्योगिक जनगणना के अनुसार कुल मिलाकर 26 लाख मज़दूर थे जो दस या इससे अधिक मज़दूरों को काम पर रखने वाले संस्थानों में लगे हुए थे। यह प्रक्रिया विश्व आर्थिक संकट और पूँजीवाद के चक्रीय संकट के दौरान न सिर्फ़ धीमी हो गयी बल्कि इसे धक्का भी पहुँचा जिससे द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारम्भ तक आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योगों में मज़दूरों की संख्या 35 लाख से अधिक न रही। यह सिर्फ़ आजादी और तीव्र विकास की इच्छा के बाद ही सम्भव हुआ कि भारतीय सर्वहारा की ताकत तेजी से बढ़ी। लेकिन इसका अध्ययन हम बाद में करेंगे।

—इसके उत्पन्न होने के आरम्भिक दशकों में भारतीय मज़दूर वर्ग पर लाद दी गयी दरिद्रता और यातनाएँ किस मात्रा में थीं? शोषण की प्रकृति क्या थी जिसके बारे में पूँजीवादी अर्थशास्त्री व इतिहासकार कुछ नहीं लिखते और इस बारे में चुप रहना ज्यादा पसन्द करते हैं। इस मुद्दे पर एस० ए० डॉगे को उद्घृत करें :

“1852 से 1880 के बीच, इन कारखानों में (अमेरिके और उनके भारतीय विचालियों द्वारा स्थापित) मजदूर वर्ग का अमानवीय हुँगा से निर्दयतापूर्वक शोषण किया गया। धृष्ट अंग्रेज, पवित्र हिंदू, धार्मिक मुसलमान और अपने धर्म, राष्ट्रीयता, भाषा या देश से निरपेक्ष बहुत से लोग पूँजी के इन दूषद्वानों में आदमियों, औरतों और बच्चों का खून बहाने के लिए एकछट हो गये। विदेशी साम्राज्यवाद द्वारा विजित और जमींदारों व भाड़े के देशोंहियों द्वारा नस्त-नस्त देश में नथी व्यवस्था, नयी मशीनों अब तक कभी न सुने गये कार्य रूपों और नये मालिकों द्वारा प्रताङ्गित एवं भारतीय जमीन पर अपने जन्म से ही पूँजी की बर्व-ताओं से इन लाखों लोगों को बचाने के लिए न तो कोई कानून था, न ही कोई नैतिक आधार।

“उन दिनों जंगल राज जारी था, काम के घंटों की कोई सीमा नहीं थी। आदमियों, औरतों और बच्चों को पूँजी की इन गुफाओं में प्रतिदिन 12 से 16, 18, यहाँ तक कि 23 घंटे कार्य करने के लिए एकत्र कर लिया जाता था। न इतवार की छुट्टी होती थी, न ही शुक्र और ब्रह्म होने का समय तय था। पांच-छह वर्ष की उम्र तक के बच्चे वयस्कों की तरह पूरा बक्स काम करते थे। और जब वे मर जाते थे या मशीनों द्वारा अंगंग कर दिये जाते थे, उनके जीवन या हाथ-पैरों की कोई कीमत नहीं रहती थी।

तो फिर पूँजी को होश में कौन लाया तथा मजदूर के जीवन में तथा उसके शोषण के क्रम में शोड़ा-सा भी मतुजोऽचित् भाव व कानून किसने कायम किया? संसार भर में मजदूर वर्ग के संघर्षों का समर्पण इतिहास यह दिखाता है कि मजदूरों द्वारा डटकर संघर्ष चलाये बिना कभी भी पूँजीपति वर्ग ने कोई संशोधन, मजदूरी बढ़ोतरी या मजदूरों की दिशाओं में सुधार नहीं किये हैं। इस रूप में उस वर्ग की सामान्य विशेषताओं से भारतीय पूँजीपति वर्ग कोई अपवाद नहीं है।”

—संक्षेप में, कार्य की दशाओं को नियंत्रित करने के लिए कोई फैक्टरी कानून नहीं था। दिजली के बन्क के आगमन के साथ कार्य-दिवस पर लागू सुर्य-दय और सूर्यस्त की प्राकृतिक सीमाओं ने भी काम करना बन्द कर दिया। ज्ञान मजदूरों को कम बेतन दिया जाता था और खाने तो वास्तव में ही मौत के ‘कुएँ’ थीं। हर कहीं मजदूर दर्दितम स्थितियों में दृट-फूट मकानों में रहते थे। बाजान-मजदूरों की हालत तो सबसे ज्यादा गयी-गुजारी थी। वास्तव में, यह एक तरह का जंगल राज था।

दूसरी ओर, पूँजीपतियों ने बेहताशा मुनाफा कमाया। एक उदाहरण के बतौर: 1927 में अपने स्वर्ण जयन्ती समारोह के दौरान, टाटा की नागपुर स्थित एम्बेस मिल्स की रिपोर्ट में मालिकों ने तुष्टि के भाव से कहा:

“...30 जून, 1926 तक एम्प्रेस मिल्स में कुल मुनाफा 92,314,527 रुपये की अधिक हुआ है जो आरम्भिक साधारण शेयर और पूँजी से 61.47 गुना ज्यादा है; और इसी तारीख तक कंपनी ने साधारण शेयरों पर लाभाओं में 59,413,267 रुपये कर दिये हैं जो आरम्भिक अवनिवेशित पूँजी पर क्रीच 80.86 प्रतिशत एम्प्रेस मिल्स किसी भी रूप में इसका अपवाद नहीं थी। इससे अन्य उद्योगों के लिए भी यही सब था।

लेकिन अन्य देशों में ठीक अपने वर्गीय बन्धुओं के समान ही, भारतीय मजदूरों ने भी अपने काढ़ों और परेशानियों को मूक पशुओं की तरह नहीं सहा। उहोंने स्वतःस्फूर्त ढंग से छिप्पट संघर्ष प्रारम्भ कर दिया। जिसे राष्ट्रीय मन:-स्थिति ने भी समर्थन दिया। भारतीय मजदूरों के हिस्से न सिर्फ़ अपनी असहनीय परिस्थितियों के विरुद्ध लड़े वर्ल्ड राष्ट्रीय हित में साम्राज्यवादी दमन के लिलाक भी लड़े। लम्बे समय तक, वास्तव में कोई स्थायी संगठन पैदा नहीं हो पाया। भारतीय मजदूर इतने निरक्षर, खेतिहर प्रबृत्ति वाले व पिछड़े हुए थे कि उस समय वे यह कार्य पूरा नहीं कर पाये।

हमने 1827 के आसपास कलकत्ता के पालकों तथाने वालों की हड़ताल और गंगा के नाविकों व बोडगाड़ियों के चालकों के एक होकर हड़ताल पर जाने के बारे में मुनाफ़ा है। हमने 1855-57 के दौरान कठार के चाय-बाजान श्रमिकों की हड़ताल के बारे में भी मुनाफ़ा है। 1862 में, हावड़ा में, रेलवे कुलियों ने हड़ताल शुरू कर दी। 1886 में बन्धवई मेहतारों (हलाल खोरों) और 1873 में छाटे-वालों ने हड़ताल कर दी। 1877 में, नागपुर में, एम्प्रेस मिल्स के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। 1882 से 1890 के बीच तकलीफ़ बम्बई और मदास प्रेसिडेंसियों में 25 से ल्यादा हड़तालें हुईं। वास्तव में, इस क्षेत्र में, ऐतिहासिक शोध के लिए काफ़ी सम्भावनाएँ हैं। इस दौरान होने वाली सभी हड़तालों और दसरी गतिविधियों का ब्यौरा देना यहाँ न हमरा इरादा है, और न ही यह सम्भव है।

—इन कार्रवाइयों का अंगेज शासकों पर असर पड़े बिना न रह सका। इसके अलावा, भारतीय मिल उद्योगों के विकास और इसके मुनाफ़े की दर देखकर लंकाशायर के नियोक्ता चौकन्ना हो गये। उहोंने ऐसे किसी फैक्टरी कानून के लिए शोरपुल मचाना शुरू कर दिया जिससे भारतीय मजदूरों के 'जहरत से ज्यादा शोषण' को रोका जा सके। मजदूरों के अपने संघर्षों और चोरों के आपसी झगड़ों के फलस्वरूप भारतीय मजदूरों के लिए 1881 में पहला फैक्टरी-एक्ट बन गया। तब से, हड़तालों की हर लहर के साथ ही कार्यदिवस को छोटा करते, बच्चों और स्त्री मजदूरों के रोजगार पर पांचवीं लगाने, आदि के संबंध में तय-तये कानून पास किये गये। 1920 के हड़ताली संघर्षों से 10 घंटे का दिन ही

गया। 1930-34 के संघर्षों ने हमें 9 घंटे का कार्यदिवस दिया। युद्ध के बाद के उत्तर-चतुर्वर्णों ने 1946 में कांगड़ी सरकारों को 8 घंटे का दिन करने के लिए मजबूर कर दिया।

—जैसाकि पहले कहा गया है कि ब्रिटिशपन में कोई कमी न होते हुए भी मजबूर सामूहिक रूप में इतने निःश्वार, गरिब और पिछड़े हुए और खेतिहार प्रवृत्ति वाले थे कि कोई स्थायी संस्थान बना पाते में वे सफल न हुए। प्रारम्भ में, जिस बीज ने कार्य किया, वह था स्वतःस्फूर्तता, बुझालपन और पारम्परिक बद्धनों जैसीकि गाँव, जाति आदि पर आधारित तत्वों का सम्प्रक्षण। केवल उपरी दर्जे के लोग ही ऐसलगामेटिड सोसायटी ऑफ रेलवे सर्वेटर्स (रेलवे कम्बिनेशनों) (1897) फ्रिट्स यूनियन ऑफ कलकत्ता (1905), बोर्डवे पोस्टल यूनियन (डाक यूनियन), (1907), कामगार हितवर्धक सभा, कम्बर्ड (1910) और इसी प्रकार के अन्य संस्थानों का निर्माण कर सके।

—विभाजन-विरोधी और स्वदेशी आंदोलनों के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन के नवे उभार, 1908 में तिलक की गिरफतारी, और 1918 व 1920 के बीच युद्ध के बाद दो उफान के साथ ही, नवजात द्वेष यूनियन संघर्षों के सम्मानण की वजह से ही मजदूर राजनीतिक क्रिया में संलग्न हुए और जिसने बाद में बुद्धिजीवियों को मजदूरों के बीच जांते के लिए प्रेरित किया जिससे भारत में आधुनिक मजदूर आंदोलन की मजबूत नींव रखी गयी।

तिलक को मुनाफी गयी सजा के विरोध में बम्बई के मजदूरों की 6 दिनों की राजनीतिक आम हड्डताल के बाद लेनिन ने 1908 में लिखा : “एक वर्ग वेत्तस राजनीतिक सामूहिक संघर्ष चलाने के लिए भारतीय संवेद्धा पहले ही काफ़ी परिपक्व हो चुका है...”।

1910 में मैकडोनाल्ड ने लिखा :

“भारतीय मजदूर वर्ग भविष्य में कभी भारत की जातियों और ब्रिटेन की द्वेष यूनियनों के बीच के रास्ते जैसा कोई ‘आधारिक सम्मानण’ पैदा करेगा।” वास्तव में, भारतीय मजदूर वर्ग उससे कहीं अगे बढ़ चुका था जिसे मैकडोनाल्ड अनिष्टापर्वक स्वीकार करते।

31 अक्टूबर, 1920 को बम्बई में द्वेष यूनियनों के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन का दीक्षात समारोह और भारतीय मजदूरों के पहले केंद्रीय संगठन, अखिल भारतीय द्वेष यूनियन कार्गेस (एट्क) का जन्म हुआ। इस सभ में 800 प्रतिनिधि उपस्थित थे जो इससे मंबद्द 60 यूनियनों और 40 सहानश्वत रखने वाली यूनियनों के 500,000 से अधिक मजदूरों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अतः इसका मतलब यह नहीं कि एट्क किसी एक व्यक्ति की आकांक्षा या फिर इस तरह की सामाज्य वातों का परिणाम थी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघठन में भारतीय

मजहूरों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा।³ इसकी नींव पहले ही रखी जा चकी थी। इस महान ऐतिहासिक घटना ने एक नये संगठन का परिचय कराया जो देंड यूनियनों को, जिन्हें मजहूरों के संघर्ष और एकता ने उनके काम के भिन्न-भिन्न स्थलों पर सामने ला दिया था, एक केन्द्रीय निवेशन प्रदान कर सकती थी। भारत का मजहूर वर्ग और इसका देंड यूनियन आंदोलन इस प्रकार निणियक स्थिति में पहुँच गया था। भारतीय देंड यूनियन एक 1926 पास किया गया जिसमें कुछ नूनतम घटाई के तहत देंड यूनियन को कानूनी मान्यता दे दी गयी।

टिप्पणियाँ :

1. हमारे मजहूर वर्ग की सौ वर्षों की उपलब्धियाँ—एस० ए० डांगे
2. विश्व राजनीति में ज्वलनशील पदर्थ—वी० आई० लेनिन
3. यह विचार केवल गौण ही था। अगर इसे मान भी लिया जाए तो इसका मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कारकों ने भारतीय मजहूरों को एक राष्ट्रीय मंच पर एकत्रुत होने के लिए बाध्य कर दिया।

चलच पढ़ें :

1. आज का भारत : रजनी पामदान
2. भारत में देंड यूनियन आंदोलन का इतिहास
3. हमारे मजहूर वर्ग की सौ वर्षों की उपलब्धियाँ : एस० ए० डांगे
4. एटक के पचास वर्ष : एस० ए० डांगे
5. भारत में हड़तालें : वी० बी० कर्णिक

मज़दूर वर्ग और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम

19वीं शताब्दी के अन्तिम दशकों से 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक, मज़दूर वर्ग उद्भव के साथ, कभी कमज़ोर, कभी जुबारू, लेकिन स्वतःस्फूर्त व छिटपुट संघर्ष आरम्भ हो गये थे। लेकिन राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के उदय के साथ ही भारतीय मज़दूर आंदोलन में उभार आया और वह एक उच्चतर स्थिति में पहुँच गया। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन द्वारा पैदा किये गये इस हौसले का प्रभाव दमन के खिलाफ खड़े हुए मज़दूरों पर पड़े बिना न रह सका। इसके तुरंत बाद ही दो ऐसे आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ जो एक साथ हासमान व प्रवाहमान थे व दोनों एक-दूसरे के प्रभाव में वृद्धि कर रहे थे।

— 1905 में बंगाल के विभाजन से एक अभूतपूर्व राष्ट्रीय उभार पैदा हुआ। स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं का परित्याग साम्राज्यवाद विरोधी प्रवृत्ति का घोतक था। न सिर्फ बंगाल में ही, बल्कि पंजाब और दक्षिण में भी मज़दूरों ने हड़ताल की घोषणा का जवाब दिया। इस उद्भूत प्रवृत्ति की सज़ीव अधिव्यक्ति कलकत्ता में गवर्नर्मेंट प्रेस कर्मचारियों द्वारा गजट छापने से इंकार कर देने में हुई। 1905 से 1909 के बीच बोम्बे मिल्स, ईस्ट बंगाल रेलवे और दूसरे अन्य स्थानों पर मज़दूरी के घंटे बढ़ाने, कल्प्रद स्थितियों और पूँजी के दुरुप्योगों के खिलाफ व्यापक हड़तालें हुईं। कभी-कभी, वे राजनीतिक दमन और विदेशी शासन के प्रत्यक्ष विरोध में थीं।

— 1908 में तिलक की गिरफ्तारी और सज़ा के विरोध में बम्बई कपड़ा मिलों के दो लाख से अधिक मज़दूरों की छह दिनों की हड़ताल—सज़ा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक दिन—एक ऐसी कार्रवाई थी जिसकी सराहना इतनी दूर से लेनिन तक ने की।

— 1919 से 1922 तक की अवधि में व्यापक राष्ट्रीय उथल-पुथल का दौर रहा। लगातार बदतर होती जा रही स्थितियों के विरुद्ध युद्ध के बाद के असन्तोष और विश्व क्रांतिकारी आंदोलन को रूस की 1917 की अक्तूबर क्रांति द्वारा दिये

गये धर्के ने राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन और मज़दूर आंदोलनों, दोनों की ताकत को बढ़ाने में मदद की। रॉलट एक्ट के खिलाफ सामूहिक हड़ताल और जलियां-वाला वाग हत्याकांड के बाद पूरे देश में फैली रोष की लहर में न सिर्फ मज़दूर वर्ग की सक्रिय हिस्सेदारी थी, बल्कि काफ़ी बड़े पैमाने पर ये मज़दूरों के अभूतपूर्व हड़ताल आंदोलन में प्रतिबिंधित भी हुए।

जनवरी 1919 के प्रारम्भ में, पहले ही लगभग 1,25,000 मज़दूर हड़ताल पर जा चुके थे। 1920 के पूर्वार्द्ध में लगभग 200 हड़तालें हुईं जिनमें लगभग 15 लाख मज़दूर शामिल हुए। नवंबर 1921 में बम्बई के मज़दूरों ने हड़ताल कर और रोषपूर्ण धरना देकर प्रिन्स ऑफ वेल्स का स्वागत किया। रजनी पामदत्त ने इसका वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया है :

“प्रथम विश्व युद्ध के अंत के नवजागरण काल में, 1918-21 के दौर का महान हड़ताल आंदोलन राष्ट्रीय मुक्ति लहर का अग्रदूत बना जिसने अंततः 1920-22 के असहयोग आन्दोलन में कांग्रेस को हरकत में आने को मजबूर किया।¹

इसी पृष्ठभूमि में 1920 में एटक का स्थापना सम्मेलन हुआ। यह संयोग मात्र नहीं था कि इस सत्र में लाला लाजपतराय के अध्यक्षीय भाषण, और आगे होने वाले एटक के अन्य सत्रों के भाषणों और प्रस्तावों में इन मूलभूत स्थापनाओं पर जोर दिया गया कि, (i) मज़दूर एक वर्ग के रूप में संगठित और सक्रिय हो रहे हैं, (ii) भारतीय मज़दूर भारत से बाहर के मज़दूरों के साथ एकजुट हो रहे हैं (लालाजी के अनुसार, “अंतर्राष्ट्रीय भ्रातृत्व की शृंखला में एक कड़ी जोड़ते हुए”), विशेष रूप से, रूस की प्रथम विजयी समाजवादी क्रांति के साथ, और (iii) संगठित भारतीय मज़दूर वर्ग स्वराज के संघर्ष में सक्रिय रूप से हिस्सेदारी कर रहा है। ये भारतीय मज़दूर वर्ग के आंदोलन के लिए तीन प्रतीक-चिह्न बन गये। सिंगारवेल्लु चेट्टियार की अध्यक्षता में 1923 में मद्रास में पहली बार मई दिवस मनाया गया।

असहयोग आंदोलन के विफल होने और वापस ले लिये जाने के बाद मज़दूर वर्ग पर आधारित एक नयी राजनीतिक शक्ति भारतीय दृश्य-पटल पर उभरने लगी। दिसंबर 1925 में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ। 1924 में, एटक पहले ही यह प्रस्ताव पास कर चुका था कि आजाद भारत एक समाजवादी गणतंत्र होना चाहिए। उभरते हुए सर्वहार की वैज्ञानिक समाजवादी विचारधारा को आम मज़दूरों के बीच ले जाते हुए कम्युनिस्टों ने ट्रेड यूनियन कार्य को गम्भीरतापूर्वक लिया। ‘कांग्रेसी समाजवादी’ और अतिवादी बुद्धिजीवी भी बड़ी संख्या में उनके बीच गये।

शुरू के वर्षों में, जैसाकि बाद के वर्षों में भी हुआ, मज़दूरों को मुक्ति संग्राम,

और उनके अपने अधिकारों और माँगों के लिए संगठित करने के दौहरे लक्ष्य के साथ बाहर से बहुत से समाज सुधारकार्दी, मानवतावादी और राष्ट्रीय उदारादी मजदूरों के बीच कार्य करते गये। लेकिन ज्यादातर पूँजीवादी और निम्न-पूँजीवादी राष्ट्रवादियों का कुल मिलाकर रवैया हैत का था—यानी दमितों और शोषितों के कट्टों और यदा-कदा होने वाले संघर्षों के प्रति सहानुभूति, मगर उनके जुझाझ वर्ग, कार्य और संगठन के प्रति विद्वेष का भाव। यह विषेषकर महात्मा गांधी के हृप में मूर्त हुआ जिन्होंने अहमदाबाद के कपड़ा मजदूरों को संगठित करते हुए और व्यक्तिगत रूप से उनके संघर्ष को चलाते हुए, मजदूरों के एक राष्ट्रीय एवं वर्गीय संगठन का निर्माण करने और उसे मजबूत बनाने के किसी भी प्रयास से स्वयं व अपने 'मज़र महाजन'²² को संबद्ध करने से इंकार कर दिया। यह इस तरह हुआ कि वर्ग-संघर्ष की विचारधारा और एक वर्ग के रूप में सर्वहारा, जो अपनी ऐतिहासिक भूमिका और समाज में अपनी निपत्ति से परिचित था, के विरोध में उन्होंने अपनी 'इस्टीशिप' की विचारधारा को सामने रखा।

इस शताब्दी के पिछले बीम वर्षों में भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन का इतिहास कई तरह से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रशुल्कशील और ट्रेड यूनियन के क्षेत्र में भी अपना प्रभाव रखने वाली पूँजीवादी विचारधारा एवं मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा के बीच संघर्षों को प्रतिबंधित करता है। यह चौज हमें चिढ़ेदें, जिसके बाद पुनर्एकोकरण हुआ, और फिर से चिढ़ेदें में, जिनसे ट्रेड यूनियन आंदोलन प्रस्त हो गया, दिखाई पड़ती है। 1927-28 में मजदूरों में नवी मुग-बुगहट हुई। रेलवे मजदूरों और बारवाई व अन्य कंद्रों में कपड़ा मजदूरों के लम्बे समय तक खिचने वाले, बुरी तरह लड़े गये और अरथं संगठित संघर्ष हुए।

3 फरवरी, 1928 को जब साइमन कमीशन बम्बई आया तो 30,000 से ज्यादा मजदूरों ने इन तारों के साथ उसका विरोध किया : हम संपूर्ण स्वराज चाहते हैं, और 'आठ घंटे का दिन,' आदि।
दिसंबर, 1928 में, कांग्रेस के कलकत्ता मत्र में, पास के कारखाना-क्षेत्रों के

50,000 से ज्यादा मजदूर कांग्रेस के पंडाल में बूस गये और "संपूर्ण स्वराज" का प्रस्ताव पारित किया। यह लक्ष्य बाद में 1929 में ताहोर में कांग्रेस द्वारा अपनाया गया।
ट्रेड यूनियन आंदोलन के इस उभार में कम्युनिस्टों की क्या भूमिका रही, यह एक सुपरिचित श्रमिक इतिहासकार द्वारा प्रमाणित की गयी है जिसकी व्यावितगत रूप से कम्युनिस्टों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। 1928 में बम्बई स्तरी कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल के बारे में, उसने लिखा है :

"कम्युनिस्ट हड़ताल का नेतृत्व ले पाने में सफल रहे क्योंकि उन्होंने मजदूरों की मनोदशा को ठीक-ठीक पढ़ दिया था और स्वयं को उनके उद्देश्यों के प्रति

समर्पित जांच योद्धा के रूप में सामने रखा था। उन्होंने ही सर्वप्रथम यह महसूस किया था कि वैज्ञानिक पुनर्गठन योजना का सुकाबला सिर्फ़ आम हड़ताल के द्वारा ही किया जा सकता है, न कि अलग-अलग मिलों में अलग-अलग हड़ताल के द्वारा। इस चीज़ को जान लेने के बाद अपनी इस कामना को मज़हूरों पर लाद देने की उन्हें कोई जलवायी नहीं थी। उन्होंने मज़हूरों को खबर अपने ही अनुचरों से सीखने का मौका दिया और आम हड़ताल की बाबत वे इसके लिए पूरी तरह परिपक्व हो गये उन्होंने अथक रूप से कार्य किया, अपनी मानोवृत्ति में वे निडर और तिथा में अटल रहे। इन गुणों का उन्हें भरपूर लाभ मिला और हड़ताल की समाप्ति के बाद वे 'वर्षाई' के मज़हूर र्वा के निवावाद लेता बन गये।¹³

1929 में 'भरत पद्यन्त कांड' में काम्युनिस्ट नेताओं की भर-पकड़ के कारण, बहुत वर्षों के लिए मज़हूर एक परिपक्व और अनुभवी नेतृत्व से वंचित हो गये। इसके बावजूद बहुत से बहाइयोर्पूण भूमिगत कार्य हुए। काम्युनिस्टों और दूसरे सक्रिय कार्यकर्ताओं ने सांगठनिक आधार-मूलक कार्यों को भली प्रकार किया था जिससे विश्वस्त नेतृत्व के बांगर भी मज़हूर कार्य में लगे रहे। जैसाकि आमतौर पर आम वापसी के दौरान होता है, कुछ भूमिगत हड़ताली गतिविधियाँ भी होती हैं जिनकी आंदोलन के लिए इसके पुनर्जन्मीवन के आने वाले वर्षों में उपयोगिता होती है। 1929 में जूट मिलों की आम हड़ताल ऐसी ही एक गतिविधि थी। भारतीय जूट मिल संघ के जूट मिलों के मालिक एक सामान्य कारंचाई के लिए एक हो गये। मगर मज़हूरों की कारंचाई इतनी मफूल थी कि मज़हूरों के बजाय नियोक्ताओं को सरकार के पास विकाद मुलाजाते के लिए हस्तक्षेप हेतु पहले जाना पड़ा। राज्यीय संघर्ष (1930-34) की दूसरी लहर, सविनय अवज्ञा आंदोलन, के साथ ही मज़हूर फिर से संघर्ष के लिए उत्तर आए। 5 मई, 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के खिलाफ शोलापुर में 50,000 से ज्यादा मज़हूरों ने हड़ताल की। आबादी के दूसरे तबक्कों के साथ, मज़हूरों ने नगर पर कब्जा कर लिया, पुलिस और नागरिक प्रशासन को भगा दिया और अपना शासन कायम कर लिया। शोलापुर पर फिर से नियन्त्रण के लिए 12 मई को अंग्रेज़ शासकों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया।

सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिये जाने के बाद राष्ट्रीय मीर्च पर तुलनात्मक चूणी का दौर आ गया। लेकिन मज़हूर वर्ग की गतिविधियाँ जारी रहीं जैसाकि 1933-34 में जी० आई० पी०, एम० एस० एम० व बी० एन० आ०० रेलवे मज़हूरों की हड़ताल और बम्बई, कानपुर, शोलापुर और दूसरे केंद्रों की बड़ी-बड़ी सूती कपड़ा मिलों के मज़हूरों की हड़तालों में देखने के लिए मिला। भयंकर दमत के बाबजूद शोलापुर के मज़हूरों की हड़ताल लगभग

चार माह चली ।

इसके बाद 1937 में हड्डतालों की और बड़ी लहर आयी जिसमें महान मंदी के दौरान, कुछ वर्षों पहले हुई मजदूरी में कटौती के खिलाफ जूट और सूती कपड़ा मजदूरों ने संघर्ष कर विजय प्राप्त की । नये साम्राज्यवादी हितों के अनुरूप नियमित संविधान, जिसका कांग्रेस ने भी जबर्दस्त विरोध किया, के विरोध में एटक ने एक दिन की राजनीतिक हड्डताल आयोजित की । इस स्थिति ने ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो पहले 1929 में विभाजित हो चुकी थी और दोबारा 1931 में विभाजित हुई, के पुनर्एकीकरण का सवाल उठाया । एटक फिर से भारतीय मजदूरों का एकमात्र केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठन बन गया । एटक के पुनर्एकीकरण से इसकी ताकत में इजाफा हुआ ।

1937 में, प्रातों में पहली कांग्रेसी मंत्रिपरिषदों ने सत्ता संभाली । सवाल उठा : भारतीय पूँजीपति वर्ग हाथ में आयी आंशिक राज्य सत्ता का इस्तेमाल मजदूर वर्ग के साथ अपने संबंधों में किस प्रकार करेगा ? जवाब था बम्बई औद्योगिक विवाद अधिनियम,—एक प्रतिक्रियावादी अधिनियम, जो मजदूरों के हितों के प्रति पूर्वाग्रहियुक्त था और जिसका उद्देश्य उनके हितों को पूँजीपति वर्ग के हितों के अधीन रखना था । 7 नवम्बर, 1938 को मजदूरों ने एक दिन की विरोध में हड्डताल कर प्रतिक्रिया व्यक्त की । कांग्रेसी सरकार ने मजदूरों पर गोली चलवाई जिसमें दो लोग मारे गये । उस समय कांग्रेसी मंत्रिपरिषदों के संक्षिप्त काल के शासन में ट्रेड यूनियन नेता हजारा सिंह को एक ट्रक के नीचे कुचल दिया गया जबकि वह टाटा लोहा एवं इस्पात कंपनी, जमशेदपुर में एक हड्डताल में धरने पर बैठे हुए थे । आसाम में, दिग्बोर्डी स्थित आसाम तेल मिल मजदूरों पर सेना द्वारा गोलियाँ चलायी गयीं जिसमें 3 लोग मारे गये । परिणाम स्वरूप, जाँच समिति के सामने गवाही देने के लिए 90 मजदूरों को सजा दी गयी । 6 अगस्त, 1938 को एटक ने अखिल भारतीय दिग्बोर्डी दिवस मनाने का आह्वान किया । मद्रास, बम्बई और दूसरी जगहों पर संघर्ष हुए जिनकी परिणति गोली-कांडों और मौतों में हुई ।

मदुरै में हावें समूह की मिलों के ब्रिटिश मालिकों के खिलाफ धारा 144 लागू करने का मामला भी सामने आया । मगर मालिकों के खिलाफ इस क्रिस्म का मामला अन्तिम भी था : सामान्य रूप से, पूँजीपति वर्ग की नीति मजदूरों के दमन की थी जब वे इकट्ठे होने लगे थे और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जुझारू गतिविधियों में सक्रिय होने लगे थे ।

सितम्बर 1939 में लड़ाई छिड़ गयी । 2 अक्टूबर, 1939 को 'साम्राज्यवादी' युद्ध के विरोध में बम्बई में मजदूरों ने काम बंद कर दिया । युद्ध के कारण बढ़ती हुई क्रीमतों को निष्क्रिय बानाने के लिए बड़ी हुई मजदूरी और महँगाई

भत्ते के अनुदान के लिए बहुत सी जगहों पर हड़तालें हुईं। जबकि युद्ध संबंधी आदेशों की वजह से पूँजीपतियों ने मुनाफा कमाया, मजदूरों को 'युद्ध बोनस' के अनुदान की माँग में बढ़ोत्तरी हुई।

जून 1941 में सोवियत संघ पर फासिस्टों के आक्रमण और 9 अगस्त, 1942 से शुरू होने वाले 'भारत छोड़ो' आंदोलन ने एक विकट स्थिति पैदा कर दी जबकि एक ओर तो एटक ने फासिस्ट विरोधी युद्ध और सोवियत संघ की सुरक्षा का आह्वान किया, तो दूसरी ओर, सक्रिय रूप से राष्ट्रीय नेताओं के दमन के खिलाफ और उनकी रिहाई के लिए एवं 'राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय सरकार' के गठन के लिए अभियान छेड़ दिया। इस जटिल परिस्थिति में रणनीति संबंधी गलतियाँ हुईं जिसका परिणाम आंशिक अलगाव के रूप में हुआ। लेकिन इस पर जल्दी ही काबू पा लिया गया।

मुख्य रूप से लाल सेना के विजय-अभियान के कारण फासिस्ट जर्मनी, इटली और जापान की परायन ने विश्व-क्रांतिकारी शक्तियों को जबर्दस्त रूप से मजबूत किया और राष्ट्रीय मुक्ति की एक ताकतवर धारा को जन्म दिया। 1945 में युद्ध के बाद के उभार ने हड़तालों की लहर को प्रगतिकामी बल प्रदान किया। राजनीतिक जन-संघर्ष (उदाहरण के लिए, आजाद हिन्द सेना के मुकदमे) आम बात हो गयी। 18 फरवरी, 1946 को रायल इंडियन नेवी के नाविकों ने विद्रोह कर दिया और जहाजों पर कब्जा कर लिया।

नाविकों की अपील के जवाब में वर्म्बई के मजदूरों ने काम बंद कर दिया। तीन लाख से अधिक मजदूर हड़ताल पर चले गये। अंग्रेज सिपाहियों ने मजदूरों और लोगों पर गोलियाँ चलायीं। 250 से ज्यादा लोगों को 'अधिकृत' तौर पर मृत घोषित किया गया। कलकत्ता, कराची, और दरअसल सारे भारत में ही, इसी प्रकार की जन-कार्रवाइयाँ हुईं। कलकत्ता की कार्रवाई पर टिप्पणी करते हुए अमृत बाजार पत्रिका ने लिखा: "साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष में इतने अधिक मजदूरों के योगदान ने भारत में एक नयी परिस्थिति को जन्म दिया है।"

'नयी परिस्थिति' यह थी कि साम्राज्यवादी बहुत समय तक भारत पर शासन नहीं चला पाये। 11 जुलाई, 1946 को डाक कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर चले गये, बाद में डाक व तार विभाग के दूसरे तबके भी उनमें सम्मिलित हो गये। इन मजदूरों के समर्थन में 29 जुलाई को अभूतपूर्व आम हड़ताल हुई। आखिरी साँचा ढल चुका था। सत्ता के हस्तांतरण की बातचीत शुरू हो गयी। इसके साथ ही साम्राज्यवाद और अंतरिक प्रतिक्रिया ने साम्प्रदायिक भावनाओं को तेज़ी के साथ उभारा। लोगों के बीच जनवादी और धर्मनिरणेक चेतना तथा मजदूरों के बीच मेहनत से विकसित वर्ग-चेतना ने सदियों पुराने विश्वासों व पूर्वाग्रहों एवं उनसे उपजती धार्मिक तथा साम्प्रदायिक आधारों पर निर्मित चेतना

की चुनौती स्वीकार की। अगस्त 1947 में आजादी मिली। मगर भारत को विभाजित कर दिया गया और एक साम्राज्यिक विनाश शुरू हो गया। लाल झंडे के नीचे एकत्रित वर्गचेतस मज़दूरों ने साम्राज्यिक दंगों की लपटों को बुझाने के लिए बहादुरीपूर्ण काम किये। मगर दोनों चेतनाओं के बीच यह युद्ध आज तक जारी है और विभाजक व साम्राज्यिक शक्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय अखंडता व मेहनतकर्णों की एकता के लिए संघर्ष में एक तत्व बन चुका है।

बार-बार यह दावा किया जाता रहा है कि अकेली कांग्रेस ने स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। यह सच है कि मुक्ति संघर्ष के राष्ट्रीय मोर्चे के रूप में इसकी हिस्सेदारी काफ़ी बड़ी है। मगर स्वाधीनता संघर्ष पर मज़दूर-आंदोलन का प्रभाव नगण्य नहीं था। यह मज़दूर संघर्षों के साथ ही बढ़ा और विकसित हुआ। हर कदम पर इसने स्वाधीनता संघर्ष को आगे बढ़ाने में मदद की, यद्यपि बहुत से वस्तुगत व व्यक्तिगत कारणों से यह आंदोलन में मज़दूर वर्ग की नेतृत्वकारी भूमिका स्थापित नहीं कर पाया। यह न देख पाना एक ऐतिहासिक भूल ही होगी कि भारतीय मज़दूरों ने स्वयं को अपने कष्टों को कम करने व अपनी दशा सुधारने की फौरी ज़रूरतों से नहीं जोड़ा था। वे उन बहुत-सी धाराओं में से एक थे जो हमारे स्वाधीनता संघर्ष के शक्तिशाली प्रवाह में आकर मिल गयीं।

टिप्पणियाँ :

1. आज का भारत : रजनी पामदत्त
2. कपड़ा मज़दूर संघ, अहमदाबाद इसी नाम से लोकप्रिय है।
3. भारत में हड़ताल : वी० बी० कर्णिक

चल्लर पढ़ें :

1. आज का भारत : रजनी पामदत्त
2. एटक के पचास वर्ष : एस० ए० डांगे
3. भारत का स्वतंत्रता संग्राम : विभिन्न धाराएँ—ज० सरकार, ए० वी० बर्धन, एन० ई० बलराम द्वारा संपादित
4. कम्युनिस्ट एवं ट्रेड यूनियन आंदोलन—पार्वती कृष्णन्
5. भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मज़दूर वर्ग—गौतम चट्टोपाध्याय
6. भारत में हड़तालें : वी० बी० कर्णिक

राजनीतिक प्रवृत्तियों के बीच संघर्ष और परिणामस्वरूप ट्रेड यूनियन आंदोलन में फूट

औद्योगीकृत पश्चिम में पहली ट्रेड यूनियनों के उदय; मार्क्स द्वारा सर्वहारा व इसकी मुक्ति के लिए संघर्ष के सिद्धांत व रणनीति के बारे में की गयी व्याख्याएँ व लेनिन के नेतृत्व में अक्तूबर क्रांति और प्रथम सर्वहारा राज्य की स्थापना के बाद से दुनिया निर्णयिक रूप से बदल गयी है। अभी भी इसका काफी तीव्र गति से बदलाव जारी है। 1857 के बाद से और 1947 में आजादी के बाद से हमारा देश भी अविश्वसनीय रूप से बदल गया है। सवा सौ वर्षों से भी अधिक पहले अपने उद्भव के बाद से भारतीय मजदूर वर्ग बदल चुका है। इसी तरह ट्रेड यूनियन आंदोलन का रूपाकार, चरित्र, समस्याएँ व इसके कार्यभारों में भी बदलाव आ गया है। हमारे अध्ययन का उद्देश्य सर्वप्रथम इन परिवर्तनों और परिवर्तनकारी शक्तियों को समझना है।

पिछले अध्यायों में, हमने बीते हुए समय के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त की थी। हम सिर्फ इतिहास जानने के लिए इतिहास का अध्ययन नहीं करते। हमारा उद्देश्य सिर्फ दुनिया को समझना और उसकी व्याख्या करना भर नहीं है, बल्कि इसे बदलना है। हमारे लिए इतिहास का ज्ञान वर्तमान और भविष्य के युद्धों को लड़ने के लिए एक जरूरी हथियार है। जब तक हमें यह मालूम नहीं होगा कि मजदूर वर्ग किस प्रकार विकसित और परिवर्तित हुआ है, किस प्रकार ट्रेड यूनियनें पैदा हुईं व आज की स्थिति तक विकसित हुई हैं, हम इन परिवर्तनों का अर्थ ग्रहण नहीं कर पाएँगे। हम सकारात्मक व नकारात्मक अनुभवों से कुछ नहीं सीख पाएँगे और इस प्रकार भविष्य के लिए हम स्वयं को तैयार एवं लैस नहीं कर पाएँगे। पूँजीवादी समाज में प्रचलित ट्रेड यूनियन आंदोलन में दो वर्गें, दो हितों और दो दृष्टिकोणों का अनवरत संघर्ष जारी है। भूत और वर्तमान को पूँजीपति वर्ग अपने तरीके से प्रस्तुत करता है और इसे इस तरह आगे बढ़ाता है कि यह भविष्य

पर अपने संकीर्ण वर्गीय हिंतों के लिए प्रभाव डाल सके। आगे बढ़ने के लिए हमें इसका हर कदम पर प्रतिरोध करना है। 1920 में दिये गये अपने भाषण में एटक के पहले अध्यक्ष, लाजपत राय ने कहा था :

“यूरोप में सत्य दो तरह का है : (क) पूँजीवादी व सरकारी सत्य, और (ब) समाजवादी व मजदूरों का सत्य। यूरोप और अमेरिका के मेरे स्वर्य के अनुभव ने मुझे यह सोचने के लिए विवश कर दिया है कि समाजवादी, यहाँ तक कि बोल्शेविक सत्य भी, पूँजीवादी और साम्राज्यवादी सत्य की अपेक्षा अधिक उचित, अधिक विश्वसनीय व अधिक मानवीय है।

यह निष्कर्ष न सिर्फ यूरोप और अमेरिका पर ही, बल्कि सभी वर्गीय समाजों पर लागू होता है।

हमने पहले ट्रेड यूनियन चेतना की तरफ रुकाते-रुकाते बढ़ते हुए मजदूर आंदोलन और पूँजीपति वर्ग व निम्न पूँजीपति वर्ग द्वारा प्रभुत्वशिल राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य अंतर्भिन्नता का जिक्र किया है। एक ओर, हमने समाज मुद्धारकों और नरम उदारराष्ट्रियों का जिक्र किया है। तो (वीस के दशक के बाद से) हमसे और मजदूरों के बीच काम आने वाले काम्युनिस्टों और समाजवादियों का अपने द्वैर्यशील और परिश्रमपूर्वक किये गये कार्य के द्वारा काम्युनिस्टों ने पहली बार ट्रेड यूनियनों को एक सिथर और सांगठनिक रूप प्रदान किया। (यहाँ 1930 में बम्बई की सरकार द्वारा जारी किये गये खेतपत्र में दिया साक्ष्य प्रस्तुत है : “1919 और 1924 में मिल चलाने वालों ने एक इकाई के रूप में हड्डताल की लेकिन उन्होंने किसी सही तरीके से संगठित ट्रेड यूनियन, जिसके ते सदस्य ही, के द्वारा दिये गये आह्वान पर यह हड्डताल नहीं की थी। व्यापक रूप से फैले कार्टों ने उनमें अस्थायी एकता स्थापित कर दी थी व उनके पास न कोई संगठन था न वैसा। घिरनी कामगार यूनियन ही वह पहली यूनियन थी जिसने इतना अधिक प्रचार-प्रसार किया और मजदूरों के एक बड़े समूह को एक नियमित संगठन बाली ट्रेड यूनियन में संगठित किया……”) काम्युनिस्टों ने मजदूरों को सिखाया था कि वे अपना आर्थिक संघर्ष गजनीतिक संघर्ष से और राष्ट्रीय कार्यभारों को अंतरराष्ट्रीय कार्यभारों से जोड़ें। ट्रेड यूनियन क्षेत्र में सुधारवाद व अर्थवाद के बिल्ड ऊहांने अर्थक संघर्ष चलाया। 1929 में काम्युनिस्ट नेताओं की धरन-पकड़ और मेरठ कांड, दोनों ही कांतिकारी ट्रेड यूनियनवादी उमड़ती हुई लहर को कुचल देने और कम्युनिस्ट नेतृत्व को जन-आंदोलन से अलग-अलग कर देने के प्रयास थे। जहाँ तक आंदोलन के उद्देश्यों व रणनीतियों, और इसके केन्द्रीय संगठन, एटक का प्रश्न है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के भीतर विभिन्न राजनीतिक समूहों और व्यक्तित्वों के अस्तित्व ने अपारिहार्य रूप से इसमें संघर्ष पैदा किया। परिणाम-स्वरूप, हमने प्रतिधातों की एक शूर्खला को जन्म दिया।

अपने विशिष्ट काइयाँपन के साथ, गांधी जी ने स्वयं को एटक की स्थापना से दूर रखा था। उन्होंने अहमदाबाद कपड़ा मज़दूर संघ ('मजूर महाजन') को स्थापित करने में अपना पूरा सहयोग दिया था क्योंकि किसी भी तरह इसे रोका नहीं जा सकता था। लेकिन उन्होंने यह पक्का कर लिया कि मज़दूरों को एक वर्ग के रूप में, और इस तरह राष्ट्रीय स्तर पर, संगठित करने के किसी भी प्रयत्न से अहमदाबाद कपड़ा मज़दूर संघ शामिल न हो।

आधुनिक उद्योग द्वारा निर्मित संचार के नवीन साधनों, जोकि विभिन्न स्थानों पर रहने वाले मज़दूरों को एक-दूसरे के संपर्क में आने का मौका देते हैं, के बारे में बोलते हुए कार्ल मार्क्स ने कहा था : "यही संपर्क था जिसकी एक ही चरित्र वाले विभिन्न स्थानीय संघर्षों को वर्गों के एक राष्ट्रीय संघर्ष में संकेद्रित करने के लिए आवश्यकता थी..." मार्क्स ने हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर मज़दूर वर्गों को संगठित करने की आवश्यकता पर बल दिया, क्योंकि यह राष्ट्रीय सीमाएँ ही हैं जो वर्ग-संघर्ष की वृद्धि और विकास और अंततः मज़दूरों की अंतर्राष्ट्रीय चेतना के उद्भव के लिए वास्तविक युद्धक्षेत्र का निर्माण करती हैं। इस प्रकार मज़दूरों को एक वर्ग के स्तर तक उठाने और किसी एक विशेष कारखाने या व्यवसाय में शुद्ध आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु चलाये जाने वाले आंदोलन को एक राजनीतिक वर्ग-संघर्ष में बदल देने के संदर्भ में गांधीवाद मार्क्सवाद के विरोध में खड़ा हो गया।

इसके विरोध में, गांधीजी ने 'ट्रस्टीशिप' का सिद्धांत रखा जिसके अनुसार, उद्योग पर समाज का अधिकार है और पूँजीपति उसके सिर्फ ट्रस्टी भर हैं। मज़दूरों को पूँजीपतियों से उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए जैसा पुत्रों का अपने पिताओं के प्रति होता है। वह किस सीमा तक जाने को तैयार थे, यह स्वयं उनके शब्दों से प्रकट है : "यदि मज़दूर एक साथ एकत्र हो जाएँ तो वे एक अप्रतिरोध्य शक्ति बन जाएँगे। यही वजह है कि मुझे वर्ग-संघर्ष की कोई ज़रूरत दिखाई नहीं देती।"

वह उनके यूनियनों के रूप में संगठित होने के विरोध में नहीं थे। मगर उन्होंने उनके कार्यभारों और रणनीतियों पर कुछ सीमाएँ बांध दी, रणनीतियों के द्वारा, उन्होंने अनिवार्य पंचायती निर्णय पर जोर दिया, उन्होंने कपड़ा मज़दूर संघ को एटक से सम्बन्धित करने से इंकार कर दिया, क्योंकि एटक वर्ग-संघर्ष में यकीन रखता था।

हमने इसका काफ़ी विस्तार से वर्णन किया है क्योंकि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के संदर्भ में—यह वर्ग-सहयोग का संपूर्ण और सुर्योदायी विचार-धारात्मक नज़रिया था, जो बार-बार अपना सिर उठाता रहा है।

मार्च 1929 में दमन के द्वारा परिपक्व और अनुभवी जनतेआओं के दृश्य

से हुटा दिए जाने ने 1929 के बाद के दिनों में नागपुर में एक के दसवें अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जयवाहरलाल नेहरू ने की, सूधारवादी दक्षिणपंथी नेतृत्व को इसके विभाजन में मदद की। फूट डालने वालों ने, जिनका नेतृत्व वी० वी० गिरि, एन० एम० जोशी और कुछ दूसरे अनुबंधी लोगों के हाथ में था, रायल कमीशन अँफ़ लेवर (जिसे विहूले कमीशन के ताप से भी जाना जाता था) का बहिष्कार करने के बारे में बहुमत के निन्दण को मानने से इंकार कर दिया और राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन संघ (एन० टी० य०० एफ०) की स्थापना के लिए बहिर्भूमन कर दिया।

जिसे वह 'वामपंथ के कुछ सदस्यों का युक्तोचित जोश' मानते हुए अपनी नाखुशी जाहिर कर रहे थे, 'फूट डालने वालों' यानी 'दक्षिणपंथियों' की आलोचना के संदर्भ में नेहरू एकदम स्पष्ट थे, उन्होंने कहा :

"वामपंथ कमीशन के बहिष्कार के पक्ष में था जबकि दक्षिणपंथ सहयोग के पक्ष में...इस संदर्भ में जैसाकि दूसरी चोजों के बारे में भी है, मेरी सहानुभूति वामपंथ के साथ थी...यह बड़ा अजीब लगता था कि हम सरकारी कमीशनों के साथ सहयोग करें जबकि हम प्रत्यक्ष कार्रवाई करके संघर्ष करता रहे हों।"

दक्षिणपंथ के व्यवहार के बारे में टिप्पणी करते हुए उन्होंने लिखा :
"बहुत से फूट डालने वालों ने वास्तव में प्रस्ताव के पक्ष में भत दिया था जिनका बाद के बक्तव्यों में उन्होंने विरोध किया। यह एक अजीब और काफी लेदाजनक व्यवहार था..."

यह समझने की बात है कि कम्युनिस्टों का यह रवैया एकदम सही था कि द्वेष यूनियन आंदोलन और इसकी रणनीतिक स्थिति राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थिति और इसकी जहरतों के विरोध में नहीं हो सकती।

लेकिन तुलाई 1931 में हुए इसके प्याहरवे अधिवेशन में, एटक में एक दूसरा विभाजन हुआ। इस बार, रेड इंटरनेशनल ऑफ़ लेबर यूनियन (आर० आई० एल० य००) से अंतर्राष्ट्रीय संबद्धता के सवाल पर, जो एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे बहुमत ने ठुकरा दिया था, कम्युनिस्टों के एक हिस्से ने बहिर्भूमन कर दिया। कम्युनिस्टों ने रेड ट्रेड यूनियन को ग्रेस बना ली। वामपंथी संकीर्णतावाद—जोकि एक बचकाना मर्ज़े है—का यह एक उदाहरण था।

वह हरहल, आर्थिक संकट और मजदूरों पर थोपे गये बोझ ने द्वेष यूनियनों के पुनर्एकीकरण का सवाल उठाया। कम्युनिस्टों ने पहली बार इस जहरत को महसूस किया। रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस को खस्त कर दिया गया और एटक में वापस में भिला लिया गया। यह कार्य एटक के बौद्धवे अधिवेशन के अवसर पर, अप्रैल 1935 को सम्पन्न हुआ।

अगला क्रदम राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन संघ से बातचीत करता था। एटक और

राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन संघ की संयुक्त कार्रवाइयों के लिए 1936 में एक संयुक्त श्रमिक बोर्ड गठित किया गया। 1938 में, विलय के प्रस्तावों पर सहमति हो गयी, एक सहमति प्राप्त कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गयी और अन्ततः 1940 में एटक के अठारहवें अधिवेशन में विलय की पुष्टि कर दी गयी।

यह स्मरण करना उपयुक्त है कि एकता के लिए उस समय ज्ञापित और सर्वस्वीकृत सिद्धांतों में वर्ग-संघर्ष के सिद्धांत की असंदिग्ध स्वीकृति, एक उच्चोग में एक ही यूनियन और भारतीय मजदूरों के केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठन के रूप में एटक के सिद्धांत शामिल थे। आशंका दूर करने हेतु, एक अंतर्निहित संवैधानिक बचाव की व्यवस्था कर दी गयी जिससे सभी राजनीतिक और हड़तालों से संबंधित प्रश्नों पर सामान्य सलाहकार समिति के तीन-चौथाई बहुमत द्वारा निर्णय लिया जा सके।

यह पुनर्एकीकरण भारतीय पूँजीपति वर्ग को पसन्द नहीं आया। आजादी के निकट होने और अपने सत्ता में आने की सम्भावना के साथ ही कांग्रेस के पूँजीवादी नेतृत्व को मजदूर वर्ग को विभाजित करने के लिए हस्तक्षेप करना व अपना एक कठपुतली संगठन स्थापित करना ज़रूरी लगने लगा। 1946 में विभिन्न प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनने के बाद, बम्बई सरकार द्वारा पास किया गया पहला कानून 'बम्बई औद्योगिक संबंध विधेयक' था, जिसका घोषित उद्देश्य पूँजी और श्रम के मध्य संबंधों को अनिवार्य पंचायती निर्णय, हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाकर और सरकार द्वारा 'सहमति प्राप्त' यूनियनों का गठन करके एकरूप बनाना था। सदन के एकमात्र कम्युनिस्ट सदस्य ने हर कदम पर इसका दृढ़ता से विरोध किया।² शासक कांग्रेस ट्रेड यूनियनों को अपने अधीन चाहती थी क्योंकि इससे भारत को पूँजीवादी विकास के रास्ते पर अग्रसर में मदद मिलती। मई 1947 में कांग्रेस मजदूर सेवक संघ द्वारा आयोजित भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक) के उद्घाटन सत्र के अवसर पर अपने भाषण में मंत्री गुलजारीलाल नंदा, जिन्होंने बम्बई विधानसभा में बम्बई औद्योगिक संबंध विधेयक को पटल पर रखा था, स्पष्ट रूप से कहा, "इस समय की फौरी ज़रूरत मजदूरों की उन विख्याती हुई ताकतों को एकजुट करने के लिए साधन जुटाने की है जो कम्युनिस्टों से मूलभूत विरोध रखते हैं," सरदार बल्लभभाई पटेल कहीं ज्यादा स्पष्ट थे, उन्होंने कहा, "एटक को सुधारना और इस पर कब्ज़ा करना बिल्कुल निरर्थक है, क्योंकि कम्युनिस्ट यूनियनें बोगस सदस्य बनाती हैं और अनैतिक उपायों को अपनाने से भी नहीं हिचकती... जो कदम अब उठाया जा रहा है, दरअसल वह पहले ही उठा लिया जाना चाहिए था।"

इस प्रकार विभाजन का औचित्य सिद्ध कर दिया गया और इंटक एटक के

विचारधारात्मक, राजनीतिक और विरोधी ट्रेड यूनियन के रूप में अस्तित्व में आ गयी।

एन० एम० जोशी द्वारा दिये गये इन आरोपों के संयत उत्तर का हमें आभार-पूर्वक स्मरण करना चाहिए, “नवनिर्मित संगठन वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सहायक अंग है और किसी भी तरह गैर-पार्टी या गैर-राजनीतिक श्रमिक संगठन नहीं है जैसाकि एटक है”… यद्यपि आज एटक में कम्युनिस्टों का बहुमत है, मगर एटक द्वारा लिये गये सभी निर्णय समूचे एटक के निर्णय हैं… दुर्भाग्यवश, घबरायी हुई कांग्रेसी सरकारें सोचती हैं कि इस परेशानी से निकलने का सबसे सरल उपाय श्रमिकों की कतारों को बाँट देने में निहित है, वे जियेंगे और सीखेंगे मगर इस दौरान यह दुष्टता कर दी गयी है।”

इन शब्दों में एक भविष्य-दृष्टि ध्वनित होती है। इंटक को जीवित रहना और उन हड्डतालों के बारे में जिनका उन्हें नेतृत्व करना था, बहुत से अवसरों पर संयुक्त हड्डतालों के बारे में भी जानना-समझना पड़ा। लेकिन गड़बड़ हो ही गयी है।

इस विभाजन ने अन्य दूसरे विभाजनों और विखंडन की प्रक्रिया को तेज़ कर दिया। 1948 में, समाजवादी एटक से निकल गये और उन्होंने एन० एम० रॉय के भारतीय श्रमिक संघ के साथ मिलकर हिन्द मजदूर सभा बना ली।

रिपब्लिकन सोसलिस्ट पार्टी ने एक दूसरी यूनियन यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस स्थापित करना उचित समझा। जब सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर अस्तित्व में आया, तो इसने एक समानान्तर अटक (यू० टी० यू० सी०) संगठित कर ली।

सोशलिस्ट पार्टी में विभाजन ने हिन्द मजदूर सभा को फिर से विभाजित कर दिया।

जनसंघ (जो अब भारतीय जनता पार्टी है) की उभरती हुई राजनीतिक आकांक्षाओं ने मजदूरों की तरफ निगाहें की। फौरन बाद ही इसने एक धार्मिक-राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की। इसके नारे थे। ‘श्रम का राष्ट्रीयकरण। उद्योगों का श्रमिकीकरण। देश का औद्योगीकरण।’ ईश्वर संपत्ति का मालिक है, और पूंजीपतियों व मजदूरों को एक औद्योगिक परिवार की तरह ईश्वरीय प्रबंध के तहत रहना चाहिए। अतः कोई वर्ग-संघर्ष नहीं, और कोई अंतरराष्ट्रीयतावाद नहीं। मई दिवस की बजाय विश्व-कर्मा दिवस मनाओ। भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को भी मजदूरों की कतारों में भरता है।

अन्ततः भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन में बिखराव ने 1964 में एटक के भीतर तनाव पैदा किये, और 1970 तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) द्वारा एक नया केन्द्रीय संगठन, सेन्टर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स स्थापित कर दिया गया।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) द्वारा एटक और वामपंथी यूनियनों व संघों पर जो विभाजन थोपा गया, उसने संगठित मजदूरों की जुझारू व क्रांति-कारी कतारों को बाँट दिया। भारतीय परिस्थितियों में अपनी सही भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध मजदूर वर्ग के हरावल और संगठित दस्ते की क्षमता को इसने कम किया है।

'प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का अलग ट्रेड यूनियन केन्द्र हो' की प्रक्रिया और आगे बढ़ी है, यहाँ तक कि अब क्षेत्रीय पार्टियाँ भी अपने अलग ट्रेड यूनियन केन्द्र बनाने की कोशिश में लगी हैं।

इस स्थिति में, स्वतंत्र, असंबद्ध व औद्योगिक संघों की प्रवृत्ति बढ़ी है। बेईमान और स्वार्थी लोगों द्वारा मजदूरों को और ज्यादा बाँटने और उन्हें भटकाने के लिए भी इसने उर्वरा भूमि प्रदान की है।

लेकिन निश्चय ही, जिंदगी के अपने दबाव हैं। इस प्रकार, दोनों ही प्रक्रियाएँ साथ-साथ चल रही हैं। जबकि बिखराव चल रहा है, एकता की ज़रूरत और इच्छा भी व्यापक रूप से बढ़ती जा रही है। ज्यादा-से-ज्यादा संयुक्त कार्रवाइयाँ और स्थायी संयुक्त फ़ोरम पैदा हो रहे थे।

टिप्पणियाँ :

1. "दार्शनिकों ने भिन्न-भिन्न तरीकों से दुनिया कि व्याख्या ही की है; मुख्य बात इसे बदलने की है।"—कार्ल मार्क्स
2. संदर्भ : 2 सितम्बर, 1946 में बम्बई विधानसभा में एस० ए० डांगे का भाषण।

ज़रूर पढ़ें :

1. एटक का संक्षिप्त इतिहास—प्रेमसागर गुप्ता
2. बंगाल में मजदूर वर्ग के आंदोलन का इतिहास—पंचानन साहा
3. हड़ताल विरोधी विधेयक के विरोध में डांगे की भूमिका
4. कम्युनिस्ट एवं ट्रेड यूनियन आंदोलन—पार्वती कृष्णन
5. मेरी अवधारणा का समाजवाद—एम० के० गांधी
6. ट्रेड यूनियन एकता की ओर—ए० बी० बर्धन
(एन० एम० जोशी० जन्म शताब्दी सेमिनार में पढ़ा गया पर्चा)

भारतीय अर्थव्यवस्था और कार्यशक्ति में स्वातंत्र्योत्तर विकास क्रम

लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद भारत जब आजाद हुआ, उसे एक औपनिवेशक, पिछड़ी व विकृत अर्थव्यवस्था विरासत में मिली।

राष्ट्रीय उत्पादन का करीब आधा हिस्सा कृषि से मिलता था और कार्यशक्ति का लगभग 70 प्रतिशत इसमें लगा हुआ था। उत्पादन के सामंती और अद्व-सामंती सम्बन्धों का जबर्दस्त नियंत्रण था। कृषि उत्पादन न केवल स्थिर था, बल्कि 1931 से 1947 के बीच कुछ हद तक गिर भी गया।

राष्ट्रीय उत्पादन का मुश्किल से 17 प्रतिशत खानों, निर्माण उद्योगों और लघु उद्योगों में पैदा होता था और अर्थव्यवस्था के इस सहायक क्षेत्र में जनसंख्या का केवल 9.6 प्रतिशत लगा हुआ था। औद्योगिक क्षेत्र पर उत्पादन के लघु रूपों का प्रमुख था। निर्माण उद्योगों में उपभोक्ता वस्तु उत्पादन छाया हुआ था और निर्माण क्षेत्र के उत्पादन में 78 प्रतिशत का योगदान देता था। ग्रामीण जनसंख्या की कम क्रयशक्ति और संकुचित देशी बाजार उत्पादन की बहुत बड़ी सीमा थीं। इस्पात का कुल उत्पादन केवल 10 लाख टन के लगभग था, कच्चे लोहे का 15 लाख टन के आसपास, पेट्रोलियम उत्पादों का केवल 2 लाख टन और मशीनों, मशीन उपकरणों, रसायनों आदि का लगभग न के बराबर। इस तरह, औद्योगिक क्षेत्र असंतुलित और तकनीकी रूप से बहुत पिछड़ा हुआ था।

इसके अलावा खानों, मिलों और फैक्टरियों में ब्रिटिश पूँजी का रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों पर कब्जा था।

अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को मजबूत बनाने के लिए, मजबूत आधारों पर एक शक्तिशाली औद्योगिक क्षेत्र निर्मित करना, आमूल परिवर्तनवादी कृषि-सुधारों को कार्यान्वित करना एक स्वतंत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास करना जरूरी था।

इससे औद्योगिक क्षेत्र में राज्य की भागीदारी और विदेशी पूँजी के प्रभुत्व से युक्त एक आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था के निर्माण हेतु नियोजन को एक उत्तोलक के तौर पर इस्तेमाल करने की अवधारणा पैदा हुई। इस संदर्भ में पूँजी-पति वर्ग और उसकी राजनीतिक पार्टी का दृष्टिकोण मूलभूत रूप से मजदूर वर्ग और वामपंथी व जनवादी पार्टियों और तत्त्वों के दृष्टिकोण से भिन्न था।

पूँजीपति वर्ग राज्य के हस्तक्षेप और नियंत्रण का उपयोग पूँजीवादी विकास को आगे बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को पूँजीवादी रास्ते पर ले जाने के लिए करना चाहता था। वामपंथी बड़ी निजी पूँजी में क्रमशः कभी, विदेशी पूँजी का अधिग्रहण अर्थव्यवस्था पर इसकी पकड़ ढीली करना और इसके आगे फैलाव पर नियंत्रण रखना और उत्पादन के प्रमुख साधनों का सामाजिकीकरण चाहते थे।

निकट भविष्य में होने वाले सत्ता-परिवर्तन के अनुमान के आधार पर टाटा, बिड़ला और दूसरे प्रमुख पूँजीपतियों द्वारा तैयार बम्बई योजना में घोषणा की गयी : “स्वामित्व अथवा प्रबन्धन की तुलना में राज्य नियंत्रण ज्यादा महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। एक व्यापक क्षेत्र में अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्पादन के सभी उपलब्ध साधनों का संगठन और सामाजिक दृष्टि से बांछनीय उद्देश्यों की ओर उनका प्रवर्तन अत्यन्त आवश्यक है। राज्य के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि इस उद्देश्य के लिए वह आर्थिक क्रियाओं पर अपना स्वामित्व स्थापित करे या उनका प्रबन्ध करे। भली प्रकार निर्देशित और प्रभावशाली राज्य का नियंत्रण पूर्ण रूप से पर्याप्त होना चाहिए।”

अतः, राजकीय हस्तक्षेप, नियंत्रण व नियोजन—हाँ

राजकीय स्वामित्व व राष्ट्रीयकरण—नहीं

1948 में, सरकार ने अपने औद्योगिक नीति प्रस्ताव की घोषणा की। इसके ज़रिये कोयला, लोहा और इस्पात, खनिज तेलों, दूर-संचार उपकरणों, वायुयान निर्माण और जहाज़रानी के क्षेत्रों में नये उपक्रमों की स्थापना के लिए राज्य को विशेष जिम्मेदारी दी गयी, लेकिन प्रचलित निजी उद्योगों को न सिफ़े रहने दिया गया बल्कि उनका विस्तार भी किया गया। सुरक्षा, रेलवे और परमाणु उद्योगों पर सार्वजनिक क्षेत्र का एकमात्र एकाधिकार रहना था, जिनमें से पहले दो तो पहले से ही थे, जबकि तीसरा उस समय अस्तित्व में नहीं था। सार्वजनिक क्षेत्र को दी गयी यह भूमिका इस प्रकार बहुत साधारण ही थी।

औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 1956 ने यह घोषणा करके एक बड़ा कदम लिया कि :

“समाजवादी ढांचे के समाज की राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकृति और नियोजित व तीव्रगामी विकास के लिए ज़रूरी है कि मूलभूत और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं जनोपयोगी सेवाओं की प्रकृति में आने वाले सभी उद्यमों

को सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए। दूसरे उद्योगों, जोकि अत्यावश्यक हैं और उस पैमाने पर निवेश की माँग करते हैं, जिसे मौजूदा परिस्थितियों में सिफ़ेर राज्य ही प्रदान कर सकता है, को भी सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाना चाहिए। एक व्यापक क्षेत्र में उद्योगों के विकास के लिए राज्य को यह प्रत्यक्ष जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए।”

उद्योगों को तीन अनुसूचियों में बांटा गया था :

- (अ) ऐसे उद्योग, जिनके भविष्य में विकास की जिम्मेदारी विशेष रूप से राज्य की होगी,
- (ब) ऐसे उद्योग, जिन्हें धीरे-धीरे सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जाएगा एवं नये उपक्रम स्थापित करने में सामान्यतः राज्य पहल करेगा,
- (स) बचे हुए उद्योगों को निजी क्षेत्र के अंतर्गत विकास के लिए छोड़ दिया गया लेकिन राज्य ने उनका नियमन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा।

दोनों ही प्रस्तावों में राष्ट्रीयकरण के बारे में कोई बात नहीं थी और यद्यपि दोनों में ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र का पूरक है वस्तुतः इसका उद्देश्य भारत में पूँजीवाद के तीव्रगामी विकास को प्रोत्साहित करना था। परवर्ती घोषणाओं में इसकी भूमिका को ‘अर्थव्यवस्था की उच्चतम ऊंचाइयों को स्पर्श करने’ व ‘मूलभूत और सामरिक उद्योगों को गतिशील बनाने’ में सक्रिय कारक के रूप में घोषित किया गया।

साख के संसाधनों पर नियंत्रण रखने, कुछ क्षेत्रों में इजारेदार पूँजीपति वर्ग पर रोक लगाने, कम उत्पादन वाले उद्योगों का प्रबन्ध करने, ‘बीमार उद्योगों की तीमारदारी करने व रोजगार को बनाये रखने की भौतिक ज़रूरतों—राजनीतिक एवं व्यावहारिक से—से राष्ट्रीयकरण का उदय हुआ।

नीचे दिये गये आँकड़ों से सार्वजनिक क्षेत्र की प्रगति स्पष्ट है :

वर्ष	उद्यमों की संख्या	निवेश (करोड़ रुपयों में)
1.4.1951	5	29
1.4.1956	21	81
1.4.1961	48	953
1.4.1966	74	2,415
1.4.1974	122	6,237
1.4.1979	176	15,602
1.4.1984	214	35,394
1.4.1985	221	42,811
1.4.1986	225	50,341

सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण करने में सोवियत संघ और दूसरे समाजवादी देशों द्वारा दिये गये आर्थिक व तकनीकी सहयोग ने बहुत बड़ी मदद की है। सोवियत मदद से निर्मित उद्यम सार्वजनिक क्षेत्र की केन्द्रीय पुरी है—जैसे इसपाल, भारी इंजीनियरी, ऊर्जा इंजीनियरी व उत्पादन, मशीन निर्माण, तेल, कोयला, आदि। इसने भारत को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर ले जाने में मदद की है। इस प्रकार के भारी उद्योगों के लिए सोवियत मदद ने भारत को ओद्योगीकरण के दृष्ट्यक्षों को खोलने और क्षेत्रीय असंतुलन को आंशिक रूप से कम करने में मदद की है। इस सबने भारत की सौदेबाजी की शक्ति को मजबूत किया है तथा आर्थिक और विदेश नीति के मुद्दों पर सामाजिकवादी दबावों और बँकमेल का मुकाबला करने में इसकी मदद की है।

सार्वजनिक क्षेत्र ने निजी क्षेत्र को आधार रखना, प्रचुर ऋण, सस्ता कारब्चा माल और निर्मित बस्तुएँ प्रदान की हैं और इसके विकास के लिए व इजटिलारियों के विकास के लिए अनुकूल दशाएँ पैदा की हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की मूल्यनीति ने निजी पूँजी को सहारा दिया है, इसके लाभों को बढ़ाया है जबकि हानि को स्वयं बहन किया है। यहाँ तक कि बड़ी पूँजी के पत्र 'कांपस' ने भी स्वीकार किया है कि "भारत के निजी क्षेत्र की जो अद्भुत प्रगति समझब हुई है उसका श्रेय सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा निर्मित संरचना को ही जाता है!" पूँजीवाद को विकसित करने पर पूँजीपति वर्ग के हथों में राजस्व की निरायक स्थितियों के होने से यह अवश्यभावी था।

कुल मिलाकर, स्वतंत्रता के बाद के चार दशकों में अपनाये गये विकास के रास्ते से आर्थिक विकास हुआ है, इसने पुराने पड़ बृकुच् भूमि सम्बन्धों को बदला है, भारी उद्योगों की धूरी वाले सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत व वैविध्यपूर्ण बनाया है और एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की नीच रखी है। लेकिन अपनाये गये पूँजी-वादी रास्ते ने विषमताएँ बढ़ायी हैं व सामाजिक ध्रुवीकरण में अपना योगदान किया है। इस रास्ते का संकट पूँजीवादी सरकारों को विभिन्न तथाकथित नवी आर्थिक नीतियों को अपनाने के लिए बाध्य कर रहा है जिसके गम्भीर परिणाम हो रहे हैं। इस बीच हम देखें कि भारतीय कार्यशक्ति के विस्तार और बदलते हुए स्वरूप के सन्दर्भ में इसका क्या मतलब है। टुच 38 पर दी गयी सारणी से स्पष्ट है :

संगठित क्षेत्र में रोजगार (10 लाखों में)

मार्च का अन्त	सार्वजनिक क्षेत्र							कुल योग
	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अर्ध सरकारी	स्थानीय निकाय	योग	निजी क्षेत्र	योग	
1961	2.09	3.01	0.77	1.18	7.05	5.04	12.09	
1971	2.77	4.15	1.93	1.88	10.73	6.74	17.47	
1976	3.05	4.90	3.39	1.98	13.32	6.84	20.17	
1980	3.18	5.48	4.34	2.08	15.08	7.23	22.31	
1982	3.25	5.85	4.81	2.04	15.95	7.55	23.49	
1984	—	—	—	—	16.85	7.40	24.25	
1985	3.34	6.3	5.51	2.51	17.3	7.32	24.62	
1986(जून)	—	—	—	—	—	—	25.37	

इन 23 वर्षों के दौरान संगठित क्षेत्र में कुल रोजगार 100 प्रतिशत से कुछ ऊपर पहुँच चुका है। सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार का भाग 58.3 प्रतिशत से बढ़कर 69.5 प्रतिशत तक पहुँच गया है, जबकि निजी क्षेत्र में यह 41.7 प्रतिशत से घटकर 30.5 प्रतिशत रह गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के संदर्भ में विकास की वार्षिक चक्रवृद्धि दर 3.0 से 3.4 प्रतिशत के लगभग रही है, जबकि निजी क्षेत्र में यह कुछ वर्षोंमें 2.3 प्रतिशत से 0.3 प्रतिशत तक नीचे पहुँच गयी है। 1982 से 1984 तक वस्तुतः गिरावट आयी है। कोई आश्चर्य नहीं कि निजी क्षेत्र में 'बीमार इकाइयों' की संख्या दिसंबर 1980 के अंत में 24,550 से तेजी से बढ़कर दिसम्बर 1984 के अन्त तक 93,282 तक पहुँच गयी और जून 1986 में इसने 1,30,606 की सीमा को भी पार कर लिया है।

आजादी के बाद से कार्यसक्ति के कौन-कौन से स्रोत रहे हैं?

पहला, किसान और देहाती मज़दूर। आजादी के बाद जमींदारी, माल-गुजारी और अन्य दूसरे मध्यस्थों को खत्म करके पुराने पड़ चुके सामंती भूमि सम्बन्धों को बदला गया, काश्तकारी कानूनों को भूमि हृदबन्दी अधिनियमों द्वारा लागू किया गया। लेकिन भू-स्वामियों और अर्द्धसामंती वर्गों के प्रति पूँजीपति वर्ग के समझौतापूर्ण रूख के कारण जनवादी क्रांति का यह पक्ष अपूर्ण रह गया। कृषि-सुधार बीच में ही छोड़ दिये गये। भू-स्वामित्व का ढाँचा वास्तविक रूप में नहीं बदला है और अतिरिक्त भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा बाँटा नहीं गया है। 2 करोड़ 15 लाख एकड़ अतिरिक्त कार्यक्षमता का भुशिकल से 10.3 प्रतिशत अभी तक बाँटा गया है। 1981 में, देश में भूमिहीन कृषि मज़दूरों की संख्या 5 करोड़,

50 लाख थी। ग्ररीब किसानों की क़तारों से प्रतिवर्ष 10 लाख लोग इसमें जुड़ जाते हैं।

छठी योजना के अनुसार, 1980 में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या 33 करोड़ 80 लाख थी (जिसमें 28 करोड़ से ऊपर देहाती इलाक़ों से थे)। एक अनुमान के अनुसार, इसमें प्रतिवर्ष 67 लाख लोगों की वृद्धि हो जाती है (51 लाख 70 हजार देहाती इलाक़ों में और 15 लाख शहरी इलाक़ों में)।

अभाव और अकाल से बार-बार होने वाले विनाशों और सामान्य काल में भी देहाती इलाक़ों में रोजगार के अभाव ने बड़े स्तर पर गाँवों से शहरों की ओर—रोजगार और जीविका की तलाश में मुख्यतः बड़े औद्योगिक संकुलों की ओर—स्थानान्तरण को बढ़ावा दिया है। देहाती बेरोजगारों की संख्या ग्ररीब 50 करोड़ के आसपास होने का अनुमान है।

दूसरे, रोजगार दफ्तरों के वर्तमान रजिस्टरों में (ज्यादातर शहरी इलाकों में) रोजगार अभ्यार्थियों की संख्या 1981 में 1 करोड़ 65 लाख 80 हजार से बढ़कर मार्च 1987 में 3 करोड़ 48 हजार हो गयी है। इसमें से, 1 करोड़ 30 लाख 26 हजार शिक्षित बेरोजगार हैं। इसने एक 'आरक्षित फौज' को जन्म दिया है जिसमें से उद्योगों और सेवाओं को नियुक्तियाँ करनी हैं।

तीसरे, शिक्षा के विस्तार ने जिसमें तकनीकी, बहुतकनीकी, इंजीनियरी, और व्यावसायिक शिक्षा भी सम्मिलित है, वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मचारियों (इस क्षेत्र में भारत का तीसरा स्थान है) की बड़ी ताकत को पैदा किया है। 1981 में केवल तकनीकी स्नातकों और अधिस्नातकों की संख्या ही 10 लाख 10 हजार थी। जबकि गैर-तकनीकी स्नातकों और अधिस्नातकों की संख्या 50 लाख 88 हजार थी। तब से यह संख्या तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। प्रौद्योगिक रूप से विकसित और अत्याधुनिक उद्योगों व उत्पादन, सेवा और प्रशासनिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं ने लगातार बढ़ती हुई संख्या में उनकी भरती को प्रेरित किया है। ये लोग शहरी मध्यवर्गों और व्यावसायिक समूहों से, मध्यम और अमीर किसानों से, यहाँ तक कि मजदूर वर्गों से भी आते हैं। उच्चस्तरीय शिक्षा संस्थाओं और सेवाओं में अनुसूचित जातियों, जन-जातियों और कुछ राज्यों में पिछड़े हुए वर्गों के लिए आरक्षण ने समाज के निम्न और अभी तक उपेक्षित हिस्सों से आने वाले लोगों को, सीढ़ी के निचले दर्जे पर जो कुछ गुंजाइश थी, उसके अलावा उच्च स्तर की श्रेणियों से जुड़ने में मदद की।

और अंत में, औद्योगिक क्रियाकलाप और दूरस्थ इलाक़ों में कुछ बड़ी परियोजनाओं के विस्तार ने स्थानीय लोगों, मुख्यतः अकुशल और अर्धकुशल मजदूर-शक्ति को अवसर प्रदान किया है जिनके पास 'औद्योगिक संस्कृति' का पिछला कोई अनुभव या ज्ञान नहीं है। इसके साथ ही, इन परियोजनाओं, मुख्यतः कुशलता

व बहुत अधिक कृशलता की मार्ग करने वाले थावसायों में कार्य करने के लिए इसने क्षेत्र से 'बाहर' के लोगों के अंतर्वाह को जन्म दिया है, बाहर जाने वाले निमण मजदूरों, जो एक परियोजना से हसरी परियोजना में घमते रहते हैं, की संख्या भी बढ़ी है।

चिभिन्न छातों, जिनमें अभी तक के गैर-मजदूर वर्ग स्थोत भी शामिल हैं, से पैदा होने वाले अंतर्वाह के साथ कार्यशक्ति भी बढ़ी है, आगे आने वाले पाठों में हम इस घटनाक्रिया, वर्तमान समय में मजदूर वर्ग के परिवर्तित स्वरूप और इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करेंगे। लेकिन ट्रेड यूनियन और आज की राजनीतिक क्रियाओं के कुछ तथ्यों और उपकरणों से स्वयं को लैस करने के उद्देश्य से यहाँ हम कुछ चुनिदा तालिकाएँ प्रस्तुत करेंगे :

1981 में मजदूर और गैर-मजदूर जनसंख्या (दस लाखों में)

	योग	ग्रामीण	शहरी
जनसंख्या (योग)	665.3	507.6	157.7
पुरुष	343.9	260.1	83.9
स्त्रियाँ	321.4	247.5	73.8
प्रमुख मजदूर (योग)	222.5	176.4	46.1
पुरुष	177.5	136.8	40.7
स्त्रियाँ	45.0	39.6	5.4
सीमांत मजदूर (योग)	22.1	20.9	1.2
पुरुष	3.5	3.1	0.4
स्त्रियाँ	18.6	17.8	0.8
गैर-मजदूर (योग)	420.7	310.3	110.4
पुरुष	162.9	120.1	42.7
स्त्रियाँ	257.8	190.2	67.7

नोट : प्रमुख मजदूर उसे कहते हैं जो गणना की तारीख से पूर्व कम-से-कम

183 दिनों के लिए आर्थिक रूप से उत्पादक क्रिया में लगा हुआ था। सीमांत मजदूर वह है जिसे 183 से कम दिनों के लिए क्राम मिला। गैर-मजदूर वह है जिसने पिछले वर्ष बिलकुल काम नहीं किया। गृहणीय विद्यार्थी व रिटायर्ड लोग गैर-मजदूरों में शामिल होते हैं। (1981 की जन-गणना के 'प्रमुख मजदूरों' और 1971 की जन-गणना के 'मजदूरों' में व्यापक समरूपता पायी जाती है),

1982 में उद्योग विभाग द्वारा संगठित क्षेत्र में रोजगार (हजारों में)

उद्योग	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र
कृषि, आखेट आदि	457	851
खनन	832	129
उत्पादन	1,592	4,661
विजली, गैस और पानी	698	36
निर्माण	1,112	71
थोक एवं खुदरा व्यापार आदि	113	277
यातायात एवं संचार आदि	2,781	60
सेवाएँ	8,362	1,463
योग	15,947	7,548

निजी क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार निर्माण उद्योगों में है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में यह सेवाओं के बाद यातायात और संचार में है।

वेतनभोगी और स्व-रोजगार प्राप्त (1977-78)

	संख्या (दस लाख में)	कुल का प्रतिशत
मजदूरी एवं वेतनभोगी	100.5	38.5
संगठित क्षेत्र	24.8	9.5
सार्वजनिक क्षेत्र	15.0	5.7
निजी क्षेत्र	9.8	3.8
असंगठित क्षेत्र	75.7	29.0
कृषि मजदूर	58.3	22.3
गैर-कृषि मजदूर	11.4	4.4
अन्य	6.0	2.3
स्वरोजगार प्राप्त	160.4	61.5
काश्तकार	128.1	49.1
गैर-काश्तकार	32.3	12.4
योग	260.9	100.0

नोट : (एक तालिका में दी हुई कुछ संख्याएँ दूसरी तालिकाओं में दी गयी संख्याओं से नहीं मिलतीं, क्योंकि दोनों का आधार एक नहीं है और स्रोत भी भिन्न हैं)।

- असंगठित क्षेत्र में रोजगार संगठित क्षेत्र में रोजगार से तीन गुना ज्यादा है। दोनों क्षेत्रों में मजदूरी और वेतनभोगी लोगों की तुलना में स्वरोजगार-प्राप्त लोगों की संख्या डेढ़ गुनी अधिक है।

टिप्पणी :

1. यह संख्या पहले ही 3 करोड़ पार कर चुकी है।

ज्ञानर पढ़ें :

1. सार्वजनिक क्षेत्र पर हमला : एम० एस० कृष्णन
2. भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र : गिरीश मिश्रा
3. उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण
4. भारतीय श्रम संस्थायकी
5. आर्थिक सर्वेक्षण : भारत सरकार
6. विकासमान देशों में राज्य क्षेत्र : एक परिचर्चा (एन० के० कृष्णन, ए० बी० वर्धन और चतुरानन मिश्र के लेख)

स्वातंत्र्योत्तर मज़दूर वर्ग-संघर्ष और ट्रेड यूनियन आंदोलन

आज्ञादी के बाद बड़े पूँजीपति वर्ग के नेतृत्व में भारतीय पूँजीपति वर्ग ने राजसत्ता की निर्णायक स्थितियों पर अपना अधिकार कर लिया है। भू-स्वामियों के साथ उसके मज़बूत संबंध व समझौते हैं। 'कल्याणकारी राज्य', 'मिश्रित अर्थ-व्यवस्था', 'समाजवादी ढाँचे का समाज' और इसी तरह के नारे देते हुए इसने स्वतंत्र पूँजीवादी विकास के दीर्घकालीन हितों को देखते हुए राजसत्ता का इस्तेमाल करना आरम्भ कर दिया। इसका आशय सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण करना था, जो तात्त्विक रूप में एक साम्राज्यवाद विरोधी धारा और चरित्र लिये हुए था। इसका आशय साख और बजट संबंधी कारकों के नियोजन के उपकरण द्वारा इजारेदारी विकास और पूँजीवादी विस्तार के विरोधी दावों को नियंत्रित करना था। इसका आशय कुछ सीमा तक कृषि संबंधी मुद्धारों और कृषि क्षेत्र में निवेशों से था, जहाँ तक मज़दूर वर्ग का संबंध है, पूँजीपति वर्ग की नीति उन्हें काढ़ में रखने और बड़ी-बड़ी रियायतें देने की थी—जब भी सामाजिक-राजनीतिक जरूरतों ने उन्हें ऐसा करने के लिए मज़बूर किया।

उसने, सबसे पहले, ट्रेड यूनियनों को विघटित कर, अपने विचारधारात्मक, राजनीतिक और व्यावहारिक नियंत्रण में यूनियनें स्थापित कर और हंगामी प्रशासनिक उपायों द्वारा उन्हें सहारा देकर इस नीति का श्रीगणेश किया। इसने औद्योगिक संबंधों की एक कार्यसूची थोप दी जिसने यूनियन को अशक्त बना डाला, वास्तविकता में हड्डालों को गैर-कानूनी करार कर दिया और कभी न खत्म होने वाली मुकदमेबाजी में मज़दूरों को फँसा कर लें खिचने वाले अनिवार्य अदालती निर्णय व्यवस्था को थोप दिया।

इसके विपरीत, एटक और अन्य दूसरी समान विचारों वाली ट्रेड यूनियनें न्यूनतम जीवन स्तरों को स्थापित करने और क्रमशः उन्हें उठाते जाने, वर्तमान

स्तरों को मुद्रास्फीति, मूल्य वृद्धि और प्रयोक्ष मजहूरी में कटौती के कारण कम होने से बचाने, आधुनिकीकरण, बैंकिंग पुर्सनेटन, स्वचालन और इसी प्रकार की अन्य कोशिशों के विरुद्ध काम की सुरक्षा बनाये रखने, दुर्बंधना, छाराब स्वास्थ्य, ठंडनी, बुझाएं और मातृत्व में कुछ हव तक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने; ट्रेड यूनियन और जनवादी अधिकारों को खत्म करने के प्रयासों के विरुद्ध उनकी रक्षा करने और उनका विस्तार करने; स्वतंत्र आर्थिक विकास, लोकतंत्र और सामाजिक प्रगति की दिशा में तथा बाहु रूप में युटनिएक्शन, साम्राज्यवाद विरोध, राष्ट्रीय मुक्ति संशासों को मदद, समाजवादी देशों के साथ मित्रता और विश्व-शांति की सुरक्षा की प्रगतिशील विदेश नीति की ओर देश को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे हैं। नेतृत्व के द्वारा गतिशील, यहाँ तक कि भव्यकर गतिशील हुई है मगर प्रमुख प्रयोग की दिशा की कमी भी दृष्टि से आवश्यक नहीं होने दिया गया।

आजादी के तुरन्त बाद, सरकार ने एटक और कम्युनिटों के नेतृत्व वाले संगठनों के लिलाक भव्यकर दमतक कचाया, तेलंगाना के किसानों का जो भूमि के लिए और निजाम के शासन के द्वारा सामंती और रक्षाकारों की कूरताओं के विरुद्ध लड़ रहे थे, सशास्त्र सेनाओं द्वारा निरंतरपूर्वक दमन किया गया जबकि यह संघर्ष बदली हुई परिस्थितियों में चलाया गया था। ट्रेड यूनियनों और दूसरे जन संगठनों के हजारों अश्रु कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं को जेल में ढूम दिया गया। उस समय नेतृत्व द्वारा अपनायी गयी बामपंथी-संकीर्णतावादी और दुसराहसिक नीति ने सरकार को अपने दमतकारी कार्यों को चलाने का अवसर प्रदान किया, उनके पारम्परिक संघ के अध्यक्ष द्वारा 9 मार्च, 1949 को दिया गया रेलवे हड़ताल का आह्वान असफल साकित हुआ। इसने आम जनता से अलगाव को प्रोत्साहित किया और एटक की गतिविधियों को छाक्का लगा।

1952 में कलकत्ता में एटक ने एक अधिकेशन बुलाया, अपने बलों को फिर से इकट्ठा किया, ट्रेड यूनियन अदीलत में आयी दरार को पाटने की अपील की और सभी स्तरों पर संगठन के पुनर्निर्माण हेतु उत्तर गयी।

सही लाइन पर सामान्य कियाकालाप की वापसी के अच्छे लाभ है। 1946 के पश्चात एक नयी धारा ट्रेड यूनियन आंदोलन के मुख्य प्रवाह के साथ मिलने लगी थी। मजदूर वर्ग की तकनीकों और सचर्व के तरीकों का सहारा लेते हुए जैक कर्मचारियों के नेतृत्व में मध्यवर्गीय कर्मचारियों यानी सफेदपोश लोगों ने स्वयं को ट्रेड यूनियनों के रूप में संगठित करता प्रारम्भ कर दिया था। अखिल भारतीय जैक कर्मचारी संघ ने, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी, 1947 में लखनऊ में अपना पहला बार्षिक सम्मेलन बुलाया। मध्यवर्गीय कर्मचारियों के दूसरे हिस्सों, जैसे बीपा, आपाटिक और सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमे चले। एटक के

कलकत्ता अधिवेशन ने इस सकारात्मक विकास का जायज़ा लिया और मध्यवर्गीय कर्मचारियों को संगठित होने और साझे संघर्षों, साझे प्रयासों और साझी नियति में मज़दूर वर्ग के साथ हाथ मिलाने का आह्वान किया।

तब से मध्यवर्गीय कर्मचारियों के संगठन हमेशा सक्रिय, जुझारू और भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन के व्यापक आधार वाले दस्ते रहे हैं। इस अवधि में अद्यापकों, प्रोफेसरों, इंजीनियरों, पत्रकारों और अन्य व्यावसायिक समूहों ने भी अपने संगठन स्थापित कर लिये हैं, जुझारू हड़ताली गतिविधियों में संलग्न हो रहे हैं और अनेक अवसरों पर ट्रेड यूनियन आंदोलन के साथ संबद्ध हो रहे हैं।

मज़दूरी वृद्धि और मज़दूरी का मानकीकरण ही औद्योगिक विवादों के एकमात्र मुख्य कारण रहे हैं जिससे इस दौरान हड़ताल की कार्रवाइयाँ हुई हैं। 1928 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई० एल० ओ०) ने न्यूनतम मज़दूरी पर एक प्रस्ताव (संख्या 26) पारित किया था। 1968 में भारत ने इसकी पुष्टि कर दी। इस बीच न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 पास कर दिया गया। इसका क्षेत्र उन रोजगारों तक सीमित था जिसमें हाड़तोड़ मेहनत अधिक प्रचलित है या जहाँ श्रम के भयंकर शोषण का कोई अवसर रहता है, सिवा इसके कि ट्रेड यूनियनों को आंदोलन के लिए एक पताका प्रदान की है, इसका क्रियान्वयन अब तक नहीं हो पाया है। राष्ट्रीय श्रम आयोग (1969) का मानना था कि “बहुत से रोजगारों में न्यूनतम मज़दूरी एक बार निर्धारित होने के बाद फिर से संशोधित ही नहीं की गयी” और फलस्वरूप बहुत सी स्थितियों में मज़दूरी की प्रचलित दरें काफ़ी पहले निर्धारित न्यूनतम दरों से ज्यादा थीं। जहाँ कहीं उच्चतर न्यूनतम मज़दूरी की परिवर्त शोषणाएँ की गयी हैं, नियोक्ताओं को उनकी उपेक्षा व अतिक्रमण करने दिया गया है और बच निकलने दिया गया है। (बीड़ी, शक्तिचालित करघे, आदि)

प्रारम्भिक वर्षों में स्थापित उचित मज़दूरी समिति ने न्यूनतम मज़दूरी और वास्तविक मज़दूरी की कुछ अवधारणाओं को इस रूप में परिभ्राषित किया कि उचित मज़दूरी की निम्न सीमा ही निम्नतम मज़दूरी होगी और उच्च सीमा का निर्धारण उद्योग की भूगतान क्षमता के आधार पर होगा।

मज़दूरी के इस संघर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि 1957 में पन्द्रहवें भारतीय श्रमिक अधिवेशन का वह निर्णय रहा जिसने ‘आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मज़दूरी’ की गणना हेतु कुछ वैज्ञानिक मानदण्डों को स्थापित किया। यह सिद्धांत के प्रश्न पर ट्रेड यूनियन आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विजय थी। व्यवहार में, बहरहाल, सभी वेतन कमीशनों, मज़दूरी बोर्डों, ट्रिब्यूनलों, आदि की नीयत वर्तमान परिस्थितियों में इसे अवास्तविक या अव्यवहार्य मानकर उपेक्षा करने की रही है, और इन मानदण्डों को नीचे की ओर संशोधित करने के षड्यन्त्र में सरकार शरीक रही है।

मज़दूरी निर्धारण के मामले में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, जिसे अनेक स्थानीय और औद्योगिक संघर्षों द्वारा प्राप्त किया गया है, ज्यादातर उद्योगों में द्विपक्षीय समझौतों की शुरुआत तथा ट्रिब्यूनलों और मज़दूरी-बोर्डों का वास्तविक परित्याग किया जाना रहा है। बैंक कर्मचारियों (अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ) द्वारा इस दिशा में रास्ता खोल दिया गया है तथा यह अब अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों और कुछ निजी क्षेत्र उद्योगों में भी आम तरीका बन गया है। इन उद्योगों में ट्रेड यूनियनों की विकसित होती हुई ताकत की वजह से सरकार द्वारा समर्पित अनिवार्य पंचायती निर्णय और अदालती फँसले के ऊपर सामूहिक सौदेबाजी के सिद्धांत ने जीत हासिल की। बदले में, इसने ट्रेड यूनियन की ताकत को और मज़बूत किता है और आगामी संयुक्त आंदोलनों और कार्रवाइयों के लिए रास्ता तैयार करते हुए भिन्न-भिन्न प्रतिबद्धताओं वाली यूनियनों को साझी सौदेबाजी की मेज पर लाने का कार्य किया है। इस प्रकार से मज़दूरी के निपटारों के द्वारा संगठित उद्योगों के संगठित मज़दूर वास्तविक लाभ प्राप्त करने में सफल रहे हैं। सरकार द्वारा इन दिनों इस तरीके को उलटने अथवा उसे जकड़ने के प्रयास किये जा रहे हैं। सार्वजनिक उद्यम बोर्ड के निर्देशों के तहत खुल्लमखुल्ला मज़दूरी-जाम लागू किया जा रहा है।

युद्ध के शुरू होने के बाद से ही महँगाई भत्ते की माँग उठायी गयी थी। (1940 में बम्बई कपड़ा मज़दूरों की महान 'महँगाई' हड़ताल इसका प्रमाण है)। इस माँग का आशय मूल्य वृद्धि के कारण मज़दूरों की वास्तविक मज़दूरी में आने वाली कमी को रोकना था। आजादी के बाद, पूजीवादी नियोजन पद्धति ने अनिवार्यतः उच्च मुद्रा प्रसार के दबाव पैदा किये हैं और मूल्य वृद्धि और अधिक बढ़ाने में मदद की है। अनेकों जाँच समितियाँ (डिवेटिया, जयरत्नम और अन्य) पहले ही युद्ध के दौरान जीवन निर्बाह लागत से सम्बद्ध महँगाई भत्ते की व्यवस्था कर चुकी थीं: बाद के वर्षों में राज्याध्यक्ष पुरस्कार (1946), प्रथम केन्द्रीय वेतन आयोग (1947), उचित मज़दूरी समिति (1948), बैंक पुरस्कार आयोग (1955), द्वितीय वेतन आयोग (1959), दास आयोग (1965), गजेन्द्रगढ़कर आयोग (1967) ने, जिनकी परिणति भारत सरकार द्वारा स्थापित केन्द्रीय महँगाई भत्ता समिति में हुई, महँगाई भत्ते के फार्मूले तैयार किये हैं। प्रत्येक के द्वारा निकायकरण की अनेकों विधियाँ व दरें सुझाई गयी, मगर हरेक अग्रणीमी कदम कड़े संघर्षों और हड़ताली कार्रवाइयों का परिणाम रहा है, जो संख्यात्मक रूप से अवर्णनीय हैं।

पहले, कम मूल वेतन व ज्यादा महँगाई भत्ता व्यवहार में था। लेकिन अब, बोनस, ग्रेचुटी आदि के मूल वेतन + महँगाई भत्ते के आधार पर गणना करने के बाद और इसके बावजूद, कि मूल्य सूचकांक में किसी वास्तविक गिरावट के कोई

आसार नहीं हैं, सूचकांक के किसी निश्चित बिन्दु पर वेतन को महँगाई भत्ते के साथ मिला देने की प्रवृत्ति पायी जाती है।

बहरहाल, संघर्षों के दबाव में इस हाथ से जो कुछ दिया जाता रहा है, सूचकांक में गड़बड़ी, नये परिवार बजट जॉच के प्रतिरोध, मनमाने ढंग से आधार-भूत वर्ष में परिवर्तन, और दरों को संशोधित करने से इंकार जैसे उपायों द्वारा उसे उस हाथ से वापस ले लिया जाता है जिससे निम्नतम मजदूरी स्तरों पर 100 प्रतिशत से अधिक मिथिक्यकरण, (क्योंकि इन स्थितियों में, कुल प्रभाव उससे कहीं ज्यादा होता है जो जीवन सूचकांक लागत दिखाती है), मध्यम स्तर पर 100 प्रतिशत निष्क्रियकरण और उच्चतर स्तरों पर क्रमशः कम दरों पर प्रबन्ध किया जा सके।

बोनस के लिए संघर्ष, जिसका एक लम्बा इतिहास रहा है। जो मजदूरों के इस दबे पर आधारित है कि यह एक 'स्थगित वेतन' है और जो अधिकतर उद्योगों में सालाना हड़तालों का कारण रहा है को सफलता तब मिली जब बोनस भुगतान अधिनियम, 1955 संविधि संहिता में शामिल किया गया। जहाँ कहीं भी नियोक्ता-कर्मचारियों के बीच मेल-जोल पाया जाता है, वहाँ उन उद्योगों में जिन्हें वेतहाशा मुनाफ़ा प्राप्त होता है, उनमें 20 प्रतिशत के प्रतिबन्ध को पार करते हुए और अधिकतम पात्रता मजदूरी आदि को ऊपर उठाते हुए आगामी संघर्षों ने 4 प्रतिशत न्यूनतम सालाना मजदूरी को 8.33 प्रतिशत तक बढ़ाने और बोनस को कर्मचारियों के सभी तबकों तक पहुँचाने में मदद की है। हरेक क़दम के लिए और अनेक मौकों पर मजदूरों को जन-कारवाइयों का सहारा लेना पड़ा है। संगठित उद्योगों और अनेक असंगठित उद्योगों में भी बोनस मजदूरों के कुल वेतन का एक आवश्यक सालाना घटक हो गया है। अब कोशिश यह है कि इसे सभी तरह के उत्पादकता मानदण्डों और प्रणालियों से जोड़कर धीण कर दिया जाय।

'वेतनभोगी मजदूर'—जो समाज की प्रमुख उत्पादक शक्ति है, के निर्वाह, उत्पादन और वित्तत् पुनरुत्पादन के लिए एक आवश्यक तत्व के रूप में सापाजिक सुरक्षा ट्रेड यूनियन संघर्षों का एक जीवंत मुद्दा रही है। ब्रिटिश शासन के दौरान मजदूर क्षतिपूर्ति अधिनियम और मातृत्व लाभ अधिनियम पहले ही लागू किये जा चुके थे। स्वतन्त्रता के बाद ट्रेड यूनियन संघर्षों और वेतनभोगी मजदूर की वंशवृद्धि से जुड़ी हुई पूँजीपति वर्ग की अपनी ज़रूरत ने अनेक सामाजिक सुरक्षा अधिनियमों जैसे कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, ग्रेचुटी भुगतान अधिनियम, 1972, परिवार पेंशन प्रणाली, अनिवार्य अवकाश और छँटनी मुआवजा आदि को लागू करने में भूमिका अदा की। संगठित मजदूर अनेक 'सीमांत लाभ' प्राप्त करने में भी

सफल हुए हैं जिनसे बेहतर जीवन स्तरों के लिए संघर्ष करने वाले मज़दूरों के अन्य हिस्से भी प्रेरित हुए हैं।

कुछ उद्योगों के लिए, जिनकी अपनी विशिष्टताएं हैं, प्रचलित अराजकता और अव्यवस्था ने कुछ विशेष कानूनों के लिए रास्ता तैयार किया है, यथा : बागान मज़दूर अधिनियम, 1951, खान अधिनियम, 1955, गोदी मज़दूर अधिनियम, 1948, कार्यरत पत्रकार अधिनियम, 1951, मोटर यातायात मज़दूर अधिनियम, 1961, बीड़ी एवं सिगार मज़दूर अधिनियम, 1966, ठेका श्रम अधिनियम 1970, विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी अधिनियम, 1976, अनेक दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, आदि।

लगभग सभी स्थितियों में क्रियान्वयन की सीमा ट्रेड यूनियनों की शक्ति और सजगता तथा उनके निरन्तर संघर्षों पर निर्भर करती है। ठेका मज़दूरों के संदर्भ में—जोकि औद्योगिक, व्यापारिक एवं निर्माण क्रियाओं के सभी क्षेत्रों में तेज़ी से फलफूल रहा है—अधिनियम के प्रावधानों को अनेदेखा कर दिया जाता है और कानून का वास्तविकता में विल्कुल भी पालन नहीं किया जाता।

इस दौरान ट्रेड यूनियन संघर्ष केवल आर्थिक माँगों तक ही सीमित नहीं थे। उन्हें प्रमुख नीतिगत मुद्दों पर भी चमाया गया था।

सार्वजनिक क्षेत्र के सवाल पर एटक ने पहली बार सकारात्मक रूख अपनाया जबकि ट्रेड यूनियन आंदोलन में कुछ दूसरे तबक्के या तो इसके प्रति उदासीन रहे या फिर उन्होंने संकीर्णतावादी शत्रुता का रूख अपनाया। एर्नाकुलम अधिवेशन (1957) में इसने सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा करने और इसका विस्तार करने और साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र में मज़दूरों के अधिकारों व माँगों के लिए संघर्ष की सुपरिचित ‘दोहरी नीति’ को अपनाया। यह प्रवृत्ति थी जिसने एटक और ट्रेड यूनियन आंदोलन को कुछ उद्योगों के राष्ट्रीयकरण और एक स्पष्ट दृष्टि के साथ सरकार द्वारा ‘बीमार इकाइयों’ के अधिग्रहण के लिए संघर्ष करने योग्य बनाया।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने, जिसे एटक का समर्थन प्राप्त था, एक निर्णायिक भूमिका अदा की। यह राष्ट्रीय आंदोलन की ही एक माँग रही थी। मगर यह अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ही था जिसने 1963 में इस मुद्दे को फिर से उठाया और 1964 में संघर्ष द्वारा इसे सहारा दिया। बढ़ती हुई माँग को देखते हुए 1968 में तत्कालीन वित्तमंत्री मोरारजी देसाई ने ‘सामाजिक नियंत्रण’ का झाँसा दिया जिसका वास्तविक आशय इजारेदारों को खुला अवसर प्रदान करना और कर्मचारियों को ज़ंजीरों में बाँध देना था। सामाजिक नियंत्रण प्रस्ताव के खिलाफ अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ की हड़ताल संसद के अन्दर संघर्ष और कांग्रेस के भीतर अंदरूनी झगड़ों ने मोरारजी देसाई की बेदखली, प्रस्ताव के विघटन और 19 जुलाई, 1969 को

बैंकों के राष्ट्रीयकरण में अपना योगदान दिया।

एटक का यह पक्का मत था कि एक ऐसे देश में जहाँ राज्य स्वयं में एक पूँजीवादी राज्य है और जो पूँजीवाद का निर्माण कर रहा है, वहाँ सार्वजनिक क्षेत्र किसी भी रूप में समाजवादी क्षेत्र नहीं है। यह एक राज्य-पूँजीवादी क्षेत्र है। लेकिन प्रस्तुत संदर्भ में इसका एक साम्राज्यवाद-विरोधी चरित्र है, यह स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था का निर्माण करने में मदद करता है और आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर इसने एटक को वाम और दक्षिण, दोनों प्रकार के भटकावों से लड़ने के लिए सक्षम बताया है।

आज के संदर्भ में, जबकि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा गिराने का प्रयास कर रही है, सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा करने, इसका विस्तार और सार्वजनिक क्षेत्र का जनतंत्रीकरण करने का बड़ा जबर्दस्त महत्व है जैसाकि हम आगामी पाठों में देखेंगे।

आर्थिक और राजनीतिक संकट के बढ़ने के साथ ही पूँजीपति वर्ग ने मजदूर वर्ग पर हमलों को बढ़ाकर अपने ही समाधान खोजने की कोशिश की है। मजदूरों का एकत्रित रोष 1974 की रेलवे कर्मचारियों की, जो अकेले एक ही उद्योग में कर्मचारियों का सबसे बड़ा अंग है, जुझारू हड्डताल के रूप में अभिव्यक्त हुआ। संघर्ष के संयुक्त मंच के रूप में रेलवे-कर्मचारियों के संघर्ष की राष्ट्रीय अभियान समिति का गठन किया गया और सिवा इंटक के, इसे सभी ट्रेड यूनियनों का समर्थन मिला। जबर्दस्त दमन की वजह से 11 दिनों के बाद संघर्ष को वापस लेना पड़ा। एटक के अनुयायी संघर्ष में फँसे हुए थे और दमन व उत्पीड़न सबसे ज्यादा उन्हें ही सहना पड़ा। मगर दुर्भाग्यवश इस बहादुरीपूर्ण कार्य में, जिसमें हमने एक गौरवरूप भूमिका निभायी थी, सही नीतिगत दृष्टिकोण नहीं था, जिसके फलस्वरूप एटक इस संघर्ष के परिणामों से न लाभ उठा सका, न ही इसे आगे बढ़ा सका।

गलत राजनीतिक दृष्टिकोण, जिससे उस बङ्ग सेवन नेतृत्व प्रस्त था, 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाये गये आपातकाल को एटक के प्रारम्भिक समर्थन की तह में मौजूदथा। सरकार द्वारा मजदूरों पर दमन तेज़ कर दिया गया। अनिवार्य जमा योजना शुरू की गयी। बोनस पर हमला हुआ। सरकार ने 'लाभ नहीं तो बोनस नहीं' कार्मूले का प्रचार किया। वेतन-जाम थोप दिया गया। एटक के जुझारू योद्धाओं समेत ट्रेड यूनियनवादियों के खिलाफ़ सीसा का प्रयोग किया गया। शीघ्र ही, आपातकाल पूर्ण रूप से उत्पादन-विरोधी साबित होने लगा। इसने पूँजीपति वर्ग को कोई रास्ता नहीं सुझाया। 1976 के अन्त तक मजदूरों के हड्डताल और संघर्ष, जो वस्तुतः कभी पूरी तरह नहीं बुझ पाये थे, फिर तेज़ी से शुरू हो गये। दक्षिणपंथी ताकतों के एक सम्मिश्रण द्वारा इस फूट पड़ते आक्रोश

का नेतृत्व व इस्सेमाल कर लिया गया। इससे आपातकाल के हटाये जाने के साथ जनता पार्टी सत्ता में आ गयी।

जनता शासन के दौरान मजदूरों द्वारा हासिल की गयी उपलब्धियों को छीन लेने और मजदूरों की कीमत पर पूँजीवादी संकट को हल करने के प्रयास बिना किसी रुकावट के जारी रहे।

वेतन-जाम हेतु भूर्तिलिंगम पेनल द्वारा की गयी सिफारिशों को थोप देने का प्रयास हुआ। 28 जून, 1978 को सावंजनिक क्षेत्र में इसके विरोध में हड़ताल के संयुक्त आह्वान ने ही सरकार को आखिरी क्षणों में पीछे हटने के लिए विवश किया। अगला लक्ष्य बैंक कर्मचारी थे जिन पर 'उच्च-वेतन द्वीप-निवासी' का लेबल लगा हुआ था और जिनका महँगाई भत्ता फ़ार्मूला संशोधित किया जाने वाला था। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत जुझारू मोर्चे ने, जिसे सारे ट्रेड यूनियन आंदोलन की भाईचारापूर्ण कार्रवाइयों द्वारा समर्थन मिला, सरकार को यह सब न करने के लिए मजबूर कर दिया। दो लाख से ज्यादा जूट मजदूरों को अपनी माँगों के लिए 50 दिन लम्बी हड़ताल चलानी पड़ी। 20 मार्च, 1979 को संसद के सामने तीन लाख से ज्यादा खेत-मजदूरों के जबरदस्त प्रदर्शन के साथ ही एक नया तत्व दृश्यपटल पर उभरा। इसने दिखाया कि हमारी जनता का सबसे ज्यादा शोषित हिस्सा, ग्रामीण सर्वहारा, संघर्ष करने वालों की क्रतारों में शामिल हो गया है और उसने संगठन और संघर्ष का रास्ता अस्थियार कर लिया है।

औद्योगिक संबंधों का प्रश्न मजदूरों और पूँजीवादी राज्य द्वारा समर्पित पूँजीपतियों के बीच निरन्तर 'गुरिल्ला युद्ध' का स्रोत रहा है, स्पष्टतः क्योंकि जारी वर्ग-संघर्ष दिन-प्रतिदिन इसी रूप में अभिव्यक्त होता है। सर्वाधिक विवादास्पद मुद्दे यूनियनों के पंजीकरण और मान्यता की परिस्थितियों के संबंध में, यूनियन के आंतरिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप के संबंध में, सत्यापन या मतपत्र के संबंध में, हड़ताल के अधिकार और विवादों को सुलझाने के तरीकों के बारे में होते हैं। सारे देश पर इस प्रकार के मजदूर-विरोधी औद्योगिक संबंध क्रान्ति थोपने के इस दौरान अनेक निष्फल प्रयास किये गये।

1978 में, जनता शासन के दौरान, इसने एक अभूतपूर्व शक्तिशाली और संयुक्त संघर्ष को जन्म दिया। 19 नवम्बर, 1978 को दिल्ली में एक बड़ा संयुक्त अधिवेशन हुआ जिसके अगले दिन संसद की ओर चार लाख लोगों ने मार्च किया। इस विरोध को देखते हुए, प्रस्ताव को नहीं रखा जा सका। जनता सरकार के पतन के साथ यह रह हो गया।

मगर 1980 में इन्दिरा गांधी की सत्ता में वापसी के साथ ही ये प्रयास फिर शुरू हो गये। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और आवश्यक सेवाएँ अनुरक्षण अधिनियम

पारित कर दिये गये। जीवन वीमा निगम के कर्मचारियों को सौदेबाज़ी के अधिकार से बचित करते हुए एक अध्यादेश (जो बाद में अधिनियम बना) जारी किया गया। भूतलिगम पैनल की सिफारिशों (जिन्हें जनता शासन में जारी किया गया) और वेतन-जाम के बारे में सार्वजनिक उद्यम व्यूरो के निर्देशों या केवल सीमांत वृद्धि को ही लागू किया गया। अनेक निर्देशित मूल्य वृद्धियाँ भी हुईं।

सभी तबकों के द्वारा, इन कानूनों के खिलाफ़ जबर्दस्त हड़ताली संघर्ष किये गये। 1980-81 के दौरान बँगलौर और हैदराबाद स्थित सार्वजनिक क्षेत्र इंजीनियरों कर्मचारियों द्वारा 77 दिनों तक चलायी गयी हड़ताल उनमें सर्वप्रमुख थी।

ट्रेड यूनियन अधिकारों पर सरकारी हमलों और इसकी मज़दूरी नियंत्रण व मूल्य वृद्धि की नीति के विरुद्ध इन संघर्षोंने ही 4 जून, 1981 के बम्बई अधिवेशन की पृष्ठभूमि निर्मित की जिसने इंटक को छोड़कर सभी ट्रेड यूनियनों समेत राष्ट्रीय अभियान समिति को जन्म दिया। हमारे ट्रेड यूनियन आंदोलन में उपलब्ध की गयी एकता की वर्तमान स्थिति के अनुरूप इस महत्वपूर्ण विकास को अगस्त 1983 में दिल्ली में हुए द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन में आगे बढ़ाया गया है। तब से राष्ट्रीय अभियान समिति को और आगे बढ़ाया गया है और यह प्रक्रिया अभी जारी है। आर्थिक स्थिति और इस संदर्भ में सरकारी नीति ही दो लाख से ज्यादा कपड़ा मज़दूरों की डेढ़ वर्ष तक चलने वाली ऐतिहासिक बम्बई हड़ताल, राष्ट्रीय अभियान समिति के आह्वान पर 19 जनवरी, 1982 को देशव्यापी आम हड़ताल और मज़दूरों की अनेक दूसरी शानदार और संयुक्त हड़ताली कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदार थी।

राजीव गांधी सरकार के सत्ता में आने से ये कार्रवाइयाँ और तीव्र हुई हैं और इसकी नयी आर्थिक नीतियों व देश में गंभीर राजनीतिक परिस्थिति के कारण इन्हें एक नया आयाम प्राप्त हुआ है। 25 फरवरी के 'भारत बन्द' इससे पूर्व 1986 में कुछ राज्यों में हुए बन्द, और 21 व 22 अक्टूबर को हुए सार्वजनिक क्षेत्र अधिवेशन जिसने 21 जनवरी, 1987 को सार्वजनिक क्षेत्र के मज़दूरों द्वारा सफल देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया, आगामी दिनों में ट्रेड यूनियन संघर्षों की गुणात्मक रूप से उच्चतर स्थिति का पूर्वसंकेत है।

जल्दी पढ़ें :

1. बोनस समिति को प्रस्तुत एटक का माँग पत्र
2. राष्ट्रीय श्रम आयोग को प्रस्तुत एटक का माँगपत्र
3. एटक के 31वें अधिवेशन में प्रस्तुत महासचिव की रिपोर्ट
4. एटक के 32वें अधिवेशन में प्रस्तुत महासचिव की रिपोर्ट

संक्षिप्त निष्कर्ष

हमारे देश में पहला आधुनिक कारखाना, भिल या उद्योग प्रारम्भ हुए एक शताब्दी और तीन दशकों से ज्यादा समय व्यतीत हो चुका है। पहली ट्रेड यूनियन की स्थापना को ८० वर्ष और एटक की स्थापना को ६७ वर्ष हो गये हैं। इन वर्षों में मज़दूर वर्ग और इसकी ट्रेड यूनियनें कितना फासला तय कर चुकी हैं?

एक शताब्दी पूर्व औद्योगिक क्षेत्र में कोई कानून नहीं चलता था। यह जंगल-कानून, असीमित काम के धंटे, बिना किसी रोकथाम के आदमियों, औरतों और बच्चों के शोषण का दौर था। ब्रिटिश पूँजीपति वर्ग सत्ता पर काबिज था और भारतीय पूँजीपति वर्ग का भी, एक वर्ग के रूप में उदय हो चुका था। मज़दूर निर्धनों, मरणासन्त भारतीय समाज के दूसरे वर्गों से आने वाले तबाह लोगों का समूह था जो मिलों, कर्मशालाओं, खानों और रेलमार्गों में भटकता फिरता था। उन्हें अभी तक एक वर्ग बनना था। जब कभी भी उन पर मुसीबत आयी, वे भय-मिथित स्वाभाविक युग्मता के साथ, मगर बिना किसी संगठन के लड़े। यह उनके पारंपरिक संबंध व साझी मुसीबतें ही थीं, जिन्होंने उन्हें जोड़े रखा। उन्होंने कारखानों में जमा हो गये किसानों की तरह व्यवहार किया।

राष्ट्रीय जागरण और राष्ट्रीय संघर्ष ने उन्हें बाणी दी। सामाजिक व राष्ट्रीय आंदोलन से आने वाले 'बाहरी व्यक्तियों' ने उनको एक स्थायी संगठन बनाने में मदद की, संघर्ष के लिए उन्हें एक लक्ष्य दिखाया और एकजुट होकर लड़ने के लिए एक समान परिचित शत्रु दिखाया। वे एक वर्ग के रूप में विकसित होने लगे।

कम्युनिस्टों और समाजवादियों के प्रवेश ने उन्हें वर्ग-चेतना और वर्ग-संघर्ष के दाँवपेच सीखने में मदद की, उनमें विजय के प्रति विश्वास भरा, उन्हें एक क्रांतिकारी ध्वजा और अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे का नारा 'दुनिया के मज़दूरों, एक हो' प्रदान किया।

हर कहीं मज़दूर अपना 'महाभारत' कार्यदिवस को सीमित किये जाने के

संघर्ष से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि 19वीं शताब्दी में असीमित कार्यदिवस बेरोक शोषण का पर्याय है। '8 घंटे का दिन' पहली पताका है जो एक शताब्दी पूर्व मज़दूरों द्वारा फहराई गयी थी। हमारे देश में भी इसी तरह शुरुआत हुई। फँक्टरी अधिनियम, 1881 पास कर दिया गया। वह एक शुरुआत थी। और जैसा कि 1952 में एस० ए० डांगे ने लिखा, "सौ वर्ष पहले मज़दूर के पास 6 घंटे भी उनके अपने नहीं हुआ करते थे। उसका सारा समय पूँजीपति वर्ग के लिए मुनाफ़ा पैदा करने हेतु मज़दूरी का समय था। अब 8 घंटे मज़दूरी का समय है और 16 घंटे उसके अपने हैं।"

इसके बाद संगठित होने के मौलिक अधिकार के मुद्दे पर संघर्ष आगे बढ़ता है। क्या उसे संघ बनाने के लिए अदालत में घसीट लिया जाना चाहिए और अपनी श्रमशक्ति मालिक को देने से इंकार करने के षड्यंत्र का आरोप मढ़ दिया जाना चाहिए, जिसे उसने मज़दूरी के बदले बेच देने का क्रारार किया है, जोकि एक ऐसा अपराध है जिसका आरोप मद्रास में वाडिया (एनी बेसेंट का एक अनुयायी) पर लगाया गया? यह मुद्दा इंग्लैंड में तथ किया गया और क़ानूनी तौर से, मज़दूरों को अपनी ट्रेड यूनियनें बनाने का अधिकार दे दिया गया। भारतीय मज़दूर ने यह जीत भी हासिल की और भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 पारित कर दिया गया।

प्रारंभ में, उसकी मज़दूरी मालिक की सनकों और इच्छाओं पर निर्भर करती थी। मालिक मज़दूर से उधार कर लेता था, क्योंकि वह वस्तु को अपना बनाकर पहले उसकी कीमत वसूल करता था, मगर मज़दूर को काफ़ी बाद में भुगतान करता था। जहाँ तक जुर्मानों व सजाओं का सवाल है, उनकी कोई सीमा नहीं थी, उसने इसके लिए संघर्ष किया और मज़दूरी भुगतान अधिनियम, 1936 पारित करवा लिया।

यह मज़दूर की श्रमशक्ति थी जिसका पूँजीपति क्रय-विक्रय करता था। जब किसी दुर्घटना, मातृत्व, बीमारी या मौत से यह श्रमशक्ति मिलनी बंद हो जाती थी, पूँजीपति पर कोई संविदात्मक जिम्मेदारी नहीं होती थी। मज़दूर लड़े और पूँजीपति को यह महसूस करना पड़ा कि श्रमकित के पुनरुत्पादन के लिए मज़दूर को स्वयं का पुनरुत्पादन करना होता है। परिणामस्वरूप, मज़दूर मुआवजा अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम लागू हुए।

आवश्यकता पर आधारित मज़दूरी, मूल्यवृद्धि के खिलाफ़ मुआवजा, व्यवसाय की सुरक्षा, बोनस, सामाजिक सुरक्षा, आदि के लिए संघर्ष चलते रहे। और हर बार, अपने लंबे संघर्ष में मज़दूरों ने नये कीर्तिमान कायम किये।

जीवंत इतिहास के अंग के रूप में, पिछले पाठों में हम इस सबका अध्ययन कर चुके हैं। कई दशकों के संघर्षपूर्ण इतिहास में मज़दूरों को जेल, लाठियाँ, पुलिस-³

फ्रायरिंग, बखास्तगी और उत्पीड़न के रूप में भारी क्रीमत अदा करनी पड़ी। हमारे पूर्ववर्तियों और उनके परिवारों की परेशानियों की कोई सीमा नहीं है। ब्रिटिश शासन के दिनों से और उस दिन से जिस दिन भारतीय पूँजीवादी वर्ग ने सत्ता की लगाम हाथ में थामी है, हमारे बहुत बड़ी संख्या में लोग शहीद हुए हैं। हमारे बीच से मज़दूर वर्ग के असंख्य सक्रिय कार्यकर्ता पैदा हुए हैं जो देश के दूर-दराज के इलाकों में लाल झंडा ले गये थीं और वहाँ उसे उन्होंने मज़बूती से गाड़ दिया, सफलताएँ भी मिली हैं और असफलताएँ भी। उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं :

- ८ घंटे का दिन, और अतिरिक्त घंटों के लिए ओवरटाइम
- साप्ताहिक छुट्टी और सवेतन अवकाश
- भोजन के लिए मध्यांतर
- सवेतन अवकाश और आकस्मिक अवकाश
- समय पर मज़दूरी का भुगतान और जुर्मानों पर सीमा
- न्यूनतम मज़दूरी (हम जहाँ भी इसे लागू कर सकते हैं) और मानकीकृत वेतन निधारण
- मूल्यवृद्धि के विरुद्ध मुआवजा
- तालाबंदी और छँटनी मुआवजा
- बोनस
- सीमांत लाभ (जहाँ हम बेहतर रूप से संगठित हैं)
- दुर्घटना, बीमारी या मौत के विरुद्ध बीमा
- मातृत्व लाभ
- बाल मज़दूरी पर प्रतिबंध तथा बाल मज़दूरों को संरक्षक
- सेवा-निवृत्ति और वृद्धावस्था के लिए भविष्यनिधि, ग्रेचुटी और पेंशन संबंधी लाभ
- विशिष्ट उद्योगों में कार्य-संबंधी परिस्थितियों को नियंत्रित करने हेतु विशेष अधिनियम

जैसाकि हमने संकेत किया है, सफलताएँ भी मिली हैं, असफलताएँ भी। वस्तुतः अधिकांश हड्डियाँ सफल होने के बजाय असफल हुईं। मार्क्स ने काफ़ी समय पूर्व संकेत किया था, “यदा-कदा मज़दूर विजय हासिल करते हैं, मगर कुछ समय के लिए ही। उनके संघर्ष का वास्तविक लाभ तात्कालिक परिणाम में नहीं, वरन् निरंतर विस्तृत होती मज़दूरों की एकता में निहित होता है।” (ज्ञोर हमारा) अतः, यद्यपि हम अपने पूर्वजों द्वारा विरासत में सौंपे गये लाभों का सुख भोग रहे हैं, प्रमुख पैतृक संपत्ति ‘निरंतर विस्तृत होती हुई मज़दूर-एकता है।’ यही चीज़ है जिसे हमें ग्रहण करना और आगे विकसित करना है।

इस संबंध में क्या स्थिति है? यहाँ हम एक तालिका दे रहे हैं जिसमें तीन

दशकों के दौरान युनियनों और उनके सदस्यों की संख्या में वृद्धि को दिखाया गया है :

वर्ष	पंजीकृत ट्रैड युनियनों की संख्या	वार्षिक विवरण देने वाली युनियनों की संख्या	वार्षिक विवरण देने वाली युनियनों की सदस्यता (हजारों में)	पुरुष	स्त्री	योग
1951-52	4,323	2,556	1,847	136		1,996
		(55.3)	(93.2)		(6.8)	
1961-62	11,614	7,087	3,607	370		3,977
		(61.0)	(90.7)		(9.3)	
1965	13,248	6,932	3,565	223		3,788
		(52.3)	(94.1)		(5.9)	
1970	20,879	8,537	4,699	421		5,120
		(40.9)	(91.8)		(8.2)	
1975	29,438	10,324	6,063	488		6,550
		(35.1)	(92.6)		(7.4)	
1979	32,361	8,727	5,771	433		6,203
		(28.5)	(93.0)		(7.0)	
1980	35,750	4,426	2,505	158		2,663
		(21.6)	(94.1)		(5.9)	

अनेक राज्यों से आंकड़ों के प्रभाव के कारण और कुछ दूसरे राज्यों से कामचलाऊ आंकड़े प्राप्त होने के कारण 1978 और 1980 के आंकड़ों को छोड़ दिया गया है। 1981 की जनगणना के अनुसार निम्न आंकड़े उपलब्ध हैं :

1. कुल श्रमशक्ति
 2. युनियनों की कुल सदस्यता
 3. कुल गैर-सेविहर श्रमशक्ति
 4. कुल श्रमशक्तियों के प्रतिशत के रूप में संघीकरण
 5. गैर-सेविहर श्रमशक्ति के प्रतिशत के रूप में संघीकरण
- | | |
|-----------------|--------------|
| 24 करोड़ 46 लाख | 77 लाख |
| 6 करोड़ 68 लाख | 3 प्रतिशत |
| | 11.5 प्रतिशत |

दोनों तालिकाओं के अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं—

- (i) तीन दशकों में, विशेषतया 1955 और 1975 के बीच यूनियनों की संख्या लगभग 8 गुनी बढ़ गयी है। उसके बाद, एक निश्चित सीमा तक पहुँचकर यह संख्या रुक गयी है।
- (ii) सदस्यता केवल 3.8 गुनी ही बढ़ी है। इसका तात्पर्य यह है कि अपेक्षतया कम सदस्यता वाली यूनियनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।
- (iii) संघीकृत मज़दूरों का प्रतिशत अभी भी बहुत कम है। अभी तक असंगठित मज़दूरों के विशाल समूह को संगठन में लाने के लिए ट्रेड यूनियनों, विशेषकर संगठित मज़दूरों को, महत प्रयास करने होंगे।
- (iv) स्त्री सदस्यों का प्रतिशत बहुत कम है और व्यापक उतार-चढ़ावों से युक्त है, जो उनकी सदस्यता की अस्थिरता को दर्शाता है।
- (v) आधे से अधिक पंजीकृत ट्रेड यूनियनें नियमित रूप से अपना वार्षिक विवरण प्रस्तुत नहीं करतीं, यह उनकी दोषपूर्ण और अनियमित कार्यप्रणाली का दोतक है। यह कुल सदस्यता, वित्तीय स्थिरता आदि के समग्र आवलन को मुश्किल भी बनाता है। रजिस्ट्रार के दफ्तर की योग्यता पर निर्भर करते हुए जो यूनियनें विवरण प्रस्तुत नहीं करतीं, मृत घोषित कर दी जाती हैं और सूची से उन्हें निकाल दिया जाता है। पिछले वर्षों में, इस संबंध में कोई सुधार नहीं हुआ है, बल्कि गिरावट ही आयी है।

“मज़दूरों की निरंतर विस्तृत होती एकता” के बारे में मार्क्स के कथन का इस तरह अक्षरणः पालन नहीं हो पा रहा है।

बहरहाल हाल ही में, जो व्यापक एकता प्राप्त की गयी है, उसने मज़दूरों, राष्ट्रीय आर्थिक व राजनीतिक मुद्दों, यहाँ तक कि मूल्यवृद्धि, आर्थिक नीतियाँ, संसदीय लोकतंत्र और जनतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा, विभाजक व अलगाववादी ताकतों के विरुद्ध, साम्राज्यवादी षड्यंत्रों के विरुद्ध शांति की सुरक्षा आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सामूहिक कार्रवाइयाँ चलाने के लिए मज़दूरों में आत्मविश्वास उत्पन्न किया है। एटक और अन्य वामपंथी यूनियनें प्रवर्तक और प्रमुख संगठनकर्ता रही हैं, मगर इन कार्रवाइयों में राष्ट्रीय अभियान समिति को संपूर्ण रूप में शामिल किया गया है, और हाल ही में, बहुत-सी संयुक्त कार्रवाइयों में इंटक को भी खोंच लिया गया है। सामाजिक शक्ति के रूप में ट्रेड यूनियनों की प्रवर्तनकारी व नेतृत्वकारी भूमिका स्पष्ट हो रही है। यदि ट्रेड यूनियन आंदोलन संगठित हों और ज्यादा ताकतवर व अधिक व्यापक आधारवाला संगठन हो, तो यह और अधिक हो जाए।¹

अब हम इतिहास से कुछ सबक सीख सकते हैं :

पहला, सभी उपलब्धियाँ संघर्षों और बलिदानों के फलस्वरूप प्राप्त हुई हैं।

इन संघर्षों और वलिदानों के कारण ही मजदूर वर्ग वह बन सका है, जो वह आज है।

दूसरा, 1947 तक विदेशी शासकों ने, और उसके बाद भारतीय पूँजीपति-वर्ग और राज्य ने हर क्रदम पर मजदूर वर्ग और बेहतर स्थितियों के लिए इसके संघर्ष का द्वेषपूर्ण विरोध किया है।

तीसरा, मजदूरों के लिए लाभप्रद अधिनियम, अधिसूचनाएँ, पुरस्कार आदि भी तभी कार्यान्वित होते हैं जब मजदूर और उनके संगठन चौकस और सक्रिय हों और उन्हें लागू करवाने के लिए वे संघर्ष करें।

चौथा, एक यूनियन के भीतर या कई यूनियनों की संयुक्त कार्रवाइयों के द्वारा जब कभी अधिकतम संभावित एकता उपलब्ध होती है, मजदूरों के संघर्ष प्रभावपूर्ण होने लगते हैं। फूट संघर्षों में बाधा पहुँचाती है और उन्हें प्रभावशून्य बना देती है अगर उन परिस्थितियों में उन्हें छेड़ा जाए।

पाँचवाँ, जब कभी तात्कालिक या आंशिक मांगों को नीतिगत प्रश्नों पर संघर्षों से जोड़ा गया है या दूसरे शब्दों में ये संघर्ष शासक वर्ग के खिलाफ राजनीतिक संघर्षों में तबदील हुए हैं, उन्होंने व्यापक सफलताएँ हासिल की हैं और वास्तविक लाभ प्राप्त हुए हैं। यह विश्वास कि एक संघर्ष को 'विशुद्ध मजदूर हितों' के लिए विशुद्ध आर्थिक संघर्ष के रूप में सीमित रखना और इसे राजनीति से अलग व अप्रभावित रखना बेहतर परिणामों को सुनिश्चित करता है, एक जबर्दस्त भूल साबित हुई है।

छठा, जहाँ कहीं मजदूर एक वर्ग के रूप में आगे बढ़े हैं और उन्हें कम्युनिस्टों जैसे वर्ग चेतस राजनीतिक हिरावल दस्ते का नेतृत्व मिला है, संघर्ष अधिक संगठित, उद्देश्यपूर्ण और बेहतर ढंग से संचालित हुए हैं। जहाँ कहीं सुधारवादी व्यक्तियों, राजनीतिक दुस्साहसवादियों और सभी किसीं के रुद्धिवादियों के हाथ में नेतृत्व रहा है, संघर्ष परिणामशून्य रहे हैं अथवा आशा के अनुकूल हो जाने में असफल रहे हैं, चाहे आरम्भ में वे कितने ही व्यापक आधार बाले और जु़जारु क्यों न रहे हों।

सातवाँ, ट्रेड यूनियन संघर्ष, जिन्हें लोगों की व्यापक सहानुभूति हासिल हुई है और जो किसानों और कामगार समूहों के दूसरे तबकों से एकता और समर्थन जुटा पाने में सफल रहे हैं, साधारणतया सफल रहे हैं।

आठवाँ, मजदूरों के ठीक प्रकार से संचालित और संयुक्त संघर्षों ने अंतर्राष्ट्रीय दिलचस्पी और सहानुभूति पैदा की है। उस वक्त जबकि भारतीय मजदूरों ने शांति, रंगभेद-विरोध, मुक्ति संघर्षों को समर्थन जैसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर आवाज उठायी है, अंतर्राष्ट्रीय भाई-चारे के संबंध मजबूत हुए हैं।

नवाँ, राजनीतिक और सामूहिक विषयों पर हमारे देश के मजदूर वर्ग की

कार्रवाइयों ने उन्हें लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक प्रगति के लिए संघर्ष के हिरावल दस्ते के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है।

टिप्पणी :

1. ट्रेड यूनियन एकता के और अधिकतम संभावित एकता तथा संयुक्त कार्रवाइयों के लिए संघर्ष का इस पुस्तक के तीसरे भाग में वर्णन किया गया है।

जारूर पढ़ें :

1. मजदूर वर्ग की सौ वर्षों की उपलब्धि : एस०ए० डांगे

भारतीय मजदूर और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन आंदोलन

1764 के आसपास चरखे के आविष्कार से, जिसके बाद एक के बाद एक अनेक दूसरे आविष्कार हुए, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। उत्पादन के साधनों में क्रांतिकारी परिवर्तन हो चुका था और वे एक ऐसी स्थिति में पहुँच चुके थे जहाँ फैक्टरी उत्पादन बड़े पैमाने पर होना प्रारंभ हुआ। प्राचीन सामंती व्यवस्था और उत्पादन संबंधों को तोड़ दिया गया और दो वर्गों—पूँजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग—को जन्म देते हुए नये पूँजीवादी उत्पादन संबंधों ने उनकी जगह ली।

औद्योगिक क्रांति का जन्मस्थल, इंगलैंड, दुनिया की कार्यशाला बन गया। पूँजीवादी शोषण के साथ ही मजदूरों—इंगलैंड के गर्म दल के सदस्यों—का प्रतिरोध, तथा मजदूरों के दंगे और विद्रोह शुरू हो गये। गिल्ड और दस्तकार संगठन, पारस्परिक सहायता संगठन और संघ मजदूरों के सम्मिश्रण का आरंभिक बिन्दु बन गये। संघ-विरोधी अधिनियम के जरिये पूँजीपति वर्ग ने जवाबी हमला किया। हड़तालों की लहर के बाद 1824 में इसे रद्द करना पड़ा।

लंदन का मगार संघ द्वारा आरम्भ किये गये चार्टिस्ट आंदोलन ने साविक वयस्क मताधिकार, गुप्त मतपत्र आदि जैसी राजनीतिक माँगों को उठाकर ट्रेड यूनियन आंदोलन को पूर्ण किया।

यूरोप महाद्वीप में औद्योगीकरण पिछड़ गया और इस तरह वहाँ ट्रेड यूनियन-वाद देरी से पैदा हुआ। 1848 में अनेक देशों में हुई क्रांतियों ने इस विकास को आगे बढ़ाया। इसी समय, माक्स और एंगेल्स ने कम्युनिस्ट घोषणापत्र जारी किया, जिसका समापन इस एकजुटता वाले आह्वान के साथ हुआ “दुनिया के मजदूरों, एक हो।”

प्रारंभ से ही, मजदूर वर्ग आंदोलन के जनक ने पूँजीवादी शोषण के विरुद्ध अपने संघर्ष में आंदोलन के अंतर्राष्ट्रीय चरित्र पर बल दिया था। 1864 में,

विशेषकर मार्क्स की पहलकदमी पर, अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर संघ (प्रथम इंटरनेशनल) स्थापित किया गया। राष्ट्रीय पैमाने पर एकजुट होने की दिशा में ट्रेड यूनियनों की शुरुआत हो रही थी। उदाहरण के लिए, 1868 में ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। न केवल इस बारे में लिखना, बल्कि मज़दूरों के अंतर्राष्ट्रीय संघ के निर्माण की दिशा में पहले व्यावहारिक क़दम उठाना मार्क्स और एंगेल्स की दूरदर्शिता पर निर्भर था। प्रारम्भिक गठन काल में, जबकि अनेक देशों में ट्रेड यूनियनें अभी पैदा भी नहीं हुई थीं, अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर संघ विशुद्धतः एक ट्रेड यूनियन संगठन नहीं था, न हो सकता था। मगर पहले ही 1869 में अपनी चौथी कांग्रेस में निम्न-लिखित शब्दों में इसने प्रस्ताव रखा।

“यह मानते हुए कि श्रम और पूँजी का अंतर्राष्ट्रीय चरित्र ट्रेड यूनियनों के एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की माँग करता है, कांग्रेस साधारण समिति को ट्रेड यूनियनों के एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण करने का दायित्व सौंपत्ति है।”

प्रथम इंटरनेशनल लंबे समय तक इस निर्देश का पालन नहीं कर सकी। बहर-हाल, इसने “कानूनी सीमा के रूप में आठ घंटे का कार्यदिवस”, व्यापक फ़ैक्टरी क्रानून, उच्चतर मज़दूरी, स्त्री और बाल-श्रमिकों की सुरक्षा जैसे नारों को विस्तृत रूप से प्रतिपादित किया, जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन आंदोलन का प्रारम्भिक बिन्दु बने। 1871 में पहले मज़दूर राज्य, ‘पेरिस कम्यून’ ने उनमें से अनेक नारों को कार्यान्वित किया। मगर 3 माह के भीतर ही पूँजीवादी वर्ग द्वारा इसे रक्त में ढुबो दिया गया।

मई 1886 में, संयुक्त राज्य अमेरिका के बड़े औद्योगिक केंद्रों में, (वह देश, जहाँ यूरोप के बहुत से पारंपरिक पूँजीवादी देशों को पीछे छोड़ता हुआ सर्वाधिक तीव्रगति से पूँजीवादी विकास प्रारंभ हो चुका था। 8 घंटे के कार्यदिवस के लिए सामूहिक मज़दूर कार्रवाइयाँ हुईं। संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका में 1 मई, 1886 को एक हड्डताल हुई, और शिकागो में मिशिगन एवेन्यू में एक प्रभावशाली जुलूस निकाला गया।

4 मई को, जब पहले दिन की पुलिस निर्देशाओं के खिलाफ़ है मार्केट स्क्वायर में मज़दूर एक सभा कर रहे थे, एक भड़काने वाली कार्रवाई की गयी, शांतिपूर्ण भीड़ पर पुलिस द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी की गयी। 6 लोग मौके पर ही मारे गये (4 पहले दिन मरे थे) और 200 घायल हो गये। दुर्घटना के बाद सैकड़ों लोगों को गिरफ़तार कर लिया गया और उनमें से 8 पर मुक़दमा चलाया गया। आठों के विरुद्ध एक भी सबूत नहीं था और जब घटना घटी, उस समय केवल एक ही व्यक्ति स्थल पर मौजूद था। इसके बावजूद, उन सबको कठोर सज़ाएँ हुईं। पांच को फ़ाँसी होनी थी, मगर उनमें से एक जेल के भीतर ही मर गया और इस तरह फ़ाँसी से बच गया। काले शुक्रवार (11 नवम्बर, 1887) के दिन अन्य चारों—अल्बर्ट

पार्सन्स, ऑंगस्टस स्पाइज़, जॉर्ज एंगिल और एडोल्फ़ किशर को फाँसी दे दी गयी। उन्होंने बहादुरी से फाँसी के तख्ते का वरण किया और उनके शब्द, जो ज़ल्लाद द्वारा उनके गलों में फंदा कस दिये जाने के बाद कहे गये थे, दंतकथा बन चुके हैं। स्पाइज़ चिल्लाया, “समय आएगा जब हमारी चुप्पी उन आवाजों से ज्यादा शक्ति-शाली होगी जिन्हें तुम आज घोट रहे हो—” सबसे आखिर में पार्सन्स बोला, “ओ अमेरिका के लोगों ! मुझे बोलने दो… लोगों की आवाज़ सुनी जाए…!” इसी समय फंदा लगा दिया गया और आवाज़ बंद हो गयी।

अपने नायकों को अंतिम सम्मान देने के लिए पाँच लाख से ज्यादा लोगों ने जुलूस निकाला।

सौ वर्ष पूर्व शिकागो में घटी घटनाओं ने विश्व मज़दूर आंदोलन की मई दिवस परंपरा को जन्म दिया। 18 जुलाई, 1889 को दूसरे इंटरनेशनल की पेरिस कांग्रेस ने 1 मई को मज़दूर-एकजुट्टा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करने के पक्ष में मत दिया। 1 मई, 1890 सभी यूरोपीय देशों और अमेरिका में अच्छी तरह मनाया गया। फ्रेडरिक एंगेल्स ने इसके बारे में लिखा : “आज… यूरोपीय और अमेरिकी सर्वहारा पहली बार एक ही ध्वजा के नीचे, एक तात्कालिक उद्देश्य के लिए, एक सेना के रूप में लामबंद अपनी संघर्षशील शक्तियों की समीक्षा कर रहा है… और आज का यह चमत्कार सारे देशों के पूँजीपतियों और भूस्वामियों की आँखें इस वास्तविकता की ओर खोल देगा कि आज सभी देशों के मज़दूर वास्तव में एकजुट हैं।

“काश, मार्क्स आज मेरे बगल में यह सब अपनी आँखों से देखने के लिए होते।” (जोर हमारा)

मई दिवस का जन्म मज़दूर आंदोलन के अंदर दो युगों के बीच की सीमारेखा का प्रतिनिधित्व करता था। सभी देशों के मज़दूरों की एकता का दिन मज़दूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष से पैदा हुआ था। उनके खून और शहादत ने इसे गरिमा प्रदान की।

ट्रेड यूनियन आंदोलन दुनिया के बहुत से देशों में फैल गया। अनेक प्रयासों और अधिवेशनों के बाद, 1913 में ट्रेड यूनियनों के अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई, मगर आंदोलन के क्षैतिज विस्तार के साथ ही ‘विशुद्ध और सामान्य’ ट्रेड यूनियनवाद (ब्रिटेन), ‘अराजक श्रमिक संघवाद’, ‘अवसरवाद’ और ‘संशोधनवाद’ जैसी अनेक दक्षिणपंथी और वामपंथी पूँजीवादी और निम्न पूँजीवादी चिचार-धाराओं की घुसपैठ शुरू हो गयी, जो मज़दूर वर्ग आंदोलन में मार्क्सवादी प्रवृत्ति का विरोध करने के लिए तैयार थीं।

ट्रेड यूनियनों के अंतर्राष्ट्रीय संघ का दिवालियापन प्रथम विश्वयुद्ध, महान आर्थिक संकट (1929-32) और तदनंतर फ़ासीवाद के उदय के दौरान उजागर

हुआ। द्वितीय विश्वयुद्ध ने इसे प्रभावशाली तरीके से दफना दिया।

उपरोक्त वर्णित सभी माक्सवाद विरोधी प्रवृत्तियों के विरुद्ध लेनिन को संघर्ष करना पड़ा। अक्तूबर कांति की विजय के बाद कांतिकारी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन संगठन के गठन के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल थीं। लाल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने, जैसाकि इसे पुकारा जाता था, अनेक देशों में कांतिकारी ट्रेड यूनियनवाद के विचारों को फैलाने और इसके केंद्रबिंदु का निर्माण करने में अपनी भूमिका निभायी, लेकिन यूरोप में फासीवाद के उभार और फासीवाद को रोकने व युद्ध बंद करने हेतु एक संयुक्त मोर्चे का निर्माण करने के फौरी कार्यभार ने एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिसमें लाल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ अपना पृथक अस्तित्व नहीं रख सका। 1937 में, इसे खत्म कर दिया गया।

फासीवाद-विरोधी युद्ध के दबावों ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन एकता का सवाल उठाया क्योंकि उस बक्त कोई एक अकेला अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन संगठन अस्तित्व में नहीं था।

अक्तूबर 1941 में स्थापित ब्रिटिश सोवियत ट्रेड यूनियन समिति की पहल-कदमी पर एक विश्व ट्रेड यूनियन अधिवेशन फरवरी 1945 में हिटलर के फासी-वाद की पराजय के तीन माह पूर्व लंदन में हुआ जिसमें 40 से ज्यादा देशों के ट्रेड यूनियन संगठन सम्मिलित हुए। उस अधिवेशन में एक नये विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ की स्थापना का निश्चय किया गया।

25 सितम्बर से 9 अक्तूबर, 1945 के बीच पेरिस में ट्रेड यूनियनों के विश्व संघ की स्थापना कांग्रेस में हुई। यह अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन एकता की प्रक्रिया और फासीवाद के खिलाफ विश्वव्यापी संघर्ष के दौरान उत्पन्न संयुक्त कार्रवाई का चरम बिंदु था। युद्ध खत्म हुआ ही था। आखिरी बार कर दिया गया था। बहुत से देश बर्बाद हो गये थे। इसके बावजूद एक साथ श्रम और शांति की एक नयी दृष्टिया बनाने की इच्छा से 56 देशों के 6 करोड़ 70 लाख मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाले 346 प्रतिनिधि इस कांग्रेस में सम्मिलित हुए। सिर्फ दक्षिण-पंथियों के प्रभुत्व वाले अमेरिकी मजदूर संघ ने भाग लेने से इंकार कर दिया। 3 अक्तूबर, 1945 को इसके संविधान के पारित होने के साथ ही विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ के जन्म की औपचारिक घोषणा कर दी गयी। तब से, 3 अक्तूबर विश्व ट्रेड यूनियन संघ के रूप में मनाया जाता है।

जैसाकि प्रस्तावना में कहा गया है,

“विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ का उद्देश्य सभी देशों के लोगों के जीवन और कार्य की परिस्थितियों को बेहतर बनाना और सभी स्वतंत्रता प्रेमी जनगण द्वारा वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें एकजुट करना है...”

“ये लक्ष्य और उद्देश्य केवल ऐसी विश्व-व्यवस्था की स्थापना द्वारा ही पूरी

तरह से प्राप्त किये जा सकते हैं जिसमें दुनिया के सभी संसाधनों का उपयोग उन सभी लोगों के लाभों के लिए किया जाएगा, जिसका बड़ा बहुमत हाथ और दिमाग से काम करने वाले मज़दूरों का है, जिसकी सुरक्षा और प्रगति सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठित ताक़तों की एकता पर निर्भर करती है।¹

विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ की स्थापना उन सभी शक्तियों के लिए एक महान और ऐतिहासिक उपलब्धि है जिन्होंने ट्रेड यूनियन एकता के लिए संघर्ष किया है। मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में इजारेदार पूँजीवादी क्षेत्रों ने, जिन्होंने युद्धोत्तर विश्व में चीजों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने की अपनी नीति का पालन करना चाहा है, अपनी योजनाओं के मार्ग में विश्व ट्रेड यूनियन को एक बाधा के रूप में ही देखा है, अतएव मज़दूर वर्ग की इस अंतर्राष्ट्रीय एकता को तोड़ने के लिए अमेरिका मज़दूर संघ के प्रतिक्रियावादी और दक्षिणपंथी नेताओं पर भरोसा किया है। उन्होंने के साथ घिसटते हुए ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस नेतृत्व और पश्चिमी यूरोप के उनके सहयोगियों ने 1949 के उत्तरार्ध में अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र ट्रेड यूनियन महासंघ नामक एक नये अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की।

बहरहाल, यह द्रष्टव्य है कि फ़ासीवाद पर विजय, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का उभार, विचारों और समाजवाद के प्रभावों में शक्तिशाली वृद्धि ने एशिया और लातीनी अमेरिका में ट्रेड यूनियनों के विकास में जबर्दस्त प्रोत्साहन दिया। तेज़ी से राष्ट्रीय व क्षेत्रीय केंद्र अस्तित्व में आने लगे। मज़दूरों के जीवंत हितों और ट्रेड यूनियन अधिकारों की दृढ़तापूर्वक हिमायत कर विश्व ट्रेड यूनियन संघ की विश्व-भर में मज़दूरों के बीच लगातार प्रतिष्ठा बढ़ी है। विश्व ट्रेड यूनियन संघ की औद्योगिक शाखाओं के रूप में ट्रेड यूनियन इंटरनेशनलों की स्थापना के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकता की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया। उनमें विश्व ट्रेड यूनियन संघ से संबद्ध संगठनों और उन देशों के असंबद्ध संगठनों को शामिल किया गया है, जिनमें विघटनकारी कार्रवाइयों ने इस तरह के संगठनों को विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ से पृथक रखा है। विभिन्न देशों में उद्योगों की सजातीय शाखाओं में मज़दूर वर्ग के हितों को थामे रखने, बेहतर स्थितियों के लिए संघर्ष को मदद करने, संघर्षकामी मज़दूरों को सहायता देने और उनके साथ एकता प्रदर्शित करने के लिए मज़दूरों की एकजुट करने का काम ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल करता है।

अपने अस्तित्व के 40 वर्षों से ज्यादा समय के दौरान, जिसकी परिणति बर्लिन में सितम्बर 1986 में 11वीं कांग्रेस में हुई, विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ की ताक़त सभी महाद्वीपों और समाज व्यवस्थाओं के 138 देशों के 21 करोड़² लाख से ज्यादा मज़दूरों को एकजुट करके बढ़ी है। एकता के लिए इसके निरंतर और दृढ़ प्रयासों ने उन यूनियनों में नये रूज़ान पैदा किये हैं जो आज अंतर्राष्ट्रीय

स्वतंत्र ट्रेड यूनियन महासंघ और वर्कर्स कम्युनिस्ट लीग से संबद्ध हैं। इसने रंगभेद नीति के विरुद्ध संघर्ष में, विश्व शांति की सुरक्षा के लिए, एक परमाणु-मुक्त विश्व के लिए, पूर्ण निःशस्त्रीकरण के लिए और एक नवी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था आदि के लिए पराराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों के संबंध में विभिन्न विश्व केंद्रों से संबद्ध ट्रेड यूनियनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकजुट और संयुक्त प्रयासों की नवीन संभावनाओं को खोला है।

मज़दूरों के एक वर्गीय संगठन के रूप में विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ एक शांतिपूर्ण श्रम की दुनिया के लिए संपूर्ण मज़दूर वर्ग की साझी युद्धविरोधी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। इसने आज तक शांति और सामाजिक प्रगति की शक्तियों को एकजुट करने, प्रत्येक साम्राज्यवादी युद्ध हशकंडे का ठोस रूप से सामना करने, हथियारों की दौड़ का विरोध करने और विकास के लिए संसाधनों को मुक्त करने, भूख और गरीबी हटाने आदि की नीति का अनुसरण किया है। विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ की पहलकदमी पर 1 सितम्बर शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसने एकता में जन्म लेकर सदा एक-रूपता और उन विषयों की सामान्यता को सामने लाते हुए जो सभी देशों के मज़दूरों को उद्देलित करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर वर्ग और ट्रेड यूनियन एकता को अपरिमित रूप से मज़बूत बनाने का कार्य किया है। परमाणु युग की वास्तविकताएँ अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र ट्रेड यूनियन महासंघ को भी युद्ध और शांति के विषयों पर साम्राज्यवादी नीतियों के लिए अपने आरंभिक बिला शर्त समर्थन पर पुनर्विचार करने और परमाणु निःशस्त्रीकरण के प्रश्न पर, साथ ही रंगभेद-नीति विरोधी संघर्ष तथा इसी प्रकार के अन्य मुद्दों पर एक सकारात्मक रूप अपनाने के लिए विवश कर रही हैं। इस प्रकार साझी अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के लिए आधार व्यापक हो रहा है, यद्यपि आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन महासंघ विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ के साथ किसी भी तरह की संयुक्त कार्रवाई करने का विरोध करता है।

1920 में अपने जन्म के बाद से एट्क ने जिन विचारों को थामे रखा है, उनमें अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर वर्ग भाईचारे का विचार भी सम्मिलित है। लाला लाजपतराय ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था : “आज हम जिस आंदोलन का श्रीगणेश कर रहे हैं, उसका राष्ट्रीय से भी अधिक महत्त्व है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की चीज़ है। भारत के मज़दूर केवल भारतीय श्रमिकों के हितों को मज़बूत बनाने के उद्देश्य से ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे की ज़ंजीर में एक कड़ी और जोड़ने के लिए हाथों और दिमागों को जोड़ रहे हैं।”

बहरहाल, अंतर्राष्ट्रीय संबद्धता का सवाल एक उलझी हुई समस्या बना रहा। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन संघ ने, जिस पर ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सुधारवादी नेतृत्व का वर्चस्व था, औपनिवेशिक देशों की माँगों का समर्थन नहीं किया। अतः

अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन संघ से संबद्ध होने का कोई प्रश्न ही नहीं था। दूसरी ओर, एटक के भीतर दक्षिण-संशोधनवादी और पूँजीवादी तबका था, जो इसे लाल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ से संबद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसा करने के प्रयास ने वास्तव में 1931 में एटक में विघटन को प्रेरित किया। इस प्रकार एटक अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन संघ और लाल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ, दोनों से ही असंबद्ध रहा।

विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ की स्थापना के दिन से ही एटक इससे संबद्ध रहा है। विश्व ट्रेड यूनियन संघ के कार्य में एटक प्रमुख भूमिका निभाता है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र की ट्रेड यूनियनों को एकजुट करने और उनके केंद्र स्थापित करने में इसने प्रमुख भूमिका निभायी है।

भारत में दूसरे बड़े ट्रेड यूनियन केंद्रों द्वारा भी अब अंतर्राष्ट्रीय संबद्धता को अंगीकृत कर लिया गया है। मगर जैसेकि विघटन को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया जा रहा हो, इंटक और हिंद मजदूर सभा ने स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र ट्रेड यूनियन महासंघ से संबद्ध होने को चुना। आधुनिक विश्व में राष्ट्रीय अलगाव की बात सोचना संभव नहीं है, सिवा भारतीय मजदूर संघ और अन्य दूसरे संगठनों के, जिनकी दृष्टि सीमित है, जिनकी विचारधारा संकुचित राष्ट्रीय उप्रवाद पर आधारित है, लेकिन जो ठीक इसी कारणवश साम्राज्यवाद और इसके समर्थकों द्वारा प्रेरित बहुत-सी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियावादी स्थितियों के साथ सामान्य अभिन्नता पाते हैं। इन प्रवृत्तियों के विरुद्ध, अन्य और सवालों के साथ ही इस सवाल पर अतिवामपंथी प्रवृत्तियों के खिलाफ़ एक विचारधारात्मक संघर्ष आवश्यक है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मजदूर वर्ग से संबंधित एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी 1919 में अंतर्राष्ट्रीय लीग द्वारा स्थापना की गयी। 1917 में रूस में अक्टूबर क्रांति के बाद विश्व में क्रांतिकारी भावनाओं के विकास का यह एक प्रकार से सुधारवादी प्रत्युत्तर था। सरकारों, श्रमिकों (बतौर नियम के, बड़े ट्रेडयूनियन केंद्रों से सरकार द्वारा मनोनीत ट्रेड यूनियनवादियों) और नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों समेत यह एक त्रिपक्षीय संरचना है। अपनी संरचना में ही इसका झुकाव नियोक्ताओं और सरकारों की तरफ है जो अपने 'मजदूर सहयोगियों' को भी चुन लेती है। फिर भी, वास्तविकताओं का दबाव अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन पर पड़ा है। श्रम संबंधों के विभिन्न पक्षों और अबाधित शोषण पर रोकथाम के संबंध में इसकी धारणाएँ पर्याप्त सरकारों पर बाध्यकारी नहीं हैं जब तक वे उनके द्वारा अभिषुष्ट न हों, फिर भी वे मजदूरों के लिए लाभदायक सिद्ध हुई हैं। मजदूरों के हाथों में वे उपयोगी हथियार हैं। इसका श्रेय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को है।

1954 में अन्य समाजवादी देशों समेत सोवियत संघ इसमें शामिल हो

गया। हाल के वर्षों में, बहुत से नवसंवंत्र देश भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में सम्मिलित हो गये हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के भीतर बहुत से परिवर्तन आए हैं, यद्यपि इसकी आधारभूत संरचना, जिसकी स्थापना 'सामाजिक हिस्सेदारी' और निजी स्वामित्व की मुरक्खा के बिचार के अनुसार हुई थी, 1919 के बाद से अपरिवर्तित रही है। समाजवादी देशों की ट्रेड यूनियनों और अन्य प्रणालियों देशों के ट्रेड यूनियन कंट्रों के अनुष्ठप विषय ट्रेड यूनियन महासंघ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मध्य का उपयोग मजदूरों के हितों को धारणे, शांति की मुरक्खा, युद्ध सामग्री का शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए रूपांतरण करने, ट्रेड यूनियन अधिकारों की सुरक्षा, बेरोजगारी के खिलाफ और काम के अधिकार आदि के लिए करता है। दूसरी ओर, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र ट्रेड यूनियन महासंघ अनेक मुद्दों पर नियोक्ताओं और पंजीयादी सरकारों के साथ स्वयं को अधिनन पाता हुआ वर्ग-संघोंग पर आधारित एक सूधारवादी रूप अपनाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इस प्रकार वर्ग-संघर्ष का अखाड़ा बन गया है जिसका परिणाम अनेक अवसरों पर विश्व में शक्तियों के सहसंबंध पर निर्भर करता है।

भारतीय मजदूरों का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में प्रतिनिधित्व स्वभावतः एक तकलीफदेह मुद्दा है, क्योंकि सरकार इटक के पक्ष में भेदभाव बरतती है।

टिप्पणी:

1. विषय ट्रेड यूनियन महासंघ की प्रस्तावना और संविधान देखिये।

जल्दी:

1. प्रकाशित
2. ट्रेड यूनियन रिकॉर्ड : 20 सितम्बर, 1984
3. ट्रेड यूनियन रिकॉर्ड : मई दिवस शताब्दी का मुद्दा
4. एटक के पचास वर्ष
5. हेमार्केट विरसत : अनातोली रेपिन : विश्व ट्रेड यूनियन संघ प्रकाशन
6. भारत में मई दिवस समारोहों का इतिहास : दिलीप बोस

ट्रेड यूनियन का चरित्र

जैसाकि हम भारत और अन्य देशों में आंदोलन के इतिहास से देखते हैं, यह एक मज़दूर का दैनिक अनुभव ही है जो उसे अपने सहयोगी मज़दूरों के साथ जुड़ने और एक यूनियन बनाने के लिए प्रेरित करता है। ट्रेड यूनियन के माध्यम से ही मज़दूर पूँजीपति के शोषण के खिलाफ़ अपना दैनंदिन संघर्ष चलाता है। और ठीक उसी प्रकार जैसे एक नवजात बच्चे को पालने में देखभाल की जाती है, इसके बाद ही वह दुनिया में पहले डगमगाते क़दम रखता है, उसी तरह 'सामूहिक श्रमिक' ट्रेड यूनियन के पालने में पालन-पोषण के बाद ही मज़दूर-वर्ग आंदोलन के रूप में क़दम उठाता है।

"ट्रेड यूनियन मज़दूर आंदोलन का पालना है, क्योंकि मज़दूर स्वभावतः उसी की तरफ़ पहले मुड़ते हैं जो उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करता है और परिणामतः वे अपने व्यावसायिक सहयोगियों के साथ जुड़ जाते हैं।"¹

पूँजीवाद के अंतर्गत, ट्रेड यूनियनें ही सामान्य वर्ग-संगठनों के रूप में मज़दूरों के व्यापक समूहों को एकजुट करती हैं और शोषक पूँजीपति वर्ग और इसके राज्य-तंत्र के खिलाफ़ उन्हें लामबंद करती हैं। इस संघर्ष में वे प्रमुख हथियार होती हैं।²

अतः, मज़दूरों के संघर्ष की मूलभूत प्रकृति की यह माँग है कि प्रभावशाली बनने के लिए ट्रेड यूनियनें कार्यस्थलों, फैक्टरी या उद्योगों में मज़दूरों के समूचे समूह को अपने अन्दर शामिल करें। इसके दरवाजे किसी भी व्यक्ति की जाति, लिंग, भाषा या धर्म—जिसे जो भी मानता हो—का भेदभाव किये बिना सभी मज़दूरों के लिए खुले होने चाहिए। प्रत्येक मज़दूर से संपर्क किया जाना चाहिए और यूनियन में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, वह मज़दूर जो अपने कार्यस्थल पर किसी ट्रेड यूनियन में सम्मिलित नहीं होता, ऐसा मज़दूर अपना प्रारंभिक वर्ग-कर्तव्य पूरा नहीं करता।

सामान्य श्रमिक अपनी यूनियन के नेतृत्व में लड़े गये संघर्ष की आग से गुज़र

कर स्वभावतः इसे अपना मानने लगता है। उसके और मालिक के बीच ट्रेड यूनियन कवच की तरह रहती है। सभी आक्रामक और सुरक्षात्मक लड़ाइयों में यह ही उसकी तलवार है। ट्रेड यूनियन ही उसके जीवन और काम की परिस्थितियों को बेहतर बनाने और जो कुछ भी उसने अब तक हासिल किया है, उसकी सुरक्षा करने में मदद करती है। कोई आश्चर्य नहीं कि एक बार अगर मज़दूर यूनियन में आ जाए और वह यूनियन उसे संघर्षों से गुज़रने दे, भले ही वे सही हों या गलत हों, वह उस यूनियन के प्रति गहरा लगाव महसूस करने लगता है। उसे वहाँ से उखाड़ने के प्रयत्न आसान नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर मज़दूर को बहकाया भी गया है, तब उस व्यक्ति को जो उसे सही रास्ते पर लाना चाहता है, अपनी विश्व-सनीयता कायम करने और मज़दूर को खुद उसके जीवनानुभवों से समझाने के लिए एक लंबी अवधि तक धैर्यपूर्वक और दृढ़ता के साथ कार्य करना होगा।

यहाँ तक कि पूँजीवादी राज्य या व्यक्तिगत मालिक द्वारा एकजुट होने और अपनी पसन्द की यूनियन में सम्मिलित होने के मज़दूरों के अधिकार का उल्लंघन या प्रतिबंध मज़दूरों द्वारा अपने मूलभूत अधिकार पर हमले, मज़दूर आंदोलन को कमज़ोर करने के इरादे से किये गये सामान्य हमले के रूप में लिया जाता है।

जहाँ कहीं मज़दूरों का एक हिस्सा स्वयं ही एक साझी यूनियन में मज़दूरों के समूचे समूहों को एकजुट करने पर रोक लगा देता है, तो वह भी जानबूझकर या अन्यथा आंदोलन को रोकने और कमज़ोर का प्रयास बन जाता है। इसका पहला उदाहरण शिल्प या श्रेणीबद्ध यूनियनों की स्थापना है।

अपने आरंभिक काल में ब्रिटिश ट्रेड यूनियनें संकीर्ण शिल्प संगठन ही थीं जिनके मज़दूरी में वृद्धि, कार्यदिवस में कमी और विशिष्ट शिल्प के लिए बेहतर परिस्थितियाँ जैसे तात्कालिक और आंशिक रूप से व्यवहार्य उद्देश्य ही थे। मार्क्स और एंगेल्स ने उनका संकुचित दृष्टिकोण देखा, यद्यपि इसे वे मज़दूर-आंदोलन के विकास के रास्ते में आगे बढ़ा हुआ एक कदम मानते थे। शिल्प-यूनियनों की उपयोगिता समाप्त होती गयी और धीरे-धीरे वे उस देश की विशाल औद्योगिक यूनियनों में बदलती चली गयीं।

भारत और दूसरे अन्य देशों में, श्रेणीबद्ध यूनियनों और संघों की समस्या बनी हुई है। किसी व्यक्ति की अपनी श्रेणी के हितों के बारे में संकुचित दृष्टिकोण से सामान्यतः ये पैदा हो जाती हैं। मगर कभी-कभी संस्थान की केवल कुछ ही श्रेणियों के प्रतिनिधियों के वर्चस्व वाली सामान्य यूनियन की, जिसमें दूसरी श्रेणियों की विशिष्ट समस्याओं की उपेक्षा होती है, असंतोषजनक और अलोकतात्त्विक कार्य-प्रणाली के कारण भी श्रेणीबद्ध यूनियनें बन जाती हैं। जब ऐसा होता है तो यह एक चेतावनी है कि सामान्य यूनियन की कार्य-प्रणाली अच्छी और स्वस्थ नहीं है और इसनिए इसे ठीक करने के उपाय किये जाने चाहिए।

हर हालत में श्रेणीबद्ध यूनियने दृष्टिकोण की संकीर्णता को बढ़ावा देती हैं और एक ही कार्यस्थल पर मज़दूरों को शेष भाइयों से श्रेणीगत रूप में अलग कर देती हैं। सभी मज़दूरों के सामान्य हितों की ओर ध्यान दिये बगैर 'मेरी अपनी श्रेणी' के हित इस गलत विश्वास से पैदा होते हैं कि इन्हें उनके लिए संघर्ष किये बिना प्राप्त किया जा सकता है। वह स्थिति अपरिहार्य रूप से उस श्रेणी को अन्य श्रेणियों के प्रति उदासीनता या उसके बिना परस्पर विरोधी की स्थिति तक ले जाती है। यह, इस तरह, मज़दूरों की कतारों के भीतर 'प्रतियोगिता' के तत्त्व का प्रवेश करती है, जिसे निकालना यूनियन का पहला लक्ष्य होना चाहिए था। यह वर्ग-चेतना के विकास को अवरुद्ध करती है।

अतः हम श्रेणीगत यूनियनों को हतोत्साहित करते हैं और औद्योगिक यूनियन-वाद का पक्ष लेते हैं। हमारा लक्ष्य है, "एक उद्योग या संस्थान में एक यूनियन," इससे भी आगे एक वृहत्तर भौगोलिक क्षेत्र में जैसेकि राज्य या सारे देश में 'एक औद्योगिक संघ'

मगर चूँकि श्रेणीगत यूनियनें वर्तमान सुधारवादी नेतृत्व और अलोकतांत्रिक कार्यप्रणाली वाली यूनियन की असफलताओं से पैदा हो सकती हैं, हम सदैव श्रेणी का विचार किये बिना मज़दूरों को अपने पीछे एक ही यूनियन की ओर आकर्षित करने का लक्ष्य सामने रखते हुए, इन यूनियनों में काम कर सकते हैं।

जाति पर आधारित यूनियनें बनाना, चाहे खुलेआम या दबे-ढके, एक खतरनाक और विघटनकारी प्रवृत्ति है। हमारे समाज में जातिगत विभाजन के संदर्भ में और जातिवाद व अपने स्वार्थपूर्ण हितों को पूरा करने हेतु निहित स्वार्थी द्वारा इसके उपयोग के मज़दूर आंदोलन के लिए गंभीर निहितार्थ हैं।

यह चेष्टा प्रायः दूसरे तबक्कों के विरुद्ध वास्तविक या काल्पनिक शिकायतों को उभार कर तथा उन पर जोर देकर, तथा जातिगत अनन्यता को प्रचारित करके 'निम्न जातियों' द्वारा की जाती है। पिछड़ी हुई जातिगत चेतना तिये मज़दूर कभी-कभी दूसरे अल्पसंख्यकों के साथ इस तरह की यूनियनों या 'सांस्कृतिक संघों' में खींच लिये जाते हैं।

यह रेखांकित करना ज़रूरी है कि प्रभुत्वशील जातियों (यह मानकर चलते हुए कि संबंधित ट्रेड यूनियन में इस तरह की कोई अभिव्यक्ति है) से निम्न या पिछड़ी जातियों की जातिगत विचारधारा का सहारा लेकर संघर्ष नहीं किया जा सकता। दोनों, बहुमत और अल्पमत हिस्सों को उच्च और निम्न जातियों को यह विश्वास दिलाना होगा कि दोनों के हित आपसी विश्वास, सहयोग, अधिक लोकतंत्र और एकता की माँग करते हैं। साथ-साथ, दूसरे हिस्सों को निम्न जातियों की वास्तविक शिकायतों का समाधान भी करना होगा।

एक शताब्दी से भी पहले, कार्ल मार्क्स ने मज़दूरों को विभाजित रखने वाले

किसी भी पारम्परिक कारण के खिलाफ एक सिद्धांतनिष्ठ संघर्ष चलाने की ज़रूरत को रेखांकित किया था। मार्क्स ने लिखा, “संयुक्त राज्य अमेरिका में मज़दूरों का प्रत्येक स्वतंत्र आंदोलन बेजान बना रहा जब तक कि गुलामी गणतंत्र के एक भाग को विरुद्धित किए रही।” अतः उन्होंने मज़दूरों से गुलामी के विरुद्ध संघर्ष करने का आग्रह किया, क्योंकि “गोरे मज़दूर तब तक स्वतंत्र अपना उद्घार नहीं कर सकते जब तक कि काली चमड़ी के मज़दूरों पर लेकुल चस्पाँ हैं।” भारत में यह और भी अधिक प्रासंगिक है जहाँ सदियों पुराने जातिवादी ट्रेडमार्क मज़दूरों को विभाजित रखे हुए हैं।

बहरहाल, भारतीय परिस्थितियों में जाति-संघर्ष को वर्ग-संघर्ष का रूप देना, जैसाकि कुछ अवसरवादी करने की कोशिश कर रहे हैं, पूर्णतः गलत और विघटन-कारी है। वर्ग-चेतना और वर्ग-संघर्ष शोषकों के विरुद्ध शोषित समूहों के सभी हिस्सों को एकजुट बनाते हैं। जातिगत चेतना और जातिगत संघर्ष शोषकों से लड़ने के नाम पर जातियों के अनुसार शोषित समूहों को विभाजित करते हैं। वे मुख्य शब्द के खिलाफ संघर्ष को दूसरी दिशा में ले जाते हैं।

जाति और समुदाय पर आधारित यूनियनों, अथवा यूनियनों के भीतर जाति या समुदाय पर आधारित मतभेदों का चौकस होकर मुकाबला करना होगा और दमित तबकों के खिलाफ भेदभावों और अत्याचारों से सक्रियतापूर्ण और प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष चलाना होगा।

कुछ व्यक्तियों के आसपास एकत्र ट्रेड यूनियनों के उद्भव, विशेषकर वृहद औद्योगिक संकुलों में, ट्रेड यूनियन आंदोलन में पाये जाने वाली ‘व्यक्तिपूजा’ की प्रक्रिया पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देना होगा।

यह अकेले हमारे देश के लिए ही एकदम नयी या विशेष चीज़ नहीं है। इस घटनाक्रिया के पीछे कुछ विशिष्ट कारण हैं :

- शहरी और ग्रामीण, धनी और मध्यम वर्गों से आने वाले नौजवान पहली पीढ़ी के मज़दूरों को उत्पन्न करने वाले उद्योगों का विस्तार;
- निम्न पूँजीपति वर्ग और मज़दूरों पर प्रभाव डालते निम्न पूँजीवादी प्रभाव में व्यापक वृद्धि;
- तकनीकी शिक्षा प्राप्त और कमाने की आकँक्षाएँ विकसित करते मज़दूरों के व्यापक हिस्से;
- तीव्र होता हुआ इजारेदारी शोषण;
- पूँजीपतिवर्ग द्वारा व्यक्तित्वों, यहाँ तक कि ‘जुझारू’ व्यक्तियों को खड़ा करने के जानबूझकर किये गये प्रयास, जिन्हें चलाना अपेक्षाकृत आसान होता है और अपरिमित रूप से शक्तिशाली प्रचार माध्यमों द्वारा फैलायी

गयी अप्सूचनाएँ जो सदैव इस प्रकार के 'नायकों' को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करती हैं; एवं

- सबसे ऊपर, वामपंथी क्रतारों में विभाजन, जो उत्पादन-विरोधी ट्रैड यूनियन शबूता को प्रेरित करता है।

ये सभी कारक जनोत्तेजकों और स्वार्थजीवियों तथा व्यक्तिगत ट्रैड यूनियन 'मालिनी', जो एक या दूसरे भौत में स्थापित ट्रैड यूनियन केन्द्रों की उन्नता में ज्यादा शक्तिशाली समझे जाते हैं, के विकास के लिए उपजाऊ भूमि निर्मात करते हैं।

प्रत्येक इथिति में, समरया का मूर्त रूप में अध्ययन करना होगा, कारकों को विश्लेषित करना होगा और उनका मुकाबला करने के लिए क्रदम जठाने होंगे। ऐसे व्यक्तियों के नेतृत्व वाली यूनियन के प्रति एक पूरी तरह से नकारात्मक रुख से बचना होगा, विशेषकर तब जबकि आग मष्टुरों का उनमें विचार बना हुआ हो। नष्टुरक आलोचना से बचना होगा विशेषकर तब जबकि संघर्ष चल रहे हों। मष्टुरों की 'मतस्थिति' का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना होगा। साथ ही, मष्टुरों को उनके स्वयं के अनुभवों द्वारा शिक्षित करना होगा। कि ऐसे व्यक्तित्व, 'नायक', 'ट्रैड यूनियन मालिक' और जनोत्तेजक कुछ भी नहीं दे सकते। यहाँ तक कि अगर तात्कालिक लाभ हासिल भी हो जाते हैं, ऐसे 'नेता' सर्वहरा संघर्षों के बर्गीय दृष्टिकोण से पूरी तरह रहित होते हैं।

यहाँ इस चीज पर बल दिया जाना चाहिए कि ट्रैड यूनियन, सबसे ऊपर, मष्टुरों का एक साझा वर्ग संगठन, एक लक्ष्य से परिचालित और प्रेरित व्यापक समूह एवं एक अंतिम लक्ष्य है, न कि सिर्फ़ किसी नेता का 'व्यक्तिगत अनुसरण।'

दिव्यणियाँ :

1. अंतर्राष्ट्रीय मष्टुर मध्य की साधारण समिति द्वारा 1876 में शिकायों के मष्टुरों को संबोधित पत्र;
2. समाजवाद के अंतर्गत, यह भूमिका भिन्न है, क्योंकि वहाँ संघर्ष के लिए न दृग्गीणतावर्ग है, न ही इसका राज्यतंत्र। मगर समाजवादी समाज में ट्रैड यूनियनों की भूमिका कुछ अधिक ही बढ़ जाती है। इस भूमिका को निभाने में असमर्थता गंभीर परिणामों को जन्म देसकती है, जैसाकि कुछ देशों में देखा गया था।

ज्ञानर पढ़ें :

1. यह ट्रेड यूनियनवाद नहीं है : बी० एस० धुमे
2. भारत में मार्क्सवाद तथा मजदूर वर्ग की भूमिका : एस० जी० सरदेसाई
3. जाति, वर्ग एवं आरक्षण : ए० बी० वर्धन
(आरक्षण पर बहस नामक पैन्फलेट का अध्याय)

क्रांतिकारी ट्रेड यूनियनवाद बनाम सुधारवादी ट्रेड यूनियनवाद

जैसाकि हमने देखा, ट्रेड यूनियनें एक-दूसरे से जुड़ने, इस तरह के सम्मिश्रण द्वारा अपनी संख्या की ताक़त को जोरदार ढंग से व्यक्त करने, शोषण के खिलाफ़ लड़ने अपनी जीवन और कार्यगत स्थितियों को बेहतर बनाने और सिर्फ़ बंधक मजदूर और बेतनभोगी गुलाम के स्तर से स्वयं को ऊपर उठाने के मजदूरों के स्वतःस्फूर्त प्रयासों से उत्पन्न हुई।

अतः ट्रेड यूनियनों का तात्कालिक कार्य-भार और लक्ष्य किसी भी कार्यस्थल या संस्थान में मजदूरों की फौरी माँगों को उठाना और उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्हें लाभवन्द करना है। इसके बिना, मजदूरों के समूचे समूह को ट्रेड यूनियन में सम्मिलित होने के लिए संभवतः प्रेरित नहीं किया जा सकता। इसे ट्रेड यूनियन गतिविधियों का आरम्भिक बिन्दु बनाना होगा।

इन माँगों के लिए संघर्षों के दौरान ही मजदूर इस्पाती बनते हैं, उनकी वर्ग-चेतना जाग्रत होती है और उनका वर्ग-संगठन मजबूत होता है। अतः दिन-प्रति-दिन के मुद्दों पर लड़े जाने वाले संघर्षों को कम करके आँकिना, जब कभी भी अवसर आए, उन्हें हथ में लेने में कोताही करना—और ऐसे अवसर पूँजीवादी समाज में अक्सर आते ही रहते हैं—पूरी तरह गलत होगा। इस प्रकार के अवमाननापूर्ण या फिर आलस्यपूर्ण रूख से सामान्य मजदूर अपनी यूनियनों में रुचि खोने लगते हैं।

मगर जिन सुधारों के लिए हम लड़ रहे हैं, वे स्वयं में साध्य नहीं हैं। जब तक पूँजीवाद अस्तित्व में है, शोषण जारी रहता है, भले ही अपने ट्रेड यूनियन संघर्षों के दौरान मजदूर कैसी भी बेहतर स्थितियों को प्राप्त करने में क्यों न सफल हो जाएँ। तब रोज़मर्रा के संघर्षों को चलाते हुए ट्रेड यूनियन आंदोलन की कार्रवाई

और लक्ष्य की क्या गुजाइश है जिधर इसे बढ़ना है? इस संदर्भ में मार्क्स ने कहा :

“साथ ही, और मजदूरी प्रणाली में निहित सामान्य दासता से एकदम अलग, मजदूर वर्ग को इन दिन-प्रतिदिन के संघर्षों की मूलभूत कार्यप्रणाली को बढ़ा-चढ़ा कर नहीं प्रस्तुत करना चाहिए। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि वे परिणामों से संघर्ष कर रहे हैं, न कि उन परिणामों के कारणों से, वे अधीगमी गति को कम भर कर रहे हैं, इसकी दिशा में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, वे प्रशासकों का प्रयोग कर रहे हैं, बीमारी का इलाज नहीं कर रहे। अतः उन्हें पूँजी के अनवरत अतिक्रमों अथवा बाजारों में परिवर्तनों से निरन्तर उत्पन्न होते इन अपरिहार्य संघर्षों में ही मुबिला नहीं रहना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि इसके द्वारा उनके ऊपर तमाम परेशानियां थोप दिये जाने के साथ-साथ मौजूदा व्यवस्था समाज की आर्थिक पुनर्रचना के लिए जरूरी भौतिक परिस्थितियों और सामाजिक रूपों को उत्पन्न भी करती है। पुरातन पंथी आदर्श-वाक्य, ‘उचित दिन के कार्य के बदले उचित दिन की मजदूरी’ के स्थान पर उन्हें अपनी छवजा पर यह क्रांतिकारी आदर्श-वाक्य लिखवा देना चाहिए, ‘मजदूरी प्रणाली की समाप्ति।’ (जोर मूल रचना में)¹

क्योंकि मार्क्स ने आंदोलन के अन्तिम लक्ष्य की ओर ध्यान आकर्षित किया था, यही कारण है कि वह संयोजनों व संघर्षों की दिशा में मजदूरों द्वारा लिये जाने वाले प्रथम व आरम्भिक कदमों के प्रति इतना सावधान थे।

यह नोट किया जाना चाहिए कि मजदूरों की जीवन व श्रमगत परिस्थितियों में सुधार, राजनीतिक व सामाजिक जीवन में सुधार महत्वपूर्ण व आवश्यक हैं। उनकी जीवन स्थितियों में सुधार स्वागत योग्य परिवर्तन है। क्रांतिकारी उद्देश्य का समर्थन करने हेतु, जनता के बड़े समूहों को खींचने की सम्भावनाओं को व्यापक बनाते हुए वे सर्वहारा के संघर्ष की परिस्थितियों में भी सुधार को प्रेरित करते हैं। लेकिन सुधारों को ही सब कुछ समझने और अन्तिम लक्ष्य अर्थात् समाजवाद के लिए संघर्ष को भूल जाने का अर्थ ट्रेड यूनियन आंदोलन को असंगत बनाना और सारी व्यवस्था को बदले बिना आज एक और कल दूसरी रियायत पाने के साधारण कार्य की हड तक नाकारा बना देना है। यह एक गोल घेरे में चक्कर लगाने के समान है। ट्रेड यूनियन आंदोलन में यह सुधारवाद है। इस प्रकार की सुधारवादी ट्रेड यूनियनें ‘समाजवाद की पाठशालाएँ’ नहीं बन सकती। क्रांतिकारी ट्रेड यूनियनवाद का आशय है तात्कालिक और आंशिक माँगों के संघर्ष को व्यवस्था परिवर्तन के संघर्ष से, अन्तिम लक्ष्य के लिए संघर्ष से जोड़ना। इसका अर्थ है आर्थिक संघर्षों को राजनीतिक माँगों और वैकल्पिक नीतियों के संघर्ष से जोड़ना।

एक को दूसरे से न जोड़ने का अर्थ मजदूर वर्ग के उत्थान के लिए संघर्ष में तोड़-फोड़ करना है। कोई चाहे या न चाहे, दोनों तरफ से ही, यह पूँजीपतिवर्ग के हाथों में खेलना है।

कई स्थितियों में ट्रेड यूनियन कार्य 'अर्थवाद' की सामान्य और पुरानी बीमारी से ग्रस्त रहता है जो सुधारवादी ट्रेड यूनियनवाद की सामान्य अभिव्यक्ति है। अर्थवाद का मतलब है ट्रेड यूनियन क्षेत्र में आंशिक और तात्कालिक माँगों के लिए स्वतःस्फूर्त संघर्ष तक स्वयं को सीमित कर लेना और यह भूल जाना कि मजदूर वर्ग का अन्तिम लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना और मजदूरी-दासता को समाप्त करना है। उदाहरण के लिए अपने ट्रेड यूनियन संघर्ष को मात्र ट्रेड यूनियन अधिकारों की रक्षा, अथवा मँहगाई भत्तों की उचित दर अथवा बेहतर मजदूरी और इसी प्रकार की अन्य चीजों तक सीमित रखना काफ़ी नहीं है। इसे सरकार की नीतियों के खिलाफ़ निर्देशित किया जाना चाहिए जो बदहाल जनता के लिए मुश्किलें पैदा करती हैं, विकास को बाधित करती हैं तथा मजदूर वर्ग के समक्ष भिन्न-भिन्न हितों, वर्ग शक्तियों और दलों को रखती हैं जो ये नीतियाँ बनाते हैं अगर ट्रेड यूनियनें इन नीतियों के खिलाफ़ व्यापक और सामूहिक संघर्ष संगठित कर सकें, तो जनता के व्यापक हिस्सों को एकजुट करना और कुछ मुद्दों पर सरकार को पीछे हटने के लिए विवश करना संभव हो जाता है। संघर्ष एक राजनीतिक चरित्र ग्रहण कर लेता है, मजदूर वर्ग की वर्गचेतना को गहराई देता है और सामाजिक प्रगति के हरावल दस्ते के रूप में अपनी भूमिका निभाने में इसे सहायता प्रदान करता है। दिन-प्रतिदिन के ट्रेड यूनियन कार्य के प्रति अत्यधिक लगाव और राजनीतिक कार्य के प्रति उदासीनता, एक ही प्रकार के भटकाव हैं, जिसे ठीक करना होगा।

कुछ ट्रेड यूनियनवादियों का राजनीति विषयक विचार केवल ऐसे राजनीतिक प्रश्नों तक ही सीमित है जो किसी विशिष्ट ट्रेड यूनियन या आर्थिक संघर्ष के दौरान सामने आते हैं। वे यह 'राजनीतिक संघर्ष' लड़ने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि परिस्थितियाँ उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करती हैं, मगर मजदूर वर्ग-सत्ता के लिए राजनीतिक संघर्ष करने के लिए नहीं। यहाँ तक कि वे सर्वाधिक जु़ज़ारू हड़ताली कार्रवाइयाँ करने के लिए तैयार रहते हैं और करते भी हैं मगर वह किसी वर्गीय परिप्रेक्ष्य से रहत होती है। 'मजदूर-राजनीति' की यह एक ट्रेड यूनियनवादी व्याध्या है जिसका अर्थ सर्वहारा के हितों को पूँजीवादी राज्य के हितों के अनुसार अनुकूलित करने से न कम है, न ज्यादा है। यह 'अर्थवाद' 'श्रमिक संघर्षवाद' का एक विशिष्ट रूप है। 'अर्थवाद' स्वतःस्फूर्तता उत्पन्न करता है और चेतना की भूमिका उपेक्षा करता है जो ज्ञान की पूर्णता पर आधारित है और इसीलिए बाहर से मजदूरों की कतारों में पैदा की जाती है। ट्रेड यूनियनवाद में इस प्रकार का सुधारवादी दृष्टिकोण क्रमिकवाद, समाजवाद की दिशा में

कदम-ब-कदम प्रगति, तथाकर्षित 'समाजवादी ढाँचे का समाज', 'लोक-पूँजीवाद' और 'रामराज्य' का इसका भारतीय संस्करण आदि, जिसका मजदूरों के बीच पाये जाने वाले पूँजीपतिवर्ग के प्रवक्ताओं द्वारा श्रमपूर्वक प्रचार-प्रसार किया जाता है, के बिचारों को बनाये रखने में मदद करता है।

मुधारबादी ट्रेड यूनियनवाद का एक बड़ा रूप मुकदमों, निर्णयादेशों और कानूनों कार्रवाइयों में अत्यधिक व्यस्तता का होता है। इसने 'ट्रेड यूनियनवादियों की एक लास किस्म को पैदा किया है जो ट्रेड यूनियन नेता और सक्रिय कार्यकर्ता की अपेक्षा बकील और अभिवक्ता अधिक है। कुछ स्थितियों में इसने परजीवियों की एक किस्म को भी पैदा किया है जो मजदूरों की असहायता और कमज़ोरी पर पलते हैं।

कुछ मौकों और विषेष स्थितियों में कानून, कच्छीरियों और टिब्बूनलों का सहारा लेना निःसंदेह ज़ाहरी है। आंदोलन के दौरान इस तरह का अवसर अनुकूल और सामयिक सहारा मददगार साबित होता है। अनेक मौकों पर कच्छीरियों ने बड़े महत्वपूर्ण और उपरोगी निर्णय दिये हैं (उदाहरण उड़त किये जा सकते हैं)। मगर जहाँ ट्रेड यूनियन मुकदमे सामूहिक कार्रवाइयों जन आंदोलन और संघर्ष का स्थानापन्न बन जाते हैं, और जहाँ कानूनी कार्यवाही मुख्य कार्य बन जाती है, वहाँ बर्ग-चेतना कुंद हो जाती है और पूँजीवादी कानूनी प्रश्नाओं में विश्वास पैदा होने लगता है जो अधिकतर हताशा में लड़ता होता है।

कुछ ट्रेड यूनियनवादी यूनियनों को परेशानियाँ हल करने के लिए किसी संस्थान में सत्ताधारियों तक पहुँच के साथन के रूप में देखते हैं जो एक ऐसी चीज़ है जिसे प्रत्येक मजदूर द्वारा व्यक्तिगत रूप से नहीं किया जा सकता। यहाँ पूँजी-पति और सरकार 'दानदाताओं' की भूमिका निभाते हैं जबकि अपनी ट्रेड यूनियनों में संघबद्ध मजदूर 'प्राप्तकर्ता' माने जाते हैं। इस तरह के ट्रेड यूनियन-बाद में मंत्रियों का सामीप्य और शासक दल के साथ निकट का संबंध भी एक बड़े सकारात्मक तत्व के रूप में निश्चित किया जाता है। सारे रूप में यह इंटक और दूसरे स्वतन्त्र मुधारबादियों का दृष्टिकोण है। अपने समस्त यन्वन्वांडबर्यूण साजो-सामान और दायांतिकता के बाबजूद इस्टीशिप के सिद्धांत में ठीक इसी किस्म का दृष्टिकोण पाया जाता है।

मजदूर वर्ग को बह-हाल अपनी आशा मालिक और सरकार की दानशीलता या मानवीयता पर नहीं, बल्कि अपनी स्वयं की कातिकारी ऊर्जा और जन-आंदोलन पर केन्द्रित करती है। जैसाकि मानस ने कहा है : "ताकातवर की कमज़ोरी से सामाजिक मुधार नैदा नहीं किये जा सकते : उन्हें कमज़ोर की ताकत द्वारा उत्पन्न किया जाना चाहिए और करना होगा।"

वर्तमान में हमारे देश में ट्रेड यूनियन आंदोलन के भीतर सर्वाधिक कपटपूर्ण

प्रवृत्ति 'स्वतन्त्र' और विशुद्ध ट्रेड यूनियन तटस्थला', 'ट्रेड यूनियन तटस्थला', सभी राजनीतिक दलों और जिसे धृणापूर्वक 'झड़ों की लड़ाई' कहा जाता है, से अलग रहते की है।

इस प्रवृत्ति के प्रचुर विकास के लिए राजनीतिक लाइनों पर ट्रेड यूनियनों का विबंदन नियमित रूप से वर्तुलित आधार का काम करता है—प्रत्यक्ष दल अपना अलग ट्रेड यूनियन पक्ष स्थापित करता है, इस तरह मजदूरों को विभाजित करता है और उनके संघर्ष को कमज़ोर बनाता है। तथाकथित 'विशुद्ध ट्रेड यूनियनवादी' मजदूरों के बीच इस विभाजन से लाभ उठा रहे हैं। वे मजदूरों को 'राजनीति' और 'राजनीतिज्ञ' से अलग रहने की सलाह देते हैं। उन्हें किस ओर मुड़ना चाहिए? कहा जाता है कि उन्हें इस तरह के संबंधों से 'मुक्त' व्यवितर्यों की ओर, यानिक अर्थों ने 'स्वच्छत्व' व्यवितर्यों की ओर मुड़ना चाहिए। इस प्रकार मजदूरों को उनके वर्तमान ट्रेड यूनियन संगठनों और उनके राजनीतिक दलों के विरुद्ध बढ़ा कर दिया जाता है। अतिवासप्रथियों के समान वे इन दलों को प्रतिष्ठान और इसी तरह की चीज के रूप में पेश करते हैं।

यह स्पष्ट है कि ये स्वतंत्र और मुक्त ट्रेड यूनियनवादी मजदूरों को वर्ग-चेतना और वर्ग-संघर्ष से दूर छोंचते और एक प्रतिशोध के साथ 'अर्थवाद' की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जुझाल जन-कारंचाहायों का अभाव और सही वक्त पर मजदूरों की मनोविज्ञा समझ पाने में असफलता उड़वे आवश्यक अवसर प्रदान करती है। उपरोक्त प्रकार का ट्रेड यूनियन जनोत्तेजन आम मजदूरों के पिछड़ेपन और संकीर्ण स्वार्थों को रास आता है। मजदूरों को जनोत्तेजकों की नहीं, कुछ ताकतवर प्रचारकों और आंदोलनकर्ताओं की जहरत है। उन्हें प्रभावशाली 'जन-जेताओं' की जहरत है।

'ट्रेड यूनियन तटस्थला' निम्न रूपों में अधिक्यक्त होती है: (1) सभी तरह की 'राजनीति' से परहेज करना और यूनियन के काम को आर्थिक मांगों के लिए संघर्ष करते तक सीमित रखना, (2) मजदूरों को सभी राजनीतिक दलों से दूर रखना—वस्तुतः विशेषकर वामपंथी दलों के प्रति उनमें गहरी शक्तुता का भाव भरना और (3) दबाव पड़ने पर, 'मजदूर-राजनीति' की एक किस्म के व्यावहारिक कार्यक्रम की अस्पष्ट चर्चा करना।

सार रूप में ट्रेड यूनियन तटस्थला एक पूँजीवादी विचार है और यह पूँजीपति-वर्ग की चक्की के लिए सामग्री प्रस्तुत करता है क्योंकि यह मजदूरों को संबंधारा वर्ग-संघर्ष से अलग-अलग कर देता है।

ट्रेड यूनियन किसी विशेष दल से उस रूप में 'स्वतंत्र' है और होनी चाहिए कि वे न तो किसी दल की मातहत हों, न ही निवेशित हों। लेकिन वे सभी तरह की 'राजनीति' से न तो 'स्वतंत्र', न ही 'मुक्त' हो सकती हैं। क्योंकि वामपंथी

दलों द्वारा भी उन पर प्रभाव डाला जाता है जो उन्हें उनकी नियति की दिशा में मार्ग दिखलाता है। हम चाहते हैं कि ट्रेड यूनियनें जनवादी रूप से अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हों। हम नहीं चाहते कि वे समाजवाद से स्वतंत्र हों, पूँजी-वादी शोषण को खत्म करने के लिए लड़े जाने वाले राजनीतिक संघर्ष से स्वतंत्र हों।

अतः क्रांतिकारी ट्रेड यूनियनवादियों को ट्रेड यूनियन आंदोलन में पाए जाने वाली इस तरह की सभी अराजक-श्रमिक संघवादी और सुधारवादी प्रवृत्तियों का मुकाबला करना होगा।

उपरोक्त वर्णित तरीकों के अलावा सुधारवाद और भी अन्य रूप ग्रहण करता है। उदाहरणार्थ, भारतीय मजदूर संघ की विचारधारा विशिष्ट भारतीय परिस्थिति के मुताबिक पूँजीवाद के लिए पूर्णरूपेण समर्थन और धार्मिक-साम्रादायिक परम्परावाद का मिश्रण है।

दूसरी ओर, संकीर्णतावाद, बचकाना उग्रवाद, अल्पसंख्यक समूह द्वारा निष्क्रिय जनता के लिए की जाने वाली जुझारू कार्रवाई की प्रवृत्ति भी बलवती हो रही है।

मूर्त अध्ययन और रहस्योद्घाटन के आधार पर इन सभी प्रवृत्तियों के विश्वदृष्ट एक दृढ़ और सैद्धान्तिक संघर्ष चलाना होगा। अन्तिम विश्लेषण में उनका लक्ष्य क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन आंदोलन है। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि सभी तरह के सुधारवादियों और संकीर्णतावादियों को—यहाँ तक कि उनमें से सर्वाधिक जुझारू दिखायी पड़ने वालों को—पूँजीपतिवर्ग से सभी तरह का प्रोत्साहन, कभी खुला कभी दबा-ढका, मिलता रहता है।

व्यापक ट्रेड यूनियन एकता के लिए संघर्ष के साथ यह संघर्ष किस प्रकार समन्वित किया जा सकता है?

एक प्रवृत्ति के रूप में सुधारवाद से राजनीतिक और विचारधारात्मक संघर्ष चलाया जाना चाहिए। मगर ऐसा करते हुए आम मजदूरों को प्रभावित करने वाले सामान्य मुद्दों पर सुधारवादियों के नेतृत्व वाली यूनियनों के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाईयां चलायी जानी चाहिए। केवल यही चीज ही उनके पीछे खड़े मजदूरों को अनुभव द्वारा सुधारवाद की त्रुटियों और सीमाओं को समझने, क्रांतिकारी ट्रेड यूनियनवाद के महत्व को पहचानने और उन्हें इसका समर्थन करने में मदद करती है। साझी संयुक्त यूनियन में जो भी कार्रवाई चलायी जाए, सही समझदारी तक पहुँचने के लिए मजदूरों को समय और धैर्य चाहिए। संकीर्णतावादी गलतियों, आकामक और हठधर्मितापूर्ण तरीकों से बचा जाना चाहिए, और किसी भी कीमत पर सामान्य मजदूरों को 'नेताओं' के साथ गड्ढमढ्ढ नहीं किया जाना चाहिए। आम जनता के प्रति भ्रातुर्पूर्ण रुख, यहाँ तक कि संयुक्त

कार्बवाइयों को आगे बढ़ाने के लिए 'नेताओं' के प्रति भी मित्रतापूर्ण सख्त और सबसे ऊपर धैर्य—इस संघर्ष में ये आवश्यक तत्व हैं। संयुक्त कार्बवाइयाँ एक चरण से अगले चरण तक सही व्यूहरचना, हमेशा मजदूरों की समझदारी का स्तर बढ़ाने और क्रांतिकारी ट्रेड यूनियनवाद को लाभ पहुँचाने में मदद करती हैं।

हमारे देश में विकसित होती हुई परिस्थिति और तीव्र होता हुआ वर्ग-संघर्ष नीतिगत और 'राजनीतिक' मुद्दों को प्रस्तुत कर रहे हैं और तात्कालिक माँगों के लिए संघर्ष को मजदूर वर्ग आंदोलन के राजनीतिक लक्ष्य हेतु संघर्ष से जोड़ने के लिए आधार प्रदान कर रहे हैं।

टिप्पणी :

1. मार्क्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की साधारण सलाहकार समिति को दिया गया संबोधन जो 'मूल्य, कीमत और लाभ' नामक पुस्तिका में प्रकाशित है।

जल्द रपड़े :

1. मूल्य, कीमत और लाभ : कार्ल मार्क्स
2. क्या करें : वी० आई० लेनिन
3. साधारण सभा के सत्रों तथा बैठकों में प्रस्तुत एटक महासचिव की रिपोर्टें।

मज़दूरी का प्रश्न

ट्रेड यूनियन कार्य का मुख्य मुद्दा मज़दूरी का प्रश्न है। अधिक मज़दूरी, कार्य के कम घंटे, व्यावसायिक सुरक्षा के लिए, मज़दूरी के कम होते जाने और श्रम के तीव्री-करण के खिलाफ संघर्ष ट्रेड यूनियन क्रियाकलाप का एक बड़ा भाग है। औद्योगिक विवादों, कामबद्दी और उद्योग में बर्बाद हुए श्रमिकों का एक बड़ा भाग इन संघर्षों के कारण ही है।

पंजीवादी व्यवस्था में, पूँजीपति और मज़दूर विकेता और केता के रूप में श्रम बाजार में एक-दूसरे का सामना करते हैं। मज़दूर के पास विक्रय के लिए उसकी श्रम करने की योग्यता, उसकी श्रम-शक्ति होती है। और पूँजीपति यह श्रम शक्ति लहरीदाता है जिसे वह इच्छित वस्तु का उत्पादन के लिए कहने भाल और उत्पादन के साधनों पर प्रयुक्त करता है।

अन्य वस्तुओं की तरह, जिन्हें बाजार में विक्रय के लिए लाया जाता है, श्रम-शक्ति भी एक तरह की वस्तु है। पूँजीपति मज़दूर को उसकी श्रम-शक्ति के तुल्य मुद्दा का भुगतान इसे कुछ समय प्रयोग करते के लिए अथवा कार्य की एक निश्चित मात्रा के लिए करता है।

उपर से देखने पर मज़दूर एक 'स्वतंत्र प्रतिनिधि' मालम पड़ता है और कानूनी भाषा में पूँजीपति और मज़दूर के बीच श्रम-शक्ति के केता और विकेता के रूप में समानता पायी जाती है। मगर आधिक दृष्टि से ऐसा नहीं है। पूँजी एक संकेन्द्रित सामाजिक शक्ति है जबकि मज़दूर के पास उसकी व्यक्तिगत श्रम-शक्ति है। मज़दूर के बल तभी रह सकता है जबकि वह अपनी श्रम-शक्ति बेचे और दूसरा दूसरे मज़दूरी के बदले खरीदे। दूसरी ओर पूँजीपति वाहे तो इसे खरीदे, न बहेतो न खरीदे। वह इसे बिना खरीदे भी रह सकता है। 'वेतनमधोरी-मज़दूर' के इस सम्बन्ध में शोषण की व्यवस्था और सामाजिक शक्ति ढकी या छिपी रहती है।

मज़दूरी कैसे निश्चित होती है?

जीसाकि हमने देखा है, मजदूरी श्रम-शक्ति नामक वस्तु की मौद्रिक जीमत है। एक वस्तु का मूल्य भुव्रा के रूप में अभियक्त विनिमय मूल्य है। अन्य चीजों के साथ माँग और पूर्ति के नियम द्वारा निर्धारित इसकी कीमत में उत्तर-चाल आते रहते हैं।

यह कीमत उत्पादन लागत द्वारा निर्धारित होती है। यह इसमें अधिक या कम होती रहती है व एक समयावधि में इसमें अने वाले उत्तर-चाल परस्पर एक-दूसरे को समायोजित करते रहते हैं। वस्तु के रूप में श्रम-शक्ति के साथ भी ऐसा ही होता है। इसकी कीमत भी श्रम-शक्ति की उत्पादन लागत द्वारा निर्धारित होती है, हमरे शब्दों में जिसका अर्थ है, एक मजदूर की निवाह लागत, उसकी जीविका के साधनों की कीमत। पूँजीवादी व्यवस्था के चलते रहने के लिए जड़री है कि मजदूर अपना कार्य प्रभावशाली ढंग से करने की स्थिति में हो। सारे दिन परिश्रम करने और स्वयं को थकाने के बाद, वह अगले दिन फिर से कार्य शुरू करने की स्थिति में होना चाहिए। इसके लिए, उसकी बुनियादी जड़रतें—न सिर्फ़ स्वयं अपने लिए बल्कि जाति के रूप में अपने सवाईन के लिए भी, साथ ही परम्पराओं, सामाजिक रीतियों और प्रगति द्वारा निर्देशित अन्य हमरी जड़रतें भी पूरी करनी होती है। इन वस्तुओं का सम्मिलित रूप में मौद्रिक मूल्य ही मजदूर के निवाह की लागत है। सामाजिक औसत वह मजदूरी है जिसका मजदूर को भुगतान किया जाता है। जैसे, हमरी वस्तुओं की कीमतों में एक ही बिन्दु-मूल्य के चारों ओर उत्तर-चाल होता रहता है, इसी तरह मजदूरी अनेक तरखों पर निर्भर करती हुई श्रम-शक्ति के मूल्य के चारों ओर चक्रकर लगाती रहती है। कई बार पूँजीपति श्रम की कीमत को कम करने में सफल हो जाता है, कई बार बहुत ज्यादा मात्रा में। हमरे अवसरों पर, कुछ कम मात्रा में।

बहुरहाल, श्रम-शक्ति अन्य हमरी वस्तुओं से भिन्न होती है। इसकी करने में प्रयोग किया जा सकता है। जबकि श्रम-शक्ति का प्रयोग, मान लीजिए, ४ घंटे कार्य और नये मूल्यों को पैदा करने में किया जा सकता है, स्वयं श्रमशक्ति का उत्पादन करने के लिए यानी इसके निवाह के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए मात्र ४ घंटों का समय ही आवश्यक हो सकता है। ऐसी संभावना पूँजीवादी समाज में उत्पादक शक्तियों की वृद्धि के कारण होती है।

आतः ४ घंटों के दौरान जिसमें एक मजदूर उत्पादन कार्य में संलग्न होता है, पहले चार घंटों में, हम कह सकते हैं, कि वह अपने निवाह के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्य के बराबर मूल्य पैदा करता है। यह आवश्यक श्रम समय है, और इसके लिए उसे मजदूरी के रूप में पारिश्रमिक मिलता है। अगले ४ घंटों के लिए वह अतिरिक्त श्रम समय लगाकर अतिरिक्त मूल्य पैदा करता है, जिसे पूँजीपति

हड्डप लेता है। निश्चय ही, यहाँ हमारा संबंध प्रत्येक मजदूर द्वारा आवश्यक वर्च किये गये समय से नहीं बरन् प्रदल परिस्थितियों में सामाजिक रूप से अवश्यक समय से है।

अतिरिक्त मूल्य का उत्पादन ही ‘पूँजीवादी’ उत्पादन का प्रत्यक्ष लक्ष्य और निधारक उत्परेक्त’ है। इसीलिए पूँजीवादी उत्पादन की ऐतिहासिक प्रवृत्ति आवश्यक श्रम समय को कम करने और अतिरिक्त समय को फैलाने; निर्माण के बाद कुल मूल्य संवृद्धि के अनुपात में मजदूरी को कम करने अथवा उत्पादन मूल्य के प्रतिशत के रूप में मजदूरी में कटौती करने और अधिक अतिरिक्त मूल्य निचोड़ने आदि-आदि के उपाय खोजने की रही है। ऐसा अनेक तरीकों से किया जाता है जो अधिक उत्पादकता के लिए श्रम के तीव्रीकरण, वैज्ञानिक पुनर्गठन, आशुनिकरण आदि के सभी प्रयासों की जड़ में मौजूद है।

पूँजीवादी व्यवस्था में शारीरिक, मानसिक और स्नायिक ‘अतिरिक्त श्रम’ एक निरत्र प्रक्रिया है जिसका प्रतिरोध मजदूर संगठन बनाकर वर्ण-संघर्ष के बारए करता है।

अन्य देशों और भारत में मजदूरी के लिए संघर्ष का इतिहास न सिर्फ कटु-संघर्ष, दृढ़ युद्धों और मैदान में असंख्य कुर्बानियों का इतिहास रहा है, बल्कि पूँजी-वादी और निम्न पूँजीवादी सिद्धांतों से, जिन्हें मजदूर वर्ग को इसके संघर्षों की व्यर्थता और निर्धनता समझाते हुए, निरस्त और निरुत्साहित करने के प्रयास किये हैं विचारधारात्मक संघर्ष का इतिहास भी रहा है। आज इनमें से कुछ तथा-कठित ‘वैज्ञानिक’ तर्क सूखंतापूर्ण और हास्यप्रद प्रतीत हो सकते हैं। मगर अपने समय में उनमें काफी वजन और प्रभाव था। और आज भी पूँजीपतिवर्ग के नवीन प्रवक्ताओं द्वारा संशोधित और परिष्कृत संस्करण पेश किये जा रहे हैं। ऐसा एक उदाहरण ‘मजदूरी-कैमत सापिल’ का सिद्धांत है या फिर अधिक मजदूरी-दरों को अधिक निवेशों और रोजगार निर्माण द्वारा प्रभावहीन बना देना, आदि। इनमें से कुछ का अध्ययन हम बाद में करेंगे।

‘मजदूरी का लोह नियम’ और ‘मजदूरी कोष सिद्धांत’ का सार या कि मजदूर कुछ भी क्यों न करे, वह कितना ही कठोर संघर्ष क्यों न करे, वह अपनी हालत सुधारने में कठाई सफल नहीं होगा।

इंटरव्यूल लेखर रिचर्ड (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की पत्रिका) में ज्याँ मॉली ने इस प्रकार के व्याख्यायित किया है:

“इस नियम के अनुसार, श्रम की ‘स्वाभाविक कीमत’ जीवन-निर्वाह लागत और मजदूर व उसके परिवार को बनाए रखने के लिए आवश्यक या उपयोगी वस्तुओं की कीमत पर निर्भर करती है। ठीक इसी समय, श्रम के लिए एक ‘प्रचलित कीमत’ है जो मजदूर वात्सविक रूप में प्राप्त करता है और जो पूर्ति और

माँग की तात्कालिक परिस्थिति पर निर्भर करती है मगर जिसकी सदा स्वाभाविक कीमत से गहन संबंध की प्रवृत्ति पायी जाती है।”

वास्तव में, अगर प्रचलित मज़दूरी कुछ समय के लिए श्रम की ‘स्वाभाविक कीमत’ से कम हो जाए, तो परिणामी गरीबी और अधिक मृत्यु-दर श्रम-शक्ति के आकार को कम कर देगे और श्रम की पूर्ति में आने वाली कमी से इसकी कीमत बढ़ जाएगी। इसके विपरीत, श्रम की ‘स्वाभाविक कीमत’ से ऊपर मज़दूरी के स्तर में कोई भी वृद्धि आने वाले समय में पहले जनसंख्या में और इसके बाद उपलब्ध मज़दूरों की संख्या में वृद्धि करेगी जिससे मज़दूरी के स्तर में ‘स्वाभाविक कीमत’ के अनुरूप कमी आ जाएगी। वास्तव में श्रम की कुल माँग सदैव ‘मज़दूरी कोष’ द्वारा निर्धारित होती है जोकि मज़दूरी के भुगतान के लिए उपलब्ध पूँजी की मात्रा के अनुरूप होती है, जबकि श्रम की पूर्ति विशुद्ध रूप से जनसंख्यात्मक तत्त्वों पर निर्भर करती है, क्योंकि मज़दूरी मज़दूरी कोष और मज़दूरों की संख्या के भागफल द्वारा नियंत्रित होती है, जनसंख्यात्मक उतार-चढ़ाव इस भागफल को पुनः स्वाभाविक मज़दूरी की ओर ले जाएँगे।

मार्क्स ने यह प्रदर्शित करके इन सिद्धान्तों का सैद्धान्तिक खंडन किया कि मज़दूरी में भौतिक और सामाजिक न्यूनतम, दोनों ही सम्मिलित होते हैं और सामाजिक न्यूनतम सामाजिक-ऐतिहासिक परिस्थितियों के साथ बदलता है। उन्होंने सामाजिक-ऐतिहासिक परिस्थितियों को आकार देने व उद्दीपित करने और इस प्रकार मज़दूरी के सामाजिक न्यूनतम में परिवर्तन लाने में ट्रेड यूनियनों की जबर्दस्त भूमिका की ओर संकेत किया।

तथाकथित ‘लौह-नियम’ पर प्रहार करते हुए मार्क्स ने दिखाया कि लाभ की शक्ति लेते हुए अतिरिक्त मूल्य की कीमत पर मज़दूरी में वृद्धि की जा सकती है।

मज़दूर मज़दूरी में बढ़ोत्तरी हासिल कर सकते हैं, यद्यपि पूँजीवादी उत्पादन की सामान्य प्रवृत्ति औसत मज़दूरी स्तर और उत्पादन में मज़दूरी के अंश में कमी करना है। ये अनुपात अनेक तत्त्वों द्वारा तय होते हैं जिनमें से स्वयं मज़दूरों का संघर्ष सर्वप्रमुख है। मार्क्स ने इन सिद्धान्त को भी खारिज कर दिया कि वस्तुओं की कीमतें मज़दूरी के स्तर द्वारा निर्धारित होती हैं, जिसे मज़दूरी-कीमत संपर्क सिद्धान्त के प्रवर्तक बार-बार दोहराते हैं।

स्वयं जिंदगी ने इन सिद्धान्तों के दीवालियेपन को जगज्ञाहिर कर दिया है हालाँकि आज भी उन्हें नये-नये रूपों में सजाकर प्रस्तुत किया जाता है।

इसलिए अब हम मज़दूरी को इसकी विभिन्न विशेषताओं के संदर्भ में और जैसाकि हमारे दिन-प्रतिदिन के कार्यों में साधारणतया समझा जाता है, परिभाषित करेंगे :

मज़दूरी, जैसाकि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में परिभाषित किया

गया है, का अर्थ है, मुद्रा के रूप में व्यक्त किये जा सकने वाले सभी भुगतान जो, यदि रोजगार की शर्तें, चाहे प्रकट या फिर अंतर्निहित, पूरी होती हों, अपने रोजगार के बदले अथवा ऐसे रोजगार में किये गये कार्य के बदले मज़दूर को देय हैं। इसमें निम्नलिखित चीजें शामिल हैं :

- (i) ऐसे भत्ते (महँगाई भत्ते समेत), जिनका मज़दूर फ़िलहाल हक़दार है;
- (ii) किसी घरेलू निवास या प्रकाश की आपूर्ति; पानी, चिकित्सा-तीमार-दारी या दूसरी सुविधा या कोई सेवा या खाद्यान्नों और दूसरी वस्तुओं की रियायती आपूर्ति का मूल्य;
- (iii) कोई यात्रा संबंधी रियायत; मगर इसमें ये चीजें शामिल नहीं हैं—
 (क) कोई बोनस, (ख) किसी पेंशन कोष अथवा भविष्यनिधि अथवा फ़िलहाल लागू किसी नियम के तहत मज़दूर के कायदे के लिए नियोक्ता के द्वारा दिया योगदान या देय; (ग) सेवा के खत्म होने पर देय ग्रेच्युटी।

सभी अधिनियमों में इस परिभाषा का पालन नहीं किया जाता है। कुछ अधिनियमों में बोनस सम्मिलित है जबकि अन्य दूसरे भत्ते या तो वर्जित हैं या सम्मिलित हैं, जैसी भी स्थिति हो। हरेक स्थिति में, हमें ठीक-ठीक परिभाषा देखनी होगी।

—नाममात्र की मज़दूरी किसी समय पर मुद्रा रूप में व्यक्त मज़दूरी है। यह मज़दूर द्वारा अपने कार्य के बदले प्राप्त नकद भुगतान है। मगर मौद्रिक मूल्य कीमतों में वृद्धि के कारण लगातार बढ़लता रहता है। अतः,

—वास्तविक मज़दूरी का आशय उन वस्तुओं और सेवाओं से है जिन्हें मज़दूर अपनी मौद्रिक मज़दूरी से खरीद सकता है। यह मज़दूरों की वास्तविक क्रयशक्ति की द्योतक है। यदि मौद्रिक मज़दूरी में वृद्धि होती है, मगर भोजन, वस्त्र, मकान और अन्य आवश्यकताओं की लागत इससे भी अधिक बढ़ जाती है, तो वास्तविक मज़दूरी कम हो जाती है जो मज़दूर और उसके परिवार के लिए कठिनाई पैदा करती है। इसे महँगाई भत्ते की क्रियाविधि द्वारा दुरुस्त किया जाता है।

—महँगाई भत्ता आवश्यक रूप में एक ऐसा भुगतान है जो वेतन-भोगी खास-कर कम वेतन-भोगी को दो वक्त की रोटी कमाने अथवा कीमतों में वृद्धि के कारण बढ़ी हुई जीवन निर्वाह लागत को प्रभावहीन कर अपने स्वाभाविक जीवन स्तर को बनाये रखने के काबिल बनाता है। यह एक मज़दूर की वास्तविक मज़दूरी में होने वाली भारी क्षति को रोकने की कार्यविधि।² ऐतिहासिक रूप में, भारत के अधिकांश उद्योगों में मज़दूरों की मज़दूरी दो भागों से बनी होती है—एक ‘आधारभूत मज़दूरी’ और दूसरा ‘महँगाई भत्ता’।

—मजदूरों को मजदूरी की दरों का भुगतान एक निश्चित समय के लिए या फिर कार्य की एक निश्चित मात्रा के लिए किया जाता है।

समय दर : इस व्यवस्था के अंतर्गत, मजदूरों को एक निश्चित मजदूरी एक घंटे, एक दिन, एक सप्ताह या एक माह काम करने के बदले दी जाती है। ‘अंतिरिक्त समय’ भुगतानों की गणना साधारणतः घंटों के आधार पर की जाती है।
बस्तु दर : इस व्यवस्था के अंतर्गत, मजदूरों को एक निश्चित मात्रा में किये गये कार्य के लिए एक निश्चित भुगतान होता है।

परिणामानुसार भगतान, उत्पादकता पर आधारित मजदूरी आदि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने हेतु मजदूरों को एक मौदीक प्रोत्साहन देने के लिए वस्तु दर के ही वृप्तिद अथवा समय और वस्तु दरों का ही मिश्न है।
एक और वे पूँजीवादी शोषण को मजदूरत करते हैं, हालांकि दूसरी ओर वे मजदूर की पहलकदमी और आत्मसमर्पण का विकास करते हैं। इन सभी की प्रवृत्त मजदूर की व्याक्रितगत मजदूरी की औसत से ऊपर बढ़ाने की है जबकि स्वयं औसत में ही कटौती कर दी जाती है। इस तरह का अंतर्विरोध पाया जाता है।
इसके अप्रै, औसत से कम कुशलता वाले मजदूर को उत्पादन प्रक्रिया से बाहर फेंक देने की संभावना बनी रहती है।

—एक मजदूर का पारिश्रमिक या आय, उसकी मजदूरी से अलग वह मौद्रिक योग है जो वह उदाहरणार्थ अंतिरिक्त समय भुगतान समेत विभिन्न मर्दों के अंतर्गत प्राप्त करता है।

—श्रम लागत का आशय मुद्रा के रूप में व्यक्त मजदूरी, अन्य भुगतान अथवा नियोक्ता द्वारा अपनी समूची श्रम-शक्ति के लिए खर्च किये व्यय (जैसे सामाजिक सुरक्षा, प्रशिक्षण लागत आदि) के कुल मूल्य से है। श्रम लागत नियोक्ता की कुल उत्पादन लागत का एक अंश है।

टिप्पणियाँ :

1. संदर्भ मार्कमवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र पर कोई भी व्याख्यान टिप्पणियाँ।
2. तालिका देवें, जिसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सहित नाममात्र और वास्तविक मजदूरी की प्रवृत्ति को दिखाया गया है।

जरूर पढ़ें :

1. पूँजी, प्रथम भाग के पहले कुछ अध्याय : कार्ल मार्क्स
2. मजदूरी नियमावली : अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित
3. मजदूरी दर एवं पूँजी : कार्ल मार्क्स
4. मूल्य, कीमत और लाभ : कार्ल मार्क्स
5. ट्रेड यूनियनवादियों के लिए अर्थशास्त्र : एम० अच्युतन
6. मजदूरी के संबंध में आँकड़ा-पुस्तिका : एम० अच्युतन
7. भारत में मजदूरी : मणिकेन कर संस्थान
8. मजदूरी नीति के बारे में एटक के दस्तावेज़ : इंदौर सम्मेलन, 1975
9. बोनस आयोग को एटक सम्मेलन का माँगपत्र ('मजदूरों का बोनस का अधिकार' में प्रकाशित)
10. भारत में वास्तविक मजदूरी : श्रीकांत पालेकर

मजदूरी का प्रश्न (जारी)

वेहतर मजदूरी के लिए संघर्ष के दौरान भारतीय मजदूर वर्ग और इसके विभिन्न छटकों ने अनेक उपलब्धियाँ हासिल की हैं। अनेक वैधानिक प्रावधान हैं, कचहरियों और पंचों के निर्णय हैं, न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय सहित) द्वारा की गयी व्याख्याएँ और निर्णय हैं, वेतन आयोगों, मजदूरी बोर्डों और न्यूनतम मजदूरी समितियों की सिफारिशें हैं, द्विपक्षीय वातावरणों द्वारा किये गये आवर्ती मजदूरी समझौते हैं, विपक्षीय सम्मेलनों और समितियों द्वारा निकाले गये कानून हैं और व्या नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ और सिद्धांतों का यहाँ हवाला देना भर काफी होगा जो हमारे देश में मजदूरी नीति के विकास और मजदूरी निर्धारण के सिद्धांतों को इंगित करते हैं। कमीशनों, पंचायतों, द्विवृन्तों, अदालतों ने अपने द्वारा अंतर: हिस्ये गये निकर्षों की पुष्टि करने के लिए अपनी अलग तरह की व्याख्याएँ करने के प्रयास किये हैं। बहुत-सी स्थितियों में वास्तविक रूप में मजदूरी तथ करते हुए आधार के रूप में निर्धारित बहु-व्यक्ति सिद्धांतों को निष्कर्षों में ठीक प्रकार से लापू नहीं किया गया है। वर्तमान व्यवस्था में यह अभिक्षित ही है। मगर फिर भी, मजदूरी निर्धारण के कुछ आधारभूत सिद्धांत ऐतिहासिक रूप से उत्पन्न हुए हैं और उन्हें महत्व मिला है।

स्वतंत्रता की पूर्व-संधया पर स्थापित अंतर्रिम सरकार ने निम्नलिखित के लिए एक कार्यक्रम घोषित किया :

- (क) श्रम-नार्थ उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी का वैधानिक निर्धारण;
 - (ख) सभी बड़े उद्योगों में मजदूरी और व्यावसायिक गति का मानकीकरण एवं मजदूरी की दरों, साथ ही एक उद्योग में विभिन्न व्यवसायों के बीच अंतरों का निर्धारण;
 - (ग) जहाँ कहीं संभव हो, उद्योग की भुगतान करने की क्षमता का पुरा ध्यान रखते हुए 'उचित मजदूरी' समझौतों को प्रोत्साहन।
- यह उपनिवेशी मजदूरी व्यवस्था को खस्त करने और इसे भारत के पूँजीवादी

विकास के लिए उपयुक्त एक नयी व्यवस्था से प्रतिस्थापित करने का पहला प्रयास था।

—इस तरह न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम 1948 पारित कर दिया गया। इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर आंदोलन पहले ही एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन समझौता, क्रमांक 26 संपन्न कर चुका था। कुछ श्रम-साध्य रोजगारों (अनुसूची के प्रथम भाग में 12 उद्योग और द्वितीय भाग में कृषि सम्मिलित) में न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम ने मज़दूरी की न्यूनतम दरों को निर्धारित करने के प्रयत्न किये। इस अधिनियम के अंतर्गत, राज्य सरकारों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सूची का विस्तार करने के अधिकार प्राप्त थे। यह सोचा गया कि न्यूनतम मज़दूरी को या तो अधिसूचना द्वारा (इस स्थिति में राज्य न्यूनतम मज़दूरी सलाहकार समिति से परामर्श लिया जाना चाहिए) अथवा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त त्रिपक्षीय समितियों की सिफारिशों पर विचार कर निर्धारित या संशोधित किया जा सकता है।

दुर्भाग्यवश, न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम ने आशाओं को पूरा नहीं किया है सिवा उन स्थानों के जहाँ किसी विशेष उद्योग में मज़दूरों द्वारा चलाये गये संघर्षों से मज़दूरी में वृद्धि हुई है। इसने यह भी साबित किया है कि यह कानून की अपेक्षा वर्ग-संघर्ष का समीकरण है जो मज़दूरों की दशा में सुधार के लिए जिम्मेदार है।

1966 में सरकार द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति की समिति ने महसूस किया कि “सारे पहले से मौजूद मानदंडों में कमी कर दी गयी है और इस तरह न्यूनतम मानक निर्धारित करने के किसी वैज्ञानिक प्रयास के बजाय यह सब विरोधी हितों के बीच एक समझौता प्रतीत होता है।”

1968 में, राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार भी, “बहुत-से व्यवसायों में एक बार निर्धारित न्यूनतम मज़दूरी को लंबे अरसे तक संशोधित नहीं किया गया हालाँकि अधिनियम के अनुसार पुनर्विचार की अवधि पाँच साल से ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए।”

इस तरह, कुछ स्थितियों में प्रचलित दरों काफ़ी पहले निर्धारित न्यूनतम दरों से ज्यादा हैं। अन्य स्थितियों में, अधिसूचित दरों को भी लागू नहीं किया गया है। नियोक्ता विना किसी सज्जा के इसकी अवज्ञा कर सकते हैं। दूसरी स्थितियों में भी, जैसे कृषि में, न्यूनतम दरों को लागू करवाने के लिए कोई संगठन नहीं है।

बहरहाल, न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम ने श्रम-साध्य उद्योगों में परिस्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया और इस तरह आजादी के बाद के वर्षों में कानूनी घोषणाओं और ट्रेड यूनियन अभियानों के लिए एक आधार प्रस्तुत किया।

1948 में नियुक्त त्रिपक्षीय उचित मज़दूरी समिति ने तीन व्यापक मज़दूरी संबंधी सिद्धांतों को परिभाषित किया और मज़दूरी संरचना सुधारने के लिए कुछ

अस्पष्ट मानदंड निश्चित किये। कमोबेश आज भी ये सिद्धांत वैध हैं:

न्यूनतम मजदूरी को न सिर्फ जीवन-निवाह के बुनियादी साधन ही मुहैया कराने चाहिए अपितु उसे मजदूर की योग्यता को बनाये रखने के लिए भी पर्याप्त होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, न्यूनतम मजदूरी कुछ मात्रा में शिक्षा, चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं और मुविधाओं के लिए भी पर्याप्त हाँनी चाहिए। समिति ने इसे अपने विचार के रूप में रखा कि “राष्ट्रीय आय के लगभग किसी भी स्तर पर न्यूनतम मजदूरी का एक निश्चित स्तर अवश्य होना चाहिए जो समाज सहन-कर सके; एक स्तर पर तथा न्यूनतम मजदूरी जो रोजगार कम करती है और इस प्रकार राष्ट्रीय आय में कमी करती है, समाज को स्वीकार्य नहीं हो सकती।” समिति के अनुसार जीवन निवाह मजदूरी एक पुरुष कमाने वाले को अपने और अपने परिवार के लिए न सिर्फ भोजन, कपड़ा और मकान की बुनियादी जल्दरत्ते पूरा करने वालिक बच्चों के लिए शिक्षा, खानब स्वास्थ्य के बिलाफ़ सरक्षण, आवश्यक सामाजिक जल्दरतों की आवश्यकताएँ और बृद्धावस्था समेत अधिक महत्वपूर्ण विषयों के विश्वद बीम का उपाय सहित सस्ती मुविधाओं की एक मात्रा जुटा सकने के काविल बनाती है।”

उचित मजदूरी, सहज रूप से परिभाषित नहीं की जा सकती। मगर समिति ने व्याख्या की है कि “जबकि उचित मजदूरी की निम्न सीमा ही स्पष्ट रूप से न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए, उच्च सीमा का निर्धारण व्यापक रूप से उद्घोग की मुग्यतान क्षमता द्वारा तय होता है। यह न सिर्फ उद्घोग की मौजूदा आर्थिक स्थिति पर निर्भर करेगा बल्कि इसकी भविष्य की समावनाओं पर भी निर्भर करेगा। इन दो सीमाओं के बीच, वास्तविक मजदूरी निम्नलिखित तर्बों पर निर्भर करेगी... (क) श्रम की उपचाक्ता, (ख) उमी या पहास के स्थानों पर प्रचलित मजदूरी की दर, (ग) राष्ट्रीय आय का स्तर और इसका वितरण, एवं (घ) देश की अर्थव्यवस्था में उस उद्घोग का स्थान।”

राज्य नीति के निवेशक सिद्धांत : इसी समय के आसपास, संविधान-निर्माताओं को भी मजदूरी नीति के सबाल और इसकी भविष्यत्वामी दिशा पर चिचार करना पड़ा। अतः निवेशक सिद्धांतों के अंतर्गत, धारा 43 में यह प्रति-पादित किया गया : “उपयुक्त कानून अथवा आर्थिक संगठन या किसी और उपाय से राज्य सभी क्रापि, औद्योगिक या और किसी क्रिस्म के सभी मजदूरों को काम, जीवन-निवाह योग्य मजदूरी, उपयुक्त जीवन स्तर, खाली समय के पूर्ण उपभोग एवं सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर जुटाने के प्रयास करेगा।”

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मजदूरी नीति पर एक त्रिपक्षीय समझौते को क्रियावित करने की दिशा में एक बड़ा अग्रामी कदम उठाया गया। इसे 1957 में पंद्रहवीं भारतीय मजदूर अधिवेशन में स्वीकृत किया गया ‘आवश्यकता

पर आधारित न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण में इसने निम्नलिखित मानदंडों को स्थापित किया :

- (क) न्यूनतम मजदूरी की गणना में मानक मजदूर वर्ग के परिवार में एक कमाने वाले व्यक्ति के ऊपर तीन उपभोग इकाइयों को लिया जाना चाहिए। स्थिरों, बच्चों और किशोरों की आय को छोड़ दिया जाना चाहिए।

(ख) न्यूनतम भोजन आवश्यकताओं की गणना सामान्य कामकाज करते वाले एक औसत भारतीय वयस्क के लिए, डॉ० आयकॉयड के अनुसार, 2,700 कैलोरी के शुद्ध अंतर्भुक्त हैं के आधार पर की जानी चाहिए।

(ग) वस्त्र आवश्यकताओं की गणना 18 वर्ष प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पर की जानी चाहिए जोकि चार लोगों के एक औसत मजदूर परिवार के लिए कुल 72 गज बचता है।

(घ) आवास के संबंध में निम्न आय वर्ग के लिए सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में विदेशी मकानों के लिए सरकार द्वारा चार्ज किया जाने वाला न्यूनतम किराया ही मानदंड होना चाहिए; एवं

(इ) कुल न्यूनतम मजदूरी का 20 प्रतिशत इधन, प्रकाश व्यवस्था और व्यय की दूसरी विभिन्न वस्तुओं के लिए होना चाहिए।

लेकिन शोध ही सरकार और इसके सलाहकारों ने उपरोक्त सभी मानदंडों में कटौती करना और समझौते से पीछे हटना प्रारम्भ कर दिया। तत्कालीन वित्त मंत्री, मोरारजी देसाई ने दूसरे बेतन आयोग को सूचित किया कि “यह बाध्यकारी नहीं है।” इंडियन कॉमिटी ऑफ मेडिकल रिसर्च की पोषण सलाहकार समिति ने यह विचार रखा कि भोजन की निम्न कैलोरी मात्रा से ही काम चलाना होगा और जितनी मात्रा का डॉ० आयकॉयड ने मुझाब दिया है, वह उपलब्ध नहीं है। विशेषज्ञों का एक बड़ा हुजम, राष्ट्रीय पोषण सलाहकार समिति और अन्य, निम्न मानदंडों की पुष्टि करने से संतुष्ट हो गये। वेतन आयोग और मजदूरी बोर्ड यह दिखाने के लिए प्रस्तर होड़ करते लगे कि ‘आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी’ अप्राप्य है और मानदंडों के अंकड़े निदेशक के रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकते। नियोक्ताओं ने गणनाएँ, वक्तव्य और प्रस्ताव प्रस्तुत किये जो इसने विदेशी क्रिस्म के अंकि इंजीनियरी उद्योग के लिए नियुक्त केन्द्रिय मजदूरी बोर्ड के तीन को नहीं स्वीकार कर सकते। यह कहना ही काफ़ी होगा कि यह वक्तव्य इसना विश्वाय सदर्यों (अध्यक्ष समेत) को कहना पड़ा, “हम इस (नियोक्ताओं के) दबे बचकाना है कि किसी भी टिप्पणी की ज़रूरत ही नहीं है।”

विश्वाय ही, नियोक्ताओं पर बचकानेपन का आरोप नहीं मढ़ा जा सकता।

ज्यादा-से-ज्यादा अतिरिक्त मूल्य निचोड़ने और मज़दूरों के लिए बुनियादी न्यूनतम ज़रूरतों से भी इंकार कर देने के रूप में यह उनका वर्गीय दृष्टिकोण था जो अभिव्यक्त हुआ।

केवल कटु संबंधों ने ही मज़दूरों को एक बेहतर मज़दूरी संरचना की दिशा में क्रदम-ब-क्रदम बढ़ने में मदद की। कुछ महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ अदालतों में लड़ी गयीं। फलस्वरूप, कुछ सिद्धांत विकसित किये गये। कुछ नाम इस प्रकार हैं :

न्यूनतम मज़दूरी और भुगतान क्षमता : क्राउन एल्यूमिनियम वर्स बनाम इसके कर्मचारियों के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा (1958 एल० एल० जे०), “एक सिद्धांत, बहरहाल, ऐसा है जिसका कोई अपवाद नहीं है। किसी भी उद्योग को बने रहने का अधिकार नहीं है अगर वह अपने कर्मचारियों को कम-से-कम बुनियादी न्यूनतम मज़दूरी का भुगतान कर पाने में समर्थ नहीं है।”

एक्सप्रेस अख्तावार बनाम इसके कर्मचारियों के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों के बीच संबंध को और अधिक विस्तार से समझाया। (1961 एल० एल० जे०)

उद्योग व क्षेत्र सिद्धांत : हिंदुस्तान मोटर्स बनाम कर्मचारी (1962), फांसीसी मोटर कार कंपनी बनाम कर्मचारी (1962), ग्रीव्ज कॉटन एंड कंपनी बनाम कर्मचारी (1964), कमानी मेटल्स एंड एलॉयज लिमिटेड बनाम कर्मचारी (1967) आदि मुकदमों में सर्वोच्च न्यायालय ने विस्तार से यह सिद्धांत समझाया है।

पहले से ही निर्णीत मुकदमे का सिद्धांत : सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पहले से ही निर्णीत मुकदमे के सिद्धांत को वर्जित कर दिया गया है, क्योंकि मज़दूरों की मज़दूरी को जीवन निर्वाह योग्य मज़दूरी, जो स्वयं बदली हुई परिस्थितियों में बढ़ती है, की दिशा में बढ़ाने का प्रयास एक चिरस्थायी प्रयास है।

मज़दूरी का मानकीकरण : प्रारम्भ में किसी उद्योग-क्षेत्र में ट्रेड यूनियनों का प्रयास मज़दूरों की मज़दूरी को एक सामान्य मानक के बराबर लाने का रहा है। मज़दूरी के मानकीकरण के प्रयत्न के साथ ही उपस्थिति, व्यवसायों की परिभाषा और उनके काम की अंतर्वस्तु के मानकीकरण का प्रयास भी हुआ है। इसका उद्देश्य कार्यों के शलत वितरण और तदनुरूप मज़दूरी में कटौती द्वारा मज़दूरों पर हमला करने के नियोक्ताओं के अधिकार को कम करना है। इसने व्यवसायों और हस्तशिल्पों के श्रेणीकरण एवं साथ ही समयानुसार पदोन्नति के लिए भी परिस्थितियाँ उत्पन्न कीं। मानकीकरण के लिए संघर्ष बंबई के कपड़ा मज़दूरों के साथ प्रारंभ हुआ। इसने बैक कर्मचारियों के दीर्घकालीन राष्ट्रीय स्तर के संघर्ष के साथ ही नयी ऊँचाइयों को छुआ। जिसके दौरान उन्होंने सफलतापूर्वक एक मज़बूत अखिल भारतीय संगठन का निर्माण किया और अक्टूबर 1966 में एक सामूहिक समझौते

द्वारा नये उच्चोगामुसार और भारत-व्यापी मानकीकृत मज़दूरी संरचना लागू करवाने में सफल हुए।

दिजली कमर्चारियों और अन्य दूसरे केंद्र व राज्य कमर्चारियों के संघर्ष द्वारा समर्थित सार्वजनिक क्षेत्र कमर्चारियों के 'बराबर मज़दूरी' की मांग के साथ इस मुद्दे पर गुणात्मक रूप से नयी ऊँचाइयाँ हासिल कर ली गयी हैं।

बेतनवृद्धि और बेतनमान : 1953 में बैंकों के लिए गठित शास्त्री ट्रिब्यूनल ने कहा कि "वार्षिक बेतनवृद्धि सहित समयबद्ध बेतनमान ही अब बेतनमान का आवश्यं ढाँचा माना जाता है।" मज़दूरों के परिवार की बढ़ती हुई जड़रतों, उच्च-अनुभव, समय के साथ साथ निखरती कायुक्षलता और एक एंसी व्यवस्था ने, जो तर प्रबंधकों की मनकों पर निर्भर नहीं करती, इसे आज की तारीख में अत्यावश्यक और सर्वस्वीकृत बना दिया है। बेतनमान का क्रियावयन पदार्थनि के अवसरों एवं अन्य कारकों पर निर्भर बेतनमान के न्यूनतम व अधिकतम और इसकी अवधि के निर्धारण से जुड़ा हुआ है।

मज़दूरी विभेद : मज़दूरी में पाये जाने वाले विभेद महाराई भर्तों की एक जैसी और दूरदृश्यतापूर्ण दरों के भूगतान और कम आय पाने वाले मज़दूरों की ज्यादा-से-ज्यादा फायदे हासिल करने के ट्रेड यूनियनों के प्रयासों के कारण प्रायः कम हो गये हैं। प्रारंभ में यह ज़रूरी था। मगर अब, बहुत-से ज्योगों में मज़दूरी संरचना इस प्रकार की है कि दक्षता प्राप्त करने या अधिक जिम्मेदारियाँ लेने के लिए कोई प्रेरणा नहीं रही है। इसीलिए मज़दूरी विभेद का सावल इतना महत्व-पूर्ण हो जाता है। इसमें कार्ये के मूल्यांकन का मुहा और दक्षता की अवधारणा, कार्य का दबाव, आवश्यक प्रणिक्षण, अंतिमिहित अनुभव, स्वीकार की गयी जिम्मेदारी, कार्य में निहित जोखिम और इसी प्रकार के अन्य तत्व शामिल हैं। जहाँ कहीं इस तरह के कार्यात्मक मूल्यांकन का प्रयास होता है, ट्रेड यूनियनों को बारीकी से देखना होता है कि मूल्यांकन जैशनिक ही और विभिन्न श्रेणियों के बीच मतभेद भड़काने वाला न हो। केवल यूनियन की हिस्सेदारी ही इसकी वस्तुनिष्ठता और स्वीकार्यता को सुनिश्चित कर सकती है।

अंतरराष्ट्रीय अम संगठन के एक अधिवेशन में लिये पर आधारित किसी भी भेद के बिना एक जैसे कार्य के लिए पुरुष और स्त्री मज़दूरों को एक जैसा पारिश्रमिक देने का प्रतिपादन किया गया है। संविधान की धारा 39(द), राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में अंकित है : "राज्य, विशेषकर, अपनी नीति इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु बनायेगा कि एक ही कार्य के लिए पुरुष और स्त्री दोनों को एक समान बेतन प्राप्त हो।"

ट्रेड यूनियनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि मज़दूरी के निर्धारण में इस सिद्धांत का प्राप्तन किया जाये।

अतिरिक्त लाभ : ये मजदूरों की मजदूरी के पुरक हैं और संगठित उद्योगों में, जहाँ ट्रेड यूनियनें मजबूत हैं, वे द्विपक्षीय वार्ताओं और मजदूरी संबंधी समझौतों के मुख्य तत्व बन गये हैं। इन लाभों में सबेतन अवकाश और छुटियाँ, सामाजिक बीमा योगदान (कानूनी प्रावधानों के अतिरिक्त), मजदूरों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा भत्ते और सुविधाएँ, सहायता प्राप्त कैटीन, शिशुगृह, अवकाश-आवास, रियायती अवकाश यात्रा, भवन निर्माण सहायता, व्यावसायिक भत्ते आदि शामिल हैं। उनकी विभिन्न क्रिस्में और मजदूरों के बेतन में उनका अनुपात ट्रेड यूनियनों की दक्षता पर निर्भर करता है। जब मजदूर 'अतिरिक्त लाभों' की माँग करते हैं, वे उस मूल्य में से एक बेहतर हिस्से की माँग कर रहे होते हैं जिसे उन्होंने स्वयं पैदा किया है। अतिरिक्त लाभों पर विचार किये बिना मजदूरों के जीवन स्तर के बारे में इन दिनों कोई भी चर्चा अपूर्ण है।

मजदूरी निर्धारण की विधियाँ : न्यूनतम मजदूरी समितियों और असंगठित उद्योगों के संदर्भ में सरकारी अधिसूचनाओं से लेकर निर्णयदादेशों, बेतन आयोगों, मजदूरी बोर्डों, पंच-फ़ैसलों और मजदूरी समझौतों की ओर बढ़ती अंतिम द्विपक्षीय वार्ताओं तक ये मौजूद हैं। संगठित क्षेत्र में, द्विपक्षीय वार्ताएँ, या दूसरे शब्दों में, सामूहिक सौदेबाजी मानदंड बनती जा रही है। दरअसल यह इन उद्योगों में ट्रेड यूनियन आंदोलन द्वारा अर्जित ताक़त और परिपक्वता का माप है। सरकार का प्रयास इस तरह के उपायों द्वारा जैसे सार्वजनिक उद्यम व्यूरो के निर्देशों को ज़ारी कर, किसी-न-किसी रूप में मजदूरी वृद्धि को उत्पादकता से जोड़ने पर बल देकर, नयी बातचीत में विलंब कर, अधिसूचना द्वारा मजदूरी और भत्तों को निर्धारित कर जैसाकि सामान्य बीमा कर्मचारियों के साथ किया गया, एकपक्षीय अधिसूचनाएँ ज़ारी कर और इसी तरह के अन्य उपायों द्वारा सामूहिक सौदेबाजी पर रोक लगाना या उसे सीमित कर देना रहा है। 'हड़ताल पर रोक' एवं 'अनिवार्य पंच-फ़ैसलों' का उद्देश्य भी समानता के कानूनी मानदंड को नकारना है जोकि सामूहिक सौदेबाजी में अंतर्निहित है।

मजदूर वर्ग इन हमलों का प्रतिरोध कर रहा है।

जरूर पढ़ें :

1. ट्रेड यूनियनवादियों के लिए अर्थशास्त्र : एम० अच्युतन
2. भारत में मजदूरी : मणिबेन कर संस्थान
3. ताजा मजदूरी समझौते : एटक प्रकाशन
4. हाल के मजदूरी समझौते : एटक प्रकाशन

महँगाई भत्ते का प्रश्न

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद के वर्षों में कीमतों में होने वाली वृद्धि ने मज़दूरों की क्रयशक्ति को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाया, जिन्हें मज़दूरी के रूप में पहले ही बेहद कम वेतन मिलता था। इसने बंबई और अहमदाबाद के कपड़ा मज़दूरों को सड़कों पर आने के लिए मज़बूर कर दिया। भयंकर हड़ताली संघर्ष हुए और पहली जीवन लागत भत्ते की लड़ाई जीत ली गयी। शीघ्र ही ये भत्ते छीन लिये गये और मंदी (1929-34) के दौरान मज़दूरी में कठौतियाँ थोप दी गयीं।

द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ होने के साथ ही कीमतें फिर से बढ़ने लगीं और 1940 में बंबई कपड़ा मज़दूरों को फिर से छह माह तक खिचने वाली 'महँगाई' हड़ताल करनी पड़ी। पहले कपड़ा मज़दूर और फिर रेलवे मज़दूरों द्वारा महँगाई भत्ते के सिद्धांत पर विजय मिली। धीरे-धीरे अन्य तबक्कों में भी इसका प्रसार हुआ। निष्प्रभावन की सीमा में कमी करने, राहत में, जितना हो सके, विलंब करने और मूल्य सूचकांक में वृद्धि के साथ स्वचालित रूप से महँगाई भत्ते को जोड़ने से इंकार करने की कोशिशें कर नियोक्ताओं ने हर क़दम पर इसका विरोध किया।

पचास के दशक में विकास कार्यों के लिए पूँजीवादी नियोजन के साथ ही उन्मुक्त स्फीतिकारी सर्पिल ने इसे औद्योगिक विवादों के एक बड़े मुद्दे में बदल दिया।

मज़दूर न सिर्फ़ स्वयं के लिए उपयुक्त और तत्काल महँगाई भत्ता पाने के लिए लड़े बल्कि कीमत-रेखा को रोकने के लिए प्रभावी क़दम उठाये जाने के लिए भी लड़े क्योंकि सिर्फ़ इसी तरह से ही व्यापक आम जनता अपने जीवन स्तर को सुरक्षित रख सकती थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राज्य द्वारा अनाज के थोक-व्यापार का अधिग्रहण करने की माँग करते हुए साठ के दशक में अनेकों जबर्दस्त कार्रवाइयों और 'बंधों' ने समूचे देश को हिला डाला। इसकी परिणति अंततः 1968 में श्री पी० बी० गजेन्द्रगड़कर की अध्यक्षता में गठित महँगाई भत्ता आयोग की स्थापना में हुई।

इस बीच विभिन्न उच्चोगों में अपनी कार्रवाइयों के द्वारा ट्रेड यूनियनों ने महँगाई भत्ता प्राप्त कर लिया। आयोगों, न्यायिकों और विधीय समझौतों के द्वारा विभिन्न फार्मले तथ्यार किये गये।

इस क्षेत्र में विभिन्न प्रणालियां प्रचलित हैं, जैसे समान-दर प्रणाली, कमबद्ध-प्रणाली, प्रतिशत के रूप में वेतन से संबद्ध महँगाई भत्ता, सूचकांक की प्रति अंक दर द्वारा मूल्य सूचकांक से संबद्ध महँगाई भत्ता और सूचकांक का एक विशेष अंक जिसके ऊपर यह देय हो जाता है, आदि। बहरहाल, साधारणतः कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की मुआवजे का एक बड़ा अनुपात पाने की प्रवृत्ति रही है। अधिक मजदूरी और वेतनों की तुलना में निष्प्रभावत अधिक रहा है।

इस मुद्दे पर अनेक सुप्रसिद्ध कानून बनाये गये हैं। मगर महँगाई भत्ता निर्धारित करने के लिए अनेकों अधिकारियों और समझौतों के परिणामस्वरूप निष्प्रभावत की दर, मूलभूत मजदूरी जिससे यह संबद्ध है, सूचकांक का अंक जहाँ से यह लागू हो जाता है, महँगाई भत्ते का पुनरीकाण करने के लिए अर्हता अवधि, आदि के बारे में पर्याप्त विवरण नहीं पायी जाती है। महँगाई भत्ते के निष्प्रभावत में एकल्पना का अभाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। अतः संघर्ष कम से कम वित्तम् और उद्दीपदों पर कार्यरत कर्मचारियों के बावजूद जयादा-से-ज्यादा संभव पूर्ण निष्प्रभावत प्राप्त करने के लिए रहा है। अपनी निर्भीक और एकजुट कार्रवाइयों के द्वारा राज्य सरकारी कर्मचारियों की ट्रेड यूनियनों व संघ केंद्र सरकार द्वारा स्थीकृत महँगाई भत्ता प्राप्त करने और अपने विरुद्ध प्रयुक्त पक्षपात्रों में भाव को हटाने में सफल रहे हैं।

महँगाई भत्ते की दर में कटौती करने के सारे प्रयासों के खिलाफ, जिन पर पहले समझौता हो चुका था, बैंक कर्मचारी मुकाबला करने में सफल हुए हैं। गजेंद्रगढ़कर महँगाई भत्ता आयोग ने इस टिप्पणी के साथ अपनी रिपोर्ट पेश की, कि,

“महँगाई भत्ते का आशय वेतनों के वास्तविक मूल्यों में आने वाली कमी को निष्प्रभावित करता नहीं है; इसे कीमतों में वृद्धि के खिलाफ जीवन निर्वाह स्तर पर या इससे कुछ ऊपर वेतनभोगियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाया गया है … जीवन निर्वाह स्तर पर या इससे कुछ ऊपर कर्मचारियों के संबंध में, नियोक्ता के रूप में सरकार का मूल्य वृद्धि से फैदा होने वाली कठिनाइयों के खिलाफ उन्हें सुरक्षा देने के लिए महँगाई भत्ता देने का दायित्व निर्विवाद है। भारत में औद्योगिक न्यायादेश में यह दृढ़तापूर्वक कहा गया है कि संगठित उद्योग में अपने कर्मचारियों को अधिक न मरी, कम-से-कम जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी देना, नियोक्ता का कर्तव्य है। यह सिद्धांत इस उपसिद्धांत को जन्म देता है कि नियोक्ता को महँगाई

भत्ते के द्वारा जीवन निर्वाह स्तर पर मज़दूरों के वेतनों में एक ऐसी राशि जोड़ देनी चाहिए जो उन्हें तेजी से बढ़ती क्रीमतों की स्थिति में स्वयं को बनाये रखने के योग्य बना दे……”

यद्यपि श्री गजेन्द्रगडकर की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय श्रम आयोग ने गैर-अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मज़दूरी स्तर पर 95 प्रतिशत निष्प्रभावन और उच्चतर स्तरों के लिए, इस आधार पर कि ऐसे कर्मचारियों को विकास लागत में हिस्सा बैटाना चाहिए, कम दर पर निष्प्रभावन की सिफारिश की है, विभिन्न संगठित उद्योगों में ट्रेड यूनियन कार्रवाइयों के फलस्वरूप 100 प्रतिशत निष्प्रभावन, यहाँ तक कि न्यूनतम मज़दूरी स्तर से ऊपर भी, प्राप्त कर लिया गया है। इसका मतलब निम्न स्तरों पर 100 प्रतिशत से कुछ ऊपर ही है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, इसके पीछे निहित कारण यह वास्तविक आधार रहा है कि कीमतों में वृद्धि के कारण अत्यधिक कम वेतन पाने वालों की कठिनाइयाँ उससे कहीं ज्यादा हैं जैसाकि मूल्य सूचकांक में वास्तविक रूप में प्रतिबिम्बित है।

बहरहाल, उच्चतर आय समूहों को देय महँगाई भत्ते पर रोक सामान्यतः स्वीकृत कर ली गयी है, हालांकि किसी भी खास सीमा को अलंघ नहीं माना जा सकता।

मज़दूरी जाम करने के अपने प्रयास के हिस्से के रूप में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो ने यह प्रतिपादित किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए महँगाई भत्ता जीवन सूचकांक लागत में प्रत्येक अंक की वृद्धि (या गिरावट) के लिए 1.30 रुपये की दर पर स्थिर कर देना चाहिए। इससे विरोध का तुफान खड़ा हो गया और 28 जनवरी, 1983 को सारे देश में एक दिन की हड़ताल की धमकी के बाद सरकार फार्मूले को संशोधित करने पर सहमत हो गयी। एक समिति का गठन कर दिया गया। लंबी वार्ताओं के बाद, समिति ने सिफारिश की कि दर को संशोधित कर 1.65 प्रति अंक कर दिया जाए।

इस बीच महँगाई भत्ते के सवाल पर चतुर्थ वेतन आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की:

- (क) 608 सूचकांक ($1960 = 100$) के ऊपर बारहमासी औसत की दर से क्रीमत वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति दी जाए, जिससे वेतनमान संबंधित है।
- (ख) वर्ष में दो बार क्षतिपूर्ति का भुगतान हो जो मार्च और सितम्बर के वेतन के साथ देय हो।
- (ग) प्रस्तावित वेतनमानों में, 3500 रुपये तक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को 100 प्रतिशत, 3,501 से 6,000 रुपये तक प्राप्त करने वालों को 75 प्रतिशत और 6,000 रुपये से अधिक प्राप्त करने वालों

को 65 प्रतिशत निष्प्रभावन दिया जाए जिसमें थोड़े-बहुत समायोजन की गुंजाइश हो।

महँगाई भत्ता निर्धारण की इस या उस प्रणाली के सापेक्षिक लाभों ने संगठित क्षेत्र में मजदूरों और कर्मचारियों के विभिन्न तबकों को वार्ताओं के दौरान किसी-न-किसी एक प्रणाली को चुनने के लिए मजबूर कर दिया है। इस सवाल पर इसने और अधिक अस्थिरता पैदा करने में मदद की है।

महँगाई भत्ते का मुद्दा हमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के सवाल से भी रुबरू करता है। ये सूचकांक श्रम ब्यूरो द्वारा एकत्र किये गये हैं। जैसाकि स्वयं ब्यूरो द्वारा परिभाषित है :

“उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाने का उद्देश्य उन चुनिदा वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा मूल्य स्तर में एक निश्चित अवधि में होने वाले परिवर्तनों को मापना है जिन पर आम उपभोक्ता या विशिष्ट समूह के लोग (जैसे किसी विशेष शहर में मजदूर वर्ग आबादी) अपनी आय खर्च करते हैं।” क्रीमतों में परिवर्तन किसी विशेष वर्ष, जिसे ‘आधार वर्ष’ कहा जाता है, के संदर्भ में पाये जाते हैं।

यह निर्धारित सूची ‘वस्तुओं और सेवाओं की टोकरी’ के रूप में जानी जाती है और इसे आबादी के एक नमूने में किये गये परिवार बजट सर्वेक्षण से ज्ञात किया जाता है। जनसंख्या के एक विशिष्ट तबके के परिवार बजट में प्रत्येक मद का उपभोग व्यय में एक निश्चित ‘वज्जन’ है और मदों की क्रीमतों में उतार-चढ़ावों का, जिनका बहुत ज्यादा ‘वज्जन’ है, स्पष्ट रूप से बजट पर काफी प्रभाव पड़ता है और तदनुसार मूल्य सूचकांक में उन्हें प्रतिबिम्बित किया जाना चाहिए। यहाँ, सिवा निम्न पर बल देने के निहित सांख्यिकीय और गणितीय व्यौरों में जाना जारूरी नहीं :

यह ‘टोकरी’ हमेशा स्थिर और अपरिवर्तित नहीं रहती क्योंकि परिस्थितियाँ, आदतें और जीवन स्तर के सिद्धांत बदलते रहते हैं।

यह भी स्पष्ट है कि जनता के विभिन्न हिस्सों के साथ-साथ यह ‘टोकरी’ भी बदलती है और इसीलिए विभिन्न वस्तुओं की क्रीमतों में परिवर्तन भिन्न-भिन्न हिस्सों को अलग-अलग तरह से प्रभावित करते हैं। इन परिवर्तनों को मापने वाले मूल्य सूचकांक भी, जाहिर है, भिन्न-भिन्न होंगे। यह नीचे दी हुई तालिका से देखा का सकता है :

औद्योगिक मज़दूरों के लिए
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

खेतिहार मज़दूरों के लिए
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(1960 = 100)

वर्ष	सामान्य	भोजन	वर्ष	सामान्य	भोजन
1971	190	203	1971-72	200	215
1974	304	342	1974-75	368	413
1977	321	343	1977-78	323	349
1980	390	406	1980-81	409	448
1982	475	498	1981-82	448	492
1986	661	685	1982-83	481	527
1987 मई	703	727	1983-84	522	573
			1984-85	525	569
			1985-86	555	600
			1986-87	578	623
			जून 1987	588	633

नीचे दी गयी तालिका से स्पष्ट है कि किस प्रकार कीमतों में वृद्धि हो रही है और परिणामस्वरूप एक और महँगाई भत्ते के मुद्दे और दूसरी ओर कीमत रेखा पर नियंत्रण के लिए संघर्ष ने ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए कितना अधिक महत्व ग्रहण कर लिया है। कीमतों और निर्देशित कीमतों में वृद्धि का मुद्दा हाल में अनेकों 'बंदों' और औद्योगिक कारंवाइयों के केंद्र में रहा है और भविष्य में भी रहेगा।

अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
(औद्योगिक मज़दूरों के लिए) आधार : 1960 = 100

वर्ष	सूचकांक	वर्ष	सूचकांक
1965	137	1987 (जनवरी)	688
1970	184	" (फरवरी)	686
1975	321	" (मार्च)	686
1980	390	" (अप्रैल)	691
1985	608	" (मई)	703
1986	661	" (जून)	715
		" (जुलाई)	724
		" (अगस्त)	736
		" (सितम्बर)	745

श्रम व्यूरो द्वारा एकत्रित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिस पर इतना कुछ निर्भर करता है, स्वयं कटु औद्योगिक विवाद का विषय बन गया है। जीवन के अनुभव से मज़दूरों ने देखा है कि बढ़ती हुई कीमतें, जिनका वे हर रोज़ मुकाबला करते हैं, मुश्किल से ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अधिक्यक्त हुई हैं। यह आशंका उत्पन्न हुई कि सरकार द्वारा उन्हें अपने हिसाब से तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है और घोषित सूचकांक सांख्यिकीय तथ्य नहीं था बल्कि राजनीतिक निर्णय था।

20 अगस्त, 1983 के बम्बई बंद समेत स्थायी विरोध ने इन आरोपों की जाँच हेतु एक समिति की नियुक्ति को ऐरिट किया। और सच्चाई सामने आ गयी यद्यपि लकड़वाला समिति (जैसाकि इसे जाना जाता था) ने सरकार के हित में इसे मुलायम बनाने का प्रयास किया। ट्रेड यूनियन केंद्रों में इसे 'सूचकांक जालसाजी' माना गया। इसके बाद इसमें कुछ संशोधन किये गये।

मगर बेचैनी जारी रही। 1977 में रथ समिति गठित की गयी। एटक ने सूचकांक को ठीक करने और किसी भी जालसाजी को खत्म करने के लिए आधार वर्ष में पारिवारिक व्यय की वास्तविक गणना, 'वजन' और 'टोकरी' की सही-सही गणना के लिए नमूने का आकार और वास्तविक खुदरा बाजार कीमतों का संग्रहण, आदि जैसे तत्वों को पहचाना। समिति ने इन चीजों पर ध्यान दिया।

बहरहाल, रिपोर्ट धूल चाट रही है और 'जालसाजी' जारी है। इसके बावजूद उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इस दौरान जारी कीमतों में होने वाली असाधारण वृद्धि को उद्घाटित करता है।

क्योंकि कीमतों में गिरावट की कोई आशा नहीं है, अतः ट्रेड यूनियनें नये और अधिक वास्तविक वेतनमानों के लिए प्रयास कर रही हैं, जिनमें महँगाई भत्ते का एक बड़ा हिस्सा मूल वेतन के साथ मिला दिया गया हो जिससे वार्षिक वेतन वृद्धि ज्यादा आकर्षक हो जाए।

टिप्पणी :

1. ट्रेड यूनियन कार्य के लिए श्रम संबंधी समंकों का बहुत महत्व है। ये श्रम व्यूरो द्वारा प्रकाशित इंडियन लेबर जनरल, इंडियन लेबर स्टेटिस्टिक्स, इंडियन लेबर इयर बुक, बुक ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स, ट्रेड यूनियन रिकॉर्ड और अन्य बहुत से स्रोतों में उपलब्ध हैं, जैसे उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण। इस काम के दौरान नवीन सांख्यिकीय समंकों पर भी ध्यान देना होगा।

ज्ञानर पढ़ें :

1. भारत में मजदूरी : मणिबेन कर संस्थान
2. ट्रेड यूनियनवादियों के लिए अर्थशास्त्र : एम० अच्युतन
3. हाल के मजदूरी समझौते : एटक प्रकाशन
4. ताजा मजदूरी समझौते : एटक प्रकाशन

मजदूरी संघर्ष के निष्कर्ष एवं जारी बहस

स्वातंत्र्योत्तर काल में, विशेषकर पिछले दशक में, मजदूरी के सबाल पर मजदूर वर्ग ने कुछ मिलाकर कुछ सफलताएँ हासिल की हैं। ये जीने दी गयी हैं: मजदूरी संबंधी कुछ मानदंड और सिद्धांत विकसित किये गये हैं। विशाल भेंतों में कितनी ही कम मजदूरी क्यों न प्रचलित हो, सैद्धांतिक रूप से मजदूर वर्ग अकाल या खुख्त से मरने की स्थिति के मजदूरी के मानदंडों को पर्याप्त छोड़ चुका है। 'आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी', जीवन निवाहि मजदूरी, कीमत बृद्धि के विरुद्ध निष्प्रभावन, जो वास्तविक मजदूरी में गिरावट पैदा करता है, बोनस, अतिरिक्त लाभ अव मुख्यापत तथ्य है;

कुछ संगठित भेंतों और उच्च-संपन्न इलाजों में, मजदूर उन्हें अवहार में उतारने और इस तरह अपनी वास्तविक आय में बृद्धि करने में सफल हुए हैं;

बड़े उद्योगों में, मजदूरी के मानकोंकरण का एक माप भी उपलब्ध कर लिया गया है; मध्यवर्गीय कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, सेवा उद्योगों के कर्मचारी विधाल स्तर पर मजदूरी संघर्ष में शामिल हुए हैं और इसे उपात्मक रूप से बढ़ावा मिला है।

और अंत में, अनेक भेंतों में मजदूरी बोर्ड, न्यायादेशों आदि की अपेक्षा मजदूरी निधारिण की एक विधि के रूप में द्विपक्षीय वार्ता पद्धति ने महत्वपूर्ण स्थान बनाया है।

बहुरहाल, ट्रेड यूनियन आंदोलन की आज की समस्याओं को समझने के लिए यह आवश्यक है कि मजदूरी संघर्ष के परिणामों का गहराई से अध्ययन किया जाए।

1939 से 1950 के बीच, वास्तविक मजदूरी प्रवृत्तियों का सामान्य चित्र संघर्ष का बनता रहा है जिससे कि युद्धदौरे की स्थिति को कोई गंभीर घटि न पहुँचे। 1951 तक वास्तविक आय मूल्कांक 92.2 (1939 = 100) पर स्थिर बना रहा। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा, "... ऐसा प्रतीत होता है कि

1947 से 1955 के बीच की अवधि में हुई बढ़ोतरी के बाद से (इस प्रक्रिया में, 1952 में 1939 के मज़दूरी स्तर तक पहुँचकर और उसके बाद इसमें सुधार प्रदर्शित करते हुए) वास्तविक मज़दूरी निरंतर घटती रही है। 1947 से 1955 के मध्य जीवन निर्वाह लागतों में कमी के कारण वास्तविक मज़दूरी वृद्धि का एक भाग आकस्मिक था……” परवर्ती काल के बारे में राष्ट्रीय श्रम आयोग ने माना, “‘कुछ मिलाकर, 1952 से 1965 के बीच जबकि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में सुधार हुआ है, मज़दूरों की वास्तविक मज़दूरी, कुछ अपवादों को छोड़कर, के बारे में ज्यादा-से-ज्यादा यही कहा जा सकता है कि वह गिरी नहीं है……’ जैसाकि राष्ट्रीय श्रम आयोग ने नोट किया, इस अवधि में प्रति मज़दूर उत्पादन लगभग 63 प्रतिशत तक बढ़ चुका था।

तालिका : 1

सार्वजनिक उद्यमों के विभिन्न उद्योग समूहों की मूल्य संवृद्धि के रूप में
उत्पादकता

क्रम संख्या	उद्योग समूह	मूल्य संवृद्धि (करोड़ रुपयों में)	प्रतिशत वृद्धि	लगायी गयी पूँजी में मूल्य संवृद्धि का प्रतिशत
		1984-85	1983-84	1984-85 1983-84
1.	इस्पात	1,119.07	740.71	51.08 30.21 24.65
2.	खनिज एवं धातु	496.32	392.28	26.52 26.42 24.26
3.	कोयला	2,415.11	1,714.24	40.89 84.33 67.16
4.	ऊर्जा	135.85	110.53	22.91 6.79 9.27
5.	पेट्रोलियम	4,610.18	3,649.45	16.73 72.50 78.14
6.	रसायन, उर्वरक व औपचार्याँ	999.76	852.48	17.28 37.53 37.54
7.	भारी इंजीनियरी	912.25	805.84	13.20 70.78 65.12
8.	मध्यम एवं हल्के इंजीनियरी	673.11	582.59	15.54 53.85 55.38
9.	यातायात साधन	742.05	564.23	31.52 52.89 46.86
10.	उपभोक्ता वस्तुएँ	116.00	82.20	41.12 330.45 66.56
11.	कृषि-आधारित उत्पाद	39.61	35.76	10.77 98.80 101.65
12.	कपड़ा	233.81	217.41	7.54 41.55 44.22

उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण ने पाया कि 1973-74 से 1977-78 की अवधि में 195 निर्माण उपसमूहों में से केवल 14 उपसमूहों में ही वास्तविक मजदूरी बढ़ी थी। अगर कुल मिलाकर इन उद्योगों में नियुक्त सभी मजदूरों की औसत आय को दृष्टि में रखा जाए तो हम पते हैं कि इस अवधि में वास्तविक आय में प्रतिशत वृद्धि वास्तव में 3 प्रतिशत की छहात्मक प्रवृत्ति दर्शाती है।

पृष्ठ संख्या 102 पर तालिका-1 में हम कुछ निर्दर्शी समंक दे रहे हैं, मगर नवीनतम स्रोतों से प्राप्त नये समंकों को सदैव उद्धृत किया जा सकता है :

तालिका : 2

उत्पादन मूल्य के प्रतिशत के रूप में श्रम लागत

उद्योग	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
चाय	—	36.9	35.5	25.2
चीनी	9.3	8.7	7.9	8.7
तम्बाकू	16.4	17.3	16.4	16.7
सूती कपड़ा	19.2	16.3	15.1	15.9
सिल्क व रेयॉन	13.5	15.1	15.8	14.1
एल्मीनियम	9.6	9.2	9.1	11.0
इंजीनियरी	12.8	12.4	13.4	14.2
रसायन	9.0	9.5	10.0	10.3
सीमेट	15.4	14.6	12.2	13.0
रबड़ एवं रबड़ उत्पाद	9.5	8.1	7.7	8.6
कागज व कागजी				
उत्पाद	14.5	13.0	13.1	12.8
विद्युत उत्पादन	7.9	4.7	5.5	5.3
व्यापार	—	4.9	5.5	6.0
जहाज रानी	10.5	11.2	12.1	13.9
कुल (अन्य समेत)	12.8	12.5	12.7	13.2

नोट : दि इकोनॉमिक टाइम्स (3 जुलाई, 1985) का अध्ययन निजी क्षेत्र में बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की लागत संरचना पर आधारित है। प्रसंगवश, श्रम लागत में न सिर्फ मजदूरी, बल्कि मैनेजरों का वेतन, विशेषाधिकार, आदि भी सम्मिलित हैं।

पूँजीपतियों के प्रवक्ता मजदूर वर्ग पर यह आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जबकि इसकी मजदूरी-लागतों में वृद्धि हो रही है, इसकी उत्पादकता नहीं बढ़ पा रही है और इस तरह पूँजी की बचतों और संग्रहण की हानि हो रही है।

तथ्यों ने इसे गलत साबित कर दिया है जो यह दिखाते हैं कि मजदूरों की श्रमशक्ति द्वारा उत्पादित निर्माण द्वारा मूल्य संवृद्धि बढ़ रही है जबकि कुल निर्माण मूल्य संवृद्धि में मजदूरों की मजदूरी का हिस्सा घट रहा है। पूँजी के हाथों मजदूर के शोषण की दर निरंतर बढ़ रही है।

अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रीय श्रम आयोग ने स्वयं ही यह निष्कर्ष निकाला :

“स्वतंत्रता के बाद (1947 के बाद से) औद्योगिक मजदूरों की मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि न तो वास्तविक मजदूरी में वृद्धि के साथ संबद्ध रही है, न ही वास्तविक मजदूरी वृद्धियाँ उत्पादकता में किसी भी सुधार के अनुरूप रही हैं। साथ ही निर्माण की कुल लागतों के एक समानुपात के रूप में मजदूरी लागतों में कमी हुई है और यही बात निर्माण द्वारा मूल्य संवृद्धि में मजदूरों के हिस्से के संदर्भ में भी सच है।”

तालिका : 3

सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ वस्तु समूहों की उत्पादन लागत में श्रम का भाग

क्रम संख्या	उद्यम समूह	श्रम का भाग	
		उत्पादन लागत का प्रतिशत	
1.	इस्पात		14.77
2.	खनिज एवं धातु		19.77
3.	कोयला		47.50
4.	ऊर्जा		5.61
5.	पेट्रोलियम		1.18
6.	रसायन व औषधियाँ		7.00
7.	भारी इंजीनियरी		18.16
8.	मध्यम व हल्के इंजीनियरी		24.32
9.	यातायात साधन		15.71
10.	उपभोक्ता वस्तुएँ		12.76
11.	कृषि-आधारित उद्यम		27.67
12.	कपड़ा		28.7

यहाँ तक कि बैंकिंग उद्योग में भी, जहाँ एक उच्च-शक्ति अभियान चलाया जा रहा है और स्टाफ की संख्या गैर-अनुपातिक रूप से अधिक है व कर्मचारी 'उच्च वेतन द्वीप' माने जाते हैं, कुल वर्तमान परिचालन व्ययों में व्यवस्थापत्र व्ययों का अंश निरंतर 1970 में 39.5% से 1981 में 22% तक गिर गया। (देखें एस० चक्रवर्तीं समिति की रिपोर्टें)

मजदूरी के सबाल पर पूँजीवादी अर्थशास्त्रियों द्वारा साँछियकीय तोड़न-मरोड़ के आधार पर रखे गये तर्कों का एक नमूना प्रो० बी० के० मदान ने प्रस्तुत किया है, जिन्होंने राष्ट्रीय श्रम आयोग के निष्कर्षों का इस आधार पर विरोध किया कि उसने कम वेतन प्राप्त मजदूरों को वास्तविक मजदूरी को कुछ अधिक ही महत्व दिया है। भारतीय निर्माण उद्योगों में काम करने वाले सभी मजदूरों से संबंधित समर्कों के विश्लेषण से प्रो० मदान ने यह निष्कर्ष निकाला कि 1951 के बाद से पिछले दो दशकों में औद्योगिक मजदूरों की वास्तविक मजदूरी में 35.3 प्रतिशत वृद्धि हुई है। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि भविष्य में भी यही प्रवृत्ति जारी रहेगी।

हिंद मजदूर सभा के महासचिव श्री बागाराम तुलपुले ने यह संकेत कर कारगर ढंग से इसका खंडन किया कि भारत के संदर्भ में वार्षिक औसत मजदूरी एक सार्थक चिनार नहीं है। दूसरे, वास्तविक मजदूरी की डॉ० मदान की तालिका का आधारवर्ष सिर्फ 1951 से बदलकर 1952 कर देने से वास्तविक मजदूरी में वृद्धि 25.1 प्रतिशत ठहरती है। वैकल्पिक रूप में, तालिकाओं के अंतिम वर्ष के रूप में 1970 के बजाय 1969 को मानने से पुनः वास्तविक मजदूरी में 19 वर्षों के दौरान 28.3 प्रतिशत वृद्धि दिखायी पड़ती है।

बागाराम तुलपुले द्वारा निकाले गये निष्कर्षों का सैद्धांतिक और व्यावहारिक महत्व है। अतः उनके कथन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। किसी परिवर्त्य मन-माने उत्तार-चढ़ावों के कारण होने वाली उपरोक्त किस्म की भिन्नताओं से बचने के लिए वह एक वेहतर संदर्भ-विद्वु के रूप में तीन-वर्षीय चक्रीय औसत की बकालत करते हैं। कुछ खास वर्षों में आकस्मिक परिवर्तनों के फलस्वरूप पैदा होने वाले विकृतीकरण को कम करने हेतु तीन-वर्षीय औसत को लेने से 1951-53 के लिए वास्तविक आय का औसत सूचकांक 105 और 1973-75 के लिए 131 बैठता है, जो 24.8 प्रतिशत की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। इसी आधार पर प्रति व्यक्ति आय का सूचकांक 23 वर्षों में लगभग 30.2 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

दूसरी ओर, 1951 की कीमतों पर प्रति व्यक्ति मूल्य संवृद्धि का औसत सूचकांक 1951 से 1953 तक के तीन वर्षों की अवधि के लिए 107.7 था व 1973-75 की अवधि के लिए 224.6 था जो 23 वर्षों की अवधि में 108.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता था।

उपलब्ध आँकड़ों के उपरोक्त विश्लेषण द्वारा, तुलनुपयोगित निष्कर्ष निकालते हैं :

- (i) 1975 में मजदूरों की औसत मजदूरी भी परिकलित गणनाओं के लिए स्वीकृत कम किये हुए पोषण मानकों के अनुसार भी न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित स्तर तक नहीं पहुँच पायी थी।
- (ii) मजदूरों की औसत वास्तविक मजदूरी 1951 के बाद से बढ़-घट रही है और 1975 तक वृद्धि की समग्र औसत दर मुश्किल से 1 प्रतिशत प्रति वर्ष से कुछ अधिक थी। यह वृद्धि दर इसी समय में स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय की दर की तुलना में निश्चित रूप से कम थी।
- (iii) 1975 में मजदूर परिवारों की औसत प्रति व्यक्ति आय इस दौरान राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय की अपेक्षा थोड़ी ही ज्यादा थी, इस तथ्य के बावजूद कि निर्माण क्षेत्र में आय पूरे समय के काम के बदले है और यह कि उच्च प्रौद्योगिक स्तर और संगठन की वजह से श्रम की उत्पादकता अपेक्षाकृत अधिक है।
- (iv) स्थिर कीमतों पर पर्युप्रति मजदूर निर्माण के द्वारा मूल्य संवृद्धि के रूप में श्रम उत्पादकता 1951 से 1975 के बीच की अवधि में 3 प्रतिशत प्रति वर्ष से ज्यादा औसत चक्रवृद्धि की दर से बढ़ी है। इसी दौरान मजदूरों की वास्तविक आमदनी मात्र लगभग 1 प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ी।
- (v) निर्माण द्वारा जोड़े गये मूल्य के एक समानुपात के रूप में मजदूरों की आमदनी 1951-53 में 50 प्रतिशत से कुछ कम से घटकर 1973-75 में 32.5 प्रतिशत के लगभग रह गयी।

“ये तथ्य क्या इंगित करते हैं? क्या वे यह दिखाते हैं कि मजदूर खुद अपनी कीमतें तथ करने वाला और असंगठित क्षेत्र का शोषण करने वाला इजारेदार है? क्या वे यह दिखाते हैं कि मजदूरों ने राष्ट्रीय आय, यहाँ तक कि अौद्योगिक उत्पाद का गैर-अनुपातिक रूप से बड़ा हिस्सा खुद के लिए हड्डप लिया है। क्या वे अनेक बार दोहराए गये इस दावे की पुष्टि करते हैं कि उत्पादन लागतों को बढ़ाने में भूतकाल में हुई मजदूरी वृद्धियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है? क्या वे यह सुझाव देते हैं कि मजदूरों को प्राप्त होने वाली आमदनियाँ और दूसरे लाभों की राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय के साथ कोई संगति नहीं रही है और यह कि कुल मिलाकर इन्होंने देश की बेहिसाब गरीबी बढ़ाने में मदद की है? क्या वे यह इंगित करते हैं कि मजदूरों की माँगों ने देश की अर्थव्यवस्था के विकास को धीमा कर दिया है? इन सभी सवालों का एक ही सुनिश्चित जवाब है ‘नहीं’।”

इंडियन लेवर जरनल (फरवरी 1982) में यह स्वीकार किया गया है कि

जबकि 1970-71 से 1979-80 के दशक में राष्ट्रीय आय 1970-71 की कीमतों पर 30.4 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी, इसी दौरान वास्तविक मजदूरी में सिर्फ़ 1.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। एक अन्य सरकारी सूत्र के अनुसार, “1975 तक 2 वर्ष की अवधि में मजदूरों की वास्तविक मजदूरी में 30 प्रतिशत से अधिक गिरावट आयी है।” संसद में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में सरकार ने स्वीकार किया। कि, “1980 तक 3 वर्षों के दौरान देश में बड़े औद्योगिक घरानों की परिसंपत्तियों में 45 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि हुई है”; जबकि “जनवरी 1973 से सितम्बर 1981 की अवधि में रुपये के मूल्य में गिरावट के कारण सरकारी कर्मचारियों की वास्तविक मजदूरी में 7 प्रतिशत से 46 प्रतिशत तक, जोकि वेतनमानों पर निर्भर करती है, गिरावट आयी है।”

इसके बावजूद, सरकार और दूसरे पूँजीवादी प्रवक्ताओं ने उन छोटे-छोटे लाभों के खिलाफ़ प्रत्याक्रमण छेड़ दिया है जिन्हें भारत के मेहनतकर्ताओं के एक हिस्से द्वारा हासिल कर लिया गया है। इस उद्देश्य के लिए सरकारी तौर पर चक्रवर्ती समिति (1973-74) और भूतलिंगम पैनल का गठन किया गया। इन दो समितियों द्वारा छेड़े गये विचारधारात्मक हमले का केंद्र, हर मीके पर सरकार द्वारा जिसे बार-बार दोहराया जाता रहा, गरीबी की सीमारेखा का सिद्धांत और ‘उच्च-वेतन द्वीप’ पर आक्रमण करना रहा। दोनों विचार एक-दूसरे के पूरक हैं और इस तर्क को कि मजदूरी संरचना को राष्ट्रीय गरीबी सीमारेखा (जिसके नीचे हमारी आवादी का 40 से 50 प्रतिशत से भी अधिक भाग रहता है) से जोड़ा जाना चाहिए, निरस्त कर देते हैं। संगठित मजदूरों द्वारा मजदूरी वृद्धि की कोई भी माँग अधिक उपभोक्ता वस्तुओं की माँग, कीमत वृद्धि और मुद्रा-प्रसार को प्रेरित करेगी और गरीबी हटाने की सामान्य सामाजिक और राष्ट्रीय समस्या का समाधान करने के प्रयासों से संसाधनों को विमुख कर देगी। ‘उच्च वेतन द्वीपों’ पर संकुचित वर्गीय स्वार्थों को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अपनी रणनीतिक स्थिति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है।

1980 में दिल्ली में हुई अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र ट्रेड यूनियन आयोग के अधिवेशन में बोलते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वाकपटुता के साथ पूछते हुए यह विचार दोहराया: “क्या रोजगार निर्माण को प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए? क्या नवीन श्रम प्रधान और रोजगार पैदा करने वाली परियोजनाओं में निवेश के स्थान पर हमारे देश के उच्च-वेतन प्राप्त लोगों के वेतनमान बढ़ाने के लिए संसाधनों को निधारित किया जा सकता है?”

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के निर्देशों में उपरोक्त आधार पर वेतनमान लागू करने के लिए अपनायी जाने वाली रणनीतियों को उल्लिखित किया। निवेश के चुनाव, विकास के रास्ते, रोजगार सृजन आदि के संबंध में आज ‘आधुनिकी-

करण' के रूप में नये और अत्यावश्यक लक्ष्य के साथ भिन्न तर्क दिये जा रहे हैं। लेकिन मजदूरों की मजदूरी के संबंध में दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वास्तव में, यह और ज्यादा मजबूत हुआ है। इसके एक हिस्से के रूप में सामूहिक सौदेबाजी अथवा मजदूरी संबंधी वार्ताओं के मुद्रे पर, जिनमें पहले ही काफी विलम्ब हो गया है, पीछे हटने की कोशिश जारी है।

इस प्रचार का मुख्य उद्देश्य मजदूरी की वर्तमान विषमताओं को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करना और स्वयं गरीब कहलाते हुए आर्थिक क्रियाकलाप के सभी क्षेत्रों में मजदूरों की गरीबी को ज्यों-का-त्यों बनाये रखना है। राष्ट्रीय शम आयोग ने यह कहते हुए इसका खंडन किया है कि "औद्योगिक एवं अन्य मजदूरों (उदाहरण के लिए, खेतिहर मजदूर) के बीच विषमता इस तथ्य के कारण संभव नहीं कि औद्योगिक मजदूरों की आय गैर-अनुपातिक रूप से अधिक है, बल्कि इसलिए कि अन्य मजदूरों की आय गैर-अनुपातिक रूप से कम है।"

यह सत्य है कि मजदूरों की संगठित कार्रवाइयों में सफलताओं का संबंध आरंभिक रूप में अल्पसमूह से है। मगर यह अधिक मजदूरी की माँग हेतु अन्य मजदूरों के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। असंगठित मजदूर, खेतिहर मजदूर अपने संगठित भाइयों का रास्ता अद्वितीय करेंगे और सफलताएं हासिल करेंगे। वास्तव में, वे यह कर रहे हैं। अतः यह गरीबों के नाम पर मजदूरी के उच्चतर स्तर को कम करने का प्रश्न नहीं है, बल्कि उच्चतर स्तर प्राप्त करने हेतु गरीबों की मजदूरी में वृद्धि के लिए संघर्ष करने का प्रश्न है। यह एक सतत संघर्ष है। वेतन जाम करने की कोशिश करना वर्ग-संघर्ष को रोकने के वरावर है।

जहाँ तक निवेशों का ताल्लुक है, मजदूरी वृद्धि अथवा वेतन जाम से उनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। वेतन जाम द्वारा लाभों में वृद्धि का स्वतः अर्थ अधिक निवेश और इस प्रकार अधिक रोजगार के अवसरों का निर्माण नहीं है। वास्तव में, अनुसंधानों ने यह सिद्ध कर दिया है कि कुछ सीमा तक निम्न मजदूरी दरें निम्न क्रम-शक्ति व एक संकुचित बाजार को जन्म देती हैं और फलस्वरूप नये निवेशों को निरुत्साहित करती हैं। बेरोजगारी पूँजीवाद की दुष्ट सहचरी है और मजदूरी वृद्धि को रोककर उससे नहीं लड़ा जा सकता।

क्या मजदूरी में वृद्धि से कीमतें बढ़ती हैं? पूँजीवादी समाज में, कीमतों का मजदूरी से कोई प्रत्यक्ष संबंध है। मार्क्स ने इसे निष्कर्षतः पहले ही प्रदर्शित कर दियाथा। आज हम 'ज्ञारेदार कीमतों', 'निर्देशित कीमतों', 'काला बाजार कीमतों', 'नियंत्रित कीमतों', 'सहयता प्रदत्त कीमतों' आदि के बारे में जानते हैं। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नयी दिल्ली ने एक अनुसंधान कराया है और यह दिखाया है कि जब मजदूरी का अंश बढ़ता है, तो निर्मित वस्तुओं की कीमतें आवश्यक रूप से नहीं बढ़तीं। दूसरी ओर, मजदूरी के अंश में कटौती आम

उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी पैदा करती है, अप्रुक्त धमता निर्मित करती है, समूची अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुँचाती है और इस तरह कीमतों में बढ़ियों परिवर्त करती है। अतः मज़दूर भारतीय संघर्ष में लागत-दबाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

उत्पादन और उत्पादकता से संबंधित मज़दूरी की क्या स्थिति है? उत्पादन और उत्पादकता अनेक कारकों पर निर्भर करती है। पूँजीबादी समाज में मज़दूर वर्ग का इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। इसके विपरीत आषासनों के बावजूद, पूँजीबाद के अंतर्गत उत्पादन की उपलब्धियों को समान रूप से नहीं बांटा जा सकता। इसके अलावा अभी हम आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मज़दूरी, जोकि हमारा तात्कालिक लक्ष्य है, 'से काफ़ी दूर है। अतः उत्पादकता पर आधारित मज़दूरी हमारी परिस्थितियों में एक हानिकारक और अस्वीकार्य सिद्धांत है।

राष्ट्रीय मज़दूरी नीति के बारे में क्या स्थिति है? पूँजीबाद के अंतर्गत, जहाँ मज़दूरी में आराजकता पायी जाती है, इस प्रकार का सिद्धांत बेहद अकादमिक होता है। सबसे तुरी चात यह है कि इसका अर्थ मज़दूरी की कम कर 'परीबी' की सीमारेखा' के समकक्ष लाना है।

- अतः मज़दूरी के सावाल पर दृढ़ युनियन संघर्ष के उद्देश्य है:
- मज़दूरी के बारे में सभी पूँजीबादी सिद्धांतों और वेतन जाप के लिए, पर्याप्त या अप्रत्यक्ष, सभी प्रयासों के छिपाक दृढ़ संघर्ष चलाना।
- मज़दूरी के आरोही संघोधन और पूर्ण निष्पादन के साथ महांगाई भवते के लिए संघर्ष करना जिससे मज़दूरी में क्षति न हो सके।
- तात्कालिक लक्ष्य के रूप में 'आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मज़दूरी' प्राप्त करना।
- अपनी न्यूनतम मज़दूरी को बढ़ावाने और उसके पक्षके क्रियाव्ययन की सुनिश्चित करने के लिए असंगठित भ्रंतों के मज़दूरों और देहाती मज़दूरों के संघर्षों को हरासंभव सहायता देना।
- समान जार्ये के लिए समान वैतन के सिद्धांत को लातूर करवाना एवं जीव वाल मज़दूरों के क्षेषण के विरुद्ध संघर्ष करना।
- बेंधुओं मज़दूर और ठेका मज़दूरों की व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करना और मज़दूरी व अन्य श्रम कानूनों के क्रियाव्ययन को सुनिश्चित करना।
- मज़दूरी निर्धारण की एक विधि के रूप में द्विक्षीय वाताओं की व्यवस्था पर बल देना व उनका विस्तार करना।

- मजदूरी में वृद्धि के संघर्ष को राष्ट्रीय-औद्योगिक स्तर तक, राष्ट्रीय नीतियों के लिए संघर्ष के स्तर तक पहुँचाना।

जरूर पढ़ें :

1. वह सब जोकि पिछले पाठ में दिया हुआ है।
2. मजदूरी नीति पर पर्चा : एटक का विशेष अधिवेशन, इंदौर।

बोनस एवं सामाजिक सुरक्षा

जैसाकि मज़दूरी के बारे में रहा है, बोनस के संबंध में उपलब्धियाँ भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन द्वारा चलाये गये दीर्घकालीन और दृढ़ संघर्षों का परिणाम है।

जबकि इस शताव्दी के आरंभिक वर्षों में इन केंद्रों में 'काली मौत' का साया घूमना शुरू हुआ, काम पर बने रहने और अपने जीवन को खतरे में डालने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में अहमदाबाद और बम्बई के कपड़ा मज़दूरों को दी जाने वाली अल्प राशि 'लेंग बोनस' से आधुनिक अवधारणा यानी बोनस भुगतान के संबंध में कानून और व्यवहार तक मज़दूरों ने लंबी दूरी तय कर ली है।

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, कपड़ा मज़दूरों ने क्रीमत वृद्धि के विश्व क्षतिपूर्ति के रूप में 'युद्ध बोनस' पाने का जुगाड़ कर लिया था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दिनों में भी जारी रहा। असल में यह एक अनुदान भुगतान था, यद्यपि मालिकों की 'इच्छा और कृपा' काफ़ी हद तक मज़दूरों की भुगतान के लिए उन्हें बाध्य करने की क्षमता पर निर्भर करती थी।

बोनस के लिए वार्षिक संघर्ष इस बिन्दु के चारों ओर केंद्रित रहा कि मज़दूर निर्वाह-मज़दूरी से पर्याप्त दूर हैं, कि बोनस को एक 'स्थगित वेतन' माना जाये जिसका वार्षिक आधार पर भुगतान हो, कि यह पूँजीपतियों द्वारा उत्पन्न और हड्डप लिये गये अतिरिक्त मूल्य के अंश में एक अधिकारपूर्ण दावा था और यह कि न तो यह प्रबंधकों की शुभाकाङ्क्षाओं पर, न ही अजित किये गये लाभ की आकस्मिकता पर निर्भर था, जिसके बारे में किसी भी स्थिति में न तो मज़दूरों की कुछ चलती ही थी, न ही उन्हें कोई सच्ची जानकारी थी।

आज्ञादी के बाद के वर्षों में श्रम अपील ट्रिब्यूनल और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने आंशिक रूप से मज़दूरों के दावे को समर्थन दिया। अतिप्रवण होने के बावजूद, जैसाकि पूँजीवादी विचारधारा में अदालतें और कच्चहरियाँ हुआ करती हैं, वे सभी औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों के प्रधान लक्ष्य के रूप में 'लाभ' के आकर्षक चक्र को तोड़कर बाहर नहीं निकल पाये। बोनस निर्धारित करने

के लिए श्रम अपील ट्रिब्यूनल के फ़ार्मूले ने एक आधार प्रस्तुत किया ।

मजदूरों के अथक संघर्ष ने 1964 में सरकार को बोनस आयोग गठित करने के लिए आध्य किया । इसने घोषित किया कि हर हालत में, मुनाफ़े अथवा घाटे का ध्यान रखे विना कुल मजदूरी (मूल + महँगाई भत्ता) का कम-से-कम 4 प्रतिशत न्यूनतम बोनस के रूप में दिया जाना चाहिए । इसके ऊपर कोई भी भुगतान अन्य दूसरे भुगतानों के बाद बचे अवशेष लाभ का ही अंश होगा । अतः न्यूनतम बोनस वर्ष के अंत में चुकायी गयी मजदूरी का हिस्सा और इस तरह एक गारंटीशुदा अधिकार बन गया, जबकि इससे ऊपर दिया गया कुछ भी, लाभ के ऊपर फुटकर और इस प्रकार एक प्रकार से लाभ में हिस्सा बॉटाना था ।

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 तुरंत बाद संविधि पुस्तक में शामिल कर लिया गया, मजदूर परिवार के गैर-आवर्ती व्ययों की पूर्ति के लिए बोनस एक संवैधानिक अधिकार यानी गैर-आवर्ती मजदूरी के रूप में विकसित हुआ । बहरहाल, यह मजदूरों के कुछ निश्चित हिस्सों तक सीमित था और अनेक प्रतिबंधों द्वारा बँधा हुआ था जिससे पूँजीपतियों को पूर्व प्रभारों के नाम पर लाभ कराने, 'उपलब्ध अधिशेष' को कम करने और मजदूरों को उनका वाजिब हिस्सा देने से इंकार करने का अधिकार मिल गया । सरकार ने स्वयं अपने कर्मचारियों, अन्य विभागीय संस्थानों, स्थानीय संस्थाओं और नगर पालिका सेवाओं के कर्मचारियों को इस अधिनियम और बोनस के भुगतान की सीमा से बाहर रखा ।

पिछले दो दशकों में मजदूरों द्वारा लड़े गये भवंकर संघर्षों को नियोक्ताओं द्वारा पैदा किये गये अवरोधों को एक के बाद एक हटाने में सफलताएँ मिली हैं । 4 प्रतिशत न्यूनतम को बढ़ाकर 8.33 प्रतिशत कर दिया गया । गैर-प्रतियोगी सावर्जनिक क्षेत्र संस्थानों के कर्मचारी, विभागीय संस्थानों के कर्मचारी, केंद्र व राज्य सरकारों के मंत्रिमंडलीय और सचिवालयीय स्टाफ़ व नगर पालिका सेवाओं के कर्मचारी आदि भी अब बोनस के लिए अधिकृत हो गये हैं । 750 रुपये प्रति माह या इससे अधिक 1600 रुपये तक वेतन पाने वालों को मात्र 750 रुपये प्रति माह वेतन के आधार पर बोनस की आरंभिक सीमा अब कुछ कारणों से संशोधित कर दी गयी है ।

बहरहाल, यह सोचना केवल आत्मतुष्टि ही होगी कि सरकार ने स्वयं ही बोनस के भुगतान को मजदूरों के अधिकार के रूप में मान्यता दे दी है । 'आपात-काल' के दिनों में इसे छीनने का प्रयास किया गया था । हाल ही में, सरकार ने पहले तो अपने कर्मचारियों के बड़े हिस्से के लिए छोटी-मोटी रियायतों की घोषणा करके और फिर इसका आधा भाग भविष्यनिधि में जमा करने की बात करके इसमें पैबंद लगाने का प्रयास किया है । अतः सतत संघर्ष बना हुआ है ।

इस मुद्दे पर संघर्ष निम्न मांगों पर आधारित है :

- जहाँ भी नियोक्ता कर्मचारियों के बीच अंतर्संबंध मौजूद हैं, बोनस-अधिनियम के लाभ और बोनस का भुगतान सभी क्षेत्रों में विद्ये जाने चाहिए। वापिक मजदूरी भुगतान के इस हिस्से को देने से किसी भी कर्मचारी को इकार नहीं किया जाना चाहिए।
- न्यूट्रन्ट्स सीमा को अतिरिक्त लाभों समेत कुल आमदनी के 10 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाना चाहिए।
- लाभ की गणना और 'उपलब्ध अधिकृत' मालूम करने के लिए प्रश्नकॉफर्मले को संशोधित किया जाना चाहिए।
- 20 प्रतिशत की सीमा उठा ली जानी चाहिए।

सामाजिक सुरक्षा

मजदूरी-निधिरण के आधार में मजदूरों का सामाजिक सुरक्षा का अधिकार सबेतन छुटियाँ और अन्य अतिरिक्त लाभ, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पेशेवर तरक्की की संभावनाएँ निहित हैं। सामाजिक सुरक्षा लाभ मजदूरों के जीवन स्तर का एक आवश्यक तत्व बन चुके हैं।

मजदूर द्वारा श्रम-शक्ति का विकल्प एक पक्षीय सौदा नहीं है। पूँजीवादी पुनर्स्थान की माँग है कि श्रम-शक्ति की आपूर्ति लगातार बढ़ी रहे। पूँजीवादी व्यवस्था की नियंत्रण श्रम-शक्ति के पुनरुत्पादन एवं बीमारी, मातृत्व, अवैधता, रोजगार के तुक्रमान, व्यवसाय की आक्रमिक हानि, दृढ़वास्था और मौत के उत्तर-चढ़ावों के बीच स्वास्थ्य और कल्याण के एक नियिकत त्वर पर मजदूर और उसके परिवार को बनाये रखने की अनिवार्यता पर निर्भर है। यह सामाजिक सहायता और सामाजिक बीमा, दोनों के योग की मांग करती है।

इसके अतिरिक्त, मजदूर वर्ग के संघर्षों, मजदूर के जीते के अधिकार, मानवीय गरिमा और बेहतर सामाजिक अस्तित्व के दावे ने 'सामाजिक न्याय' की मान्यता को जन्म दिया है। आज का समाज अब और अचानक इस मानवाचित अवधारणा की उपेक्षा नहीं कर सकता और मजदूर वर्ग आदोलन इतना ताकतवर हो चुका है कि वह इसे ऐसा करने की हजाजत नहीं दे सकता। समय के साथ-साथ सामाजिक न्याय के आधुनिक सिद्धांत और अधिक विकासित हो रहे हैं।

आजादी से पूर्व, भारतीय मजदूरों ने दो आक्रियकताओं अर्थात् दुर्घटना एवं मातृत्व के विकल्प सुरक्षा हासिल कर ली थी। इन्हें मजदूर अधिकृत अधिनियम, 1923 और दूसरे अन्य मातृत्व लाभ अधिनियमों के तहत प्रदान किया गया। आजादी के बाद, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में प्रचुर विकास हुआ है।

उदाहरण के लिए उनमें समिलित हैं :

- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
- कोयला खान भविष्यनिधि और बोनस योजना अधिनियम, 1948
- कर्मचारी भविष्यनिधि और परिवार पेंशन कोष अधिनियम, 1952
- ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972
- मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधनों के द्वारा अर्जित ले-अँफ व छंटनी क्षतिपूर्ति, निलंबन के दीरान निर्वाह भत्ता ।

इनके अलावा, मजदूरों के विशिष्ट तबकों पर लागू कुछ अनुभागीय सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ हैं ।

कानूनी योजनाओं के अतिरिक्त, अनेक बेहतर संगठित श्रमिकों द्वारा अर्जित द्विपक्षीय समझौतों पर आधारित गैर-कानूनी सामाजिक सुरक्षा लाभ हैं ।

सामाजिक सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधान की बहुत-सी सीमाओं से ग्रस्त हैं :

- (i) सामाजिक सुरक्षा के बहुत से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो अब तक पूरी तरह से अरक्षित हैं । उदाहरण के लिए, जैसे अभी तक वेरोजगारी बीमा, वृद्धावस्था पेंशन आदि का कोई प्रावधान नहीं है सिवा उन जगहों के, जहाँ मजदूरों ने इसे बंदोवस्त अथवा पुरस्कार के जरिये अर्जित किया है; (ii) ऐसे प्रावधान, जो आज मौजूद हैं, सभी उद्योगों या सभी मजदूरों पर लागू नहीं होते । विकेंद्रित उद्योगों और असंगठित क्षेत्र में मजदूरवास्तव में असुरक्षित है तथा कुछ उद्योगों में, जो सुरक्षित हैं, मजदूरों के बहुत से तबके उनमें शामिल नहीं हैं; (iii) लाभ बहुत थोड़े हैं और पूर्णतः अपर्याप्त हैं; (iv) अनेक योजनाओं को लागू करने के लिए मजदूरों को अपनी मजदूरी के भरपूर हिस्से का योगदान देना होता है, नियोक्ता का अंश अपर्याप्त है और काफी मात्रा में बकाया है, सरकार का हिस्सा नगण्य है और अभी तक निर्णायक नियंत्रण सरकार और नियोक्ताओं के हाथ में है; (v) योजनाओं का प्रशासन नौकरशाही और लेटलतीकी से भरपूर है ।

इस सवाल पर संघर्ष का उद्देश्य वृद्धावस्था, वेरोजगारी आदि, जैसी आकस्मिकताओं से सुरक्षा प्रदान करने की मुंजाइश को बढ़ाना, सभी उद्योगों में मजदूरों की सुरक्षा का विस्तार करना, मजदूरों को प्राप्त लाभों में संशोधन करना, भविष्यनिधि के मिवा मजदूरों से अन्य किसी योगदान का न होना, अफसरशाही विलंबों और परेशानियों से बचने के लिए ट्रेड यूनियनों की हिस्सेदारी के साथ प्रबंधन का लोकतंत्रीकरण और विकेंद्रीकरण है । संघर्ष, कानूनी और सामूहिक सौदेबाजी—दोनों ही क्षेत्रों में होता है ।

बढ़ती हुई वेरोजगारी के साथ वर्तमान परिस्थिति में, ज्यादा-से-ज्यादा बंद व छंटनी, वेरोजगारी बीमे के लिए संघर्ष और छंटनी लाभों का बड़ा महत्व है ।

आधुनिकीकरण औद्योगिक संकट एवं जीवन व स्वास्थ्य के लिए जोखिम

बढ़ता है। मज़दूरों और सामाज्य सामाजिक पर्यावरण—दोनों के हितों में एक सचेत ट्रेड यूनियन आंदोलन द्वारा बेहतर सामाजिक सुरक्षा उपायों व साथ-साथ प्रतिबंधात्मक उपायों के लिए संघर्ष किया जाना चाहिए।

विकसित पूँजीवादी देशों में, हथियारों की दौड़ और भारी सैनिक व्यय आज तक मज़दूर वर्ग द्वारा अर्जित सामाजिक सुरक्षा उपलब्धियों पर प्रत्यक्ष हमले को प्रेरित कर रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में हम देखते हैं कि किस तरह 'रेगनवादी अर्थशास्त्र' और 'थैचरवाद' के एक अंश के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों में भयंकर कटौतियाँ की जा रही हैं।

हमारे देश में भी ट्रेड यूनियनों को इस तरह के विकास के विरुद्ध सजग रहना है।

ज़रूर पढ़ें :

1. बोनस एवं सामाजिक सुरक्षा पर पर्चा : इंदौर एटक का विशेष अधिवेशन दस्तावेज़ ।
2. राष्ट्रीय श्रम आयोग को एटक का ज्ञापन
3. स्वतंत्र भारत में श्रम : हिंद मज़दूर सभा प्रकाशन

औद्योगिक संबंध : ट्रेड यूनियन अधिकारों के लिए संघर्ष

ट्रेड यूनियन आंदोलन का केन्द्रीय मुद्दा मजदूरों को स्वतंत्र रूप से संगठित होने, अपनी यूनियन बनाने और बिना किसी रोकटोक के इसकी कार्रवाई चलाने का अधिकार, जब भी वह ज़रूरी समझे, हड़ताल का आह्वान कर उत्पादन प्रक्रिया से हटने की ताकत के बलबूते पर उसे नियोक्ताओं के साथ सामूहिक सौदेबाजी करने का अधिकार है।

इन तीन मौलिक और जैविक अधिकारों के संदर्भ में जो परिस्थिति उभरती है, जैसे :

- यूनियन बनाने और अपनी सामूहिक शक्ति व उनकी तरफ से सौदाकारी एजेंट के रूप में मान्यता दिलवाने का अधिकार
- सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार, एवं
- हड़ताल का अधिकार

वह ही देश में औद्योगिक संबंधों की आवोहवा तथा चरित्र का निर्धारण करती है।

राष्ट्रीय श्रम कमीशन को दिया गया एटक का ज्ञापन हमारे सैद्धांतिक आधार को निम्न रूप में रेखांकित करता है।

पूँजी के विरुद्ध मजदूरों के संघर्ष, दैनंदिन सुरक्षा, मजदूरी व कार्य की दशाओं में ट्रेड यूनियन ही उसकी सामूहिक शक्ति और ताकत का संगठन है। हड़ताल या अपने श्रम को वापस ले लेना ही उसका एकमात्र संघर्ष का कारण हथियार है।

और यूनियन तथा हड़ताल, इन दो चीजों के द्वारा वह नियोक्ता से सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार अर्जित करता है। इनके द्वारा ही वह संगठित पूँजी की सामूहिक शक्ति के स्तिलाफ़ अपने वर्ग के व्यक्तिगत सदस्य की कमज़ोरी पर जीत हासिल करता है।

अतः, ट्रेड यूनियनों को मान्यता, सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार और हड्डताल करने का अधिकार मजदूर वर्ग के लिए औद्योगिक संबंधों के सर्वाधिक मूलभूत और जैविक सिद्धांत हैं।

1926 में भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम के पारित होने से कुछ न्यूनतम परिस्थितियों के तहत किन्हीं भी सात मजदूरों को ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार मिल गया। मगर 1928 और 1929 की हड्डतालों की लहर के बाद और फिर 1937 व 1946 में संघर्ष के बाद पहले उपनिवेशी शासकों और बाद में कांग्रेसी सरकारों द्वारा आंदोलन और मजदूरों के बढ़ते संगठनों का प्रतिरोध करने तथा समझौतों व निर्णयादेशों को थोपकर हड्डताली संघर्षों को तोड़ने के प्रयास किये। 7 नवम्बर, 1938 को एक आम हड्डताल द्वारा बम्बई के मजदूरों ने 1937 के अधिनियम का विरोध किया, और पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के परिणामस्वरूप दो मजदूर मारे गये।

आजादी के बाद सरकार ने इस दिशा में अपने प्रयास शुरू कर दिये, ट्रेड यूनियन आंदोलन को विभाजित कर दिया। खुद अपनी यूनियनें स्थापित कीं और बम्बई औद्योगिक संबंध अधिनियम (गुजरात और म० प्र० में भी लागू) के अंतर्गत उन्हें तुरन्त मान्यता प्रदान कर दी।

1957 में भारतीय श्रम अधिकार विभाग के द्विपक्षीय संगठन ने अनुशासन आचार-संहिता पेश की जिसे एटक ने इसकी कुछ जबर्दस्त खामियों के बावजूद (मुख्यतः सरकार द्वारा प्रवर्तित यूनियनों के पक्ष में अधिक वजन होने से सदस्यता प्रमाणित करने के बारे में) सिफ़र इसीलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि पहली बार यूनियनों की मान्यता के लिए रास्ता खुला था।

मजदूर आंदोलन के द्वारा सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार लागू हुआ जिसने सरकार और नियोक्ताओं को अदालतों व न्यायादेश संगठनों को त्याग देने एवं द्विपक्षीय वार्ताओं और वेतन समझौतों हेतु बातचीत के लिए विवश कर दिया।

सभी तरह के प्रतिबंधों और दमन के उपायों के बावजूद औद्योगिक कर्मचारियों के अलावा सरकारी और अर्द्ध-सरकारी कर्मचारियों द्वारा वास्तविक जीवन में हड्डताल के अधिकार का प्रयोग किया गया, उदाहरणार्थ, 1960 व 1968 की केन्द्र सरकार कर्मचारियों की हड्डताल, 1974 की रेलवे कर्मचारियों की हड्डताल व अन्य।

1960 में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की हड्डताल के बाद संयुक्त सलाहकार तंत्र की योजना प्रस्तुत की गयी जो कुछ मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत एवं दूसरे अन्य मुद्दों के अंतर्गत अनिवार्य मध्यस्थता प्रदान करती है।

अंतरराष्ट्रीय ट्रेड यूनियन आंदोलन को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा कुछ समझौतों को स्वीकृत कराने में सफलता मिल चुकी है जो मजदूरों के संगठित होने के

अधिकार व सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को परिभ्राषित करते हैं। 1948 का समझौता क्रमांक 87 संगठन की स्वतंत्रता और संगठित होने के अधिकार के संरक्षण से संबंधित है। 1949 का समझौता क्रमांक 98 संगठित होने व सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार से संबंधित है। 1971 में मजदूर प्रतिनिधियों (नियोक्ता एवं अधिकांश सरकारी प्रतिनिधि यह देखने के लिए एक जुट हो गये कि यह समझौते की शक्ल न ले ले) को प्रदत्त संरक्षण और सुविधाओं से संबंधित एक सिफारिश स्वीकृत की गयी। ये विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ की पहल पर स्वीकृत किये गये।

इन समझौतों और सिफारिशों में निहित सिद्धांतों को हमारे देश में सरकार और एक वर्ग के रूप में नियोक्ताओं की तरफ से स्पष्ट स्वीकृति व समर्थन नहीं मिले हैं।

उन्होंने हर प्रकार से संगठित होने की स्वतंत्रता को खंडित किया है, हड़तालों पर रोक लगाकर उन्हें गैरकानूनी करार दिया है, दमन के द्वारा उन्हें तोड़ा है व सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार से वंचित किया है। इस रूप में, अभिव्यक्ति और मजदूरों के संगठित होने की स्वतंत्रता पूँजीवादी व सरकार द्वारा नियंत्रित प्रचार माध्यमों द्वारा काटी-छाँटी गयी है जो उसे हर तरह के प्रचार से वंचित करती है और उसकी स्थिति को हर प्रकार से विकृत करती है।

1974 की रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल, आपातकाल के दौरान अपनाये गये अनेक दमनकारी उपाय, 1982-83 में 2 लाख से ज्यादा कपड़ा-मजदूरों की डेढ़ वर्ष लम्बी हड़ताल औद्योगिक संबंधों के प्रति सरकारी रखेंये के शानदार उदाहरण हैं।

जनता पार्टी जब सत्ता में आयी तो उसने व्यापक औद्योगिक संबंध कानून के नाम पर मजदूरों के ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमला करने की कोशिश की। इसने समूचे ट्रेड यूनियन अंदोलन के एक जुट और जुझारू प्रतिरोध को जन्म दिया जिसने सरकार को इसे वापस लेने को मजबूर किया। जनता सरकार के पतन के साथ ही यह विधेयक रद्द हो गया।

सत्ता में कांग्रेस की वापसी के साथ ही अनेक खंडशः कानूनों और अधिसूचनाओं के जरिये मजदूरों के अधिकारों पर नये-नये कुटिल हमले हुए, यथा, 30 सितम्बर, 1980 को सामान्य वीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 के तहत जारी अधिसूचना, अस्पताल एवं अन्य कर्मचारियों पर लगाये गये प्रतिबंध, आवश्यक सेवा अनुरक्षण अध्यादेश, 1981 जिसे उसी वर्ष अधिनियम के रूप में पारित कर दिया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर पारित किये गये अनेक अधिनियम, जिनकी परिधि में कानूनी ट्रेड यूनियन और जन कार्रवाइयाँ शामिल थीं और अंततः औद्योगिक संबंधों पर नवीनतम प्रस्तावित कानून रद्द हो गये

जनता विधेयक को पुनर्जीवित करता है।¹

आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, एक बहु प्रयोजन धारा के अंतर्गत, जिसे देश के किसी भी सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के प्रत्येक प्राधिकरण व उद्योग तक फैलाया जा सकता है, सरकार को हड़तालों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है।

यह सरकार की मुद्राप्रसार बढ़ाने, मज़दूरी व महँगाई भत्ता जाम थोपने, इजारेदारों को ज्यादा-से-ज्यादा मुनाफ़ा बटोरने और मेहनतकश जनता पर अधिक-से-अधिक परेशानियाँ डालकर संकट का विशिष्ट पूँजीवादी तरीका खोजने की निहायत दिवालिया नीतियों के खिलाफ़ जनता के उभरते हुए विरोध के स्वर को दबाने का जबलन्त प्रयास था।

17 अगस्त, 1981 को सारे देश में 'काला दिवस' मनाकर, 23 नवम्बर, 1981 को राष्ट्रीय अभियान समिति के आह्वान पर संसद तक आज तक के सबसे बड़े मज़दूरों के मार्च और उसके बाद 19 जनवरी, 1982 को 'भारत बन्द' द्वारा मज़दूर वर्ग ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

तथापि आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम संसद में पारित करा लिया गया और उसका हड़तालों व हड़ताल के आह्वानों के खिलाफ़ बार-बार प्रयोग किया जाता रहा है।

अध्यादेश से भिन्न, विधेयक को जब संसद में लाया गया, इसमें निष्पक्षता दिखाने हेतु तालाबन्दी व बन्दों से संबंधित दो नयी धाराएँ जोड़ दी गयीं। मगर क्या हड़तालों और तालाबन्दी को एक समान माना जा सकता है? पहले भी 1954 में औद्योगिक संबंधों पर एक प्रश्नावली का जवाब देते हुए एटक ने इस विषय पर प्रकाश डाला था। उसका वक्तव्य यहाँ प्रस्तुत है:

"इस देश में व अन्य सभी पूँजीवादी राष्ट्रों में वर्तमान कानूनों के अंतर्गत हड़तालों व तालाबन्दियों को एक ही धरातल पर रखा जाता है। मगर वे हड़ताल का अधिकार स्वीकार करते हैं तो तालाबन्दी का अधिकार भी स्वीकार करते हैं। और जब वे हड़ताल पर प्रतिबंध या रोक लगाते हैं, वे तालाबन्दियों पर भी रोक लगाने की बात कहते हैं..."

"इसमें कानून निर्माताओं ने नियोक्ताओं और मज़दूरों के बीच औपचारिक समानता के सिद्धांत के आधार पर अपना रुख अङ्गित्यार किया है।

"ऐसे सिद्धांत परिस्थिति की वास्तविकता पर आधारित नहीं हैं ..."

"नियोक्ता द्वारा तालाबन्दी क्यों घोषित की जाती है? क्योंकि वह ज्यादा-से-ज्यादा मुनाफ़ा कमाना चाहता है या मज़दूरी में कटौती कर अथवा मज़दूरों की काम की परिस्थितियों को बदतर बनाकर घाटा कम करना चाहता है। जब मज़दूर

नियोक्ता की शर्तों को मानने से इन्कार कर देते हैं, उन्हें काम से निकाल दिया जाता है।

“अगर नियोक्ता एक मज़दूर को काम से निकाल देता है और उत्पादन बन्द कर देता है, क्या वह अपनी जीविका खो बैठता है?

“मगर मज़दूर पर इसका क्या असर होता है? जीविकोपार्जन के एकमात्र साधन के खो बैठने पर मज़दूर को, जो केवल अपने श्रम के सहारे ही जीवित रहता है, भूखों मरने की स्थिति का सामना करना पड़ता है और लबे गतिरोध की स्थिति में अनेक मौतें भी हो जाती हैं।

“अतः तालाबन्दी का अधिकार एक मज़दूर को भूखे मारने का अधिकार अथवा उसे भूख और मौत से डराने का अधिकार है।

“अगर एक मज़दूर हड्डताल में शामिल होता है और उत्पादन रोक देता है, वह अपनी जीविका खो बैठता है लेकिन अपने नियोक्ता की जीविका पर कोई प्रभाव नहीं डालता।

“अतः हड्डताल करने का अधिकार नियोक्ता को भूखे मारने का अधिकार नहीं है बल्कि मुनाफ़ा पैदा करने से इन्कार कर एवं ऐच्छिक दुखों और सामूहिक कार्रवाई द्वारा दबाव पैदा करने का अधिकार है। प्रभाव की दृष्टि से तालाबन्दी और हड्डताल के अधिकार एक जैसे नहीं हैं। एक भूखा मारने का अधिकार है जबकि दूसरा जीवित रहने का अधिकार है।

“अतः हड्डताल करने का अधिकार परम पावन है जबकि तालाबन्दी का अधिकार असामाजिक है व उचित नहीं है।”

जिन्दगी ने यह दिखा दिया है कि जबकि मज़दूरों पर हमला किया जाता है, उन्हें दंडित व दमित किया जाता है, यहाँ तक कि हड्डताल पर जाने के जुर्म में गोली से उड़ा दिया जाता है, किसी नियोक्ता पर तालाबन्दी का सहारा लेने के लिए अभियोग नहीं चलाया जाता, न ही जेल में डाला जाता है। मज़दूरों और नियोक्ताओं के बीच ‘बराबर दूरी बनाये रखने’ के बारे में यह बहुप्रचारित दावा है।

नवीनतम प्रस्तावित क्रानून में ट्रेड यूनियन विरोधी उपायों का एक सम्पूर्ण समुच्चय मौजूद है। यथा :

(क) ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने के लिए मतदान की लोकतांत्रिक माँग को अस्वीकार कर देना और वेतन में से सदस्यता शुल्क की कटौती प्रणाली लागू करना जो जुकाम ट्रेड यूनियनों के हितों के प्रतिकूल और आज्ञाकारी ट्रेड यूनियनों के पक्ष में आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है।

(ख) व्यापक शक्तियों समेत औद्योगिक संबंध आयोगों को थोपने का प्रयास करना जो वास्तविकता में हड्डतालों को गैर-क्रानूनी करार कर देंगे और

सामूहिक सौदेबाजी खत्म कर देगे।

- (ग) तथाकथित शैर-कानूनी हड्डतालों का समर्थन करने के लिए यूनियनों को पंजीकृत न करना एवं उन्हें व उनके पदाधिकारियों को दंडित करना।
- (घ) रजिस्ट्रार को ट्रेड यूनियनों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के अधिकार दे देना।
- (च) यूनियनों के पंजीकरण पर गम्भीर प्रतिबन्ध लगाना।
- (छ) ट्रेड यूनियनों पर मजदूर-वर्ग विरोधी आचार संहिता थोपने का प्रावधान करना, जिसमें एकजुट कार्रवाइयों अथवा बन्दों में भागीदारी से मजदूरों को वंचित करना सम्मिलित है।

नियोक्ताओं द्वारा उत्साहपूर्वक समर्थित प्रस्तावित कानून का उद्देश्य ट्रेड यूनियन आंदोलन को नपुंसक बनाना और मजदूरों पर अनुशासित व पिछलभूग्ल ट्रेड यूनियनों को थोपना है।

ये ट्रेड यूनियन विरोधी उपाय सरकार द्वारा चलायी जा रही जन विरोधी और इजारेदार समर्थक आर्थिक नीतियों के पूरक हैं। न ही वे अलग-थलग घटनाएँ हैं; वे सभी पूंजीवादी शासक वर्गों द्वारा चलायी जा रही मजदूर-वर्ग विरोधी मुहिम का एक हिस्सा हैं।

वर्तमान स्थिति में, अनेक देशों में पूंजीवादी शासक वर्ग श्रमिक-संघर्षों की उपलब्धियों को उलटने और वास्तविक रूप में सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों को छोनने का प्रयास कर रहे हैं। पहला, 'लचीलेपन' के नाम पर, जिसके बारे में उनका कहना है कि नयी प्रौद्योगिकी के आने पर यह अत्यावश्यक होता है, अनेक 'अनुचित श्रम हथकंडे' अपनाये जा रहे हैं। स्थायी मजदूर अपने व्यवसाय की सुरक्षा खो बैठते हैं। अस्थायी कार्य, अंशकालिक कार्य और गृहकार्य की योजनाओं पर ज्यादा बल दिया जाता है। सामूहिक समझौते पूरी तरह से खत्म कर दिये जाते हैं अथवा द्विस्तरीय मजदूरी प्रणालियों को लागू किया जाता है। दूसरे, पूंजी-वादी इजारेदारों के पक्ष में राज्य का हस्तक्षेप लगातार बढ़ रहा है और मजदूरों की प्रतिरोध कार्रवाइयों को दबाने के लिए दमनकारी तंत्र का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। श्रम कानून में बहुत से प्रतिक्रियावादी संशोधन किये गये हैं। विदेशी नियोक्ता ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमला करने के लिए सरकारों पर दबाव डाल रहे हैं और कुछ सरकारें विदेशी निवेशों व व प्रौद्योगिकी के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करने के नाम पर ऐसा करने की इच्छुक हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्रूरों के लिए अपनी एक शर्त कठोर ट्रेड यूनियन विरोधी कानूनों पर जोर देता है। ये आधुनिक नव-उपनिवेशी हमलों के तत्व हैं।

हमारे देश में व अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर ट्रेड यूनियन आंदोलन इन हमलों के

विरुद्ध कड़ा प्रतिरोध प्रस्तुत कर रहा है और उन्हें परास्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है।

ट्रेड यूनियन आंदोलन का कार्य मजदूरों के अधिकारों के प्रत्येक अतिक्रमण अथवा उन पर लगाये जाने वाले प्रतिबन्ध के विरुद्ध एवं लोकतांत्रिक औद्योगिक संबंधों के लिए संघर्ष करना जो प्रारम्भ में उद्धृत तीनों मौलिक व जैविक अधिकारों को मान्यता प्रदान करते हैं।

टिप्पणी :

1. हाल ही में, ट्रेड यूनियनवादियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, यहाँ तक कि आतंकवादी-विरोधी अधिनियम, संसद में इसके विपरीत आश्वासनों के बावजूद, प्रयोग में लाये गये हैं।

जारूर पढ़ें :

1. भारत में औद्योगिक संबंधों की समस्याएँ : एटक प्रकाशन
2. इन्द्रजीत गुप्त द्वारा लिखित मुख्य दस्तावेज व ट्रेड यूनियन अधिकारों पर सहयोगी रिपोर्ट—11वीं विश्व ट्रेड यूनियन कांग्रेस, बर्लिन

श्रम कानून

श्रम कानूनों की जानकारी देंड पूनियन कार्य का एक आवश्यक अंग है।

अनेक विशेषज्ञों के इस क्षेत्र में आने के साथ आज श्रम कानून कानून की एक विशिष्ट शाखा बन चुके हैं। विशेष उद्योग में लागू हो सकते वाले कानूनों की कामचलाऊ जानकारी देंड पूनियन कार्यकर्ताओं के शस्त्रागार का एक ज़रूरी हथियार है।

श्रम कानून देंड पूनियन संघर्षों के कई दशकों से होकर विकसित हुए हैं इसके साथ ही आरभिक पूँजीबादी युग के प्राचीन जंगल राज की जगह कानून का शासन व्यापित करने के पूँजीबादी कानून-निर्माणों और विधेयताओं के प्रयास हुए जो पूँजीबादी उत्पादन संबंधों को नियंत्रित करते हैं और व्यवस्था की कार्यप्रणाली में उत्पन्न समस्याओं को हट करते हैं। श्रम कानूनों की प्रवृत्ति सामाजित, श्रम के क्षेत्र में ठेका कानूनों और 'अनुबंध की पवित्रता' की 'सामाजिक न्याय' और 'मातवाधिकार' के सिद्धान्तों द्वारा संतुलित सामाजिक कानूनों से प्रतिस्थापित करते की रही है।

बहुत-से कानूनों के अंतराष्ट्रीय मानक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के समझौतों एवं सिफारिशों द्वारा प्रतिपादित किये गये हैं जो एक विपक्षीय संगठन की सीमा के भीतर ही अंतराष्ट्रीय मजदूर आदोलन के प्रतिफल हैं। इन्हें भारत जैसे सदस्य देशों द्वारा क्रियान्वयन के लिए आधार प्रस्तुत किया है।
विशेषकर औद्योगिक संबंधों एवं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में, कुछ अन्य कानून भारतीय परिस्थितियों, विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक संरचना, संवर्धित उद्योगों की विशिष्टताओं और देश के अन्दर वर्ष-संवर्ष के समीकरण से उत्पन्न हुए हैं।

श्रम कानूनों का अध्ययन उन नियमों के अध्ययन से शुरू होता चाहिए जो प्रत्येक देंड पूनियन के लिए आधारभूत महत्व रखते हैं, ये हैं:
1. देंड पूनियन अधिनियम, 1926 : एक ऐसा कानून है जो देंड पूनियनों के

पंजीकरण के लिए अवसर प्रदान करता है और कुछ संदर्भों में पंजीकृत ट्रेड यूनियनों से संबंधित कानूनों को परिभाषित करता है।

यह अधिनियम एक यूनियन के संविधान व कार्यप्रणाली, कोषों के उपयोग, वार्षिक विवरण के प्रस्तुतीकरण और ऐसा न कर सकने की स्थिति में जुमर्ने के लिए न्यूनतम नियम प्रस्तुत करता है।

इस अधिनियम के तहत राज्य सरकारों ने नियम बनाये हैं एवं पंजीकरण हेतु प्रार्थनापत्र दाखिल करने व वार्षिक विवरणों आदि को प्रस्तुत करते समय ट्रेड यूनियनों द्वारा इन नियमों का हवाला दिया जाना होता है।

2. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 : इसका उद्देश्य आशंकित विवादों समेत औद्योगिक विवादों की जाँच और निबटारे एवं कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए प्रावधान करना है।

इस अधिनियम में दी गयी उद्योग की परिभाषा से संबंधित निर्णय विधियों का एक बृहत संस्थान है। 'औद्योगिक विवाद' शब्द में रोजगार व शैर-रोजगार से पैदा होने वाले विवाद एवं रोजगार की शर्तों व कार्यगत परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाले विवाद, जैसे, तालाबंदी, छँटनी, हड़ताल, मज़दूरी, अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि शामिल होते हैं।

यह अधिनियम बातचीत के द्वारा ज्ञागङ्गों के निबटारों, श्रम-अदालतों में निर्णयदेशों और औद्योगिक पंचायतों द्वारा विवादों को सुलझाने के लिए एक कार्यप्रणाली निर्मित करता है। यह विवादों के संयुक्त संदर्भों, पंच-फैसलों आदि के लिए असर प्रदान करता है। कुछ परिस्थितियों में यह हड़तालों व तालाबंदियों को प्रतिबंधित भी करता है।

इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य-समितियाँ बनायी गयी हैं।

यद्यपि यह एक केन्द्रीय अधिनियम है, इसका प्रशासन राज्य के अधिकारियों के हाथ में है जिन्होंने इस अधिनियम के अंतर्गत स्वयं अपने नियम गढ़ लिये हैं।

(महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों को नियंत्रित करने और इस अधिनियम की परिधि में आने वाले कुछ उद्योगों में विवादों के निबटारे के लिए बम्बई औद्योगिक संबंध अधिनियम या इसका प्रतिरूप भी मौजूद है)

3. औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1966 : यह अधिनियम औद्योगिक संस्थानों में नियोक्ताओं से अपने अंतर्गत रोजगार की स्थितियों को परिभाषित करने और उनकी जानकारी मज़दूरों को उनके द्वारा समझी जाने वाली भाषा में कराये जाने की माँग करता है।

इस अधिनियम के तहत आदर्श स्थायी आदेश तैयार किये जाते हैं और नियोक्ता व कर्मचारियों की सुनवाई के बाद अधिकृत अधिकारियों द्वारा प्रमाणित

किये जाते हैं। स्थायी आदेशों में मजदूरों का वर्गीकरण, दुर्व्यवहार व सजाएँ विशेष रूप से उल्लिखित हैं।

4. फँक्टरी अधिनियम, 1948 : यह अधिनियम कारखानों में श्रम व कार्यगत परिस्थितियों को नियंत्रित करता है, यथा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण, काम के घंटे, मध्यावकाश, समय-विस्तार, अतिरिक्त समय, स्त्रियों व नौजवानों का रोजगार, सबेतन वार्षिक अवकाश आदि।

5. मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 : इसका उद्देश्य मजदूरी के भुगतान, मजदूरी अवधि को परिभाषित करना, मजदूरी से स्वीकृत कटौतियाँ एवं गलत कटौतियों या भुगतान में विलम्ब आदि से उत्पन्न दावों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करना है।

श्रम कानूनों की दूसरी श्रेणी उन नियमों की है जो कुछ उद्योगों से विशेष रूप से संबंधित हैं और उनमें रोजगार की परिस्थितियों को परिभाषित करते हैं। इन उद्योगों से जुड़े हुए ट्रेड यूनियनवादियों को संबंधित कानून का अध्ययन करना आवश्यक है, उदाहरण के लिए :

—खान अधिनियम, 1952

—बागान मजदूर अधिनियम, 1951

—कार्यरत पत्रकार (सेवा शर्तें) और मिश्रित प्रावधान अधिनियम, 1955

—मोटर यातायात कर्मचारी अधिनियम, 1961

—गोदाम जदूर (रोजगार नियंत्रण) अधिनियम, 1948

—बीड़ी और सिगार मजदूर (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976

—बिक्री पदोन्नति कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976

सरकारी कर्मचारी, रेल कर्मचारी, बैंक और बीमा कर्मचारियों के अपने स्वयं के अधिनियम, सेवा-शर्तें व नियम हैं।

कानूनों की तीसरी श्रेणी असंगठित क्षेत्र के और कठोर श्रम करने वाले मजदूरों से संबंधित है। विशाल असंगठित व कठोर श्रम क्षेत्र में साहस दिखाने वाले ट्रेड यूनियनवादियों को इन अधिनियमों और विधिनिर्णयों, जो उनके चारों ओर निर्मित किये गये हैं, की जानकारी होनी चाहिए। इन कानूनों में सर्वाधिक प्रमुख हैं :

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 : इसका उद्देश्य कुछ अनुसूचित व्यवसायों में मजदूरी की न्यूनतम दरें निश्चित करने का प्रावधान करना है।

उचित सरकार द्वारा, या तो एक सलाहकार समिति की नियुक्ति कर अथवा अधिसूचना द्वारा दरों को पहली बार तय किया जा सकता है या संशोधित किया जा सकता है।

इस अधिनियम में प्रत्येक नियोक्ता द्वारा रजिस्टरों व रिकार्डों के अनुरक्षण,

कर्मचारियों को वेतन-पुस्तिका व उपस्थिति कार्डों की पूर्ति एवं सरकार द्वारा किये गये दावों और शिकायतों के निर्णय हेतु इस्पेक्टरों व अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है।

2. ठेका मज़दूर (नियंत्रण एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970
3. बाल रोजगार अधिनियम, 1970
4. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
5. अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासी मज़दूर (रोजगार नियंत्रण व सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979

ये अधिनियम ठेका मज़दूरों के शोषण के खिलाफ बेगार और 'ताक़त के जोर पर किये जाने वाले श्रम के खिलाफ (संविधान की धारा 23), निर्माण कार्यों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार के खिलाफ (धारा 24), लिंग को ध्यान में रखे बिना समानता (धारा 14) आदि के लिए लक्षित हैं। क्योंकि ये मज़दूर अधिकार असंगठित हैं, इन कानूनों का साधारणतया पालन नहीं किया जाता। इससे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1982 में कुछ ऐतिहासिक निर्णयों और उसके तुरन्त बाद, एशियाई खेलों से संबंधित परियोजनाओं में नियुक्त कर्मचारियों के मुक़दमे में, जवाहरलाल नेहरू केंद्रों में रोजगार प्राप्त अनियमित मज़दूर और इसी तरह के अन्य मुक़दमों में परिपृष्ठ 'सार्वजनिक हित मुक़दमों' का विचार उत्पन्न हुआ। एशियाई खेल परियोजना मुक़दमे में सर्वोच्च न्यायालय का 18 सितम्बर, 1982 का निर्देश द्रष्टव्य है :

“...जब कभी भी विभागीय रूप से अथवा ठेकेदारों द्वारा कोई निर्माण कार्य कराया जा रहा हो, सार्वजनिक क्षेत्र निगम समेत सरकार अथवा अन्य कोई सरकारी अधिकारी, जो इस तरह का कोई कार्य करा रहा हो, उसे यह देखने की पूरी सावधानी बरतनी चाहिए कि श्रम कानूनों का पूरी कड़ाई से पालन हो रहा है या नहीं। गड़बड़ी करने वाले अफ़सरों या ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने से पूर्व उन्हें ऐसे किसी प्रावधान का अनुपालन न किये जाने के बारे में मज़दूरों की ओर से प्राप्त किसी शिकायत की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें सावधिक निरीक्षण के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि श्रम कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हो रहा है और मज़दूरों को उनके अधिकारों और लाभों से बंचित नहीं किया जा रहा है जिसके बे इस तरह के प्रावधानों के तहत हक़दार हैं, और अगर ऐसे कोई उल्लंघन दृष्टि में आते हैं, तो गड़बड़ी करने वाले अफ़सरों या ठेकेदारों के विरुद्ध तुरन्त कार्रवाई की जानी चाहिए, उच्च अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षणों की एक प्रभावी प्रदृष्टि शुरू करनी चाहिए।”

उपर्युक्त कानूनों के अलावा, विभिन्न राज्यों में असंगठित शारीरिक मज़दूरों की विशिष्ट किस्मों से संबंधित कुछ अन्य कानून भी हैं, जैसे,

महाराष्ट्र का मठाडी हम्माल और शारीरिक श्रमिक अधिनियम; आंध प्रदेश का मुट्ठा, जट्ट, हम्माल एवं अन्य शारीरिक श्रमिक अधिनियम, 1976, आदि। कानूनों की चौथी शेरणी बोनस के भुगतान अथवा सामाजिक मुरक्खा लाभों से संबंधित है, वे हैं :

1. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
2. मजदूर शक्तिपूर्ति अधिनियम, 1923
3. कर्मचारी राज्य बोनस अधिनियम, 1948
4. कर्मचारी भवित्यनिधि अधिनियम, 1952
5. मानव लाभ अधिनियम, 1961
6. ग्रेन्यूटी भुगतान अधिनियम, 1972

पहले के एक पाठ में इन पर चर्चा की जा चुकी है।

कानूनों की पांचवीं शेरणी उनकी है जो राज्यों द्वारा कार्यान्वयन किये जाते हैं और संबंधित राज्यों में ड्रेड युनियनों को उनकी जानकारी होनी चाहिए। उनमें से कुछ हैं :

—बम्बई औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1946 (एवं गुजरात व म० प्र० में इसके सहयोगी अधिनियम)

1971

—टुकान व संस्थान अधिनियम (प्रत्येक राज्य में) एवं अन्य। कानूनों की छठी शेरणी अपनी प्रकृति में बिशुद्धतः दमनकारी है जो या तो विशेषकर श्रम से संबंध रखती है, या फिर सामान्य दमनकारी कानूनों का हिस्सा है। यह अन्य कानूनों में कुछ मजदूर-विरोधी श्रावधानों के अतिरिक्त है। दमनकारी कानूनों का युख्य उद्देश्य सावर्जनिक उपयोग सेवाओं, आवश्यक सेवाओं, सावर्जनिक सेवाओं को बनाए रखने आदि के नाम पर हड़तालों और संघर्ष के अन्य रूपों पर प्रतिबंध लगाना है। विधि संहिता में मौजूद उनमें से प्रमुख हैं :

- आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम
औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम
नियम का घंड 36 A (d) भी कर्मचारियों के विरुद्ध लक्षित है और प्रशासन द्वारा उन्हें मनमाने देगा से उनके लियाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है।

अतः थम से संबंधित कानूनों को मोटे रूप में दो शेरणियों में विभाजित किया जा सकता है—अनुकूल एवं प्रतिकूल। अनुकूल कानून ज्यादा अधिकारों और

बेहतर परिस्थितियों के लिए मज़दूर वर्ग के संघर्षों के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं। जबकि प्रतिकूल कानून इन संघर्षों को तोड़ने, उनमें अवरोध पैदा करने व नष्ट करने के लिए शासक वर्ग के प्रयासों का परिणाम हैं। वर्तमान व्यवस्था में दोनों तरह के दबाव एक साथ काम करते हैं और श्रम कानून के परिणाम को तय करते हैं।

श्रम कानूनों के इतिहास, उनके क्रियान्वयन और व्यवहार के अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं :

केवल मज़दूर वर्ग-संघर्ष ही अनुकूल श्रम कानून के मानदण्ड निर्धारित करता है।

समय के गुज़रने और बदलती हुई परिस्थितियों के साथ मज़दूर वर्ग की कार्रवाईयाँ इन मानदण्डों में बदलाव लाती हैं।

मज़दूर वर्ग की कार्रवाई और चौकसी ही कानूनों में निहित अनुकूल प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है।

मज़दूर वर्ग की कार्रवाई अर्जित की गयी कानूनी उपलब्धियों से मुकरने अथवा अनुकूल प्रावधानों को खत्म करने से रोकती है।

मज़दूर वर्ग-संघर्ष ही भारी दमन और मज़दूर-विरोधी कानूनों को रोकता है।

अतः श्रम कानूनों का क्षेत्र वर्ग-संघर्ष का कार्य-क्षेत्र है, न कि सिफ़े मुकदमे-बाजी का।

ज़रूर पढ़ें

विशेष व्यवसाय या उद्योग में ट्रेड यूनियन कार्य से संबंधित सभी श्रम कानून।

प्रत्येक व्यक्ति को इन अधिनियमों में होने वाले नवीनतम संशोधनों एवं नये श्रम अधिनियमों से परिचिय होना चाहिए।

ट्रेड यूनियन कार्य-प्रणाली

ट्रेड यूनियन कार्य-प्रणाली का आरंभिक बिन्दु यह है कि यूनियनें व्यापक संगठन हैं। उनकी प्रकृति से ही, उनके दरवाजे प्रतिष्ठान अथवा उद्योग में किसी भी व प्रत्येक मजदूर के लिए खुले हैं। वे सभी मजदूरों को अपनी चौहड़ी में खींचती हैं, और ऐसा करने की उनसे आशा भी की जानी चाहिए, यद्यपि पूंजीवादी समाज की सर्वश्रेष्ठ परिस्थितियों में भी ट्रेड यूनियनें सम्पूर्ण वर्ग को समाहित नहीं कर पाती। जैसाकि लेनिन ने लिखा है, “प्रत्येक मजदूर, जो नियोक्ता व सरकार के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए संगठित होने की ज़रूरत अनुभव करता है, उसे ट्रेड यूनियनों से जुड़ना चाहिए। ट्रेड यूनियनों को अपना उद्देश्य प्राप्त करने में असफलता हाथ लगेगी अगर वे उन सबको नहीं जोड़ पाईं जिन्होंने कम-से-कम समझदारी का यह प्रारंभिक स्तर हासिल कर लिया है, अगर वे व्यापक संगठन नहीं बन पाईं।”

अतः ट्रेड यूनियन कार्य-प्रणाली का पहला कार्य संस्थान अथवा उद्योग में, जिसकी यह यूनियन है, प्रत्येक मजदूर को अधिकतम संभावित किसी भी तरह से भर्ती करना है, जिन्हें भी इस तरफ आर्कषित किया जा सके। क्योंकि सदस्यता हमेशा वार्षिक होती है (चाहे सदस्यता शुल्क मासिक, तिमाही या वार्षिक जमा किया जाए), अतः बिना किसी ढीलढाल के इसे एक निरंतर व सावधिक अभियान बनाना चाहिए।

संघर्ष में अथवा आंदोलन में स्वतःस्फूर्तता संगठन में स्वतःस्फूर्तता की पूरक होती है। इसकी सबसे ख़राब अभियक्ति सदस्यता के प्रति अनियमित व छिटपुट रुख के रूप में होती है। एक यूनियन की ताकत परिमाणात्मक रूप से सदस्यता के संदर्भ में मापी जाती है, न कि ‘प्रभाव’ के किसी अमूर्त दावे के आधार पर। स्वतःस्फूर्तता को आम मजदूरों के बीच संगठित कार्रवाई से प्रतिस्थापित करना होगा।

आम मजदूरों से निकटता का संबंध ही ट्रेड यूनियन कार्य का क ख ग है। नये मजदूर समेत, जिसे यूनियन में शामिल होने के लिए सहमत किया जाना है, प्रत्येक मजदूर के साथ निरन्तर संबंधों को विकसित करने और बनाए रखने का सबसे

अचूक उपाय नियमित सदस्यता अभियान है। यह उन्हें भी प्रभावित करने में सहायता पहुँचाता है जो यूनियनों के आपसी द्वेष से धृणा करते हैं और इसीलिए किसी भी यूनियन में शामिल होने में संकोच बरतते हैं। उनकी शंकाओं का समाधान करना होगा, उन्हें जुझारू ट्रेड यूनियनवाद की स्थिति में लाना होगा और यूनियन में भर्ती करना होगा। नियमानुसार, प्रत्येक वर्ष में एक या दो माह 'भर्ती माहों' के रूप में निश्चित कर दिये जाने चाहिए। वेतन में से सदस्यता शुल्क की कटौती प्रणाली के हमारे विरोध का एक आधार यह है कि सदस्यता अभियान के द्वारा मजदूरों के साथ निजी संबंध को सदस्यता जुटाने की एक प्रशासकीय योजना द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

ट्रेड यूनियन कार्यप्रणाली का दूसरा कार्यभार यूनियन की सांगठनिक संरचना के नियमित रूप से कार्य करने की ज़रूरत महसूस करना है। अपने उपनियमों और नियमावलियों के अनुसार, प्रत्येक यूनियन में सबसे नीचे एक साधारण सभा अथवा प्रतिनिधि सभा एवं सबसे ऊपर एक प्रबन्धक समिति और मनोनीत अधिकारी होते हैं एवं बड़ी यूनियनों तथा व्यापक अधिकार क्षेत्र में फैली यूनियनों के सन्दर्भ में कुछ मध्यवर्ती शाखाएँ, स्थानीय अथवा फैक्टरी समितियाँ भी गठित की जाती हैं।

साधारण सभा अथवा प्रतिनिधि सभा की या तो वार्षिक बैठक, या फिर नियमों के अनुसार दो या तीन वर्षों में एक बार बैठक होती है। कम सदस्यता वाली यूनियन अथवा किसी एक स्थान या फैक्टरी तक सीमित यूनियन के सन्दर्भ में सभी सदस्यों के लिए मिलना और साधारण संगठन में भागीदारी करना संभव है। मगर जब सदस्यता अधिक हो या फिर यूनियन का व्यापक क्षेत्र में प्रभाव हो, तब यह व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं है। ऐसी स्थितियों में साधारण सभा की बैठकों में ज्यादातर सदस्यों को भागीदारी करने का और अपने विचार प्रकट करने का मौका नहीं मिलता। वस्तुतः, थोड़े-से सदस्य या फिर एक ही स्थान से संबंधित सदस्य साधारण सभा के क्रियाकलाप को हथिया लेते हैं जबकि सदस्यों का बहुमत अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने की संभावनाओं से बंचित रह जाता है।

ऐसी स्थितियों में उचित यह रहता है कि सदस्यतानुसार विभागीय साधारण सभाओं अथवा शाखा साधारण सभाओं द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों की सभा हो। तब विभागीय अथवा स्थानीय शाखाएँ ट्रेड यूनियन संगठन की आधारभूत इकाई बन जाती हैं। यूनियन सदस्यता अभियान का लक्ष्य केवल ज्यादा-से-ज्यादा सदस्यों की भर्ती करना ही नहीं है बल्कि उन्हें फैक्टरी या विभागीय, खान के मुहानों और परियोजना स्थल, कार्यशाला और पॉवर स्टेशन शाखा समितियों में संगठित करना भी है। मात्र यह ही कार्यस्थल को यूनियन के 'गढ़' में तब्दील कर सकता है और

इसकी स्थिति को सुदृढ़ बना सकता है। यूनियन की प्रबन्धक समिति व केन्द्रीय दफ्तर को शाखाओं से नियमित सम्पर्क बनाए रखना चाहिए, संचार का द्विमार्गी माध्यम सुनिश्चित करना चाहिए, शाखाओं द्वारा संप्रेषित सदस्यों की माँगों और शिकायतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, एकत्र की गयी राशि व केन्द्रीय खजाने में जमा की गयी राशि की जाँच करते रहना चाहिए। केन्द्र द्वारा नियमित चुनाव और शाखा समितियों की कार्यप्रणाली पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शाखाएँ यूनियन द्वारा निर्धारित एक सामान्य नीति के अंतर्गत कार्य करें व उचित अनुशासन बना रहे जिससे एकता मजबूत हो सके। यह भी ध्यान रखा जाए कि शाखाएँ कमज़ोर न होने लगें या कागज पर ही उनका अस्तित्व न हो। यह सिर्फ़ शाखा सचिव व अन्य पदाधिकारियों से निकट सम्पर्क रखकर उन्हें व्यक्तिगत सहायता व सलाह देकर एवं उनकी शिक्षा व प्रशिक्षण पर भरपूर ध्यान देते हुए ही किया जा सकता है।

इससे हम तीसरे कार्यभार पर पहुँचते हैं अर्थात् यूनियनों के नियमों और उपनियमों के अनुसार नियमित चुनाव कराना।

प्रबन्धक समिति का चुनाव करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह यूनियन की सम्पूर्ण सदस्यता का अधिक-से-अधिक संभव प्रतिनिधित्व करती हो। बृहद वर्गों के प्रतिनिधियों को समिति में जगह दी जानी चाहिए जिससे उपेक्षा की किसी आरंभिक अनुभूति को बड़ी शिकायतों के रूप में और अंततः संगठन के विखंडन में विकसित होने का अवसर न मिल सके। नियमों और परंपराओं में सभी शाखाओं के उचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर विरोधी समूह मौजूद हैं तो बहुमत द्वारा अल्पमत समूहों को निकाल बाहर करने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए।

हाथ उठाकर भी चुनाव कराया जा सकता है। लेकिन अगर स्थिति की यही माँग है तो गुप्त मतदान बेहतर है। किसी निष्पक्ष संगठन अथवा सरकार का कोई प्रतिनिधि या अखिल भारतीय केन्द्र से चुनाव कराने का अनुरोध किया जा सकता है। मगर मतदान का कोई भी तरीका क्यों न अपनाया जाए, सर्वैतिनिक सदस्यों का (साधारण सभा की बैठक की स्थिति में) या उचित प्रकार से चुने गये प्रतिनिधियों का (प्रतिनिधि सभा की स्थिति में) रजिस्टर समय पर उपलब्ध होना चाहिए, सभी की उपस्थिति, जो मौजूद हों, उचित प्रकार से रिकार्ड की जानी चाहिए, सारी कार्रवाई ठीक तरह से नोट की जानी चाहिए एवं अंतिम परिणाम अध्यक्षता करने वाले अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने चाहिए। इस संबंध में कोई भी अक्षमता अथवा अनुचित आचरण और जोड़-तोड़ विवादों को बढ़ाते हैं, मुकदमेबाजी पैदा करते हैं और यूनियन में बिखराव पैदा करते हैं।

चुनाव परिणाम की खबर तुरन्त ही प्रेस और आम मजदूरों को दी जानी

चाहिए और उचित रूप में ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार, साथ ही राज्य व अधिकारीय केन्द्र को सूचित कर दी जानी चाहिए। राज्य और अधिकारीय केन्द्र का तुरन्त और प्रभावशाली हस्तक्षेप बहुत विवाद में विकसित होते हुए, किसी भी विवाद को आरंभिक अवस्था में ही खत्म कर सकता है।

पदाधिकारियों के चुनाव में संगठन में स्थिरता की प्रमुख आवश्यकता को पदाधिकारियों के चुनाव में संगठन में स्थिरता की प्रमुख आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए और अपनी प्रतिष्ठा, प्रशुल्क व अनुशुल्क नियमित करते हुए निरंतरता की ज़रूरतों और नेतृत्व में परिवर्तन के बीच सामर्ज्य बनाया जाना चाहिए।

ट्रेड यूनियन जनवाद का अर्थ मात्र यूनियन के नियमित चुनाव करना नहीं है। वास्तविक जनवाद, न कि औपचारिक जनवाद, का अर्थ आम मजदूरों की यूनियन की गतिविधियों में शामिल करना है। केवल इस प्रकार का वास्तविक जनवाद और आम भागीदारी ही बहुत-सी यूनियनों द्वासकर पिछड़े हुए मजदूरों की यूनियनों, में प्रचलित ढाँचे 'नेतृत्व का जनता द्वारा अनुसरण', 'एक नेता—हजारों अनुयायी को खिलौना कर देते हैं। इसके अलावा ट्रेड यूनियन मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला एक अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी संगठन है। सदस्यों को अपनी यूनियन में निरन्तर रुचि बनाए रखने के लिए सहमत किया जाना चाहिए। सर्वोधिक धन्नन समूहों और मजदूर तबकों की अधिकतम संभावित संख्या तक विस्तृत आंदोलन और विभिन्न अन्य गतिविधियों में शागिदारी ही वास्तविक ट्रेड यूनियन जनवाद का प्रमाण है। और एक वर्ग के रूप में मजदूरों की शिक्षा की शुरुआत है। आरम्भ में यूनियन में भर्ती ही मजदूर को संगठन बनाने, किसी बड़े दुर्योगहार या अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट होने की वर्णमाला सिखाती है। लेकिन यह सिर्फ़ संघर्षों और जन कार्रवाईयों के दौरान ही होता है कि मजदूर वर्ग के विरुद्ध वर्ग का अर्थ व बढ़ुईआ शासन की प्रकृति समझता है एवं समाजवाद व समाजवादी जनवाद में दीक्षित हो जाता है।

ब्यक्तिगत मालिकों की संकुचित सीमाओं के रूप में यूनियनों को चलाने की प्रवृत्ति, यूनियन कार्यकारियों को एक छोटे और कुनैदा युट तक सीमित कर देने, व्यापक संभव तबकों को आकर्षित करते हुए यूनियन संघठनों को एक जनवादी तरीके से चलाने में असफलता, यूनियन की नियमित सभाओं और चुनावों को कराने में असफलता—इन प्रवृत्तियों से संवर्ध किया जाना चाहिए और इन पर विषय प्राप्त की जानी चाहिए।

संस्थाओं में सहकारी समितियों और कार्य-समितियों के चुनावों को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए। वे यूनियन को मजदूरों पर अपना प्रभाव और पकड़ बनाने में मदद करती हैं। कभी-कभी जहाँ यूनियनों पर दूसरी शक्तियों का नियंत्रण होता है, ऐसे चुनावों में सीमित सफलता भी आम मजदूरों के साथ सम्पर्क कायम

करने में मदद करती है। प्रकट है कि इन निर्वाचित संगठनों में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों को पर्याप्त मात्रा में योगदान देना होता है।

ट्रेड यूनियन कार्यप्रणाली का चौथा महत्वपूर्ण कार्यभार यूनियन के योग्य पदाधिकारियों का चुनाव है।

पदाधिकारियों को नियोक्ताओं, सरकार और अन्य यूनियनों के आगे यूनियन का प्रतिनिधित्व करना होता है, समझौता वार्ताएँ करनी होती हैं और शिकायतें प्रस्तुत करनी होती हैं, निर्णयादेशों और दूसरी कानूनी कार्रवाइयों को चलाना व मॉनीटर करना होता है, मजदूरों के समूहों के साथ सम्पर्क रखना व उन्हें नेटूव देना होता है।

हमारी विशिष्ट स्थितियों में इसका तात्पर्य है 'वाहरी व्यक्तियों' और पदाधिकारियों के रूप में अनुभवी सक्रिय कर्मचारियों का एक सम्मिश्रण। पदाधिकारियों के चुनाव में उत्पीड़ित कर्मचारियों का एक विशिष्ट स्थान है।

बड़े संगठनों में विकसित होती यूनियनों और परिणामतः कार्यभार में वृद्धि के कारण दूसरे अंशकालिक कार्यकर्ताओं के साथ-साथ कुछ पूर्णकालिक पदाधिकारियों (कम-से-कम बड़ी यूनियनों में) का होना जरूरी हो गया है। पूर्णकालिक पदाधिकारी औपचारिक अथवा अनौपचारिक 'टाइम-ऑफ' आधार पर कार्यरत कर्मचारी या कोई दंडित मजदूर अथवा कोई 'वाहरी व्यक्ति', जिसे उचित वेतन दिया जाता हो, हो सकता है। इसके अलावा, अधिक सदस्यता व अनेक शाखाओं वाली बड़ी यूनियनों को रोजमर्रा के दफ्तरी कामों—जैसे, टाइप करना, पत्राचार करना, हिसाब आदि—के लिए वेतन प्राप्त स्टाफ़ की आवश्यकता होती है। बहर-हाल, ऐच्छिक आधार पर यूनियन के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में अधिक-से-अधिक यूनियन कार्यकर्ताओं को शामिल करने के प्रयास किये जाने चाहिए। वे ही, न कि वेतनभोगी स्टाफ़, यूनियन संगठन और इसकी कार्यप्रणाली की रीढ़ निर्मित करते हैं।

पाँचवाँ महत्वपूर्ण कार्यभार एक कार्यशील यूनियन दफ्तर स्थापित करना है। बड़ी यूनियनों का एक स्वतंत्र दफ्तर हो सकता है और प्रायः होता है। मगर छोटी यूनियनों को अपने दफ्तर के रूप में एक निश्चित स्थान, अगर जरूरत हो तो दूसरों के साथ साझे में भी, पाने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी स्थिति में ऐसे यूनियन दफ्तरों को नहीं सहन किया जाना चाहिए, जो या तो किन्हीं मटरणश्ती करने वाले नेताओं के 'शबनमी बस्तों' या फाइलों के भीतर पाए जाते हों या किसी के घर में पड़ी धूल भरी फाइलों में पड़े रहते हों।

दफ्तरी प्रबन्धन के लिए विभिन्न पदाधिकारियों के बीच कार्य का वैटवारा, प्रत्येक को उसकी क्षमता और इच्छा के अनुसार विशिष्ट कार्यों और विभागों का वितरण आवश्यक है। इसका आशय पदाधिकारियों के बीच कमबद्ध सहयोग,

नियतकालिक अभियानों के लिए शक्ति और संसाधनों के एक स्थान पर एकत्री-करण से भी है।

आजकल अधिकांशतः दफ्तरी कार्य की बेहद उपेक्षा की जाती है। फ़ाइलें अस्तव्यस्त रहती हैं। पत्रों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। दफ्तरों का कोई निश्चित समय नहीं है, आदि-आदि। कुछ नेताओं के दिमाग में दूसरे संभावित ‘क्रांतिकारी’ कार्यों की तुलना में इस कार्य की सबसे कम प्राथमिकता है। प्रायः ‘समय के अभाव’ का भी हवाला दिया जाता है। वास्तव में, यह काम की अनियमित आदतों, गतिविधियों के नियोजन और जिम्मेदारियों को बाँटने में असफलता की स्थिति है। इस तरह की अविवेकी और अराजक प्रवृत्ति के विरुद्ध संघर्ष किया जाना चाहिए।

कमबढ़ दफ्तरी-प्रबन्धन के लिए आवश्यक है कि सभी छोटे-बड़े यूनियन के दफ्तरों द्वारा निम्नांकित कागजों और रिकार्डों को ठीक प्रकार से रखा जाए :

- पंजीकरण प्रमाणपत्र
- संबद्धता प्रमाणपत्र (अगर संबद्ध हो)
- संविधान की प्रतियाँ (नवीनतम संशोधनों सहित, अगर कोई हों)
- पदाधिकारियों एवं प्रबन्ध समिति सदस्यों की सूची
- सदस्यता रजिस्टर और तदनुरूप प्रतिपत्रक (अगर इसकी शाखाएँ हों तो शाखाओं द्वारा भेजे गये सदस्यता चार्ट और प्रतिपत्रक)
- बही-खते व वाउचर
- कार्यवृत्ति-पुस्तक
- कुछ आवश्यक पत्राचार व परिपत्रों आदि की फ़ाइलें
- ‘ट्रेड यूनियन रिकार्ड’ एवं अन्य ट्रेड यूनियन व श्रमिक-पत्रों की फ़ाइलें
- स्थायी आदेश और अथवा उद्योग पर लागू सेवाशर्तें
- प्रमुख श्रम कानून (उनके नवीनतम संशोधनों समेत) एवं मुख्य निर्णय-विधियाँ

काम के वितरण के दौरान कम-से-कम एक पदाधिकारी को जिसमें एक दफ्तर को चलाने की योग्यता है, इंचार्ज बना दिया जाना चाहिए, उसे मजदूरों की सुविधानुसार एक निश्चित समय पर नियमित रूप से दफ्तर में आना चाहिए। उसे एक-दो अन्य व्यक्तियों के साथ स्वयं को प्रतिवेदन की वर्तमान व्यवस्था सहित स्थायी आदेशों और अनुशासन संबंधी कानूनों से परिचित कर लेना चाहिए जिससे चार्जशीटों आदि के जवाब दिये जा सकें।

यूनियन के दफ्तर में आने वाले मजदूरों के साथ सम्मान, सहानुभूति और व्यवहार-कुशलता से बर्ताव किया जाना चाहिए। बातचीत और व्यवहार में न तो रौब का स्वर होना चाहिए, न चिड़चिड़ाहट। मजदूर को विकापित नहीं किया

जाना चाहिए और उसे यह महसूस होना चाहिए कि उसकी बात को गंभीरता-पूर्वक लिया जा रहा है। उसे महसूस होना चाहिए कि यह उसका 'अपना' दृष्टर है, कोई बाह्य संस्थान नहीं।

सरकारी अधिकारियों और प्रबन्धकों को संबोधित पत्र और प्रार्थनापत्र तथ्यों पर आधारित, विषय से संबंधित व तर्कपूर्ण होने चाहिए। वे नम्र किन्तु अत्म-गौरवपूर्ण, दृढ़ मगर उकसाने वाले नहीं, होने चाहिए।

व्यक्तिगत मामलों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और उनकी तह में जाना चाहिए। सामान्य पिछड़ा हुआ मजदूर इस चीज़ को बहुत महत्व देता है एवं स्वयं को असहाय व अप्रसन्न महसूस करता है अगर उसे अनुचित तरीके से किंडक दिया जाए।

कोशों की हिफाजत, सदस्यता शुल्क और लेवी का क्रमिक एकत्रीकरण, वाउचरों द्वारा पुष्ट वैध व्यय एवं नियतकालिक लेखादेय दृष्टरी प्रबन्धन के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। इस संबंध में की गयी गलतियाँ प्रतिष्ठा को चोट पहुँचाती हैं। और कूठों, विवादों के उर्वर स्रोत बन जाती हैं। अगर ज़खरत हो तो लेखाकार द्वारा सहायता प्राप्त कोषाध्यक्ष को इसके लिए उत्तरदायी होना चाहिए। प्रत्येक यूनियन के लिए एक बैंक-एकाउंट आवश्यक है एवं हमेशा संयुक्त संचालन होना चाहिए।

दृष्टर का कार्य संगठित करते हुए, जो अन्य सभी गतिविधियों को चलाने के लिए स्टाफ कार्य का ही एक रूप है, "किसी भी बारीकी की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए अगर उसका मजदूरों के साथ कोई संबंध हो।"

छठा महत्वपूर्ण कार्य गोप्तियों का संचालन करना है।

दृढ़ यूनियन कार्य-प्रणाली में आम सभाएँ, गेट मीटिंग, सामूहिक सभाएँ, शाखा सभाएँ, साक्षात्कार सभा की बैठकें, प्रबंध समिति की बैठकें आदि सम्मलित हैं। प्रत्येक सभा की अपनी विशेषता होती है, अतः प्रत्येक के संचालन का अपना विशिष्ट तरीका है। जहाँ तक संघठन व उपरिषदि, तकनीकी तैयारी व बैठक की विषय-वस्तु का प्रश्न है, प्रत्येक बैठक के लिए सावधानीपूर्वक तैयारी की निरपवाद ज़खरत है।

अगर कोई बैठक समय का सामूहिक दुर्योग सिद्ध होती है, जहाँ केवल जबाती ज्या-खबर होता हो, तो उसका आगामी बैठकों पर भी प्रभाव पड़ता है। रुचि कम हो जाती है, उपरिषदि बढ़ जाती है और काफी संख्या में मजदूर आगामी बैठकों से गायब हो जाते हैं। ज्यादातर सभाएँ इसीलिए प्रभावित करते में असमर्थ रहती हैं क्योंकि मंच उचित प्रकार से नहीं सजाया गया, पर्याप्त मात्रा में अधिम प्रचार नहीं किया गया, लाउडस्पीकर धीमा रहा और परिणामतः शक्ति बरबाद होती है और काफी मात्रा में धन व्यर्थ चला जाता है।

वार्षिक साधारण सभा की बैठकों अथवा प्रतिनिधि सम्मेलनों में निरपवाद रूप से एक लिखित रिपोर्ट तथा चर्चा व अंगीकरण हेतु एक लिखित वक्तव्य का होना आवश्यक है। ये पुनर्विचार, अनुभव के सामान्यीकरण और इस प्रकार सदस्यता के स्तर को बढ़ाने व यूनियन के प्रति अपनी निष्ठा को दृढ़ करने के भौके होते हैं। उन्हें गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए। संपर्क बनाये रखने, वापस रिपोर्ट करने और सदस्यों की रुचि बनाये रखने के लिए समय-समय पर सामान्य कोटि की साधारण बैठकें भी की जाती रहनी चाहिए।

प्रबंध समिति बैठकों की उचित सूचना और एक निश्चित कार्य-सूची होनी चाहिए तथा उन्हें व्यावसायिक तरीके से संचालित किया जाना चाहिए। कार्यवृत्त-पुस्तक में कार्यवृत्त को रखा और निर्णयों को चढ़ाया जाना चाहिए। उपस्थिति को दर्ज करने, अध्यक्ष द्वारा बैठक की शुरुआत की घोषणा करने एवं कार्य-सूची को अंगीकार करने के बाद पहला कार्य पिछली बैठक के कार्यवृत्त को पढ़ना व उसकी पुष्टि करना होना चाहिए जिसके तुरंत बाद पहले लिये गये निर्णयों के कार्यनिवायन और किये गये कार्य के बारे में सचिव की संक्षिप्त रिपोर्ट हो। इसके बाद दूसरी चौजे, उनमें से प्रत्येक पर चर्चा और तदनुरूप निर्णय आते हैं, अगर कहीं वैचारिक मतभेद हों तो एक सामूहिक निर्णय पर पहुँचा जा सकता है। इस पर भी अगर कोई सदस्य अपनी बात पर ज़ोर देता है तो मतदान कराया जा सकता है और बहुमत द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का दायित्व है कि वे देखें कि चर्चा भले ही गर्म क्यों न हो, वह कहा-मुनी में न बदल जाये। मुख्य बात है, दूसरे के विचारों को सुनना, चाहे कोई उससे पूर्णतः असहमत क्यों न हो।

सातवाँ महत्वपूर्ण पहलू नेताओं के निजी व्यवहार से संबंधित है। यह नैतिक उपदेशों के समूह सदृश दिखायी पड़ सकता है। मगर एक ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता को अपने दैनिक कार्यों में व्यवहार के कुछ निश्चित मानदंडों, एक आचार-संहिता का पालन करना चाहिए।

६ आम जनता के साथ वह विनीत और धैर्यशील हो, न कि नौकरशाह और 'दंभी'। अबखड़पन, अहम्मन्यता, धोखेबाजी, व्यक्तिगत आत्म-प्रदर्शन और आम जनता के प्रति एक कृपाकारी प्रवृत्ति उन्हें केवल विर्किषित करती है। उसे प्रत्येक व्यक्ति के प्रति एक सुसंकृत व्यवहार करना चाहिए, यहाँ तक कि समझौते और वार्ता की मेज पर 'कुपमन' के साथ बातचीत करते हुए उसे नम्र और गौरवपूर्ण, किन्तु अपनी पहुँच में धारदार व दृढ़ होना चाहिए। अभद्रता वर्ग-संघर्ष का गुण नहीं है। गेट मीटिंगों में वह, जहाँ भी ज़रूरी हो, मजाक, कटाक्ष और समुचित क्रोध के हथियार का प्रयोग कर सकता है, मगर भद्री गालियों का नहीं जोकि दुर्भाग्य-वश कुछ वक्ताओं के साथ आम बात है।

६ उसे दूसरी यूनियन के सक्रिय कार्यकर्ताओं और मजदूरों के प्रति संकीर्णता-

वादी व कटाक्षपूर्ण व्यवहार से बचना चाहिए। कभी-कभी तीखी आलोचना जाहरी हो सकती है, मगर आदर और समानता की प्रवृत्ति बनी रहनी चाहिए। जब कभी आवश्यक हो जाये, विरोधी युनियनों की आलोचना व आकमण एवं शत्रुतापूर्ण विषयकारी कार्रवाइयों का धारदार व प्रभावशाली हंग से उत्तर देना चाहिए, तेकिन प्रतिशोध के लिए उचित नहीं होना चाहिए। आखिरकार द्वितीयनएकता और इन युनियनों के साथ संयुक्त कार्रवाई हमारा लक्ष्य है।

उसे किसी भी तरह के सांप्रदायिक, जातिवादी अथवा उपराष्ट्रवादी व्यवहार के विरुद्ध सन्तुष्ट रहना चाहिए, तथा अपने आपसमें इन्हें विकासित होने से रोकना चाहिए।

इन मजहूरों की भाषा और रीति-रिवाजों की कम-से-कम एक कामचलाऊ जानकारी प्राप्त करने का उसे प्रयास करना चाहिए जिनके बाब उसे काम करना है। असंगठित, पिछड़े हुए और जनजातीय मजहूरों के प्रति उसे विशेष रूप से लिहाज करना चाहिए जिससे उन्हें ‘हैर दूषित से देखते’ का आरोप उन पर न लगे।

उसे नियमितता एवं सम्यकता की आदत विकासित करनी चाहिए।

साथीयों और सामान्य सदस्यों से अपनी आलोचना सुनने की आदत उसे उल लेनी चाहिए और आगामी कार्यों के दौरान उनका ध्यान रखना चाहिए।

द्वितीयनएकता कार्यकर्ता का प्रतिमान न तो गोरवालित द्वितीयनबॉस’ है, न ही कोई जनोत्तेजक जो मजहूरों के पिछड़ेपन के साथ खिलवाड़ करता है तथा उनकी मूल वृत्तियों को उकसाता है, बल्कि एक ऐसा जननेता है जो कूरता व अन्याय की प्रतीक अधिक्यक्षित के विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, जो आम जनता की भावनाओं और मनोदशा के प्रति संवेदनशील है, दमनकर्ताओं और शोषकों के विरुद्ध संघर्ष में उन्हें लामबंद कर सकता है और उन्हें आगे का मार्ग दिखाता है।

ट्रेड यूनियन कार्य-प्रणाली (जारी)

पिछले पाठ में हमने कार्य-प्रणाली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य-भारों की चर्चा की थी। अब हम ट्रेड यूनियन कार्य-प्रणाली की अंतर्बस्तु पर विचार करेंगे।

ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता को अपने उद्योग के बारे में जानना चाहिए। तभी वह अपने व्यवसाय व उद्योग से संबंधित मजदूरी, काम की दरों, कार्य के बोझ एवं आधुनिकीकरण की योजनाओं आदि की समस्याओं को समझ सकता है। उद्योग में मजदूर ही सर्वोत्कृष्ट शिक्षक होता है और कार्यकर्ता को बेहचक उससे सीखना चाहिए। यह सिफ्ट 'बाहरी व्यक्ति' पर ही लागू नहीं होता बल्कि एक कर्मचारी कार्यकर्ता पर भी लागू होता है क्योंकि शुरुआत में प्रत्येक कर्मचारी केवल अपने ही विशिष्ट कार्य को जानता है, न कि संपूर्ण उद्योग को।

अगली चीज अपने उद्योग से संबंधित श्रम कानूनों के कम-से-कम मूल तत्वों, स्थायी आदेशों आदि की जानकारी प्राप्त करना है। कानूनों और स्थायी आदेशों के सभी प्रावधानों की, जो मजदूरों के हित में हैं, लागू व प्रयुक्त किया जाना चाहिए। सिवा उन जगहों के जहाँ वास्तविक रूप से कच्चहरी में पेशी की ज़बरत हो, इन सब चीजों को 'वकीलों के हवाले कर देने की' प्रवृत्ति नहीं पायी जानी चाहिए। उसे ज्ञात होना चाहिए कि कौन से कानून मजदूरों के खिलाफ़ हैं और किनके खिलाफ़ संघर्ष किया जाता है।

ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता को अपने उद्योग के अर्थसामूहिक, विकास के तरीके, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एवं सरकार द्वारा चलायी जा रही आर्थिक नीतियों की मूल-भूत जानकारी होनी चाहिए। इसके बिना उसे माँग और पूर्ति, कीमतों, उसके द्वारा उपाधित वस्तु के बाजार, अपने उद्योग में लाभ अथवा हानि, सामाज्य अर्थ-व्यवस्था में उस उद्योग के स्थान, उसके विशिष्ट व्यवसाय में व कुल मिलाकर पूरे देश में चलायी जा रही आर्थिक नीतियों के प्रभाव की जानकारी नहीं हो सकती। इसके बिना वह मुद्रा-प्रसार व बढ़ती हुई कीमतों, बजट करारोपण व बाटे, पूँजी-पतियों को दी गयी वियायतों व गरीबों पर पड़ते। अतिरिक्त बोझ, अंतर्राष्ट्रीय

व्यापार और भुगतान संतुलन, विदेशी ऋणों और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से सहयोग आदि की प्रक्रिया नहीं समझ सकता। जब तक उसे इन चीजों की जानकारी न हो, वह अपने व्यवसाय अथवा उद्योग के आम मजदूरों को न तो शिक्षित कर सकता है और न उनके विश्वासों को दृढ़ बना सकता है, न ही अपने क्षेत्र के संघर्ष को आज अपनायी जा रही सामान्य आर्थिक नीतियों के विरुद्ध संघर्ष से जोड़ सकता है।

ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता को स्वयं को वर्गीय दृष्टिकोण से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से परिचित कराना चाहिए। इसके बिना वह आर्थिक संघर्ष को राजनीतिक संघर्ष से, बेहतर जीवन के लिए संघर्ष को शांति, निःशस्त्रीकरण व परमाणुमुक्त विश्व एवं सांप्रदायिक एकता व राष्ट्रीय अखंडता आदि के लिए संघर्ष से नहीं जोड़ सकता, जोकि ऐसे महत्वपूर्ण कार्यभार हैं जिनसे वह वर्तमान में जूझ रहा है। इसके बिना, वह मजदूरों की वर्ग-चेतना का स्तर ऊपर नहीं उठा सकता।

उसे ट्रेड यूनियन आंदोलन के इतिहास व अपने विशेष दायरे में विशिष्ट संघर्षों और उपलब्धियों के बारे में थोड़ी-बहुत जानकारी होनी चाहिए जिससे वह न सिफ़ अतीत के अनुभवों से सबक ले सके बल्कि मजदूरों को प्रेरित करने, उनमें संघर्षों और त्याग के जरिये विजय हासिल करने की भावना भरने एवं एक बेहतर भविष्य के लिए एक वर्ग के रूप में संघर्ष करने में समर्थ हो सके।

यह हमें विशेष व्यवसाय अथवा उद्योग के लिए यूनियन द्वारा माँगों के सूत्रीकरण के सवाल से रूबरू कराता है।

- (i) माँगें स्थितियों की वास्तविकताओं से उत्पन्न होनी चाहिए। जिसके नाम पर माँगों का सूत्रीकरण होना है, वह व्यक्ति मजदूर है। अतः सामान्य बुद्धि की माँग है कि मजदूरों से सर्वप्रथम सलाह की जानी चाहिए। केवल तभी ज्ञात हो सकता है कि कौन-सी चीज़ मजदूरों को आंदोलित कर रही है। मजदूर के मूड़ को भाँपना आवश्यक है, वह मनःस्थिति जो परिस्थिति की निचोड़ है व मजदूरों की तत्परता की सीमा को निर्धारित करती है।
- (ii) यह सोचना कि माँगों को 'नेताओं' की आकँक्षाओं अथवा अन्य बाहरी दबावों पर आधारित किया जा सकता है, पूरी तरह से व्यक्तिवाद व नौकरशाहीवाद है।
- (iii) कभी-कभी ऐसी माँगें भी पेश की जाती हैं जिनके बारे में स्वयं मजदूर सोचते हैं कि उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। कभी-कभी पुरानी माँगें भी यांत्रिक रूप से दोहरायी जाती हैं यद्यपि परिस्थिति बदल चुकी होती हैं और वे पुरानी पड़गयी होती हैं। कभी-कभी प्रतिष्ठा की झूठी धारणाओं के तहत अथवा 'प्रतियोगी अर्थवाद' के तहत माँगें रख दी जाती हैं। कभी-कभी पूर्व अतिशयोक्तिपूर्ण माँगों, जो बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गयी थीं और

असफल सावित हुई, के प्रतिक्रियास्वरूप उन्हें छोड़ दिया जाता है, माँगों को सूचबद्ध करते हुए इन चीजों के विरुद्ध सुरक्षा करनी होती है।

- (iv) यह देखना ज़रूरी है कि सूचबद्ध माँगें आम जनता में उत्साह जाग्रत कर सकें और इस प्रकार जन-कारवाई प्रवर्तित कर सकें। इसका अर्थ है कि माँगें सभी तबकों और श्रेणियों को समाहित करती हों और इस प्रकार की हीं जो उनमें से सर्वाधिक पिछड़े लोगों सहित सभी के लिए बोधगम्य व स्वीकार्य हों।
- (v) यह धारणा त्याग दी जानी चाहिए कि 'माँग-पत्र' जितना लंबा और वजनदार होगा, उतना अच्छा होगा। माँग-पत्र कितना ही बड़ा और प्रभावशाली क्यों न हो, जब तक मज़दूर उसे व्यवहार में न लायें, वह कागज़ पर ही बना रहेगा। केवल वही माँग-पत्र प्रभावपूर्ण होगा जिसे आम मज़दूर याद रख सकें, दोहरा सकें तथा उसे अपना समझें। अतः माँग-पत्र को सभी मज़दूरों के लिए अभीर, तथ्यपूर्ण व बोधगम्य होना चाहिए।
- (vi) इन दिनों संगठित क्षेत्र में माँगों के सूचीकरण को उसी अथवा अनेक एक जैसे व संबद्ध उद्योगों में मज़दूरों द्वारा सामान्य सहयोगी कारवाइयों हेतु माँग-पत्र के स्तर तक उठाया गया है। इसके लिए उसी अथवा संबद्ध उद्योगों में अन्य यूनियनों के साथ व्यापक सलाह-मणिविरा आवश्यक है।
- (vii) इससे पूर्व कि माँग-पत्र को अंतिम रूप दिया जाये और पेश किया जाये, मज़दूरों के विभिन्न स्तरों द्वारा इस पर व्यापक रूप से चर्चा की जानी चाहिए एवं प्रबंधक समिति व साधारण सभा द्वारा इसे अंगीकृत किया जाना चाहिए।
- (viii) विभिन्न तरीकों को अपनाते हुए आम मज़दूरों के बीच एक प्रचार-अभियान तुरंत छेड़ा जाना चाहिए जिससे कि माँग-पत्र को आवश्यक जन-समर्थन प्राप्त हो सके।

माँग-पत्र के पेश करने और प्रबंधकों को इसका नोटिस लेने के लिए बाध्य करने के बाद (यह केवल तभी संभव है जबकि आम जनता को इसके पीछे एकजुट कर दिया गया हो), मज़दूरों को समय-समय पर होने वाली प्रगति से अवगत कराते रहना चाहिए। यहाँ सत्य एवं तथ्यपूर्ण वक्तव्य चालबाजी और शब्दाङ्कबर की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली सिद्ध होते हैं। जहाँ कहीं नियोक्ताओं के कुछ तर्क, या फिर दूसरी यूनियनों द्वारा लिये गये क़दम से संदेह उत्पन्न हो गये हों, उनका तथ्यों व तर्कों द्वारा प्रत्युत्तर दिया जाना चाहिए; और अगर कोई संशोधन आवश्यक समझा जाये तो मज़दूरों के समक्ष इसकी विवेचना की जानी चाहिए। इन सभी चरणों से होकर, माँगों के सूचीकरण से लेकर पेश किये जाने और वार्ता होने

तक मज़दूरों के बीच वर्गीय आत्म-विश्वास की भावना जीवित बनाये रखी जानी चाहिए।

मज़दूर वर्ग आंदोलन के महानतम सिद्धांतकार मार्क्स ने स्वयं ट्रेड यूनियन व्यवहार, मज़दूरों की वास्तविक स्थिति के विस्तृत अध्ययन पर आधारित मज़दूर वर्ग की आर्थिक व राजनीतिक माँगों के सूत्रीकरण का एक मॉडल प्रस्तुत किया है। 1886 में उन्होंने जाँच की एक सामान्य तालिका बनायी, जिसमें मज़दूरी से संबंधित सवाल—उनकी किस्में और दरें, व्यवसाय, रोजगार प्राप्त लोगों की आयु व लिंग, शिक्षार्थन, काम के धंटे, कार्यस्थलों की परिस्थितियों, भौतिक परिस्थिति पर रोजगार का प्रभाव, शिक्षा एवं नैतिक परिस्थिति, आदि-आदि शामिल किये गये हैं। 1880 में फिर से अपनी प्रसिद्ध रचना 'मज़दूरों के लिए प्रश्नावली' में, जिसमें चार भागों में 100 प्रश्न सम्मिलित हैं, वह इस तरह की जाँच की आवश्यकता पर लौटे हैं। जैसाकि एंगेल्स ने लिखा है, "मज़दूर वर्ग की दशा ही आज सभी सामाजिक आंदोलनों का आरंभिक बिंदु है।" यह कथन सूत्रीकृत माँगों पर संघर्ष के प्रत्येक आगामी चरण समेत आंदोलन के प्रत्येक चरण पर लागू होता है।

इस सन्दर्भ में, संघर्ष का प्रश्न और इस प्रकार संघर्षों के रूपों का प्रश्न मुख्य मुद्दा बन जाता है।

मज़दूर वर्ग आंदोलन की इसी प्रतिभा ने संघर्ष के विभिन्न रूपों की खोज की है जो ऐतिहासिक अनुभव, राष्ट्रीय परम्पराओं, विशिष्ट परिस्थितियों, मज़दूरों की चेतना के स्तर, उनकी मनोदशा, शत्रु के रूख व व्यवहार आदि पर निर्भर करते हैं। हमेशा नये-नये रूप खोजे जाते रहे हैं और आंदोलन के भंडार में एकत्र होते रहे हैं। अतः, ट्रेड यूनियनें कुछ परम्परागत व अप्रचलित रूपों—किन्हीं सर्वस्वीकृत रूपों अथवा रूपों की किन्हीं श्रेणियों से नहीं बँधी हैं जो एक नियम के तहत एक के बाद एक आते रहते हैं।

पहली चीज़, जो नोट करने की है, वह यह है कि ट्रेड यूनियनें मज़दूरों के संगठन का एक रूप नहीं हैं, बल्कि 'संघर्ष का एक अंग' हैं। संघर्ष के अलावा किसी अन्य तरीके से वे स्वयं को वर्ग संगठनों के रूप में नहीं बनाये रख सकतीं। ऐसे दिन हो सकते हैं, जबकि मज़दूरों के समूह सङ्क के बीच कंधे से कंधा जोड़े मार्च करते हुए, उड़ती हुई पताकाओं और कसी हुई मुट्ठियों के साथ वर्ग शत्रु के खिलाफ बहादुरीपूर्वक आगे बढ़ रहे हों। दूसरी ओर ऐसे दिन भी हो सकते हैं जबकि वे अकेले अथवा समूहों में छायादार फुटपाथों और गलियों में सिर्फ़ टहलकदमी करते फिर रहे हों। लेकिन सन्नाटे का लम्बा समय आगामी दिनों के टकराव की तैयारी भी है। यहाँ कोई ठहरा हुआ तालाब नहीं है बल्कि बहता हुआ प्रवाह है—कभी शांति से बहता हुआ, कभी उफनता और उग्र रूप से निकलकर आगे बहता हुआ। प्रमुख

चीज़ आंदोलन की अप्रगतिमात्रा है—वेग, रफ्तार और रूप गौण हैं।

संघर्ष स्वतःस्फूर्ति हो सकते हैं या पिर योजनाबद्ध पहलकरदारी के एक इस्से के रूप में उन्हें छोड़ा जा सकता है। मगर स्वतःस्फूर्ति संघर्ष भी कोई आकस्मिक घटना नहीं है। जैसाकि लेनिन ने कहा है, “अपने सार में यह श्रृंखलीय अवस्था में जैतना का—न इससे ज्यादा, न इससे कम—प्रतिनिधित्व करता है।” जैतना की स्वतःस्फूर्ति ता यानी मजदूरों के स्वतःस्फूर्ति उभार ट्रैड यूनियन नेतृत्व द्वारा दक्षता-पूर्वक हस्तक्षेप की मांग करते हैं, जिससे कि इन्हें दिशा दी जा सके और इन्हें सफल परिणाम तक ले जाया जा सके। ऐसे अवसरों पर नेतृत्व की महत जिम्मेदारी होती है, कम नहीं। मगर ऐसी स्थितियों से निपटने की सामाच्य अनिच्छुकता, ‘असंगठित जनता’ एवं कुछकर दिखाने की इसकी तप्तपता अथवा ‘संगठित जनता’ के कारबाई करने के मुड़ की कम करके आँकड़ा हमारा साझा दुर्भाग्य रहता है।

किसी दिये हुए समय पर संघर्ष का सर्वश्रेष्ठ रूप वह होता है जो जनता के व्यापकतम सम्भावित तबकों को संगठित कर सकें और उन्हें स्वीकार्य हो। संघर्ष का यही रूप आगामी कारबाई की श्रीमिता बनता है। ट्रैड यूनियन आंदोलन की धारणा वह नहीं है जो कुछ नेताओं के दिमाग में है, बल्कि वह है जो मजदूरों के व्यापक समूह की जैतना में विद्यत है, जिन्हें संघर्ष के लिए तैयार किया गया है। क्या संघर्ष के उच्चतर स्तर के बाद निम्न स्तर आ सकता है? क्या किसी संघर्ष को एक रूप से अगले उच्चतर रूप की ओर उन्मुख नहीं होता चाहिए? उत्तर है, यह आंदोलन की ज़रूरतों से निर्धारित होगा, न कि किसी गणितीय क्रम से। आंदोलन का प्रत्येक वास्तविक चरण, प्रत्येक रूप—चाहे पूर्ववर्ती हो अथवा अनुवर्ती—मजदूरों की अधिकतम सम्भव संख्या के समर्थन व सहयोग पर निर्भर करता है। सिफ़े कुछ ही लोगों की मंच-संचालित कारवाई, जो जनसमर्थन पर आधारित नहीं होती, दर्यनीय और महँगी विफलता में परिणत हो सकती है। ट्रैड यूनियन कार्यकर्ता को न तो जनसमूह से आगे-आगे भागना चाहिए, न ही पीछे रहना चाहिए। वह यह चीज़ केवल अनुभव और अध्ययन से एवं जन-समूहों के निकट संपर्क से ही सीख सकता है। कभी-कभी उसे अनुभवहीन व्यक्तियों को नियंत्रित करना होता है और कभी सही कारबाई हेतु प्रेरित करना होता है।

वर्ग-संघर्ष के एक हथियार और प्रकार के रूप में हड़ताल के साथा पर इस दृष्टि से विचार करना होगा। हम हड़ताल के बेरोक अधिकार के पक्ष में स्पष्टतः इसलिए हैं क्योंकि हम इसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली हथियार मानते हैं। इसलिए इसका उपयोग उचित समय पर उचित तरीके से किया जाना चाहिए। हमारे देश में दो यूनियन आंदोलन (एक दिवसीय हड़ताल) (एक तरह की दृढ़ संकल्प की जैतावनी), ‘विरोध हड़ताल’, ‘एकता हड़ताल’, ‘सीमित अवधि की हड़ताल’ (कुछ

धंटे अथवा कुछ दिन), 'अनिश्चितकालीन हड्डताल', 'राजनीतिक हड्डताल', 'औद्योगिक हड्डताल' और अंततः 'बन्द'—यानी सभी उद्योगों, व्यवसायों व अन्य गतिविधियों का पूर्णतः रुक जाना, जिसमें मज़दूर वर्ग विशेष मुद्दों पर लोगों के दूसरे तबक्कों को कार्रवाई के लिए प्रेरित करता है, के विभिन्न प्रकारों में पारंगत हो चुका है। ऐसे 'बन्द' स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्यस्तरीय अथवा अखिल भारतीय हो सकते हैं।

हड्डताल का जो भी स्वरूप हो, इसकी अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए, व ठीक प्रकार से संगठित करना चाहिए, तथा इसे किसी व्यवसाय के मज़दूरों की सामान्य एकता, उनके नैतिक व वस्तुगत समर्थन पर निर्भर करना चाहिए। एक हड्डताल को यदि सक्रिय समर्थन नहीं तो कम-से-कम चारों तरफ लोगों का निष्क्रिय समर्थन तो मिलना ही चाहिए, खासतौर से जहाँ सार्वजनिक उपयोगिता अथवा सेवा उद्योग से ताल्लुक है। ऐसी परिस्थितियों में यह उक्ति, 'हम मछलियों की तरह हैं और लोग पानी की तरह' पूर्णतया चरितार्थ होती है। मज़दूर वर्ग आम जनता का हिरावल दस्ता नहीं होता जबकि इसकी गतिविधियाँ सहानुभूति के बजाय शत्रुता भड़काती होती हैं और जब वह आम जनता के विरोध में जा रहा होता है।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मज़दूरों की माँगों की तर्कसंगति, नियोक्ताओं और सरकार के खल, हड्डताल की अपरिहायता और इसकी प्रगति बैठकों, प्रेस (जो पूर्ण सत्य ज्ञाहिर कर भी सकता है और नहीं भी) एवं प्रसिद्धि व प्रचार के अन्य माध्यमों द्वारा पूर्ण रूप से प्रचारित किये जाने चाहिए। सक्रिय एवं नियोजित रूप में लोगों का समर्थन प्राप्त किया जाना चाहिए।

हड्डताल के सन्दर्भ में क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए ?

- हड्डताल का आद्वान करने से पूर्व समझौते के सभी रास्तों की छानबीन करो।
- हड्डताली कार्रवाई हेतु मज़दूरों की तत्परता एवं इच्छा पूरी तरह से व गम्भीरतापूर्वक सुनिश्चित करो। (हड्डताल के लिए मतदान सामान्यतः एक औपचारिक तरीका है, अतः ऐसा करने के लिए यह आवश्यक रूप से सर्वोत्कृष्ट तरीका नहीं है)
- एक बार हड्डताल छेड़ दिये जाने पर (अगर यह अनिश्चितकालीन हड्डताल है) दृढ़ता के साथ आगे बढ़ो और तोड़फोड़, नियोक्ताओं के गुंडों व पुलिस के दमन से इसकी रक्षा करो।
- योजनाबद्ध रूप से मज़दूरों के अन्य तबक्कों एवं लोगों का समर्थन व एकता हासिल करो। इस उद्देश्य हेतु एकता समितियाँ कारगर साबित हो सकती हैं।

- उचित प्रचार-प्रसार का इन्तजाम करो ।
 - हड़ताल के दौरान मजदूरों के समूहों को संगठित रखो । यहाँ तक कि अगर कुछ मजदूर लम्बी हड़ताल के दौरान अपने गाँवों को वापस चले भी जाएँ, तो भी उनसे सम्पर्क रखो । इसके लिए उचित तरीकों को कार्यान्वित करो । हड़ताल का प्रयोग मजदूरों के समूहों को वर्ग-चेतना की शिक्षा देने व उनके संघर्ष के सामान्य वर्ग-संघर्ष के साथ संबंध को समझाने के लिए करो ।
 - अगर हड़ताल लम्बी खिच जाये अथवा ऐसा होने की गुंजाइश हो तो उस स्थिति में राहत का इन्तजाम करो । (यह मनोबल बनाये रखने के लिए ज़रूरी है, भले ही वास्तविक उद्देश्यों के लिए यह अपर्याप्त हो) ।
 - उचित अवसर आने पर वार्ताओं के लिए तैयार रहो ।
- 'क्या नहीं करना चाहिए'** के संबंध में:
- मजदूरों की मनोदशा और आकॉक्शनों को जाने वाले हड़ताल मत शुरू करो ।
 - जब वार्ताएँ असफल हो जाएँ या फिर नियोक्ता वार्ता करने से इन्कार कर दें और जब मजदूर इसकी आवश्यकता पर सहमत हों, हड़ताल प्रारम्भ करने से मत हिचको ।
 - पूर्ण प्रतिबन्ध की स्थिति को छोड़कर, जबकि हड़ताल को किसी तरह गैर-क्रानूनी घोषित कर दिया गया हो, कुछ अनिवार्य क्रानूनी प्रक्रियाओं का जान-बूझकर उल्लंघन मत करो ।
 - जबकि स्थिति की माँग हो, वार्ताओं अथवा मध्यस्थिता प्रयासों के लिए दरवाजे बन्द मत करो ।
 - कोई ऐसा कार्य मत करो जो तुम्हें जनता की सहानुभूति से वंचित कर दे ।
 - यद्यपि हड़ताल के दिन-प्रतिदिन के आचरण की क्रीमत पर नहीं, सभी प्रमुख काड़ों को बेनकाब मत करो ।
 - और अंत में, जब मजदूरों की मनोदशा पीछे हटने की हो, तो मनोबल और संगठन, जितना सम्भव हो, अक्षुण्ण बनाये रखते हुए क्रमबद्ध रूप से हड़ताल वापस लेने में मत छिपको । दूसरी तरफ, आतंकित मत होओ और दमन व हार की सम्भावना से डरकर हड़ताल वापस मत लो । वास्तविक वापसी से पूर्व सभी तथ्यों को सामने रखते हुए आम मजदूरों से विचार-विमर्श किया जाना चाहिए । जहाँ विभिन्न केन्द्रों में मजदूर विभाजित हों, वहाँ जनवादी रूप से निर्वाचित कार्यकारिणी या सलाहकार समिति से अनिवार्य रूप से सलाह ली जानी चाहिए¹ ।

इन दिनों बहुत-सी हड्डाले संयुक्त रूप से की जा रही हैं, जिनमें बहुत-सी गुनियन शामिल हैं। ऐसे मामलों में हड्डाल के संचालन के लिए संयुक्त समितियाँ बनानी होंगी और हमें यह देखने में पहल करनी होगी कि ये समितियाँ सर्वसम्मति के आधार पर नियमित रूप से कार्य कर सकें।

यद्यपि ग्रनियन कार्यकारिणी न शाखा समितियाँ पहले से ही मौजूद हैं, यह गुनियन शामिल है। ऐसे मामलों में हड्डाल के संचालन के लिए संयुक्त समितियाँ बनानी होंगी और हमें यह देखने में पहल करनी होगी कि ये समितियाँ सर्वसम्मति

कोई भी हड्डाल अपने आप में अंतिम व निर्णायक संघर्ष नहीं होती। संगठित पूँजी के खिलाफ लम्बे संघर्ष में यह एक प्रकार की मुठभेड़ है। यह 'युद्ध' की पाठ-शाला है। अतः हड्डाल का एक अंत होता है जैसे इसकी एक युरुआत होती है और अंत कमोबेश एक पूर्ण विजय, एक समझौता, यहीं तक कि एक खिलायत वापसी होता है। आधिकारिक दृष्टिन के साथ लगातार और लम्बी लड़ाई के बाद किसी सेना की सर्वाधिक विशिष्ट रेजिमेंट भी थकान का प्रभाव अनुभव कर सकती है और उसे उद्धसेन से क्रमिक रूप से हटाना पड़ सकता है। अन्यथा, परिणाम तुक्सानदायक हो सकते हैं। हमारे पास बम्बाई के दो लाख कपड़ा मजदूरों का जदाहरण मौजूद है, जो 1982-83 के दौरान डेढ़ वर्ष से ज्यादा समय हड्डाल पर रहे। यह एक अस्तरपर्व एवं दीरोधित हड्डाल थी। मगर नेतृत्व द्वारा समझौते और क्रमबद्ध वापसी के अवसरों का तिरसकार किया गया। परिणाम हुआ कि हड्डाल व्यक्ति रूप से टूट गयी और भयंकर दमन हुआ, जिसके प्रभाव अभी भी जारी है। दूसरी ओर, फ्रेस के डेढ़ लाख से ज्यादा खान-मजदूरों द्वारा एक वर्ष लम्बी हड्डाल हुई, जिन्होंने अपनी हड्डाल एक संगठित रूप में वापसी ली एवं बैठ बजाते हुए व फ़फ़ड़ती पताकाओं के साथ अपने परिवारों की मुख्खा में वे काम पर वापस लौट आये। मगर सर्वाधिक कड़वे धनके व रक्तरंजित पराजयों का भी एक सकारात्मक पक्ष होता है, अगर मज़दूर तथा नेतृत्व उनसे सबक हासिल करें और उनका पालन किया जाए।

हड्डाल के दौरान एकजुटता की कार्रवाई हमारे क्रियाकलाप का सबसे कम-जोर व उपेक्षित पक्ष रहा है। कई बार एकजुटता की अभिव्यक्ति के लिए पड़ोसी की फ़ैक्टरी के मज़दूरों तक से सम्पर्क नहीं किया जाता। उन औद्योगिक कर्त्त्वों में, जहाँ देहाती बातावरण मौजूद है, किसानों से सम्पर्क नहीं किया जाता। हमें यह देखना है कि यह एकजुटता की कार्रवाई ही मज़दूरों की क्रातिकारी चेतना को रूपांतरित करती है। अपने समय में, हड्डाली कार्रवाईयों के दौरान मालसंको हमेशा 'हड्डालियों' की विधावाओं, पतियों और बच्चों को हल्का करने के लिए धन संग्रहीत करने के लिए अपील करने का मौका मिला। यही चीज़ है, जो मज़दूरों को एक वर्ग के रूप में सोचने और कार्य करने को बाध्य करती है।

टिप्पणी :

1. नेतृत्व के कुछ हिस्सों में इस न्यूनतम जनवादी सिद्धांत को अनदेखा करने की प्रवृत्ति पायी जाती है जब कोई समझौता हो चुका हो और हड़ताल, जिसमें हजारों लोग शामिल हों, बापस ले ली गयी हो। यह प्रवृत्ति कि जनता सब समझती है, कर्मचारियों के उद्देश्य और उनके संगठन दोनों के लिए अनपेक्षित एवं अप्रिय परिणामों को जन्म देती है। हाल में ही कॉलिज अध्यापकों की हड़ताल का टूटना इस संदर्भ में एक ताजा उदाहरण है।

सामूहिक कार्य और सामूहिक लामबंदी

जनता की भागीदारी वास्तविक ट्रेड यूनियन जनवाद का आधार है, सामूहिक लामबंदी ट्रेड यूनियन संघर्षों का सार है।

अतः हमें 'मजदूर वर्ग तक अपनी आवाज पहुँचाने' के लिए हरसम्भव प्रयास करना चाहिए। 'जनता के बीच में' हमारा एकजुटता का नारा होना चाहिए। और उनके साथ हजारों तरीकों से संबंध स्थापित करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को हाथ में लेना एवं प्रत्येक प्रकार के मजदूर संगठनों जैसे, ट्रेड यूनियनों, सहकारी समितियों, महिला व नौजवान संगठनों, खेल व सांस्कृतिक संघों और समूहों आदि को विकसित व मजबूत करना होगा।

पिछले तीन दशकों के दौरान हमने मजदूर वर्ग में आने वाले परिवर्तनों को देखा है। विशेषकर सार्वजनिक व इजारेदार क्षेत्रों में औद्योगिक विस्तार एवं आधुनिक जटिल उद्योगों की वृद्धि ने समाज के सर्वाधिक अलग-अलग तबक्कों और भिन्न-भिन्न पृष्ठभूमियों से आये मजदूरों की क़तारों में 'नये रंगरूटों' की भयंकर बाढ़ लादी है। नया मजदूर अधिक शिक्षित व बेहतर व्यावसायिक दक्षता लिये हुए है। विशेषज्ञों और तकनीकी अहंता प्राप्त मजदूरों का अनुपात ज्यादा है। गैर-तकनीकी तबक्कों में भी हमारे पास व्यापार, लेखाकर्म, घंडारण और विपणन आदि क्षेत्रों में अहंता प्राप्त लोग मौजूद हैं।

आंदोलन के समग्र तत्वों के रूप में उन्हें आर्कषित करने के लिए ट्रेड यूनियनों को उनके प्रति एक विशेष दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा।

कुल मिलाकर अधिकांश उद्योगों में मजदूरों का शैक्षिक स्तर उन्नत हुआ है। यह एक लाभ है क्योंकि इससे शिक्षित मजदूर की प्रकाशित साहित्य तक पहुँच आसान हो जाती है और उसकी समझने की शक्ति तीक्ष्ण होती है। लेकिन दूसरी ओर, चीजों को समझने और तथ्यों व तर्कों से क्रायल होने की उसकी प्राकृतिक अपेक्षा भी होती है। मात्र नारों से ही उसकी उदर-पूर्ति नहीं हो सकती व निर्देशित नहीं किया जा सकता।

यही नहीं, 'मध्यवर्गीय कर्मचारियों' के विशाल तबके, अध्यापक; इंजीनियर, अराजपत्रित अधिकारी, कनिष्ठ डॉक्टर आदि भी ट्रेड यूनियनों की जुझारु क़तारों में शामिल हो गये हैं।

दूसरे सिरे पर असंगठित उद्योगों एवं विकेन्द्रित क्षेत्र में मजदूरों का समूह है। इसके अतिरिक्त दक्ष एवं अतिदक्ष तकनीशियनों के अल्पसंख्यक वर्ग से लेकर खदानों में लगे हुए, पत्थर तोड़ते हुए, जमीन खोदते हुए, भूमि साफ़ और समतल करते हुए, बोझा ढोते हुए अदक्ष मजदूरों के विशाल समूह तक निर्माण मजदूरों की एक बड़ी संख्या है। वे या तो बड़ी निर्माण फर्मों अथवा हजारों ठेकेदारों की वंश-परंपरा की चाकरी में हैं। कैम्पों में रहने वाले ये परियोजना मजदूर सबसे बुरी तरह शोषितों में से हैं। समस्या है, इस समूह तक पहुँच पाना, इस पर स्थायी रूप से पकड़ बनाना और इसके जुझारूपन व शक्ति को संगठन तथा संघर्ष के लिए उपयोग में लाना।

अतः, एक ही समय पर ट्रेड यूनियन आंदोलन को 'प्रबुद्ध वर्ग' से लेकर सर्वाधिक पिछड़े हुए ठेका मजदूर, जनजातीय अथवा देहाती मजदूर तक—एकदम भिन्न किस्मों के 'नये मजदूर' को सम्भालना व लामबंद करना होता है। ऐसा कर पाने में असफलता ऐसे 'दुस्साहसियों' और 'जनोत्तेजकों' को जन्म देने के लिए उवंरा भूमि का सृजन करती है जो उहें रास्ते से विमुख कर देते हैं।

नौजवान मजदूरों की अपनी इच्छाएँ व आकंक्षाएँ एवं भाँति-भाँति के स्वार्थ होते हैं। इन नौजवानों से सम्पर्क करने के लिए और आंदोलन के साथ उनके संबंधों को और मजबूत करने के लिए ट्रेड यूनियनों को साधनों और विधियों को खोजना होगा। आज, सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधियाँ हमारे ट्रेड यूनियन कार्य का मामूली हिस्सा बनकर रह गयी हैं।

रोजगार में लगे हुए नौजवान मजदूरों के अतिरिक्त हजारों ऐसे भी हैं जो बेरोजगार हैं। कुछ लोग, जो रोजगार पा चुके हैं और उन लोगों के बीच, जो रह गये हैं, एक सहानुभूति का बन्धन पाया जाता है। उदाहरण के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षित लड़कों, शिक्षार्थी प्रणाली के अंतर्गत लड़कों, 'बड़ली मजदूरों', काम के लिए एवं कुछ ही वर्षों के भीतर परियोजनाओं के शुरू होने की उम्मीद में इन स्थानों पर तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों को स्थापित करने की माँग करते हुए इन परियोजना स्थलों पर भूमि-प्रभावित नौजवानों तथा तालाबन्दी व छँटनी से प्रभावित मजदूरों की विशिष्ट समस्याएँ हैं। ट्रेड यूनियनों, रोजगारशुदा नौजवान मजदूरों का, साथ ही उनका, जो गेट पर खड़े होकर काम माँग रहे हैं, ध्यान रखना होगा अन्यथा या तो वे अतिदक्षिणवादी अथवा अतिवामपंथी दिशा में मुड़ जाएँगे।

स्त्री मजदूरों का यूनियनीकरण करने एवं उनकी विशिष्ट समस्याओं को

उठाने की समस्या की सामन्यतया घोर जेपेशा की जाती है । वे सबसे कम मज़दूरी प्राप्त करती हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक शोषण से ब्रह्म हैं तथा छेत्री का प्रायः पहला लिंगार बनती है । मातृत्व लाभ के अलावा फ़ैक्टरी शिषुगृह जैसी विशेष मर्मों, माताओं के लिए अपने बच्चों को दूध पिलाने की मुश्विधाएँ, नहाने-धोने और शौचालय की मुश्विधाओं की मांग उनकी तरफ से उठायी जानी चाहिए ।

अनुभव यह बताता है कि जब भी कभी उन्हें सधर्म में खोना गया है, वे सचिविक जुझाल तबके साथ है तथा उन्हें सधर्म में खोना गया है । मुख्य बात है स्त्री ट्रेड यूनियन संगठनकारियों को शिक्षित करना और यह देखा गया कि बैठकों का समय स्थान आदि स्थिरों की सभाओं के लिए इस तरह तय किए जाएँ कि वे उनकी मुश्विधा के अनुसार रहें । वर्तमान समय में स्थिरों के यूनियनकरण की संभावनाएँ बढ़ गयी हैं ।

वर्णीय संघटन में हेतेवाले परिवर्तनों से वैदा हेतेवाली समस्याओं के अलावा आधुनिक मज़दूर वर्गों की भौतिक स्थिति, ब्रवहरात्मक ढांचों और विकासशील आवश्यकताओं के कारण अन्य समस्याएँ भी उत्पन्न हुई हैं ।

बड़े औदोगिक केंद्रों में 'उपनगरीकरण' की भी समस्या है । कुछ दशक पूर्व, भौतिक रूप से लाम्बंदी का कार्य सरल था व्यांक हजारों लोगों को रोजगार देने वाली मिले और फ़ैक्टरियाँ चारों ओर चारों से घिरे शहरी केंद्रों में स्थित थीं । प्राथमिक विधि भी मज़दूरों के समझों को पारी शुरू होने से पहले अथवा बाद में गेट पर पफ़न लेना । ट्रेड यूनियन संगठनकारी और नेता गेट मीटिंगों में लंबे-चौड़े भाषण देने में माहिर थे । गेट पर चिपके हुए पोस्टर और यदा-कदा फ़ैक्टरी के आसपास वितारित हाथ के लिए पुर्जों में संदेश निहत होता था । यह बड़े दफ़तरों पर भी लागू होता था । यहरी विस्फोट ने बहुहाल शहरों के नियोजन और बाहरी स्वरूप को आधारभूत रूप से बदल दिया है । मज़दूरों और नियोक्ताओं का विशाल आकार उपनगरों में बिसक चुका है अब उन्हें घटने आने-जाने में खाली करने पड़ते हैं । घर वापस लौटने के लिए लोकल ट्रेनों, बसों अथवा किसी भी सवारी को पकड़ने के लिए बेहिसाब भीड़भाड़ रहती है । पारी जल्दी होने के बाद गेट पर यूप्सन के लिए कुछ ही लोग इच्छुक होते हैं । हृपते के सभी दिनों में ऐसा ही रहता है । छुट्टियों में उपनगरीय स्थानों में बिखरे हुए मज़दूरों का मीटिंग और जुलूसों में शामिल होने के लिए शहर आने का मन नहीं होता जब तक कि आंदोलन पुरी ऊँचाई तक न पहुँच जाए । ट्रेलिविजन माध्यम भी उन्हें घरों में बोध्य रखता है ।

इन मज़दूरों से कैसे संपर्क किया जाए? एक तरीका है 'भोजनकाल में एकत्रित होना' । गेट मीटिंगों और पोस्टरों के पुराने तरीकों की उपयोगिता हलाँकि खत्म नहीं हुई है, लेकिन भाषणों को और ज्यादा स्पष्ट व उद्देश्यपूर्ण एवं पोस्टरों को और अधिक आकर्षक होना चाहिए और उन्हें ऐसी जगहों पर लगाया जाना चाहिए, जहाँ वे 'ध्यान आकृष्ट' कर सकें । इस स्थिति में बिखरी हुई जगहों पर,

जहाँ काम के खत्म होने के बाद मजदूरों से संपर्क किया जा सके, सक्रिय कार्यकर्ताओं के समूहों को गठित करना एवं अधिक सूचनाप्रद पोस्टर, पचें और पैम्फलेट प्रकाशित करना महत्व रखता है।

सक्रिय कार्यकर्ताओं की एक विशाल संख्या और जनता को सूचनाएँ देने व शिक्षित करने के लिए ट्रेड यूनियन अखबारों और राजनीतिक अखबारों की भूमिका पर भी जोर दिया जाना चाहिए। सभी ट्रेड यूनियनें अपने अखबार प्रकाशित नहीं कर सकतीं। मगर केंद्र व राज्य स्तर के अखबारों और औद्योगिक अखबारों को गंभीरतापूर्वक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ट्रेड यूनियन अखबारों की गुणवत्ता, उनकी आवृत्ति और उनके वितरण को कई गुना बेहतर बनाया जाना होगा।

भारत का औद्योगिक मानचित्र हजारों मजदूर बस्तियों से आच्छादित है... उनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है।

सुरक्षा मजदूरों, विद्युत श्रमिकों की बस्तियाँ, इस्पात नगर-स्थेत्र, नवीन व आधुनिकीकृत खानों, तेल, पेट्रो-रसायन आदि संकुलों की बस्तियाँ हैं; बड़े शहरों में सरकारी कर्मचारियों की बस्तियाँ भी पैदा हुई हैं।

मजदूर बस्तियाँ न सिर्फ़ शहरी इलाकों में ही पायी जाती हैं बल्कि गाँवों में भी पायी जाती हैं, जहाँ वे गाँवों के समुद्र में द्वीप की तरह दिखायी पड़ती हैं।

औद्योगिक मजदूर कुकुरमुत्तों की तरह उगती हुई स्लमों और झोंपडपट्टियों की एक बड़ी संख्या में भी रहते हैं। मगर यहाँ वे अर्द्धसर्वहारा व लुम्पेन तत्वों से मिलेजुले रहते हैं। स्लमों और झोंपडपट्टियों में संगठन और संघर्ष की समस्याओं की अपनी चारित्रिक विशेषताएँ हैं। यही बात सरकारी आवास बोर्ड कॉलोनियों के बारे में भी सच है जहाँ इसी तरह यद्यपि कुछ भिन्न किस्म का मिश्रण पाया जाता है।

ट्रेड यूनियन संगठनकर्ता प्रायः मिलों, फँक्टरियों अथवा दफ्तरों के गेटों पर मजदूरों से मिलते हैं, उन्हें लबे-चौड़े भाषण देते हैं या फिर उनसे चर्चा करते हैं मगर बहुत कम ऐसा होता है कि वे उनसे उनके घरों पर मिलते हों।

और यही वह बिंदु है जहाँ उनसे निकट संपर्क स्थापित करने, उन्हें शिक्षित करने, उनकी राजनीतिक चेतना बढ़ाने और इस प्रकार अपना आधार मजदूर करने में हमारी कमज़ोरी ज्ञालकती है।

फँक्टरी का सायरन बजने के साथ ही मजदूर की जिंदगी आरम्भ या खत्म नहीं होती। फँक्टरी अथवा दफ्तर में बिताये गये आठ घंटों के बाद शेष समय वह बस्ती या उसके आसपास बिताता है। वही उसका सामाजिक जीवन तथा उसके अन्य सम्बन्ध विकसित होते हैं।

जब वह अपने क्वार्टर पर लौटता है और फँक्टरी की धूल-मिट्टी और कालिख

साफ़ करता है, वह भी उन सभी चीजों को बिसारने के लिए प्रबृत्त होता है जो उसे उसके कार्यस्थल पर प्रभावित करती है व गतिशील बनाती है। उन अवसरों को छोड़कर जबकि अंदेलन पूरे जोर पर हो और मालिकों तथा सरकार के साथ गंभीर टकराव अथवा संघर्ष की स्थिति पैदा हो गयी हो, ऐसा होता है। शेष दिनों के लिए वह उन गतिविधियों में फैसा रहता है जो उसे वर्ग बैठना की ओर प्रेरित करते वाली गतिविधियों की ओर उलटी होती है। इनमें धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, यहाँ तक कि जातिवादी व सांप्रदायिक गतिविधियाँ भी सम्मिलित हैं जो हमारी विशिष्ट पृष्ठभूमि में उसके दिमाग पर ब्यापक प्रभाव डालती हैं।

जहाँ कहीं इस तरह की गतिविधियों का भी अभाव होता है, निरी ऊब उसे उक्सानदेव व नकारात्मक गतिविधियों की तरफ प्रेरित करती है—खासकर तब जब बुर्जुआ व्यवस्था के गहराते हुए संकट के साथ समाज में सामाजिक और नैतिक सूख हर रोज पतनशील होता जा रहा हो।

जबकि सबंध मजदूर कम-से-कम गेट पर, यूनियन के दफ्तर में, या फिर मैदान में लाल झंडे का सामना करता है और इसीलिए उसके दिमाग पर कब्जा करने के लिए दो विपरीत प्रभावों में परस्पर प्रतिपर्द्धा होती है, उसके पल्टी व बच्चे लाल झंडे के संदेश के प्रत्यक्ष संपर्क में इस तरह नहीं आ पाते।

अतः हम देखते हैं कि जबकि ट्रेड यूनियन के मुद्दों पर मजदूर बड़ी संख्या में लाल झंडे के मिछे एकजुट होते हैं, राजनीतिक, सामाजिक या सांप्रदायिक मुद्दों पर वे और उनके परिवार के सदस्य एकदम दूसरे झंडे के नीचे एकन हो जाते हैं, यहाँ तक कि सर्वाधिक ऊझाल ट्रेड यूनियन संघर्ष एवं सर्वाधिक सक्रिय ट्रेड यूनियन भी इस स्थिति को मूलभूत रूप से बदलने में असफल रही है।

बहुत-सी ऐसी बरिती है जहाँ मजदूरों का बहुताहुदक मधुदय हमारी युनियनों व हमारी ट्रेड यूनियनों के प्रभाव में है, मगर इसके बावजूद अगर हम दोबारों को, उन पर लिखे नारों और इबारतों को देखें तो हम पाएँगे कि ये हमारे अपने नारों के बजाय कुछ और ही हैं। जो गतिविधियाँ वहीं होती हैं, वे हमारी विचारधारा, राजनीति और हमारे क्रांतिकारी वर्ग-इकट्ठों का तिषेक्षण करती हैं।

अगर हमें इस स्थिति को बढ़ाता है, तो ट्रेड यूनियन कार्य के साथ-साथ हमें वास्तवों में रहने वाले मजदूरों और उनके परिवार के महस्यों के बीच बहुत-सी दूसरी तरह की गतिविधियों को भी विकसित करता होगा। एक ही उद्योग से संबंधित मजदूरों के विशाल संकेदांग की मौजूदगी इन विविध प्रकार के पोजनाबद्द रूप से हाथ में लेने के लिए उत्तम अवसर प्रदान करती है।

हरेक बरसी में हमें नियमी-न-क्रियाएँ तरह के ‘कल्याणकारी संघों’ को गठित करने का प्रयास करना होता है। बड़े नगरों में क्षेत्रों के हिसाब से एक से अधिक ऐसे संघ

गठित करना आवश्यक हो सकता है।

ट्रेड यूनियन और राजनीतिक नेतृत्व के प्रयासों से प्रारंभिक रूप में गठित संघ, जितना संभव हो, उतने व्यापक आधार वाले होने चाहिए, अनेक नागरिक मुद्दों जैसे पानी, बिजली, सफाई, जोड़े वाली सड़कें, स्कूल की सुविधाएँ या बच्चों के लिए स्कूल-बसों की सुविधा आदि, को हाथ में लेने के लिए वे आवश्यक और उपयोगी हैं।

कुछ नगर-क्षेत्रों में मजदूरों और उनके परिवार के सदस्यों को अपने स्थानीय संगठनों को चुनने के नागरिक अधिकार से वंचित किया जाता है। यूनियन और व्यापक आधार वाले कल्याणकारी संघों को इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए लड़ना है।

संयोगवश, यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र आवास बस्तियों का निर्माण करता है, तथापि वह ऐसा सभी मजदूरों के लिए नहीं करता बल्कि केवल कुछ ही प्रतिशत के लिए करता है। पास के इलाकों या गाँवों में कुछ मजदूर अपने खुद के मकानों में रहते हैं। शेष लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है।

अतः हम देखते हैं कि अधिकांश बस्तियों के आसपास गंदी बस्तियाँ उग आती हैं। और मजदूरों के एक निश्चित तबके को उनमें रहना पड़ता है। निःसंदेह, उन्हें वे सुविधाएँ नहीं मिल पातीं जो उनके अधिक सौभाग्यशाली भाईबंद पाते हैं। यह एक मुद्दा है जिसे हमें उठाना चाहिए।

इसके साथ ही हमें उन गैर-मजदूर तबकों की समस्याओं को नहीं नकारना चाहिए जो बस्तियों में छोटे दुकानदारों के रूप में जमा हो जाते हैं और मजदूरों को अपनी सेवाएँ देते हैं। हमारी यह देखने की कोशिश होनी चाहिए कि हमारे कार्यकर्ता इन सभी गतिविधियों में और कल्याणकारी संघों के कार्य में प्रमुख हिस्सा लें क्योंकि केवल यही चीज़ सुनिश्चित कर सकती है कि उनकी गतिविधियों का दायरा व्यापक बने।

शहरी इलाकों में गंदी बस्तियों का प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होना पूँजीवादी विकास का, विशेषकर हमारे जैसे विकासशील देशों में, एक नियम है, जहाँ आधिक विकास के साथ-साथ दरिद्रता, देहाती गरीबी एवं सामाजिक व आर्थिक शोषण भी विकसित होते हैं और बड़ी मात्रा में ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों की ओर प्रवासन को प्रेरित करते हैं। जैसे-जैसे अधिक-से-अधिक लाभ कमाने की होड़ में पूँजी अपने अनथक अभियान में आगे बढ़ती है, यह ज्यादा-से-ज्यादा शहरी और उपनगरीय भूमि पर कब्जा करती जाती है एवं श्रमिक आबादी व रोजगार के इच्छुकों को अवैध रूप से कब्जा कर गंदी बस्तियों में रहने वालों के रूप में दलदली बैकार भूमि और साँपों व कीड़ों से भरपूर परती जमीन के नरक में धकेल देती है। गंदी बस्तियों की जनसंख्या को नियंत्रित रखने के लिए यह लुम्पेन—और गंदी

बस्तियों के मालिकों, गैर-कानूनी ढंग से शराब बनाने वालों व मटका वालों (सद्गुणवाने वालों), 'दादा' और 'मवालियों' की परजीवी सेना को पालता और बनाए रखता है, ठीक वैसे ही जैसे फँकटरियों में उन पर नियंत्रण रखने के लिए यह ठेकेदारों और ओवरसियरों की फ़ौज को रखता है।

मजदूरी देने के साथ-साथ मजदूर को आवास प्रदान करना पूँजीपति का दायित्व नहीं है। पूँजीवादी राज्य आवास के अधिकार को एक जनवादी व मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं देता।

संगठित क्षेत्र में ट्रेड यूनियन आंदोलन ने मजदूरों और कर्मचारियों के लिए 'मकान किराया भत्ता' के लिए संघर्ष किया है और जीत हासिल की है। एक अधिक वास्तविक आधार पर इसने मकान किराये भत्ते में बढ़ोत्तरी हासिल की है। इसने सरकार को आवास बोर्ड गठित करने और औद्योगिक आवास, निम्न आय-वर्ग और मध्यम आय-वर्ग आवास आदि का निर्माण कार्य हाथ में लेने के लिए बाध्य किया है। इसने कुछ नियोक्ताओं को बस्तियाँ बनाने और कुछ ठेकेदारों को निर्माण-स्थलों पर अस्थायी आवास सामग्री मुहैया कराने के लिए बाध्य किया है। द्विपक्षीय समझौते के हिस्से के रूप में अनेकों यूनियनों ने 'आवास अग्रिम' हासिल किया है। और अभी तक, सभी शहरी केन्द्रों और औद्योगिक संकुलों में आवास का प्रश्न ज्यादा-से-ज्यादा प्रखर होता जा रहा है। अतः आवास के प्रश्न को ट्रेड यूनियन कार्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए।

दूसरा फ़ौरी कार्य महिलाओं को एकजुट करना है जो बस्तियों में रहती हैं और उन्हें महिला संघ की इकाइयों के रूप में गठित करना है। संघर्ष और कारंवाइयों के दौरान ऐसे महिला संगठन न सिर्फ विश्वसनीय निधि के रूप में कार्य करते हैं, बल्कि वे अपनी स्वतंत्र कार्यवाइयाँ भी विकसित करते हैं। महिला संघ इकाइयों की गतिविधियों के फलस्वरूप बस्तियों के सामाजिक और नैतिक वातावरण में हमेशा पर्याप्त सुधार होता है।

ऐसे ही प्रयास बस्तियों में रहने वाले मजदूरों के नौजवान बेटों को युवा संघों और नौजवान पायोनियरों की इकाइयों में संगठित करने के लिए किये जाने चाहिए। हर स्थिति में इस कार्य की उपेक्षा के अत्यंत नुकसानदेह परिणाम निकलते हैं।

जबकि मजदूर लाल झंडे का एक विश्वासपात्र समर्थक हो, यह हो सकता है कि युवाओं के विशाल तबक्कों, उसी मजदूर के बेटों या छोटे भाइयों पर शत्रुतापूर्ण प्रभावों का गहरा असर हो। क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन और राजनीतिक नेतृत्व के लिए यह एक दूसरी समस्या पैदा करता है।

अतः यह ज़रूरी है कि 'जवानी में ही उनसे संपर्क' किया जाये और उन्हें युवा संघ व नौजवान पायोनियरों के कार्य में खींच लिया जाये। इस संबंध में अखिल भारतीय युवा संघ नेतृत्व की मदद और सहयोग के साथ ट्रेड यूनियन नेतृत्व को

गंभीर कदम उठाने चाहिए।

बस्तियों के भीतर चिकित्सित होती सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इनमें कलबों अथवा सामुदायिक केन्द्रों, अध्ययन-कक्षों और पुस्तकालयों के गठन एवं नाटक व गायन मंडलियों का संगठन शामिल हैं। सभीषणर्ती इष्टा इकाइयों से इस बारे में मदद ली जा सकती है।

संस्कृति के लिए प्यास इतनी मज़बूत है और हमसे पैदा होती हुई वस्तु इतनी कम, यहाँ तक कि गैर-मौजूदा है कि हमारे अपने मज़दूर और उनके परिवार दूसरे स्रोतों की ओर उन्मुख होने लगते हैं। प्रतिक्रियावादी पुनरुत्थानवाद एवं और जातिगत विभाजकता के बढ़ते हुए वातावरण में, जो जनता की प्रगतिकामी, जुझारू और वामोन्मुख मनोदशा का विरोध करने के लिए सोच-समझकर लक्षित है, इन दूसरे स्रोतों द्वारा डाला गया प्रभाव वेहिसाब जहरीला है।

प्रत्येक वर्ष उपयुक्त मौसमों में बहुत से त्यौहार मनाये जाते हैं। बहुत से अवसरों पर मुद्दा यह होता है : कौन विभिन्न संघों, कलबों या अस्थायी इकाइयों पर नियंत्रण रखता है जो त्यौहारों या कार्यक्रमों को संचालित करते हैं? आम मज़दूर और उनके परिवार इन सभी त्यौहारों में उत्साहपूर्वक हिस्सा लेते हैं।

क्या उन्हें उन लोगों के हाथों में छोड़ दिया जाना चाहिए जो उनके महत्व को कम करने का प्रयास करते हैं और उनका अपने प्रतिक्रियावादी व साम्प्रदायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं अथवा सामाजिक प्रगतिशील शक्तियों द्वारा उनका प्रयोग किया जाना व उन्हें समझाया जाना चाहिए ताकि वे एक नयी अंतर्बस्तु के साथ पुराना रूप ग्रहण कर सकें? निश्चित रूप से ऐसे सभी कार्यक्रम अपनी प्रकृति से ही भागीदारी की माँग नहीं करते। इस क्षेत्र में विभेद और निर्णय किया जाना चाहिए।

कुल मिलाकर यह मज़दूर बस्तियों के विभिन्न क्षेत्रों में—ट्रेड यूनियन, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक—मज़दूरों, स्थियों और नौजवानों के बीच—समानांतर और समकालिक कार्य को हाथ में लेने का प्रयत्न है। यहाँ विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ और उन्हें संचालित करने वाले संगठनों का समन्वय करने के काफ़ी अवसर मौजूद हैं।

उन बस्तियों में, जो देहातों में स्थित हैं, हमें इसके अलावा खेतिहार मज़दूरों और मेहनती किसानों के साथ सचेतन संबंध और संपर्क स्थापित करने चाहिए।

ट्रेड यूनियन संगठनों को अपने संसाधन और संस्तरों को इन तबक्कों को किसान सभा और खेत मज़दूर यूनियन संगठित करने, हरेक अवसर पर उनकी ओर बिरादराना हाथ बढ़ाने और जब कभी उनके संघर्ष हों, उनसे स्वयं को संबद्ध करने के कार्य में लगा देने चाहिए। जब कभी ग्रामीण निहित स्वार्थों द्वारा कमज़ोर तबक्कों के खिलाफ़ हमले हों, उन्हें समर्थन के लिए एकजुट हो जाना चाहिए।

मजदूर वर्ग की कार्रवाइयों और जन-संघर्षों और मजदूर प्रमुख तत्व हैं, की बहती हुई लहर को रोकने के प्रयास में प्रतिक्रियावादी निहित स्वार्थ दर्किया-तस्पीत, धार्मिक तत्ववाद, साम्राज्यिकता, जातिवाद, क्षेत्रियतावाद के विचार-धारात्मक माल—कोई भी और हरेरक क्रिस्म का हथियार जो सेहनतकश जनता को विभाजित और विचारित करता है—का प्रयोग कर रहे हैं। आज की दुनिया में तभी चुनौतियों का बहासा लेकर डुर्जुआ प्रचारक मजदूर वर्ग के बीच वर्ण-समन्वय और वर्ण-शान्ति, ‘राजनीति’ से तटस्था और विरोध (जिसका सीधा अर्थ है कि दुर्जुआदी राजनीति के आगे समर्पण), उपभोक्तवाद आदि विचारधाराओं को प्रचारित कर रहे हैं। बहरहाल, जीवन स्वयं ही अधिक-से-अधिक राजनीतिक कार्रवाइयों में, राष्ट्रीय प्रक्रिया और अखंडता के मुद्दे पर जन-संघर्षों में, साम्राज्यिक एकता की सुरक्षा में मजदूर वर्ग को खींच रहा है।

हमारा कार्य है मजदूरों के संघर्षों के जीवनानुभवों को समाजवाद की बैज्ञिक शिक्षाओं से जोड़ना। देउ यूनियनों में विचारधारामूलक कार्यों को काम करके अँकना व इसकी उपेक्षा करने का अर्थ है मजदूरों को पूंजीवादी विचारधारा का धिकार बनने देना। लेनिन के शब्दों का यहाँ स्मरण करना कफी उपयोगी है: “पूंजीवादी विचारधारा समाजवादी विचारधारा की तुलना में कफी पुरानी है... यह ज्यादा पूर्ण रूप से विकसित है और इसके पास प्रचार-प्रसार के कहीं ज्यादा साधन मौजूद है।”

अतः देउ यूनियन शिक्षा अर्थात् विचारधारामूलक शिक्षा के कार्य को प्राथ-मिकारा दी जानी चाहिए। कैप और विद्यालय, अध्ययन केंद्र और अध्ययन समूहों को कमबद्ध रूप से नियोजित करना होय।

भृष्टाचार, छिटपुट चोरी, सार्वजनिक सेवा और सार्वजनिक संपत्ति के प्रति उदासीन व गौन-जिम्मेदार प्रवृत्ति, अधिकतम व्यवितरण लाभों की आकांक्षा और आत्म-प्रशंसा, यही ‘मुक्त समाज’ के ‘पूल्य’ और ‘गुण’ हैं। यह सार्वजनिक जीवन में नैतिक उच्छृंखलता और प्रतनशीलता का बातावरण फैला रहा है। ठोस रूप में, यह हमारे सार्वजनिक क्षेत्र को तुकसान पहुँचा रहा है। इस सबके खिलाफ संघर्ष केवल एक जागरूक मजदूर वर्ग द्वारा किया जा सकता है, जो उसी समय इस संक्रमक रोग से स्वयं को प्रशावित होने से बचता है। सामाजिक विकास का उद्देश्य केवल मजदूर वर्ग द्वारा ही आगे बढ़ाया जा सकता है जो नैतिक रूप से मजबूत है और एक अग्रणी विचारधारा से सन्तुष्ट है।